"व्यापारिक बैंको के वित्त का कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव"

(उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

से

पी–एच0डी0 (अर्थशास्त्र) उपाधि हेतु

प्रस्तुत



शोध-प्रबन्ध

शोध निर्देशक

(डॉ0 मुकेश द्विवेदी)

रीडर एवं विभागाध्यक्ष

अर्थशास्त्र विभाग

रा०स्व०ग्रा०उ० (पो०ग्रे०) कालेज

पुखरायाँ, कानपुर देहात

सह–निर्देशक

(डॉ0 रजनी त्रिपाठी)

रीडर, अर्थशास्त्र विभाग

डी०वी० कालेज, उरई

प्रस्तुतकर्त्ता

(पर्वत सिंह)

शोध छात्र

शोध केन्द्र

डी0वी0 कालेज, उरई

सन् 2008 ई0

डॉ० मुकेश द्विवेदी
एम.फिल., पी-एच.डी.

रीडर एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र
रा०स्व०ग्रा०उ० (पो०ग्रे०) कालेज
पुखरायाँ (कानपुर देहात)
जिला प्रतिनिधि/सदस्य कार्यकारिणी
कानपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ
9838687305

पत्रांक .... दिनांक 14.4.2008

प्रमाण–पत्र

सहर्ष प्रमाणित किया जाता है कि श्री पर्वत सिंह ने " व्यापारिक बैंकों के वित्त का कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव " (उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में) विषय पर पी–एच.डी. उपाधि के लिए बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के नियमों का पालन करते हुये 200 से अधिक दिनों तक मेरे निर्देशन में अपना शोध कार्य सम्पन्न किया।

इनकी वृत्ति सारगृही एवं दृष्टि अन्वेषी रही है। इन्होंने बड़ी लगन, परिश्रम एवं रुचि के साथ अपने अभिप्रेत कार्य को पूर्ण किया है। मेरी दृष्टि से यह शोध कार्य मौलिक एवं ज्ञान के क्षेत्र में प्रेरणादायी होगा। अतः निरीक्षण के पश्चात् इनकी सफलता की कामना करते हुये इस शोध प्रबन्ध को मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान करता हूँ।

Dwivedi

डॉ0 मुकेश द्विवेदी
(शोध–निर्देशक)

प्राक्कथन

वर्तमान शोध प्रबन्ध में व्यावसायिक बैंकों का कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने के योगदान को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न जनपदों को अध्ययन में शामिल किया गया है। कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत 6 जनपद कृमशः फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर व कानपुर देहात हैं। वैसे तो सम्पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि यह एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है आर्थिक विकास के प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप कृषि का महत्व कृमशः कम होता जाता है पर अभी भी देश की आधे से अधिक जनसंख्या कृषि से अपनी आजीविका अर्जित करती है।

उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक बड़ा राज्य है इसकी भी आधे से अधिक जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर क्षेत्र को अध्ययन के लिए चुना गया है। जिसके अन्तर्गत उपरोक्त जनपद आते हैं। यह एक व्यष्टि स्तर का अध्ययन है। व्यष्टि स्तर के अध्ययन के अन्तर्गत किसी अध्ययन इकाई की सम्पूर्ण इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि उनमें से कुछ इकाइयों का चुनाव सांख्यिकी शास्त्र के किसी विशेष सिद्धान्त के आधार पर करके उनका अध्ययन किया जाता है। वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत भी अध्ययन की इसी प्रक्रिया को अपनाया गया है।

कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में 188 व्यावसायिक बैंक कार्यरत हैं इनमें से 30 प्रतिशत इकाइयों का रैन्डम सैम्पलिंग के आधार पर चुनाव करके इनका अध्ययन किया गया है। इस प्रकार यह अध्ययन विभिन्न जनपदों में कार्यरत 57 व्यावसायिक बैंक शाखाओं पर आधारित है। ये शाखायें विभिन्न जनपदों के विभिन्न विकास खण्डों में कार्य कर रही हैं।

वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक समंक चुनी हुयी व्यावसायिक बैंकों की इकाइयों में व्यक्तिगत रूप से जाकर बैंक कर्मचारियों से पूछतांछ करके प्राप्त किये गये हैं। और द्वितीयक संमक जनपद स्तर पर इन बैंकों से प्रकाशित विभिन्न पत्र एवं पत्रिकाओं से एकत्र किये गये हैं।

कृषि के सम्बन्ध में किसानों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त

शर्तों पर वित्त प्रदान करने की रही है यद्यपि इस क्षेत्र में सहकारी समितियों का प्रारम्भ किया गया पर उनके द्वारा उनके संसाधनों के सीमित होने के कारण किसानों को पर्याप्त मात्रा में वित्त नहीं प्रदान किया जा सका। वर्ष 1969 में व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् से इन बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उचित दरों पर वित्त प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हुई है। इस दिशा में इन बैंकों को कितनी सफलता प्राप्त हुई है इसके मूल्यांकन करने का प्रयास वर्तमान अध्ययन में किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को निम्नलिखित महत्वपूर्ण अध्ययायो में विभक्त किया गया है।

1. कृषि साख प्रणाली का वर्तमान स्वरूप
2. साख के संगठित स्रोत
3. अध्ययन क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक दशायें
4. व्यापारिक बैंकों का विकास
5. कृषि साख में व्यापारिक बैंकों का वित्त
6. व्यापारिक बैंकों के वित्त का प्रारूप
7. व्यापारिक बैंकों से प्राप्त साख के लाभार्थियों का विश्लेषण
8. निष्कर्ष एवं सुझाव

शोध प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में कृषि क्षेत्र में असंगठित संगठनों के माध्यम से प्राप्त होने वाले वित्त तथा अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण कमेटी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट, अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत स्पष्ट की जाने वाली परिकल्पनाओं को स्पष्ट किया गया है।

द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण के पूर्व संगठित स्रोतों से प्राप्त साख तथा राष्ट्रीयकरण के पश्चात् संगठित स्रोतों से कृषि क्षेत्र को प्राप्त वित्त, देश में वाणिज्यिक बैंक कार्यालय संख्या तथा अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न जनपदों की सामाजिक व आर्थिक दशाओं को स्पष्ट किया गया है।

तृतीय अध्याय के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का प्रारूप, जनसंख्या का

आर्थिक वर्गीकरण, कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादन का स्वरूप व कृषि साख के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है।

चतुर्थ अध्याय के अन्तर्गत देश में बैंकिंग व्यवस्था का विकास, कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में बैंकिंग व्यवस्था का विकास तथा कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित व्यावसायिक बैंकों द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षों में वितरित ऋण व जनता द्वारा स्वीकार की गई जमाओं के तुलनात्मक अध्ययन को स्पष्ट किया गया है।

पाँचवें अध्याय में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर क्षेत्र में कार्यरत समस्त व्यावसायिक बैंकों द्वारा जनपद स्तर पर विभिन्न वित्तीय वर्षों में वितरित ऋण के तुलनात्मक अध्ययन को स्पष्ट किया गया है।

छठे अध्याय में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा समय के आधार पर वितरित साख को जनपद स्तर पर स्पष्ट किया गया है।

सातवें अध्याय के अन्तर्गत कानपुर क्षेत्र में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों में से 30 प्रतिशत बैंक शाखाओं का रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर अध्ययन के लिए चयन कर इन शाखाओं द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वितरित ऋण की मात्रा व लाभार्थियों की संख्या तथा साख प्राप्त लाभार्थियों में से 25 प्रतिशत लाभार्थियों का रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर चयन कर उनकी बैंक शाखाओं से नामावली लेकर साख प्राप्त लाभार्थियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके बैंकों से प्राप्त वित्त के उपयोग व इस वित्त का उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव तथा इन साख प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा स्पष्ट किये गये सुझाव व बैंकों की कार्यप्रणाली के प्रति या वित्त प्राप्त करने के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं आदि को स्पष्ट किया गया है।

आठवें अध्याय के अन्तर्गत शोध प्रबन्ध में स्पष्ट की गई परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है। तथा निष्कर्ष व सुझाव दिये गये हैं।

प्रबन्ध की यात्रा एक महायात्रा होती है। इसमें अनेकानेक ऋण, स्नेह, आत्मीयता

के दर्शन होते हैं। मनुष्य की यही पूँजी है– यही जीवन धन है। इस कार्य में श्रद्धेय गुरूवर डॉ0 मुकेश द्विवेदी, रीडर एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, रामस्वरूप ग्राम उद्योग स्नातकोत्तर कालेज, पुखरायाँ कानपुर देहात का मैं हृदय से ऋणी हूँ जिनके मार्गदर्शन के अभाव में शायद ही यह यात्रा गंतव्य तक पहुँचती। इनके स्नेह और ज्ञान ने मुझे अभिभूत किया है। डी0वी0 कालेज उरई की विद्वान रीडर, डॉ0 रजनी त्रिपाठी का मैं हृदय से ऋणी हूँ जिन्होंने शोध कार्य को गंतव्य तक पहुँचाने में उत्तम सुझाव व मार्गदर्शन किया। शायद इनके मार्गदर्शन के अभाव में भी शोध कार्य को पूर्ण कर पाना किंचित मात्र सम्भव नहीं था। श्रद्धेय गुरूवर डॉ0 एस0 पी0 तिवारी (प्राचार्य) रामस्वरूप ग्राम उद्योग महाविद्यालय पुखरायाँ, कानपुर देहात का हृदय से ऋणी हूँ जिनके संरक्षण व सानिध्य में यह शोध कार्य पूर्ण करने में मदद मिली। डॉ0 एन0डी0 समाधिया प्राचार्य डी0 वी0 कालेज, उरई का जीवन पर्यन्त ऋणी रहूँगा। जिन्होंने शोध कार्य पूर्ण करने के लिए समय–समय पर हमें मार्गदर्शित किया। डॉ0 रजनी त्रिपाठी, रीडर एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग, डॉ0 एस0सी0 मिश्र, रीडर एवं अध्यक्ष भूगोल विभाग, डॉ0 राकेश शुक्ल, रीडर हिन्दी विभाग, डॉ0 सविता गुप्ता, रीडर एवं अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग, डॉ0 रंजन तिवारी, रीडर हिन्दी विभाग, डॉ0 रामेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, रीडर एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग, डॉ0 मीनाक्षी व्यास, प्रवक्ता एवं अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, डॉ0 हेमेन्द्र सिंह, प्रवक्ता एवं अध्यक्ष राजनीति विभाग, डॉ0 प्रबल प्रताप सिंह तोमर, प्रवक्ता एवं विभागध्यक्ष वाणिज्य संकाय का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिनके कुशल मार्गदर्शन व स्नेह से शोध कार्य को पूर्ण करने में सुगमता प्राप्त हुई। श्री हृदयकान्त ग्रन्थालय अधीक्षक, डी0 वी0 कालेज उरई का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिनके कुशल मार्गदर्शन व समयाभाव में शायद ही यह कार्य पूर्ण हो सकता। श्री केदार नाथ द्विवेदी ग्रन्थालय अध्यक्ष व श्री श्रीकान्त तिवारी ग्रन्थालय सहायक जिनका सरल–तरल स्नेह उनके स्वभाव की अपनी विशेषता है। शोध पूर्ण करने हेतु इनके द्वारा व्यक्त किये गये विचार व पुस्तकों का अवलोकन करने हेतु दिया गया अमूल्य समय जीवन पर्यन्त स्मरण रहेगा। श्री राघवेन्द्र सिंह (शोध छात्र) को तो मैं जीवन पर्यन्त विस्मृत नहीं कर सकता जिन्होंने समय–समय पर आने वाली प्रत्येक समस्याओं को सरल व सुगम बनाया है। अतः इनके सहज हृदय का मैं ऋणी हूँ। पूज्यनीय माता जी श्रीमती शीला देवी व पूज्य पिता जी श्री बाबूराम का जिन्होंने मेरी आत्मा को इस शरीर में आकार देकर बाल्यकाल में उंगली पकड़कर मात्र चलना ही नहीं सिखाया वरन् मानसिक विकास के अन्तर्गत बौद्धिक रूप से तार्किक एवं विश्लेषणात्मक समझ को विकसित किया। जिसके फलस्वरूप यह शोध कार्य करने में समर्थ हो सका। अपने हृदय की कृतज्ञता और एक व्यक्ति के

प्रति अर्पण करने में मुझे गौरव का अनुभव होता है जिन्हें कर्म योगी कहने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता है। श्री ओम प्रकाश, श्री प्रहलाद सिंह, श्री हरमन सिंह, श्री सरमन सिंह व श्री सुनील कुमार का मैं चिर ऋणी हूँ जिनके संरक्षण में बाल्यावस्था से लेकर आज तक जीवन को विकसित करने में सहयोग प्राप्त हुआ। जो मेरे भाई भी हैं, अध्ययनशील रहने के लिए सदैव प्रेरणा देते रहे हैं। समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे आभार व्यक्त करना भी चाहिए या नहीं, मेरे जीवन की संगिनी, कोमलता की साक्षात् प्रतिमूर्ति श्रीमती अर्चना देवी जिनका स्नेहिल साथ व सहाय्य मैं मात्र अनुभव कर सकता हूँ व्यक्त नहीं। कानपुर क्षेत्र के समस्त जनपदों के अर्थ एवं संख्या अधिकारी तथा कार्यालय से सम्बन्धित समस्त स्टाफ का मैं जीवन पर्यन्त आभारी रहूँगा। जिन्होंने शोध कार्य को गति प्रदान करने के लिए शोध कार्य में प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक आंकड़ों को उपलब्ध कराने में मदद की। कानपुर क्षेत्र के समस्त जनपदों के लीड बैंक प्रबन्धक व सम्बन्धित स्टाफ को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिनके द्वारा शोध कार्य को पूर्ण करने में आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराये गये। कानपुर क्षेत्र के समस्त बैंक शाखा प्रबन्धक का मैं जीवन पर्यन्त ऋणी रहूँगा जिनके द्वारा बैंकों से सम्बन्धित समस्त आंकड़े उपलब्ध कराये गये। जिसके कारण शोध कार्य को पूर्ण कर सका अन्त में मैं श्री सुशील कुमार प्रजापति, (अंश कम्प्यूटर पुखरायाँ, कानपुर देहात) जिन्होंने अथक एवं अदम्य उत्साह के साथ इस ग्रन्थ का टंकण किया, का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में मैं अपने कार्य की उत्कृष्टता का तनिक भी दावा नहीं करता हूँ क्योंकि शोध कर्ता एक विचारग्राही पाठक भर रहा है, अस्तु, व्यापारिक बैंकों के वित्त का कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जैसे विस्तृत विषय के सन्दर्भ में मात्र कुछ बूंदे ही निकाल कर रख सका हूँ। विद्वान समीक्षक मेरी इस सीमा को समझते हुये मुझे क्षमा करेंगे तथा मेरा उत्साहवर्द्धन करेंगे ऐसी मेरी आशा है।

विनम्रता एवं प्रणति के साथ।

सादर–

भवदीय
पर्वत सिंह
पर्वत सिंह
(शोध छात्र)

रामनवमी दिन सोमवार
14.04.2008



विषयानुक्रमणिका

अध्याय - एक

कृषि शास्त्र प्रणाली का वर्तमान स्वरूप

अध्याय – एक : कृषि शाख प्रणाली का वर्तमान स्वरूप

कृषि साख प्रणाली का अर्थ साख या ऋण की उस व्यवस्था से लगाया जा सकता है जिसके अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए किसानों को ऋण प्राप्त होता है। देश में कृषि ही एक ऐसा व्यवसाय रहा है जो अभी भी निजी क्षेत्र में है। सरकार द्वारा समय – समय पर किसानों को आवश्यक वित्तीय सहायतायें प्रदान की जाती रही हैं। 18वीं शदी के अन्तिम वर्षों में सरकार द्वारा भूमि सुधार एवं किसानों को आवश्यक वित्त प्रदान करने के सम्बन्ध में वर्ष 1883 व 1884 में इससे सम्बन्धित अधिनियम बनाये गये थे। इन्हीं अधिनियमों को कृषि विकास का प्रारम्भ कहा जा सकता है। इसके पश्चात् देश को स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न पचंवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा कृषि विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत कृषि साख व्यवस्था में भी समय–समय पर आवश्यक सुधार एवं विकास किया जा रहा है। इस पर संक्षेप में विचार किया जा सकता है। जो निम्न प्रकार हैं :–

उद्योग की भाँति कृषि क्षेत्र में भी विभिन्न फसलों के उत्पादन की प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर उत्पादन कार्य को पूरा करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। जिसे ऋण प्राप्त करके पूरा किया जाता है। कृषि क्षेत्र में भी किसानों को यह ऋण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता रहा है। कृषि क्षेत्र में विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए प्राप्त ऋण को कृषि ऋण या कृषि साख कहा जाता है। कृषि क्षेत्र में ऋण व्यवस्था के विकास व सुधार के लिए सरकार के द्वारा समय–समय पर आवश्यक प्रयास किये जाते रहे हैं। इसके अन्तर्गत प्रथम प्रयास के रूप में कृषि बैंकों की स्थापना को स्पष्ट किया जा सकता है। कृषि बैंकों की स्थापना का विचार सर विलियम वेडर वर्न (Ser William Wedder Burn) और जस्टिस एन0 सी0 रानाडे (Justic N.C. Ranade) द्वारा वर्ष 1882 में स्पष्ट किया गया था। इन बैंकों की स्थापना वर्ष 1883 और 1884 में पारित भूमि सुधार एवं कृषक ऋण अधिनियमों में स्पष्ट बातों के आधार पर किया गया था। इन अधिनियमों के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसानों को 3 से 6.5 प्रतिशत ब्याज की दर

पर उत्पादक कार्यों के लिए आवश्यक ऋण प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई थी। इसी सन्दर्भ में वर्ष 1904 में प्रथम सहकारी साख अधिनियम पारित करके सहकारी आन्दोलन का प्रारम्भ किया गया।

वर्ष 1947 में देश को स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पचास के दशक के प्रारम्भ से ही देश के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक आयोजन का मार्ग अपनाया गया। इसके लिए योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1950 में प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–1956) की रूपरेखा तैयार की गई। प्रथम योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि प्रधान होने के कारण कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। प्रथम योजना के कुल व्यय की लगभग 37 प्रतिशत व्यय राशि कृषि, सामुदायिक विकास, सिचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण आदि कार्यों के लिए निर्धारित एवं व्यय की गई। साथ ही कृषि क्षेत्र में साख की उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था के विकास के लिए एक अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी की नियुक्ति 1951–52 में की गई। जिसकी रिपोर्ट वर्ष 1954 में प्राप्त हुई। कमेटी ने कृषि क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न साख स्रोतों व संस्थाओं का विस्तृत अध्ययन किया और यह पाया कि कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने के कार्य में गैर संस्थागत स्रोतों का महत्व अभी भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार किसानों द्वारा लिए जाने वाले ऋणों का लगभग 93 प्रतिशत भाग अभी भी पेशेवर व कृषि महाजनों, सगे सम्बन्धियों, व्यापारियों एवं भूस्वामियों द्वारा ही प्राप्त होता है। जिसे कमेटी ने गैर साख संस्थागत स्रोतों के अन्तर्गत रखा है। संस्थागत स्रोतों में सरकार एवं सहकारी संगठनों का विकास किया गया है। जिनके द्वारा किसानों की ऋण आवश्यकता के मात्र 6 प्रतिशत भाग की आपूर्ति की गई है। किसानों के शेष एक प्रतिशत भाग की आपूर्ति व्यापारिक बैंकों द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने ग्रामीण क्षेत्र में साख प्रदान करने वाले विभिन्न स्रोतों के महत्व को अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है। कमेटी द्वारा स्पष्ट इन विभिन्न स्रोतों को सारणी संख्या 1 में स्पष्ट किया गया है।[1]

सारणी संख्या – 1

ग्रामीण साख के विभिन्न स्रोत

स्रोत	कृषि साख आवश्यकताओं की आपूर्ति प्रतिशत में
1	2
1. सगे सम्बन्धी	14.2
2. भू–स्वामी	1.5
3. कृषि महाजन	24.9
4. पेशेवर महाजन	44.8
5. व्यापारी एवं कमीशन एजेण्ट	5.5
6. सरकार द्वारा	3.3
7. सहकारी समितियाँ	3.1
8. व्यापारिक बैंक	0.9
9. अन्य	1.8
योग :–	100

सारणी संख्या– 1 से यह स्पष्ट है कि ग्रामीण साख/ऋण के लगभग 24.9 प्रतिशत तथा 44.8 प्रतिशत या कुल 69.7 प्रतिशत भाग की आपूर्ति कृषि एवं पेशेवर महाजनों द्वारा की जाती है। व्यापारिक बैंकों द्वारा मात्र 0.9 प्रतिशत कृषि साख/ऋण की आपूर्ति की गई है। इस प्रकार कृषि साख के अधिकांश भाग की आपूर्ति व्यक्तिगत स्रोतों द्वारा ही की जाती है। संस्थागत स्रोतों का महत्व अभी नहीं बढ़ सका है।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी द्वारा स्पष्ट किये गये कृषि साख/ऋण के विभिन्न स्रोतों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है–

(1) कृषि साख के संस्थागत स्रोत

(2) कृषि साख के व्यक्तिगत या गैर संस्थागत स्रोत

---

1. स्रोत– अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी रिपोर्ट (भाग–2) पृष्ठ 167 पर दिये गये तथ्यों पर आधारित ।

(1) कृषि साख के संस्थागत स्रोत : इन स्रोतों के अन्तर्गत उन संस्थाओं और संगठनों को रखा जा सकता है जिनके द्वारा किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार समय–समय पर ऋण या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से सहकारी संगठनों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, व्यापारिक बैंकों एवं सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को रखा जा सकता है।

(2) कृषि साख के व्यक्तिगत या गैर संस्थागत स्रोत : इन स्रोतों के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को रखा जा सकता है। जिनके द्वारा किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समय–समय पर आवश्यक ऋण या वित्त प्रदान किया जाता रहा है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने इन स्रोतों के अन्तर्गत कृषक व पेशेवर महाजन, भूस्वामी, सम्बन्धी व मित्र, व्यापारी व कमीशन एजेण्ट तथा अन्य व्यक्तियों को रखा है।

आर्थिक आयोजन के प्रारम्भ (1954) में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने यह पाया था कि किसानों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले ऋणों का 69.7 प्रतिशत या 70 प्रतिशत भाग की आपूर्ति कृषि एवं पेशेवर महाजनों द्वारा की जाती है। शेष में से 14.2 प्रतिशत भाग सगे सम्बन्धियों, 5.5 प्रतिशत व्यापारियों एवं कमीशन एजेण्टों , 3.3 प्रतिशत भाग सरकार, 3.1 प्रतिशत सहकारी समितियों तथा मात्र 0.9 प्रतिशत भाग की आपूर्ति व्यापारिक बैंकों द्वारा की जाती है। इस प्रकार संस्थागत स्रोतों से कृषि साख या ऋण का मात्र 7.3 प्रतिशत भाग ही प्राप्त हो सका था।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने कृषि साख के विभिन्न स्रोतों एवं संगठनों पर विचार करते हुए यह स्पष्ट किया कि कृषि क्षेत्र में साख या ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी संगठनों को ही सबसे उपयुक्त साधन माना गया था। अतः कमेटी की राय में सहकारी संगठनों का विकास किया जाना चाहिए। कमेटी ने सहकारी संगठनों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में विभिन्न कमियों को स्पष्ट किया। सहकारी संगठनों के इन कमियों को दूर करने के लिए इनके पुर्नगठन की सिफारिश की थी। कमेटी की राय में यदि सहकारिता असफल होती है तो भारत के

अधिकांश जनहित की रक्षा नहीं की जा सकती है। अतः सहकारिता का विकास किया जाना परम आवश्यक है।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी के सिफारिशों के पश्चात् लगभग एक दशक तक विचारकों द्वारा कृषि क्षेत्र में साख या ऋण प्रदान करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में सहकारी संगठनों के विकास के ही सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये जाते रहे हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1957–61) में आद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66) में पुनः कृषि विकास को देश को खाद्यान्नों के दृष्टिकोण से स्वावलम्बी बनाने, उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति तथा आयात को कम करने और निर्यात प्रोत्साहन आदि के उद्देश्यों को ध्यान मे रखकर तीसरी पंचवर्षीय योजना को कृषि प्रधान बनाया गया। योजना में उद्योगों के विकास के साथ–साथ कृषि विकास पर भी पर्याप्त महत्व दिया गया। तीसरी योजना में कृषि विकास के लिए सहकारी ऋण व्यवस्था के प्रारूप को निश्चित करने के लिए श्री वैकुण्ठ लाल मेहता की अध्यक्षता में सहकारी साख कमेटी की नियुक्ति वर्ष 1959 में की गई।[2] कमेटी ने तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में कृषि विकास के लिए आवश्यक ऋण की मात्रा का अनुमान लगाकर सहकारी संगठनों के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की। कमेटी की राय में सहकारी संगठनों का प्रत्येक स्तर पर पुर्नगठन एवं वित्तीय दृष्टिकोण से उन्हें मजबूत एवं स्वालम्बी बनाने के लिए उनके कार्यशील पूँजी में राज्य की भागीदारी किये जाने के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये। वर्ष 1966 में तीसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल समाप्त हो गया। योजना के कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् अगले तीन वर्षों तक वर्ष 1966–67, 1967–68 व 1968–69 तक आयोजन के कार्य को स्थगित रखा गया। इन वर्षों में विकास की एकवर्षीय योजनायें बनाई गई। अर्थशास्त्रियों द्वारा इन वर्षों को 'योजनावकाश' (Plan Holiday) की संज्ञा दी गई। इसके पश्चात् वर्ष 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल के पश्चात् विचारकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। वर्ष 1961–62 म भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण के अन्तर्गत ग्रामीण

---

2. The Committee On Co-operative Credit Chairman V.L. Mehta

क्षेत्र में ऋण प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के कार्य प्रणाली एवं उनके महत्व पर पुनः विचार किया गया। इस सम्बन्ध में ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी द्वारा ग्रामीण साख या ऋण प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों के महत्व में परिवर्तन पाया गया। ग्रामीण ऋण प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों जिन्हें ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी (1951–52) द्वारा स्पष्ट किया गया था, के महत्व में परिवर्तन हुआ है। इन परिवर्तनों को सारणी संख्या 2 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।[3]

सारणी संख्या–2

कृषि साख या ऋण के स्रोत

संस्थायें	कुल कृषि साख आवश्यकता की आपूर्ति प्रतिशत में	
	वर्ष 1951–52	वर्ष 1961–62
1	2	3
1. सहकारी संस्थायें	3.1	15.5
2. सरकार (तकाबी)	3.3	2.6
3. व्यापारिक बैंक	0.9	0.6
4. साहूकार या महाजन तथा जमींदार	71.2	49.8
5. व्यापारी व कमीशन एजेण्ट	5.5	8.8
6. सगे सम्बन्धी	14.2	8.8
7. अन्य स्रोत	1.8	13.9
योग :–	100	100

सारणी संख्या 2 से यह बात स्पष्ट है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने के सम्बन्ध में विकास किया जा सका है। 10 वर्षों के समय अन्तराल के पश्चात वर्ष 1961–62 में कृषि ऋण के लगभग 15.5 प्रतिशत भाग की आपूर्ति इनके माध्यम से की जा सकी थी। इसी प्रकार साहूकार या महाजनों द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रदत्त ऋण का प्रतिशत 71.2 से कम होकर 49.8 प्रतिशत हो गया। महाजनों या साहूकारों तथा जमींदारों द्वारा कृषि आवश्यकता के ऋण का लगभग आधा भाग प्रदान किया गया था।

3. स्रोत– भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त वर्षों के प्रकाशित बुलेटिन में दिये गये आंकड़ों पर आधारित।

शेष स्रोतों में साधारण परिवर्तन हुये हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल (1961–66) के पश्चात् या आर्थिक आयोजन के लगभग दो दशकों के समयावधि में कृषि क्षेत्र के ऋण व्यवस्था में सुधार एवं विकास के सम्बन्ध में विचारकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ ऐसा अनुभव किया जाने लगा कि कृषि विकास केवल सहकारी संगठनों द्वारा प्रदत्त ऋणों के आधार पर तीव्र दर से नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक बड़ी मात्रा में ऋण या वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। इस विचार के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने के लिए बहुएजेन्सी दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया। तीसरी योजना के पश्चात् वर्ष 1966–67 में कृषि विकास की नवीन रणनीति का विचार प्रस्तुत किया गया। इस रणनीति के अन्तर्गत कृषि के आधुनिकीकरण के लिए उन्नत बीज, उर्वरक, सिचाई के साधनों का विकास, कृषि में उन्नत यन्त्रों एवं उपकरणों के प्रयोग के लिए अधिक वित्त की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा जो केवल सहकारी संगठनों द्वारा नहीं प्रदान किया जा सकता। बल्कि इसके लिए एक बड़ी मात्रा में ऋण या वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। इस विचार के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने के लिए बहुएजेन्सी दृष्टिकोण अपनाये जाने का विचार स्पष्ट किया गया। ऐसी परिस्थिति में अन्य संस्थागत स्रोतों का विकास किया जाना आवश्यक हो गया। कृषि वित्त आवश्यकता के आपूर्ति के लिए वर्ष 1967 में व्यापारिक बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण किया गया। इसके पश्चात वर्ष 1969 में 14 प्रमुख बड़े व्यापारिक या व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अन्तर्गत जिन बैंकों की जमा पूँजी 50 करोड़ रूपये से अधिक थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य इन बैंकों को कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना था। इसके पश्चात् वर्ष 1980 में 6 और व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत 28 प्रमुख व्यापारिक बैंक हैं। इन बैंकों के पास कुल बैंकिंग व्यवसाय का लगभग 90 प्रतिशत है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात से कृषि वित्त के क्षेत्र में व्यापारिक बैंकों द्वारा किसानों को अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक तीनों प्रकार के वित्तों का प्रबन्ध किया जा सका है। इसके अतिरिक्त विपणन संसाधन एवं भण्डारण के लिए भी इनके द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है।

व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीकरण के पश्चात से इनके क्रियाकलापों मे विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। वर्ष 1969 में राष्ट्रीकरण के समय व्यापारिक बैंकों की मात्र 22 प्रतिशत शाखाायें ग्रामीण क्षेत्रों में थीं। वर्ष 1969 में 14 प्रमुख व्यापारिक बैंकों (जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया) की कुल 8262 शाखायें थीं। जिनमें से केवल 1832 या लगभग 40 प्रतिशत शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही थीं। इसके 20 वर्षों के पश्चात् वर्ष 1989 में इनकी शाखाओं की संख्या बढ़कर 58.4 हजार हो गई और इनकी लगभग 68 प्रतिशत शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित की गईं। वर्ष 2004 के अन्त में व्यापारिक/वाणिज्यिक बैंकों की लगभग 67.2 हजार शाखायें कार्य कर रही थीं।[4] वर्ष 1985 तक ऐसा निश्चित किया गया था कि इन बैंकों द्वारा अपने कुल ऋणों का लगभग 15 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय। बाद में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया, जिसे वर्ष 1990 तक प्राप्त किया जाना था। वर्ष 2004 के अन्त में इन बैंकों द्वारा कृषि एवं उससे सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 93.56 हजार करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया था। जो इन बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋण का लगभग 15.34 प्रतिशत था।[5]

1. कृषि साख के असंगठित स्रोत :– अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी (1954) ने अपने सर्वेक्षण के दौरान इस बात को पाया था कि किसानों द्वारा लिये गये कुल ऋण का लगभग 93 प्रतिशत भाग निजी साख एजेन्सियों द्वारा प्रदान किया गया था। निजी साख संस्थाओं या एजेन्सियों के अन्तर्गत कमेटी ने पेशेवर महाजन, कृषि महाजन, सगे सम्बन्धी, व्यापारी एवं भूस्वामियों आदि को शामिल किया था। कमेटी की राय में इन निजी साख एजेन्सियों में सबसे अधिक महत्वपूण स्रोत पेशेवर महाजनों का रहा है। इसके पश्चात कृषि महाजन एवं सगे सम्बन्धियों का क्रम से स्थान रहा है। कमेटी द्वारा स्पष्ट किये गये ग्रामीण साख या कृषि साख के निजी साख संस्थाओं के क्रम को सारणी संख्या 3 में स्पष्ट किया गया है।[6]

---

4. भारत 2006, पृष्ठ 322
5. भारत 2006, पृष्ठ 322

सारणी संख्या– 3
कृषि साख के असंगठित स्रोत

साख एजेन्सी	कृषकों द्वारा प्राप्त ऋण (प्रतिशत में)
1	2
1. पेशेवर महाजन	44.8
2. कृषक महाजन	24.9
3. सगे सम्बन्धी	14.2
4. व्यापारी एवं कमीशन एजेन्ट	5.5
5. भूस्वामी	1.5
योग :–	90.9

सारणी संख्या 3 से यह स्पष्ट है कि पेशेवर महाजनों द्वारा किसानों के ऋण आवश्यकता का लगभग 44.8 प्रतिशत भाग व 24.9 प्रतिशत ऋण की आपूर्ति कृषक महाजनों द्वारा की गई थी। इस प्रकार किसानों की ऋण आवश्यकता का लगभग 69.7 या 70 प्रतिशत भाग पेशेवर महाजन एवं कृषक महाजनों द्वारा पूरा किया गया था। इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने ऐसा पाया था कि लगभग 68 प्रतिशत महाजन कृषि का कार्य भी कर रहे थे, तथा 10 प्रतिशत महाजन कृषि न करने वाले भू–स्वामी थे। कमेटी की राय में किसानों को प्राप्त होने वाले ऋण का लगभग चौथाई भाग किसानों से ही प्राप्त होता है। कमेटी ने ऐसा उन किसानों के सम्बन्ध में पाया था जो स्वयं ऋण देने की स्थिति में थे।[7] कमेटी ने जिन जनपदों में सर्वेक्षण का कार्य किया था उनमें से एक जनपद में ऐसा भी पाया गया था कि कुल ऋण का 90 प्रतिशत से अधिक ऋण उन किसानों का रहा है जिन्हें बड़े कृषक कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कमेटी द्वारा सर्वेक्षण के लिए चुने गये 75 जनपदों में से 58 जनपदों में किसानों द्वारा लिये गये ऋणों का 60 प्रतिशत से अधिक बकाया रकम बड़े किसानों की रही है। इस सम्बन्ध में वर्ष 1931 में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच कमेटी ने यह स्पष्ट किया था कि बम्बई बैंकिंग कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा पाया गया है कि कृषक महाजन पेशेवर महाजनों की तुलना में किसानों के लिए ऋण प्राप्त करने के स्रोत के रूप में अधिक उपयुक्त सिद्ध हुये हैं। साथ ही पंजाब बैंकिंग कमेटी ने यह पाया था कि कृषक महाजनों एवं पेशेवर महाजनों की कार्य प्रणाली में कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है पर कृषक

6. स्रोत– अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी रिपोर्ट 1954 भाग–2, पृष्ठ 167
7. अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी रिपोर्ट भाग–2 सामान्य रिपोर्ट पृष्ठ 169

महाजनों द्वारा ऋण की रकम पर ली जाने वाली ब्याज की दर पेशेवर महाजनों की तुलना में कम रही है। कृषक महाजनों की स्थति पेशेवर महाजनों की तुलना में अधिक मजबूत व बलवान होती है। वह अपने बकाया धनराशि की अधिक मात्रा में वसूली करने में समर्थ होता है। कृषक महाजनों का मुख्य उद्देश्य अपने ऋण प्राप्तकर्ताओं या ऋण लेने वाले कर्जदारों की भूमि पर अधिकार प्राप्त करना होता है। इसी प्रकार यूनाइटेड प्राविन्सेस कमेटी ने ऐसा पाया था कि कृषक महाजनों की कार्यप्रणाली व पेशेवर महाजनों की कार्यप्रणाली में कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है। इनके द्वारा ऋण देने में स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूति पुराने ऋणों को नये ऋण में बदलने के कार्य, ब्याज की दर तथा उसे चार्ज करने के तरीके आदि में कोई बड़ा अन्तर नहीं हो सकता है पर कृषक महाजनों द्वारा आवश्यक रूप से ऋण देने के कार्य को अलग दृष्टिकोण से किया जाता है। ऋण देने का कार्य उनके लिए केवल एक निवेश मात्र ही नहीं है बल्कि इसका एक अलग उद्देश्य या प्रेरक होता है।[8]

उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने ऐसा पाया था कि इन दोनों प्रकार के महाजनों की कार्यप्रणाली में भूमि को ऋण के प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करने में यह अन्तर है। कमेटी ने ऐसा पाया था कि आसाम और पश्चिमी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में कृषक महाजनों द्वारा लिए जाने वाले ऋण की अधिकांश रकम स्थिर सम्पत्ति के प्रतिभूति के आधार पर प्राप्त की जाती है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में स्वर्णाभूषण और स्वर्ण को ऋण प्राप्ति के लिए प्रतिभूति के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण तथा स्वर्णाभूषण को ऋण की सुरक्षा के रूप में पेशेवर महाजनों द्वारा अधिकांश क्षेत्रों में स्वीकार किया जाता है। कमेटी ने इस बात को पाया था कि पेशेवर तथा कृषक महाजनों दोनों के ऋणों की रकम का लगभग चौथाई या पांचवा हिस्सा बिना किसी प्रतिभूति के आधार पर दिया गया था।

पेशेवर महाजन :— ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत या असंगठित स्रोतों में ऐसे महाजनों जिन्हें पेशेवर महाजन कहा जाता है का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके महत्वपूर्ण स्थान पर बने रहने का प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में साख आपूर्ति के लिए एक ऐसे प्रभावी संगठन के विकास का न होना रहा है। जिसके माध्यम से महाजनों के स्पर्धा में कार्य किया जा सके, जबकि ऐसे संगठन की

8. The Indian Central Banking enquiry Committee 1931, Majority Report Page-75-76 Quated From All India Rural Credit Survey Committee Report Vol-II Page- 169.

आवश्यकता हमेशा से बनी रही है। एक उपयुक्त प्रभावी संगठन के विकास के अभाव में महाजनों की स्थिति बलवान बनी रही है। भले ही इनके द्वारा ग्रामीणों के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती रही है, फिर भी अन्य संगठनों के अभाव में महाजनों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में उनका शोषण किया जाता रहा है। अन्य संगठनों के अभाव में महाजनों द्वारा ग्रामीणों का शोषण किये जाने के बावजूद भी उसका अस्तित्व ग्रामीण क्षेत्रों में बना रहा है। और उनके क्रियाकलापों पर नियन्त्रण के लिए जो भी वैधानिक कार्यों या कानूनों का निर्माण किया गया वह केवल कागजों तक ही सीमित रह गया। इस सम्बन्ध में महाजनों की क्रियाकलापों के कुछ अंगों पर विचार किया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं–

1– वह अपने ऋण प्राप्तकर्ताओं व अन्य ग्राम वासियों की परिस्थितियों से पूर्णतया परिचित होता है उसे उनके चरित्र एवं पुर्नभुगतान या ऋण वापस करने की क्षमता के सम्बन्ध में पूरी जानकारी होती है।

2– जिन्हें उसे (महाजनों) को ऋण देना होता है उनके सम्पत्तियों और दायित्वों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी होती है। महाजनों को रकम वसूली के लिए कानून का सहारा लेना सबसे अन्तिम शस्त्र होता है। अपने ऋण प्राप्तकर्ताओं की सम्पत्ति को हड़पने पर बहुत कम विचार किया जाता है। इस सम्बन्ध में महाजनों द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता के भू–स्वामित्व को ही ऋण की सुरक्षा के रूप में स्वीकार किया जाता है।

3– रकम की वापसी का समय आने पर महाजनों द्वारा अनिवार्य रूप से विवशता की स्थिति नहीं उत्पन्न की जाती है। जैसा कि अन्य संगठनों द्वारा किया जाता है। बल्कि वह इस सम्बन्ध में कठोर से क़ठोर या सरल से सरल बना रहता है। जैसा कि परिस्थिति में आवश्यक होता है। उसे इस बात का एहसास रहता है कि उसे तथा ऋण प्राप्तकर्ता दोनों को एक ही गाँव में रहना रहता है।

4– विभिन्न परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात उसे यह निश्चित करना होता है कि उसे कितनी रकम तथा किन शर्तों पर देना है। इसके अन्तर्गत मूलधन, ब्याज दर तथा ऋण की वापसी का समय तथा प्रतिभूति आदि पर विचार करता है।

ब्याज की दर के सम्बन्ध में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण ने यह पाया था कि महाजनों, भू–स्वामियों, व्यापारियों आदि द्वारा अधिक से अधिक दबाव बनाये रखने का प्रयास किया जाता है। कमेटी ने यह पाया था कि किसानों द्वारा निजी साख संस्थाओं (व्यापारिक बैंकों

को छोड़कर) से लिये गये ऋण के अधिकांश भाग पर 25 प्रतिशत ब्याज की दर प्राप्त की जाती है। कमेटी ने यह पाया था। उड़ीसा में ब्याज की दर अधिक ऊँची 70 प्रतिशत, त्रिपुरा में 49 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल 40 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश और बिहार में 27 प्रतिशत ब्याज की दर ली जाती है।

ब्याज की दर से सम्बन्धित कानूनों का बहुत कम प्रभाव किसानों पर पड़ा है। कमेटी ने यह पाया था कि पश्चिम बंगाल, बिहार, मद्रास, उड़ीसा और हैदराबाद में अधिकतम 85 प्रतिशत तक ब्याज की दर प्राप्त की जाती है इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में लगभग 65 प्रतिशत ब्याज की दर प्राप्त की जाती है।

इण्डियन सेन्ट्रल बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी ने रकम उधार के लेन देन के सम्बन्ध में चली आ रही कुछ ऐसी परम्पराओं और व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली प्रणालियों पर विचार किया है। इस सम्बन्ध में कमेटी ने कुछ महत्वपूर्ण अंगों पर विचार किया है। इनमें (अ) ब्याज की रकम को अग्रिम रूप में प्राप्त करना। (ब) रकम उधार देने के कार्य को करने के लिए कुछ उपहार प्राप्त करना जिसे गिरह खोलाई कहा जाता है। (स) सादे कागज पर उधार प्राप्त करने वाले का अंगूठा निशान प्राप्त करना जिससे उस पर इच्छानुसार यदि उधार प्राप्तकर्ता ब्याज की रकम का भुगतान करने में अनियमित होता है। (द) ऋण प्राप्तकर्ता के अहित में कोई भी विवरण बाद में लिखकर उस पर दबाव बनाया जा सके। (य) वास्तविक रूप में जितनी रकम दी गयी है उससे अधिक रकम को लिखा जा सके। (र) ऋण प्राप्तकर्ता की ओर से फसल के बिक्री के सम्बन्ध में विक्रयनामा लिखा जाना जिससे ऋणदाता की रकम के भुगतान को छिपाया जा सके।

कृषि वित्त उपसमिति ने महाजनों एवं उनके कार्यों के बारे में यह यह स्पष्ट किया है कि यद्यपि यह सत्य है कि देश के कृषि साख प्रणाली में महाजन एक महत्वपूर्ण अंग है पर उसके द्वारा अपनाये जाने वाले बहुत से व्यवहार ऐसे हैं जिन्हें उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। वह अपने इस सेवा को प्रदान करने में बहुत सी रकम वसूल करता है। ऋणदाता द्वारा लिये जाने वाली रकम का उसके द्वारा उधार दी जाने वाली रकम से कोई सम्बन्ध नहीं होता है बल्कि इसके द्वारा असहाय, अज्ञान तथा ऋण प्राप्तकर्ता की आवश्यकता में उसका शोषण होता है। इसके परिणामस्वरूप उसके द्वारा उधार दी जाने वाली रकम से कृषि व्यवस्था में सम्पन्नता के

बजाय वह कृषि विकास में बाधक सिद्ध होती है।[9]

भूस्वामी व कृषक महाजन :– ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी (1954) ने यह पाया था कि किसानों द्वारा प्राप्त कुल ऋण का 2 प्रतिशत भाग भूस्वामियों द्वारा तथा 25 प्रतिशत भाग कृषक महाजनों द्वारा पूरा किया गया था।

कमेटी की राय में एक बड़ी संख्या में ऋण देने का कार्य करने वाले कृषक भी थे जो इस बात से स्पष्ट होता है कि लगभग 68 प्रतिशत ग्रामीण महाजन कृषि का कार्य भी कर रहे थे केवल 10 प्रतिशत ऐसे थे जो कृषि का कार्य नहीं कर रहे थे केवल भूस्वामी थे। कमेटी ने ऐसा अनुमान लगाया था कि किसानों को प्राप्त होने वाली साख का चौथाई हिस्सा किसानों में आपस में ही प्राप्त हो जाता है। यह कार्य बड़े किसानों द्वारा किया जाता है जो उधार देने की स्थिति में होते हैं। कमेटी ने अपने सर्वेक्षण में यह पाया था कि किसानों पर लगे कुल ऋण का 90 प्रतिशत भाग बड़े किसानों से प्राप्त हुआ था। कमेटी ने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण के लिए चयनित 75 जनपदों में 58 जनपद ऐसे थे जिनमें किसानों पर लगे ऋण का 60 प्रतिशत भाग बड़े किसानों का ही रहा है।

बड़े किसानों के रकम उधार देने के कार्य के सम्बन्ध में वर्ष 1931 में केन्द्रीय बैंकिंग जांच कमेटी ने यह स्पष्ट किया था कि बम्बई कमेटी ने कृषक महाजन के कार्य को पेशेवर महाजन की तुलना में अधिक स्पष्ट है। पंजाब कमेटी के अनुसार कृषक महाजन या ऋणदाता और पेशेवर महाजन या ऋणदाता के तरीकों में कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है। कृषक ऋणदाता पेशेवर ऋणदाताओं की तुलना में आर्थिक दृष्टि से अधिक मजबूत स्थिति में होता है। तथा उसके कार्य पेशेवर ऋणदाताओं की तुलना में अधिक स्पष्ट व सही होते हैं। वह अपने द्वारा दी गयी रकम की एक बड़े भाग की वसूली करने में समर्थ होता है उसके मूल उद्देश्य और कभी–कभी एकमात्र उद्देश्य ऋण प्राप्तकर्ता के भूमि पर अधिकार प्राप्त करना या हथियाना होता है। यूनाइटेड प्राविन्सेस कमेटी ने भी यही अपने रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि कृषक ऋणदाताओं की कार्यप्रणाली के तौर तरीके पेशेवर महाजनों के तौर तरीकों से अलग नहीं हो सकते हैं। विशेषकर प्रतिभूति के स्वरूप बाण्ड के पुर्ननवीनीकरण, ब्याज की दर ज्ञात करने के तरीके आदि एक से हो सकते हैं। इतना होते हुये भी इन दोनों द्वारा अपने कार्यों को अलग–अलग दृष्टिकोण से पूरा किया जाता है।

---

9. Report of the Agricultural Finance Survey Committee 1945. Page 59.

रकम उधार देने का कार्य उनके लिए केवल एक निवेश मात्र ही नहीं होता है, बल्कि वह बहुत आगे के भविष्य के बारे में सोचकर कार्य करता है। उसका एक दूरस्थ लक्ष्य या उद्देश्य भी होता है।[10]

सगे सम्बन्धी एवं मित्र :– अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी द्वारा ग्रामीण साख के स्रोतों में दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत सगे सम्बन्धियों द्वारा प्राप्त होने वाले ऋण या वित्त को स्पष्ट किया गया है। कमेटी के अनुसार किसानों द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले कुल ऋणों का लगभग 14 प्रतिशत भाग सगे सम्बन्धियों द्वारा प्राप्त हुआ था। इनसे प्राप्त ऋण प्रायः ब्याज मुक्त होते हैं। कमेटी ने यह स्पष्ट किया है कि जिनके द्वारा उधार प्राप्तकर्ताओं से ब्याज प्राप्त किया जाता है या गया है उन्हें सगे सम्बन्धी की परिभाषा में न रखकर अन्य वर्ग के अन्तर्गत जैसे कृषक महाजन, व्यापारी वर्ग के अन्तर्गत रखा गया है या उनके पेशे के अनुसार उन्हें वर्गीकृत किया गया है।

व्यापारी एवं कमीशन एजेण्ट :– अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने यह पाया था कि किसानों द्वारा प्राप्त कुल ऋण का लगभग 6 प्रतिशत व्यापारियों और कमीशन एजेण्टों से प्राप्त हुआ था। कमेटी की राय में कुछ ऋणदाता या महाजनों (ऐसा विशेषकर शहरी ऋणदाताओं के सम्बन्ध में लागू होता है) द्वारा रकम उधार देने के कार्य के साथ–साथ कुछ अन्य कार्य भी सम्पन्न किये जाते हैं। अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण कमेटी ने अपने अध्ययन में पाया था और यह स्पष्ट किया कि लगभग 10 प्रतिशत ग्रामीण एवं 14 प्रतिशत शहरी महाजन ऐसे भूस्वामी थे जिनके द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जाता था इसके अतिरिक्त ग्रामीण महाजनों में 30 प्रतिशत तथा शहरी महाजनों में 78 प्रतिशत महाजनों द्वारा रुपया उधार देने के कार्य के अतिरिक्त एक या उससे अधिक आर्थिक क्रियायें भी सम्पन्न की जाती थीं। इन क्रियाओं में व्यापार, सामान्य जर्नल मर्चेन्ट या दुकान आदि किये जाते रहे हैं। ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने अपने अध्ययन के लिए चयनित 75 जनपदों में यह पाया था कि तीन जनपदों में कुल ऋण का लगभग 57 प्रतिशत, 29 प्रतिशत तथा 22 प्रतिशत ऋण व्यापारियों एवं कमीशन एजेण्टों द्वारा दिया गया था। इसी प्रकार कमेटी ने अपने अध्ययन में यह पाया था कि कुछ व्यापार प्रधान जनपदों में व्यापारियों एवं कमीशन एजेण्टों द्वारा दिये जाने वाले ऋण का अनुपात अन्य जनपदों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक रहा है। कमेटी ने अपने अध्ययन में यह पाया था कि कपास उत्पादन करने वाले जनपदों में कुछ

10. Report of the Agricultural Finance Survey Committee 1945. Page 59.

जनपदों में कुल ऋण का 57 प्रतिशत प्राप्त किया जाने वाला ऋण इन्हीं से प्राप्त हुआ था। कमेटी ने यह पाया था कि व्यापारियों द्वारा दिये जाने वाला ऋण का एक बड़ा भाग ऐसा था जिस पर ब्याज नहीं लिया जाता था। इसके पीछे यह बात आवश्यक रूप से जुड़ी होती थी कि किसानों को अपने फसल के अतरेक को इन्हीं व्यापारियों के हाथ सस्ते दर पर बेचना अनिवार्य होता है।

2. कृषि साख के संगठित स्रोत :– जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक आयोजन के प्रारम्भ (1951–52) में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने यह पाया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में साख के गैर संस्थागत स्रोतों की प्रधानता साख के संस्थागत स्रोतों के अन्तर्गत सरकार सहकारी संगठन तथा व्यापारिक बैंक थे। इन संस्थाओं द्वारा ग्रामीण साख का मात्र 7.3 प्रतिशत भाग की आपूर्ति की गई थी। कमेटी ने ग्रामीण क्षेत्रों में साख के उपयुक्त साधनों के विकास के अन्तर्गत मुख्यतया सहकारी संगठनों के विकास पर जोर दिया था क्योंकि सरकार के माध्यम से किसानों को प्राप्त होने वाली सहायता जिसे तकाबी ऋण कहा जाता है उसकी सबसे मुख्य कमी यह रही है कि वह हमेशा नहीं प्राप्त होती है यह केवल प्राकृतिक आपदाओं के ही समय प्राप्त होती है। इसकी रकम बहुत अधिक नहीं होती है। इसे किसानों को एक निश्चित समय पर वापस करना अनिवार्य होता है तथा इसके अन्तर्गत प्राप्त होने वाली रकम किसानों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर होती है इसके अतिरिक्त व्यापारिक बैंकों के निजी क्षेत्र में होने के कारण इनके द्वारा किसानों को ऋण देना या न देना उनकी इच्छा पर निर्भर था। ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने एक बड़ी संख्या में जनहित की रक्षा के लिए देश में सहकारी आन्दोलन के विकास के सम्बन्ध में अपनी सिफारिश की थी।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने सिफारिशों के पश्चात लगभग एक दशक तक विचारकों द्वारा कृषि क्षेत्र में साख या ऋण प्रदान करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में सहाकरी संगठनों के सम्बन्ध में ही अपने विचार व्यक्त किये जाते रहे हैं। ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी की सिफारिशों के 5 वर्षों के पश्चात तीसरी पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1961–66) में कृषि विकास के लिए सहकारी ऋण को निश्चित करने के लिए श्री वी0एल0 मेहता की अध्यक्षता में सहकारी साख कमेटी नियुक्त की गई है।[11] कमेटी ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास

---

11. The Committee of Co-opperative Credit Chairman V.L. Mehta.

के लिए आवश्यक वित्त/ऋण का अनुमान लगाकर सहकारी साख संगठनों के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की वर्ष 1966 में तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पश्चात अगले तीन वर्षों (1966–67, 1967–68, 1968–69) तक आयोजन के कार्य को स्थगित रखा गया इन वर्षों में एक वर्षीय योजनायें बनाई गयी। अर्थशास्त्रों द्वारा इन तीन वर्षों के समय को योजनावकाश कहा गया है। इसके पश्चात वर्ष 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात विचारकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ।

वर्ष 1961–62 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं के महत्व पर पुनः विचार किया गया। इस सर्वेक्षण में ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी द्वारा ग्रामीण साख के विभिन्न स्रोतों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन पर विचार किया गया। इन दोनों सर्वेक्षणों में ग्रामीण ऋण प्रदान करने वाले विभिन्न स्रोतों के महत्व में परिवर्तन स्पष्ट हुआ है। इन परिवर्तनों को सारणी संख्या– 4 में स्पष्ट किया गया है।[12]

सारणी संख्या–4

कृषि साख के संस्थागत स्रोत

संस्थायें	कुल कृषि साख आवश्यकता की आपूर्ति प्रतिशत में	
	वर्ष 1951–52	वर्ष 1961–62
1	2	3
1. सहकारी संस्थायें	3.1	15.5
2. सरकार (तकाबी)	3.3	2.6
3. व्यापारिक बैंक	0.9	0.6
योग :–	7.3	18.7

सारणी संख्या–4 से यह स्पष्ट है कि सन् 1951–52 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी के रिपोर्ट के समय विभिन्न संस्थागत स्रोतों से प्राप्त होने वाला कृषि ऋण जो किसानों की कुल आवश्यकता का केवल 7.3 प्रतिशत था, व आर्थिक आयोजन के 10 वर्षों के पश्चात किसानों की कुल ऋण आवश्यकता का 18.7 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार आर्थिक आयोजन के 10 वर्षों

12. **स्रोत– भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त वर्षों के प्रकाशित बुलेटिन में दिये गये आंकड़ों पर आधारित।**

के अन्तराल में संस्थागत स्रोतों से प्राप्त होने वाले कृषि साख के महत्व में 156.2 प्रतिशत की वृद्धि हुयी और पहले की तुलना में किसानों की ऋण आवश्यकता को इसके माध्यम से अधिक मात्रा में पूरा किया जा सका। 10 वर्षों की समयावधि में सरकार के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक सहायता में कमी हुई है। वर्ष 1951–52 में सरकार के माध्यम से किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता उनकी आवश्यकता का 3.3 प्रतिशत थी, जो 1961–62 में कम होकर 2.6 प्रतिशत हो गयी जो इस बात को स्पष्ट करता है कि देश में 10 वर्षों के आर्थिक आयोजन के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र का विकास हुआ है। जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इन दस वर्षों में देश में प्रथम व द्वितीय दो पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो चुकी थी।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने देश में सहकारी संगठनों के विकास के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें की थीं और इस समय अन्तराल में अधिक से अधिक सहकारी संगठनों का विकास किया गया। परिणामस्वरूप सहकारी संगठनों के माध्यम से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता जो किसानों की ऋण आवश्यकता का मात्र 3.1 प्रतिशत थी वह वर्ष 1961–62 में बढ़कर 15.5 प्रतिशत हो गयी।

व्यापारिक बैंकों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि इन बैंकों ने कृषि क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं को और सीमित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1951–52 में व्यापारिक बैंकों द्वारा किसानों की ऋण आवश्यकता का 0.9 प्रतिशत भाग पूरा किया गया था वह 1961–62 में कम होकर 0.6 प्रतिशत हो गया।

तीसरी योजना (1961–66) के पश्चात या आर्थिक आयोजन के लगभग दो दशकों की समयावधि में कृषि क्षेत्र में ऋण व्यवस्था में सुधार एवं विकास के सम्बन्ध में विचारकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। ऐसा अनुभव किया जाने लगा कि कृषि विकास केवल सहकारी संगठनों द्वारा प्रदत्त ऋणों के आधार पर तीव्र दर से नहीं किया जा सकता बल्कि इसके लिए एक बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। इस विचार के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने के लिए बहुएजेन्सी दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है। ऐसा विचार स्पष्ट किया गया। वर्ष 1966–67 में कृषि विकास की नवीन रणनीति का विचार प्रस्तुत किया गया

इस रणनीति के अन्तर्गत कृषि के आधुनिकीकरण के लिए उन्नत बीज, उर्वरक, सिचाई के साधनों का विकास, कृषि में उन्नत यन्त्रों और उपकरणों के प्रयोग के लिए अधिक वित्त की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। कृषि क्षेत्र में इस बड़ी मात्रा में वित्त आवश्यकता की पूर्ति सहकारी संस्थाओं के क्षमता के बाहर थी। ऐसी परिस्थिति में अन्य संस्थागत स्रोतों का विकास किया जाना आवश्यक हो गया। कृषि क्षेत्र में वित्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्ष 1967 में व्यापारिक बैंकों पर समाजिक नियन्त्रण किया गया। इसके पश्चात वर्ष 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का जिनकी जमा पूँजी 50 करोड़ रूपये से अधिक थी, राष्ट्रीयकरण किया गया। व्यापारिक बेंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य इन बैंकों को कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना था। इसके पश्चात वर्ष 1980 में 6 और व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत कुल राष्ट्रीयकृत व्यवसायिक/वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 28 है। जिसमें एस0बी0आई0 समूह की 8 बैंक व आई0डी0बी0आई0 शामिल हैं। जिसके विवरण को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम

1. बैंक आफ बड़ौदा
2. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
3. इलाहाबाद बैंक
4. पंजाब नेशनल बैंक
5. बैंक आफ इण्डिया
6. यूनियन बैंक
7. ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स
8. सिन्डीकेट बैंक
9. देना बैंक
10. यूको बैंक
11. विजया बैंक
12. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया
13. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक

14. केनरा बैंक

15. आन्ध्रा बैंक

16. कारपोरेशन बैंक

17. इण्डियन बैंक

18. बैंक आफ महाराष्ट्रा

19. इण्डियन ओवर सीज बैंक

स्टेट बैंक समूह के बैंक

1. स्टेट बैंक आफ इण्डिया
2. स्टेट बैंक आफ पटियाला
3. स्टेट बैंक आफ इन्दौर
4. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
5. स्टेट बैंक आफ ट्रावन कोट
6. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर
7. स्टेट बैंक आफ मैसूर
8. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद

आई0डी0बी0आई0 बैंक

1. इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट बैंक आफ इण्डिया

वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है जबकि राष्ट्रीयकरण के समय प्रथम बार 14 व द्वितीय बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी संख्या 20 होती है किन्तु न्यू बैंक आफ इण्डिया का विलय पंजाब एण्ड सिंध बैंक में हो जाने के कारण वर्तमान में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की संख्य 19 व एस0बी0आई0 समूह की बैंकों की संख्या 8 है। जिनके द्वारा ग्रामीण साख को उनकी आवश्यकतानुसार समय–समय पर ऋण उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इन बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु वितरित ऋण की मात्रा को आगे के अध्यायों में विस्तृत से विश्लेषित किया जायेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के इन व्यापारिक बैंकों के माध्यम से कुल बैंकिंग व्यवस्था का 90 प्रतिशत लेन देन इन बैंकों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात से कृषि वित्त के क्षेत्र में व्यापारिक बैंकों द्वारा किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन तीनों प्रकार के वित्तों का प्रबन्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा कृषि विपणन, संसाधन एवं भंण्डारण के लिए वित्त प्रदान किया जाता है।

व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीकरण के पश्चात से इनके क्रियाकलापों में विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। वर्ष 1969 में राष्ट्रीयकरण के समय व्यापारिक बैंकों की कुल शाखाओं की मात्र 22 प्रतिशत शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में थीं। वर्ष 1969 में 14 प्रमुख व्यापारिक बैंकों की 8262 शाखायें थीं जिनमें 1832 शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही थीं। इसके 20 वर्षों के पश्चात वर्ष 1989 में इनकी शाखाओं की संख्या बढ़कर 58.4 हजार हो गयी। और इनकी लगभग 68 प्रतिशत शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित की गयीं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात से वाणिज्यिक बैंकों के शाखा विस्तार व वर्ष 1969 की तुलना में होने वाली वृद्धि को सारणी संख्या 5 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या– 5
वाणिज्यिक बैंक कार्यालयों की संख्या

वर्ष	कार्यालयों की संख्या	वर्ष 1969 की तुलना में शाखा विस्तार प्रतिशत में
1	2	3
1969	8262	–
1973	15362	85.9
1978	28016	239.0
1980	32419	292.3
1981	35707	332.1
1982	39177	374.1
1983	42079	409.3

वर्ष	कार्यालयों की संख्या	वर्ष 1969 की तुलना में शाखा विस्तार प्रतिशत में
1	2	3
1984	45332	448.6
1985	51385	521.9
1986	53265	544.6
1987	53840	621.6
1988	55410	570.6
1989	57699	598.3
1995	62495	656.4
1998	64267	677.9
1999	65118	688.2
2000	65521	693.0
2001	65908	697.7
2002	66276	702.2
2003	66436	704.1
2004	66970	710.6
2005	68116	724.4
2006	68881	733.7

सारणी संख्या– 5 से यह स्पष्ट है कि वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय वर्ष 1969 में कुल बैंक कार्यालयों की संख्या 8262 थी, जो वर्ष 2006 में बढ़कर 68881 हो गयी है। शाखा विस्तार में होने वाली यह वृद्धि वर्ष 1969 की तुलना में 733.7 प्रतिशत रही है। वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीकरण के वर्ष 1971 में वाणिज्यिक बैंकों के शाखा कार्यालयों की संख्या 8262 थी जो वर्ष 1973

स्रोत – वर्ष 1969 से 2006 तक की संख्या 'इण्डिया' के विभिन्न वर्षों के विभिन्न पेजों पर अंकित आंकड़ों पर आधारित है।

में बढ़कर 15362 हो गयी। वाणिज्यिक बैंकों की शाखा कार्यालयों की कुल संख्या में होने वाली यह वृद्धि 85.9 प्रतिशत हुयी थी। इसके पांच वर्षों के पश्चात 1978 में वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या बढ़कर 28016 हो गयी। सन् 1978 में वाणिज्यिक बैंकों की शाखा कार्यालयों में होने वाले वृद्धि की तुलना यदि 1969 की संख्या से की जाय तो यह स्पष्ट होता है कि 1978 में होने वाली वृद्धि 239 प्रतिशत रही है। इस प्रकार 9 वर्षों के पश्चात वाणिज्यिक बैंकों की संख्या में होने वाली वृद्धि दो गुने से अधिक रही है। वर्ष 1980 में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या बढ़कर 32419 हो गयी। यदि इसकी तुलना वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीकरण के समय की संख्या से की जाय तो यह बात स्पष्ट की जाती है कि इन बैंकों के राष्ट्रीकरण के एक दशक के अन्त में इनकी संख्या में होने वाली वृद्धि लगभग 300 प्रतिशत रही है। वर्ष 1980 के लगभग एक दशक के पश्चात इन बैंकों की संख्या 1989 में बढ़कर 57699 हो गयी है। जो राष्ट्रीकरण के वर्ष 1969 की तुलना में 600 प्रतिशत से अधिक व वर्ष 2006 में बढ़कर 733.7 प्रतिशत रही है।

वाणिज्यिक बैंकों के विकास एवं विस्तार की स्थिति पर उत्तर प्रदेश राज्य के दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है जिसे सारणी संख्या–6 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–6

उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक बैंक कार्यालयों की संख्या

वर्ष	कार्यालयों की संख्या	वर्ष 1994 की तुलना में शाखा विस्तार प्रतिशत में
1	2	3
1994	8604	–
1995	8655	0.6
1998	8810	2.4
1999	8902	3.5
2000	8905	3.5
2001	8095	–5.9

वर्ष	कार्यालयों की संख्या	वर्ष 1994 की तुलना में शाखा विस्तार प्रतिशत में
1	2	3
2002	8178	–4.9
2003	8184	–4.8
2004	8213	–4.5
2005	8299	–3.5
2006	8347	–2.9

सारणी संख्या–6 से यह स्पष्ट है कि राष्ट्र स्तर पर वाणिज्यिक बैंकों के विकास के साथ–साथ उत्तर प्रदेश राज्य में भी इनकी शाखा में विस्तार हुआ है। वर्ष 1994 की तुलना में वर्ष 1999 में शाखा विस्तार में होने वाली वृद्धि 3.5 प्रतिशत रही है। इसके पश्चात इनकी संख्या व शाखा विस्तार में वृद्धि में कृमशः कमी दृष्टिगोचर होती है। शाखा विस्तार में होने वाली इस कमी का मुख्य कारण यह है कि वर्ष 2000 के पश्चात राज्य का बटवारा हो जाने के पश्चात और उत्तरांचल राज्य का गठन होने के परिणामस्वरूप राज्य के क्षेत्र में कमी हुयी है। जिसके कारण व्यापारिक बैंक शाखाओं में कमी स्पष्ट होती है।

अध्ययन का विस्तार या क्षेत्र : वर्तमान अध्ययन ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विकास के लिए प्राप्त होने वाली संस्थागत वित्त से सम्बन्धित है। कृषि क्षेत्र में संस्थागत वित्त मुख्यतया तीन स्रोतों से प्राप्त होता है।

1. सहकारी संगठन
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. वाणिज्यिक बैंक

सहकारी संगठनों के सीमित विकास एवं विस्तार के कारण कृषि विकास के लिए वाणिज्यिक बैंकों को इस कार्य में लगाये जाने का प्रयास किया गया। इसके लिए वाणिज्यिक बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण करके उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। जिससे उन्हें सार्वजनिक

स्रोत – वर्ष 1994 से 2006 तक के सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ में दिये आंकड़ों पर आधारित ।

क्षेत्र के अन्तर्गत लाकर उनके वित्तों का प्रयोग अधिक से अधिक जनहित में करके साधारण जन के आर्थिक विकास में किया जा सके। इन बैंकों के राष्ट्रीकरण के पहले वाणिज्यिक बैंक निजी क्षेत्र के अन्तर्गत थे। निजी क्षेत्र के संगठन अपने निजी लाभ के लिए कार्यशील होते हैं। इनके द्वारा साधारण जनहित की रक्षा नहीं की जा सकती, जबकि दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र साधारण जनहित या सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर कार्यशील होता है।

वर्तमान अध्ययन क्षेत्र : सार्वजनिक क्षेत्र की वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि विकास तथा इनके द्वारा प्रदान किये जाने वाले वित्त से कृषि अर्थव्यवस्था किस सीमा तक प्रभावित हुयी है। इसका मूल्यांकन करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र को चुना गया है। यह एक व्यष्टिप्रकार का अध्ययन है जो प्राथमिक एवं द्वितीयक संमकों पर आधारित है। प्राथमिक समंक कानपुर क्षेत्र के उन बैंकों के कार्यालयों के अधिकारियों, लाभार्थियों तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके एकत्र किये जायेंगे। और द्वितीयक समंक कानपुर क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न व्यापारिक बैंकों की वार्षिक रिपोर्टों एवं उनके द्वारा प्रकाशित अन्य रिपोर्टों तथा प्रकाशनों एवं लीड बैंक कार्यालयों से प्राप्त किये जायेंगे।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य 17 मण्डलों में विभक्त है जिसे सारणी संख्या 7 के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–7

उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक मण्डल एवं उनके अन्तर्गत उनके जिलों की संख्या

मण्डल का नाम	जिलों की संख्या
1	2
1. आगरा	7
2. झाँसी	3
3. चित्रकूट धाम	4
4. लखनऊ	6
5. बरेली	4

मण्डल का नाम	जिलों की संख्या
1	2
6. मेरठ	4
7. सहारनपुर	3
8. मुरादाबाद	4
9. वाराणसी	4
10. विन्ध्यांचल	3
11. गोरखपुर	4
12. बस्ती	3
13. आजमगढ़	3
14. इलाहाबाद	4
15. कानपुर	6
16. फैजाबाद	4
17. देवीपाटन	4

स्रोत : साख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश वर्ष 2006

सारणी संख्या–7 से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न मण्डलों में सबसे अधिक जनपद आगरा मण्डल में हैं इसके पश्चात लखनऊ व कानपुर मण्डल का स्थान है। जबकि सबसे कम जनपद झाँसी, बस्ती, गोरखपुर आदि मण्डलों में हैं।

अध्ययन के लिए कानपुर क्षेत्र के चुनाव का औचित्य : वर्तमान अध्ययन के लिए कानपुर क्षेत्र का चुनाव निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर लिया गया है। जिसके आधार पर इस अध्ययन की सार्थकता को स्पष्ट किया जा सकता है।

कानपुर मण्डल उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के मण्डलों में से एक है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसे एक बड़ा क्षेत्र कहा जा सकता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य 17 मण्डलों में विभाजित है। भौगोलिक दृष्टिकोण से कानपुर क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल 14776 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के विभिन्न मण्डलों में इसका 6वाँ क्रम पर स्थान है। फिर भी अध्ययन के लिए सीमित समय व साधनों को ध्यान में रखकर अन्य मण्डलों में से किसी और बड़े भौगोलिक दृष्टिकोण से बड़े मण्डलों का चुनाव नहीं किया गया है। फिर भी विभिन्न मण्डलों में जनपदों की संख्या के आधार पर यह दूसरे क्रम पर है।

राज्य के विभिन्न मण्डलों के क्षेत्रफल को सारणी संख्या 8 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–8

उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न मण्डलों का भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में)

मण्डल का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल
1	2
1. लखनऊ	31054
2. आगरा	22430
3. बरेली	17362
4. इलाहाबाद	15814
5. चित्रकूट धाम	14790
6. कानपुर	14776
7. झाँसी	14628
8. देवीपाटन	14230
9. फैजाबाद	13529
10. मुरादाबाद	12995

मण्डल का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल
1	2
11. विन्ध्यांचल	12324
12. गोरखपुर	11717
13. वाराणसी	11491
14. मेरठ	10853
15. आजमगढ़	8748
16. सहारनपुर	7697
17. बस्ती	7229

स्रोत : सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश वर्ष 2003 पेज, 206 से 211 तक

सारणी संख्या 8 से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न मण्डलों में सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल लखनऊ मण्डल का 31054 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आगरा, बरेली, इलाहाबाद, चित्रकूट व कानपुर मण्डल का स्थान है, जबकि सबसे कम भौगोलिक क्षेत्रफल बस्ती मण्डल का है।

जनसंख्या के दृष्टिकोण से कानपुर मण्डल राज्य के विभिन्न मण्डलों में सातवें क्रम पर है, और जनसंख्या के घनत्व के दृष्टिकोण से मण्डल का स्थान दशवें क्रम पर है। ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टिकोण से कानपुर मण्डल का स्थान 11वें क्रम पर है।

राज्य के विभिन्न मण्डलों की जनसंख्या, जनसंख्या के घनत्व, जनसंख्या व कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत को सारणी संख्या–9 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–9

उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न मण्डलों की जनसंख्या (लाख में)

मण्डल का नाम	जनसंख्या	जनसंख्या का घनत्व व्यक्तिप्रति वर्ग कि.मी.	ग्रामीण जनसंख्या	कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. सहारनपुर	65.5	338.5	47.9	73.1
2. मुरादाबाद	103.6	797.6	75.9	72.2
3. मेरठ	115.7	1065.8	69.4	60.1
4. आगरा	164.6	733.9	118.4	71.9
5. बरेली	108.8	626.7	83.1	76.3
6. लखनऊ	171.2	551.5	152.5	89.1
7. कानपुर	120.1	758.6	75.5	64.7
8. झॉसीं	41.9	286.9	30.0	71.5
9. चित्रकूट धाम	40.6	274.2	34.0	83.9
10. इलाहाबाद	114.7	760.5	95.8	82.3
11. फैजाबाद	100.0	739.5	91.4	91.4
12. देवी पाटन	80.0	562.6	74.0	92.9
13. बस्ती	55.5	767.0	52.5	94.7
14. गोरखपुर	115.5	995.7	102.9	89.1
15. आजमगढ़	85.5	977.9	76.27	89.2
16. वाराणसी	117.3	1020.9	97.7	83.3
17. विन्ध्यांचल	49.3	400.2	41.9	85.1

स्रोत : साख्यिकीय साराश उत्तर प्रदेश वर्ष 2003 पेज, 206 स 211 तक

उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न मण्डलों में ग्रामीण जनसंख्या में कृषि पर आश्रित जनसंख्या के दृष्टिकोण से कानपुर मण्डल 7वें क्रम पर है। जिसको सारणी संख्या 10 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या 10

उत्तर प्रदेश राज्य की कृषि पर आश्रित जनसंख्या

मण्डल का नाम	कृषक	कृषि मजदूर
1	2	3
1. सहारनपुर	537245	327112
2. मुरादाबाद	1033547	460481
3. मेरठ	849298	255555
4. आगरा	1668396	435794
5. बरेली	1420333	394373
6. लखनऊ	2662449	1293599
7. कानपुर	1111127	315479
8. झॉसी	585986	138492
9. चित्रकूट धाम	612405	2200734
10. इलाहाबाद	1885564	488469
11. फैजाबाद	1298963	405960
12. देवी पाटन	1699211	377733
13. बस्ती	782245	233379
14. गोरखपुर	1036937	394979
15. आजमगढ़	764258	278786
16. वाराणसी	1055458	300558
17. विन्ध्यांचल	401054	207779
योग :	**1940476**	**8509262**

स्रोत : सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश वर्ष 2003 पेज, 61– 62 तक

परीक्षण की जाने वाली परिकल्पनायें :

वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जायेगा।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात से कृषि क्षेत्र में जब से ऋण प्रदान करने के लिए बहुएजेन्सी दृष्टिकोण अपनाया गया। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत एक नवीन कृषि रणनीति अपनायी गयी। इसी रणनीति के अन्तर्गत कृषि के आधुनिकीकरण के लिए उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई के साधनों का विकास, कृषि में उन्नत यंत्रों एवं उपकरणों के प्रयोग के लिए अधिक वित्त की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। जो केवल सहकारी संगणनों द्वारा नहीं प्रदान किया जा सकता था बल्कि इसके लिए एक बड़ी मात्रा में ऋण या वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। कृषि वित्त आवश्यकताकी आपूर्ति के लिए वर्ष 1967 में व्यापारिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण किया गया व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य इन बैंकों में कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना था। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के अर्न्तगत 28 बैंक हैं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात से कृषि वित्त के क्षेत्र में व्यापारिक बैंकों द्वारा किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन तीनों प्रकार के वित्तों का प्रबन्ध किया जाता है।

व्यापारिक बैंकों के उपरोक्त भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण कानपुर क्षेत्र के संदर्भ में किया जायेगा।

1. वाणिज्यिक बैंकों के वित्त प्रदान करने के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत वित्त का ढाँचा अधिक विस्तृत और मजबूत हो सका है।
2. वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से किसानों को पर्याप्त मात्रा में वित्त प्राप्त होने के परिणामस्वरूप कृषि के विकास में सहायता प्राप्त हुई है।
3. कृषि के लिए आवश्यक वित्त प्रदान करने के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक वित्त पोषण के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए उत्पादन के कार्य में आवश्यक संगठनात्मक ढाँचे का विकास एवं विस्तार हुआ है।
4. किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
5. किसानों को महाजनों के आर्थिक शोषण से बचाया जा सका है।

निष्कर्ष

वर्तमान अध्याय के निष्कर्ष के रूप में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि साख प्रणाली का अर्थ साख या ऋण की उस व्यवस्था से लगाया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए किसानों को ऋण प्राप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि अभी भी निजी क्षेत्र में है, फिर भी सरकार द्वारा समय–समय पर किसानों की आर्थिक सहायता के लिए प्रयत्न किये जाते रहे हैं पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले इस दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं किया जा सका था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा कृषि विकास के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में सरकार द्वारा कृषि विकास के लिए आवश्यक साख प्रदान करने के लिए विभिन्न स्रोतों की जानकारी के लिए राष्ट्र स्तर पर एक अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी की नियुक्ति की गयी कमेटी ने यह पाया कि कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने के कार्य गैर संस्थागत स्रोतों का स्थान महत्व महत्वपूर्ण बना हुआ है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार किसानों द्वारा लिए जाने वाले ऋणों का लगभग 93 प्रतिशत भाग अभी भी पेशेवर व कृषि महाजनों, सगे सम्बन्धियों, व्यापारी एवं कमीशन एजेन्टों, भू–स्वामियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त साख के संस्थागत स्रोतों से किसानों की ऋण आवश्यकता का मात्र 7 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। इसके अन्तर्गत सहकारी संगठन, सरकार एवं व्यापारिक बैंक है।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने कृषि साख प्रदान करने के लिए सहकारी संगठनों को सबसे उपयुक्त साधन माना था और कमेटी ने सहकारी संगठनों के विकास के सम्बन्ध में अपनी सिफारिश की थी। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी के सिफारिशों के पश्चात लगभग एक दशक तक विचारकों द्वारा कृषि क्षेत्र में साख या ऋण प्रदान करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये जाते रहे हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात विचारकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ ऐसा अनुभव किया जाने लगा कि तीव्र दर से कृषि विकास केवल सहकारी संगठनों के द्वारा प्रदत्त ऋणों के आधार पर नहीं किया जा सकता इसके लिए एक बड़ी मात्रा में ऋण या वित्तीय संसाधनों

की आवश्यकता है। जो केवल सहकारी संगठनों के माध्यम से प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है बल्कि इसके लिए बहुएजेन्सी दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है। इस विचार के परिणामसवरूप अन्य संस्थागत श्रोतों का विकास किया जाना आवश्यक समझा गया वर्ष 1967 में व्यापारिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण किया गया इसके पश्चात वर्ष 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकारण किया गया तत्पश्चात वर्ष 1980 में 6 प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य इन बैंकों को कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना था।

वर्तमान में कृषि साख के संस्थागत श्रोतों के अन्तर्गत मुख्य रूप से सहकारी संगठन, व्यापारिक बैंक एवं सरकार यह कार्य सम्पादित कर रहे हैं। अपने सीमित साधनों और सीमित कार्य क्षेत्र के कारण सहकारी संगठनों को एक निश्चित सीमा तक सफलता प्राप्त हो सकी है। कृषि क्षेत्र में एक बड़ी मात्रा में आवश्यक वित्त प्रदान करने का कार्य मुख्य रूप से व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है।

अपने पर्याप्त संसाधनों और विस्तृत कार्य क्षेत्र होने के कारण कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। वर्तमान अध्ययन ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विकास के लिए प्राप्त होने वाले संस्थागत वित्त से सम्बन्धित है।

कृषि क्षेत्र में संस्थागत वित्त मुख्यतया दो श्रोतों से प्राप्त होता है–

1. सहकारी संगठन
2. व्यापारिक बैंक

उपरोक्त के संदर्भ में वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि विकास तथा इनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले वित्त से कृषि अर्थव्यवस्था किस सीमा तक प्रभावित हुई है, इसका मूल्यांकन करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र को चुना गया है। यह एक व्यष्टि प्रकार का अध्ययन है, जो प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित है। प्राथमिक समंक कानपुर क्षेत्र के उन बैंकों के कार्यालयों के अधिकारियों, लाभार्थियों, सम्बन्धित व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके ज्ञात किये जायेंगे और द्वितीयक संमक कानपुर क्षेत्र में

की आवश्यकता है। जो केवल सहकारी संगठनों के माध्यम से प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है बल्कि इसके लिए बहुएजेन्सी दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है। इस विचार के परिणामसवरूप अन्य संस्थागत श्रोतों का विकास किया जाना आवश्यक समझा गया वर्ष 1967 में व्यापारिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण किया गया इसके पश्चात वर्ष 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकारण किया गया तत्पश्चात वर्ष 1980 में 6 प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य इन बैंकों को कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना था।

वर्तमान में कृषि साख के संस्थागत श्रोतों के अन्तर्गत मुख्य रूप से सहकारी संगठन, व्यापारिक बैंक एवं सरकार यह कार्य सम्पादित कर रहे हैं। अपने सीमित साधनों और सीमित कार्य क्षेत्र के कारण सहकारी संगठनों को एक निश्चित सीमा तक सफलता प्राप्त हो सकी है। कृषि क्षेत्र में एक बड़ी मात्रा में आवश्यक वित्त प्रदान करने का कार्य मुख्य रूप से व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है।

अपने पर्याप्त संसाधनों और विस्तृत कार्य क्षेत्र होने के कारण कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। वर्तमान अध्ययन ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विकास के लिए प्राप्त होने वाले संस्थागत वित्त से सम्बन्धित है।

कृषि क्षेत्र में संस्थागत वित्त मुख्यतया दो श्रोतों से प्राप्त होता है–

1. सहकारी संगठन
2. व्यापारिक बैंक

उपरोक्त के संदर्भ में वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि विकास तथा इनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले वित्त से कृषि अर्थव्यवस्था किस सीमा तक प्रभावित हुई है, इसका मूल्यांकन करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र को चुना गया है। यह एक व्यष्टि प्रकार का अध्ययन है, जो प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित है। प्राथमिक समंक कानपुर क्षेत्र के उन बैंकों के कार्यालयों के अधिकारियों, लाभार्थियों, सम्बन्धित व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके ज्ञात किये जायेंगे और द्वितीयक संमक कानपुर क्षेत्र में

कार्यरत विभिन्न व्यापारिक बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट एवं उनके द्वारा प्रकाशित अन्य रिपोर्टों तथा प्रकाशनों एवं वैलेन्स सीटों से प्राप्त किये जायेगें।

वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाना है।

1. वाणिज्यिक बैंकों के वित्त प्रदान करने के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत वित्त का ढॉचा अधिक विस्तृत एवं मजबूत हो सका है।
2. वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से किसानों को पर्याप्त मात्रा में वित्त प्राप्त होने के परिणामस्वरूप कृषि के विकास में सहायता प्राप्त हुई है।
3. कृषि के लिए आवश्यक वित्त प्रदान करने के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक वित्त पोषण के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए उत्पादन के कार्य में आवश्यक गठनात्मक ढांचा का विकास एवं विस्तार हुआ है।
4. किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।
5. किसानों को महाजनो के आर्थिक शोषण से बचाया जा सकता है।



अध्याय – दो

साख के संगठित स्रोत

अध्याय – दो : साख के संगठित स्रोत

कृषि शाख के संगठित स्रोत के अन्तर्गत उन संगठनों या स्रोतों को रखा जा सकता है जिन संगठनों द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र के लिए वित्त या ऋण निम्न चार संस्थागत या संगठनों के माध्यम से प्राप्त होता है –

1. व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. सहकारी बैंकिंग व्यवस्था या बैंक
4. सरकार

उपरोक्त चारो स्रोतों द्वारा कृषि क्षेत्र में वित्त या ऋण प्रदान करने का कार्य किया जाता है। वर्ष 2005–06 में इन संगठनों द्वारा कृषि क्षेत्र में 117.89 हजार करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया था जिसमें लगभग 28.9 हजार करोड़ रुपये या कुल कृषि संस्थागत ऋण का लगभग 24.5 प्रतिशत सहकारी बैंकों द्वारा, लगभग 11.1 हजार करोड़ रुपये या 9.4 प्रतिशत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं 77.8 हजार करोड़ रुपये या कुल कृषि संस्थागत ऋण का 66.3 प्रतिशत ऋण वाणिज्कि बैंकों या व्यापारिक बैंकों द्वारा दिया गया था। इसके अतिरिक्त समय–समय पर सरकार द्वारा किसानों को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती रही है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता मुख्यतया विस्तृत या बड़े पैमाने पर होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के समय दी जाती है। इन संस्थागत स्रोतों से कृषि क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करने के कार्य में निरन्तर वृद्धि हुयी है। इनके क्रियाकलापों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण केन्द्र एवं राज्य सरकारों की कृषि नीति के अन्तर्गत कृषि विकास को प्राथमिकता प्रदान करना रहा है। कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक से अधिक वित्त प्रदान करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र का निर्धारण किया जाता रहा है। प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि, लघु उद्योग एवं समाज के कमजोर वर्गों को रखा गया है। प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों में कृषि क्षेत्र को अधिक से अधिक संस्थागत वित्त या ऋण प्रदान किये जाने का प्रयास किया जाता रहा है।

वर्ष 2002 में कृषि क्षेत्र में 60.8 हजार करोड़ रुपये का ऋण संस्थागत स्रोतों द्वारा प्रदान किया गया था जो वर्ष 2005 में बढ़कर 122.4 हजार करोड़ रुपये हो गया।[1]

वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात से इन बैंकों द्वारा अधिक से अधिक ऋण कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 1969 में (व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय) इन बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋण का मात्र 3.6 प्रतिशत था। राष्ट्रीयकरण के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का 15 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष वित्त या ऋण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिसे वर्ष 1985 तक प्राप्त किया जाना था। इस लक्ष्य को बाद में बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया। जिसे वर्ष 1987 तक प्राप्त किया जाना था।[2] वर्ष 1988 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल ऋण का लगभग 16.8 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष ऋण के रूप में प्रदान किया गया था। राष्ट्रीयकरण के पश्चात से वर्ष 1990 तक सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र मे प्रत्यक्ष ऋण या वित्त को सारणी संख्या 11 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–11

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया अग्रिम या ऋण (ऋण खातों की संख्या लाख में)

क्षेत्र	वर्ष							
	1969	**1984**	**1985**	**1986**	**1987**	**1988**	**1989**	**1990**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कृषि क्षेत्र में प्रदत्त कुल ऋण	3.28	216.11	241.94	269.74	297.98	303.92	354.22	355.34
(अ) प्रत्यक्ष ऋण	2.67	134.79	150.27	165.58	180.34	180.93	207.50	203.54
(ब) परोक्ष ऋण	–	9.91	9.73	9.56	7.73	7.23	7.46	6.88

सारणी संख्या 11 से यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण देने के खातों में आधे से अधिक खाते कृषि क्षेत्र के ऋण प्राप्तकर्ताओं के हैं। वर्ष 1969 में कृषि क्षेत्र के ऋण प्राप्तकर्ताओं के खातों की कुल बैंकों के कुल खातों में 8.1 प्रतिशत थी। जो वर्ष 1988 में बढ़कर 60.1 प्रतिशत हो गयी थी साथ ही यह भी स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष वित्त प्राप्तकर्ताओं के खातों की

1 – भारत 2002–2005
2 – भारत 1988–1989 पृष्ठ 303
3 – सारणी संख्या 11 भारत 1988–1989 पृष्ठ 305

संख्या में वृद्धि और परोक्ष वित्त के खातेदारों की संख्या में समय व्यतीत होने के साथ–साथ निरन्तर कमी हुई है। वर्ष 1984 में परोक्ष वित्त प्राप्तकर्ता खातेदारों की संख्या 9.91 लाख रही है जो वर्ष 1988 में कम होकर 7.23 लाख हो गई इसके विपरीत कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्राप्तकर्ता खातेदारों की संख्या जो वर्ष 1969 में 2.67 लाख थी वह 1988 में बढ़कर 180.93 लाख हो गई।

यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रदान किये गये वित्त/ऋण की मात्रा पर विचार किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि वाणिज्यिक बैंकों के विभिन्न उद्देश्यो के लिये दिये गये ऋणों में वृद्धि के साथ–साथ कृषि क्षेत्र के लिए दिये जाने वाले ऋणों में भी वृद्धि हुई है। इस बात का अनुमान बैंकों के कृषि क्षेत्र में लगे हुये ऋण की रकम द्वारा लगाया जा सकता है। वर्ष 1969 में इन बैंकों का कुल 483.30 करोड़ रुपये का ऋण विभिन्न क्षेत्रों में लगा हुआ था। जो 1988 में बढ़कर 28467.8 करोड़ रुपये हो गया। इस लगे हुये ऋण का लगभग 30 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र में लगा हुआ था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लगे हुये ऋण की स्थिति को सारणी संख्या 12 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–12

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऋण वितरण (करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	वर्ष						
	1969	1984	1985	1986	1987	1988	1989
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कृषि क्षेत्र							
(i) प्रत्यक्ष वित्त	188.40	5970.36	7415.13	8929.97	10287.23	10437.95	14897.35
(ii) परोक्ष वित्त	–	1373.70	1378.32	1377.50	1425.27	1418.99	1286.13
2. लघु उद्योग क्षेत्र	285.90	6233.61	7470.70	8684.07	10166.32	10547.59	14281.40
3. थल (सड़क) एवं जल परिवहन	8.20	1774.08	1882.70	1958.62	–	–	–
4. स्वरोजगार	0.30	510.00	653.29	883.68	5931.22	6063.26	–
5. शिक्षा	0.50	25.28	32.68	35.85	–	–	–

क्षेत्र	वर्ष						
	1969	1984	1985	1986	1987	1988	1989
1	2	3	4	5	6	7	8
6. गृह निर्माण	–	53.14	63.80	106.06	–	–	–
7. उपभोग	–	18.52	21.01	18.91	–	–	–
8. अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	–	1419.25	1730.11	2140.62	–	–	–
9. फुटकर और लघु व्यापार	–	–	–	–	–	–	7643.01
योग –	**483.30**	**17377.94**	**20647.80**	**24085.28**	**27940.57**	**32662.14**	**39832.56**

स्रोत – इण्डिया 1988–89 पृष्ठ 305 व 306 पर दिये गये आंकड़ों पर आधारित

सारणी संख्या 12 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1969 में व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले बड़े एवं मध्यम आकार के उद्योगों एवं थोक व्यापार के लिए 78 प्रतिशत ऋण इन बैंकों द्वारा दिया गया था पर राष्ट्रीयकरण के पश्चात के वर्षों में वर्ष 1988 में इन क्षेत्रों को प्राप्त ऋण का भाग कम होकर 41 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत प्राथमिकता क्षेत्र को प्राप्त होने वाले ऋण में निरन्तर वृद्धि हुयी है।

वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात (1969) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में वित्त प्रदान करने को प्राथमिकता प्रदान की गई जिन्हें राष्ट्रीयकरण के पहले वित्त नहीं प्रदान किया जाता था। इसके अन्तर्गत लघु ऋण प्राप्तकर्ताओं को इन बैंकों द्वारा वित्त नहीं प्राप्त नहीं हो पाता था। इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात लघु ऋण प्राप्तकर्ताओं को ऋण प्रदान करने को प्राथमिकता प्रदान की गई। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लघु ऋण प्राप्तकर्ताओं को शाख की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्कीम तैयार की गई। इसके अन्तर्गत कृषि, लघु पैमाने के उद्योग, सड़क एवं जल परिवहन, फुटकर व्यापार एवं छोटे मोटे लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करने का कार्य किया गया। इन वर्गों को बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकरण के पहले कोई महत्व नहीं प्रदान किया जाता था। वाणिज्यिक बैंकों के वित्त का एक बहुत थोड़ा भाग ही इन्हें प्राप्त हो पाता था। कमजोर वर्गों को उनके संसाधनों की आवश्यकता

को पूरा करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के वित्त/ऋणों में उपभोग ऋण को ही शामिल किया गया इसी प्रकार अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को गृह निर्माण के लघु ऋणों को भी प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल किया गया। परिणामस्वरूप वर्ष 1969 से 1988 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उपरोक्त प्रकार के ऋण प्राप्तकर्ताओं के खातों की संख्या जो वर्ष 1969 में 2.60 लाख थी वह 1988 में बढ़कर 303.92 लाख हो गई। इन ऋण प्राप्तकर्ताओं पर लगे हुये ऋण की मात्रा वर्ष 1969 में 441 करोड़ रुपये थी जो वर्ष 1988 में बढ़कर 28468 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 1988 में कुल वाणिज्यिक बैंको द्वारा दिये जाने वाले ऋण का 45.8 प्रतिशत ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया था।[4]

लघु ऋण प्राप्तकर्ताओं तथा अर्थव्यवस्था के जिन क्षेत्रों को वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले परित्यज क्षेत्र माना जाता था। उन्हें साख प्रदान करने को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य में एक प्रमुख चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृषि, लघु उद्योग, सड़क एवं जल परिवहन, फुटकर व्यापार एवं छोटे व्यवसायों के छोटे ऋण प्राप्तकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्कीमों का निर्माण किया गया। इन ऋण प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रीयकरण के पहले बैंकों के माध्यम से बहुत कम मात्रा में ऋण प्राप्त हो पाता था या नहीं प्राप्त हो पाता था। कमजोर वर्ग के लोगों को उनकी आवश्यकतानुसार ऋण प्रदान करने के कार्य में कुछ सीमा तक के उपभोग के लिए ऋण दिये जाने के कार्य को भी प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के गृह निर्माण के लिए छोटी रकम के ऋणों को भी प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों में शामिल किया गया। इन सब कार्यों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण प्राप्तकर्ताओं के खातों की संख्या जो वर्ष 1969 में 2.60 लाख थी वह वर्ष 1990 में बढ़कर 35.5 लाख हो गयी तथा इन ऋण प्राप्तकर्ताओं के ऊपर लगे हुये ऋण की रकम इन्हीं वर्षों में 441 करोड़ रुपये से बढ़कर 3983.3 करोड़ रुपये हो गयी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों द्वारा सभी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋण का लगभग 42.7 प्रतिशत ऋण वर्ष 1990 में दिया गया था। वाणिज्यिक बैंकों के इस प्रगति को सारणी संख्या 13 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

---

4 — इण्डिया 1988—89 पृष्ठ 304

सारणी संख्या–13

कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण का प्रवाह (हिस्सा प्रतिशत में)

संस्थायें	वर्ष				
	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5	6
1. सहकारी बैंक (हिस्सा प्रतिशत में)	44%	43%	40%	39%	42%
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	6%	7%	7%	8%	8%
3. वाणिज्यिक बैंक	50%	50%	53%	53%	50%
कुल रकम (करोड़ रुपये में)	31956.0	36860	46268	52714	64000

स्रोत : इकोनामिक सर्वे 2002–03 पृष्ठ 166

सारणी संख्या 13 से यह स्पष्ट है कि सहकारी बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को कृषि आवश्यकता का 1997–98 में 44 प्रतिशत ऋण दिया गया था। जो वर्ष 2001–02 में 42 प्रतिशत रहा है जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इन्हीं वर्षों में कुल कृषि आवश्यकता का क्रमशः 6 प्रतिशत व 8 प्रतिशत रहा है जबकि इंन्हीं वर्षों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 50 प्रतिशत व 50 प्रतिशत रहा है।

9वीं पचंवर्षीय योजना (1997–2002) के समयावधि में कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्रों में 229000 करोड़ रुपये के ऋण दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जबकि वास्तविक रूप में 233700 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये गये। इसी प्रकार 10 वीं पंचवर्षीय योजना काल में (2002–2007) कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्रों में सभी बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से 736570 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये गये जो 9 वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदत्त ऋणों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक रहा है।[5]

राष्ट्रीयकरण के पश्चात से वर्तमान समय (वर्ष 2001) तक के सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक के विभिन्न क्रियाकलापों को सारणी संख्या 14 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

---

5 – इकोनामिक सर्वे 2002–03 पृष्ठ S- 57

सारणी संख्या–14

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का अग्रिम

संस्थायें	वर्ष				
	1969	1998	1999	2000	2001
1	2	3	4	5	6
1. खातों की संख्या (हजार में)					
(i) प्रत्यक्ष वित्त	160	16722	16349	15754	18482
(ii) परोक्ष वित्त	4	295	285	293	271
2. लगा हुआ ऋण (करोड़ रुपये में)					
(i) प्रत्यक्ष वित्त	40	27746	31167	34247	38137
(ii) परोक्ष वित्त	122	5396	6464	11049	15434
3. बैंक के कुल ऋणों का कृषि क्षे में लगा हुआ ऋण (प्रतिशत में)					
(i) प्रत्यक्ष	1.3	10.9	11.7	10.8	11.2
(ii) परोक्ष	4	2.1	2.4	3.5	4.5
4. कुल ऋणों में प्राथमिकता क्षेत्र का अग्रिम प्रतिशत में	14.6%	35.7%	39.2%	40.3%	43.7%

स्रोत– इकोनामिक सर्वे 2002–03 पृष्ठ 166 पर दिये गये आंकड़ों पर आधारित

सारणी संख्या 14 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1969 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल प्रत्यक्ष खातो की संख्या 107 थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 18482 हो गई वहीं इन्हीं वर्षों में परोक्ष वित्त खातों की संख्या 4 थी जो बढ़कर 271 हो गई तथा लगे हुये ऋण की रकम वर्ष 1969 में प्रत्यक्ष वित्त के रूप में 40 करोड़ रुपये थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 38137 करोड़ रुपये हो गयी। वहीं परोक्ष वित्त

इन्हीं वर्षों में 122 करोड़ रुपये से बढ़कर 15434 करोड़ रुपये हो गया, बैंक के कुल ऋणों का कृषि क्षेत्र में लगा हुआ ऋण वर्ष 1969 में प्रत्यक्ष रूप से 1.3 प्रतिशत था, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 11.2 प्रतिशत हो गया। वहीं परोक्ष ऋण इन्हीं वर्षों में 4 प्रतिशत से बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गया, कुल ऋणों में प्राथमिकता क्षेत्र का अग्रिम वर्ष 1969 में 14.6 प्रतिशत था जो वर्ष 2001 में बढ़कर 43.7 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2004–05 में कृषि क्षेत्र को 115.2 हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया जो लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक था, जबकि लक्ष्य 105 हजार करोड़ रुपये का निर्धारित किया गया था। वर्ष 2005–06 में पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक ऋण कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्र में वितरित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 50 लाख और अधिक ऋण प्राप्तकर्ताओं को ऋण दिये जाने की सलाह दी गई थी। लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्रत्यक्ष ऋण का 40 प्रतिशत भाग विशेष कृषि साख योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007 तक वितरित किया जाना था। इसके लिए बैंकों को कृषि क्षेत्र में ऋण की मात्रा में वृद्धि करने के लिए सीमा सुरक्षा के रकम की आवश्यकता को समाप्त करके भी किये जाने का प्रावधान बनाया गया। इसके अन्तर्गत 50 हजार रुपये तक के ऋणों को शामिल किया गया। ऋणदाता व ऋणी के बीच रकम पहुंचने से सम्बन्धित जितनी भी बाधायें आती हैं उन्हें समाप्त करने का प्रयास करके कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में वृद्धि की जा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक व नाबार्ड (NABARD) द्वारा लागू किया जा चुका है। वर्ष 2005 तक कमेटी की 99 सिफारिशों में से 33 सिफारिशों को स्वीकार करके लागू किया जा चुका है। इन सिफारिशों को बैंकों द्वारा छोटे उत्पादकों के साख सीमा के निर्धारण तथा पारिवारिक ऋणों में अस्थाई कमी को पूरा करने के लिए निवेश ऋण उपलब्ध कराने से सम्बन्धित रही है। वर्ष 2004–05 में कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण का लक्ष्य 105 हजार करोड़ रुपये निश्चित किया गया था। इस लक्ष्य के सम्बन्ध में सभी संस्थागत स्रोतों के माध्यम से 115 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में संस्थागत साख के प्रवाह को सारणी संख्या 15 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–15

कृषि क्षेत्र में संस्थागत वित्त का प्रवाह (धनराशि करोड़ रुपये में)

संस्थायें	वर्ष			
	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4	5
1. सहकारी बैंक	23716	26959	30639	28947
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	8070	7581	11718	11146
3. वाणिज्यिक बैंक	39774	52441	72886	77806
योग –	**71560**	**86981**	**115243**	**117899**

स्रोत– इकोनामिक सर्वे 2005–06 पृष्ठ 64 पर दिये गये आंकड़ों पर आधारित

सारणी संख्या 15 से यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2002–03 में सहकारी बैंकों द्वारा 23716 करोड़ रुपये का ऋण कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए दिया गया था जो वित्तीय वर्ष 2005–06 में बढ़कर 28947 करोड़ रुपये हो गया था। इसी प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2002–03 में 8070 करोड़ रुपये के ऋण कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्रों को दिये गये। जो वित्तीय वर्ष 2005–06 में बढ़कर 11146 करोड़ रुपये हो गये, और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इन्हीं वर्षों में क्रमशः 39774 करोड़ रुपये व 77806 करोड़ रुपये का कृषि क्षेत्र में ऋण वितरित किया गया।

व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक के कार्य :

विस्तृत अर्थों में वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंकों का अर्थ उन सभी बैंकिंग संस्थाओं से लगाया जा सकता है जो किसी अर्थव्यवस्था में रुपये के लेन–देन या व्यवसाय का कार्य करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर वाणिज्यिक बैंकों का कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए उन सभी बैंकिंग संस्थाओं पर विचार किया जायेगा जो कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए ऋण प्रदान करने का कार्य करते हैं।

कृषि अर्थव्यवस्था में एक केन्द्रीय बैंक होता है जो व्यवसायिक बैंकों की क्रियाओं पर नियन्त्रण और नियमन उनके व्यवसायिक क्रियाओं के मार्ग दर्शन तथा उन पर नियन्त्रण बनाने

का कार्य करता है। साथ ही अर्थव्यवस्था में सम्पूर्ण मौद्रिक अर्थव्यवस्था में नियन्त्रण बनाये रखने का कार्य करता है इस प्रकार किसी देश का केन्द्रीय बैंक समय–समय पर विभिन्न नीतियों को अपनाकर न केवल व्यवसायिक बैंकों पर नियन्त्रण का कार्य करता है बल्कि वह इनका कस्टोडियम होता है। व्यवसायिक बैंकों की उनकी आवश्यकतानुसार मुद्रा की आपूर्ति करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में केन्द्रीय बैंक के कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किये जाते हैं। अतः भारतीय केन्द्रीय बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक का नाम दिया गया है।

उपरोक्त अर्थों में भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर सभी बैंकिंग संगठनों को व्यवसायिक बैंकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत कुल 218 अनुसूचित (विदेशी बैंकों सहित) वाणिज्यिक बैंक हैं। इनमें से 161 सार्वजनिक क्षेत्र के हैं जिनमें से 133 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर0 आर0 बी0) हैं और ये सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि का 75.2 प्रतिशत एकत्र करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे ऋण प्राप्तकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए विशेष रूप से की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा बाकी 28 बैंकों में 19 राष्ट्रीयकृत, 8 एस0 बी0 आई0 समूह के व आई0 डी0 बी0 आई0 लिमिटेड शामिल हैं और ये सभी तरह का बैंकिंग व्यवसाय करते हैं।

1999 से भारत में वाणिज्यिक बैंकों की प्रगति सम्बन्धी कुछ प्रमुख संकेतक सारणी संख्या 16 में स्पष्ट किये गये हैं।

सारणी संख्या–16

भारत में वाणिज्यिक बैंकों की प्रगति (स्थिति 31 मार्च)

मद	वर्ष					
	1999	**2000**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
1	2	3	4	5	6	7
1. वाणिज्यिक बैंकों की संख्या	303	297	298	294	291	288
(क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	302	297	294	289	286	284
(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	196	196	196	196	196
(ग) गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1	–	4	5	–	4
2. देश में बैंक कार्यालयों की संख्या	64939	65412	66190	66535	67188	68355

मद	वर्ष					
	1999	2000	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7
3. कार्यालयों के अनुसार जनसंख्या (हजार में)	15	15	16	16	16	16
4. देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल डिपाजिट (करोड़ रुपये में)	714025	851393[@]	1131187[#]	1311761[#]	1542284[&]	1732858[&]
5. देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल ऋण (करोड़ रुपये में)	368887	454069	609053	746432	865594	1124300
6. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिव्यक्ति जमा (रुपये में)	7237	8998	10994	12554	14550	16091
7. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया हुआ प्रतिव्यक्ति ऋण	3738	4531	6919	7143	8166	10440
8. वर्तमान मूल्यों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि राष्ट्रीय आय के प्रतिशत में	49.8%	53.5%	60.5%	65.3%	68.5%	68.3%

स्रोत– सारणी संख्या 16 इण्डिया 2007 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित पृष्ठ 362

वर्तमान अध्ययन में कृषि अर्थव्यवस्था पर वाणिज्यिक बैंकों के वित्त का पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना है इसलिए सभी प्रकार के वाणिज्यिक बैंकों के बजाय उन व्यावसायिक बैंकों के क्रियाकलापों पर विचार किया जायेगा जो कृषि क्षेत्र में किसानों एवं कृषि से सम्बन्धित व्यक्तियों को उधार देने का कार्य करते हैं अतः इन संस्थाओं के क्रियाकलापों का मूल्यांकन कानपुर क्षेत्र के सन्दर्भ में किया जा रहा है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश 17 मण्डलों में विभक्त है। कानपुर मण्डल के अन्तर्गत 6 जनपद आते हैं जो क्रमशः फर्रूखबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर व कानपुर देहात हैं। वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत इन बैंकों के क्रियाकलापों पर उक्त जनपदों को दृष्टिकोण में रखकर

@ इसमें रिसर्जेन्ट इण्डिया बाण्ड (17945 करोड़ रुपये) शामिल है।

इसमें रिसर्जेन्ट इण्डिया बाण्ड (17945 करोड़ रुपये) तथा इण्डिया मिलेनियम डिपाजिट्स(25662 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

& इसमें इण्डिया मिलेनियम डिपाजिट्स (25662 करोड़ रुपये) शामिल है।

किया जायेगा। इन बैंकों के क्रियाकलापों पर विचार करने के पहले इन जनपदों के सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं पर संक्षेप में विचार किया जाना आवश्यक हो जाता है जो निम्न प्रकार है–

1. **फर्रूखाबाद जनपद** – फर्रूखाबाद जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 2181 वर्ग किलोमीटर है जनपद में 3 तहसीलें व 7 विकास खण्ड हैं। जिसमें 219911 हेक्टेयर प्रतिवेदित क्षेत्रफल है। प्रतिवेदित क्षेत्रफल के अन्तर्गत रिपोर्ट की गयी भूमि विभिन्न उपयोगों में लगी हुई है जिसके विवरण को सारणी संख्या 17 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–17

फर्रूखाबाद जनपद में प्रतिवेदित भूमि का वितरण (वर्ष 2001–02)

प्रतिवेदित क्षेत्रफल के मद	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिवेदित क्षेत्रफल से प्रतिशत
1	2	3
1. वनो का क्षेत्रफल	1085	0.5
2. ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि	6844	3.1
3. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने लगी भूमि	17934	8.2
4. कृष्य बेकार भूमि	4990	2.3
5. चरागाह तथा अन्य वृक्ष, झाडियों आदि की भूमि	4338	2.0
6. वर्तमान परती एवं अन्य परती	25053	11.4
7. शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	152191	69.2
8. अन्य भूमि	7476	3.3
योग –	**219911**	**100**

स्रोत – सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश वर्ष 2006 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित पृष्ठ 102, 103

सारणी संख्या 17 से यह स्पष्ट है कि जनपद के प्रतिवेदित क्षेत्रफल में 0.5 प्रतिशत क्षेत्र बनों से आच्छादित है, 3.1 प्रतिशत भूमि ऊसर एवं खेती के अयोग्य है, 8.2 प्रतिशत भूमि कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगों में लगी हुई है, 2.3 प्रतिशत भूमि कृषि के दृष्टिकोण से बेकार है, 2.0 प्रतिशत भूमि चरागाह व अन्य वृक्ष झाड़ियों के अन्तर्गत लगी है, 11.4 प्रतिशत भूमि वर्तमान परती एवं अन्य परती भूमि है। जनपद के प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 69.2 प्रतिशत भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र है तथा शेष 3.3 प्रतिशत भूमि अन्य उपयोगों में लगी हुई है जिसका विवरण नहीं प्राप्त हो सका है।

जनसंख्या सम्बन्धी विशेषतायें : जनपद की वर्तमान जनसंख्या 1570 हजार है जिसमें से 1229 हजार या 78.3 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में व 341 हजार या 21.7 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में आवास करती है। जनपद की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है जो निम्न वर्षों के जनगणना आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट की जा सकती है जिसे सारणी संख्या 18 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–18

फर्रुखाबाद जनपद की जनसंख्या का विवरण

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या	जनसंख्या में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में)	दशक
1	2	3	4
1961	1295071	–	–
1971	1556930	20.22	1961–71
1981	1949137	25.19	1971–81
1991	1284419	25.20	1981–91
2001	1570408	22.27	1991–2001

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश वर्ष 2003 के पृष्ठ 24 व 26 पर दिये गये आंकड़ों पर आधारित

सारणी संख्या 18 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1961 में जनपद की जनसंख्या 2295071 थी, जो वर्ष 1971 में बढ़कर 1556930 हो गई। जनसंख्या में होने वाली यह वृद्धि 20.22 प्रतिशत रही है।

वर्ष 1981 में जनपद की जनसंख्या 1949137 हो गई जो गत दशक की तुलना में 25.19 प्रतिशत अधिक रही है, जनपद की जनसंख्या वर्ष 1991 में 1284419 हो गई जो यह स्पष्ट करती है कि जनपद की जनसंख्या में कमी आई है। वर्ष 2001 में जनसंख्या बढ़कर 1570408 हजार हो गई जो गत वर्ष की तुलना में 22.27 प्रतिशत अधिक रही है इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि जनपद की जनसंख्या में कुछ वर्षों को छोड़कर शेष वर्षों में लगभग वृद्धि ही स्पष्ट होती है।

ग्रामीण व शहरी जनसंख्या : जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात 1229 : 341 हजार है। जो अनुपात में 1 : 027 बनता है। यदि प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाय तो कहा जा सकता है कि कुल जनसंख्या का 78.3 प्रतिशत ग्रामीण एवं 21.7 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है।

जनसंख्या का घनत्व : जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार फर्रूखाबाद जनपद की जनसंख्या का घनत्व 720 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर निवास करते हैं।

जनसंख्या का पेशेवर विभाजन : फर्रूखाबाद जनपद की जनसंख्या विभिन्न देशों में लगी हुई है जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनपद की जनसंख्या के पेशेवर विभाजन को सारणी संख्या 19 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–19

फर्रूखाबाद जनपद की जनसंख्या का पेशेवर विभाजन (वर्ष 2001)

पेशा	पेशे में लगी जनसंख्या	कार्यशील जनसंख्या से प्रतिशत
1	2	3
1. कृषक	207120	44.7
2. कृषि श्रमिक	54405	11.7
3. पारिवारिक उद्योग मे लगे व्यक्तियों की संख्या	22356	4.9
4. अन्य कर्मकर	97020	21
5. अन्य मुख्य कर्मकर	81943	17.7
योग –	**462853**	**100**

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश वर्ष 2003 पर दिये गये आंकड़ों पर आधारित पृष्ठ 61, 62 व 63

सारणी संख्या 19 से यह बात स्पष्ट होती है कि फर्रूखाबाद जनपद में पेशेवर लगी जनसंख्या में 207120 या 44.7 प्रतिशत कृषक, 54405 या 11.7 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 22356 या 4.9 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग में लगे व्यक्तियों की संख्या है, 97020 या 21 प्रतिशत जनसंख्या अन्य कर्मकर और अन्य मुख्य कर्मकरों में लगे व्यक्तियों की संख्या 81943 या 17.7 प्रतिशत है इस प्रकार कहा जा सकता है कि जनपद की कुल जनसंख्या में 462853 कार्यशील जनसंख्या है जो कुल जनसंख्या के सापेक्ष 29.5 प्रतिशत है जबकि शेष जनसंख्या 1107555 या कुल जनसंख्या का 70.5 प्रतिशत जनसंख्या काम न करने वालों की है जिसमें 442054 पुरुष व 666501 स्त्रियां आती है।

पुरुष व स्त्री अनुपात : वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर फर्रूखाबाद जनपद की जनसंख्या में पुरुष स्त्री अनुपात 849800 : 720608 या 1 : 0.84 रहा है जो इस बात को स्पष्ट करता है कि जनपद में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की कमी है।

कृषि की दशायें : फर्रूखाबाद जनपद में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है जिनमें मुख्यतया धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहं, चना, दाले, मूंगफली, तिलशुद्ध, लाही तथा सरसों, अलसी, गन्ना व आलू आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। इन फसलों का उपयोग खाद्यांश, तिलहन, व दलहन के रूप में किया जाता है। खाद्यांशों के अतिरिक्त इन्हीं फसलों को किसान व्यवसायिक फसलों के रूप में बेचकर आय प्राप्त करते हैं। जनपद में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली गेहूं की फसल है तत्पश्चात मक्का, आलू, धान, लाही/सरसों, दालें गन्ना बाजरा, चना, ज्वार आदि का नम्बर आता है इन सबके उत्पादन स्तर एवं औसत उत्पादन को क्षेत्रफल के आधार पर उगाई जाने वाली फसलों को क्रमवार करके सारणी संख्या 20 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है

सारणी संख्या–20
फर्रुखाबाद जनपद में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लगा क्षेत्र (वर्ष 2001–02)

फसल का नाम	फसल में लगा क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उत्पादन (मीट्रिक टन में)	औसत उपज (कुन्तल/हेक्टेयर)
1	2	3	4
1. गेहूं	77062	258113	34.49
2. मक्का	44890	87482	19.49
3. आलू	29382	818700	278.64
4. धान	14306	30081	21.03
5. लाही/सरसों	9505	11913	13.23
6. दालें	8701	8996	10.34
7. गन्ना	7483	429764	574.32
8. बाजरा	4162	4406	10.59
9. चना	1823	2223	12.19
10. ज्वार	1635	1227	9.34
11. तिलसुद्ध	1221	200	1.64
12. मूंगफली	109	91	8.39

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश वर्ष 2003 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित पृष्ठ 236–255 तक

सारणी संख्या 20 से यह स्पष्ट है कि फर्रुखाबाद जनपद के सबसे अधिक प्रतिवेदित क्षेत्र में गेहूं की फसल उगाई जाती है। इसके बाद क्रमशः मक्का, आलू, धान, लाही/सरसों व दालों आदि की खेती की जाती है। जनपद के शुद्ध बोये गये क्षेत्र में से शुद्ध सिंचित क्षेत्र 131444 या 85.6 प्रतिशत है जबकि जनपद का सम्पूर्ण सिंचित क्षेत्रफल 167981 या 73.34 प्रतिशत सम्पूर्ण बोये गये क्षेत्र का है।

कानपुर क्षेत्र का विस्तार दूसरे जनपद कन्नौज तक है जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 2093 वर्ग किलोमीटर है जनपद का प्रशासनिक ढॉचा 3 तहसीलों एवं 8 विकास खण्डों में विभक्त है।

कन्नौज जनपद में भूमि उपयोग : जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 2093 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 208973 हेक्टेयर प्रतिवेदित क्षेत्रफल है जो विभिन्न उपयोगों में लगा हुआ है। प्रतिवेदित क्षेत्र के वितरण को सारणी संख्या 21 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–21
कन्नौज जनपद में प्रतिवेदित भूमि का वितरण (वर्ष 2001–02)

प्रतिवेदित क्षेत्रफल के मद	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिवेदित क्षेत्रफल से प्रतिशत
1	2	3
1. वनो का क्षेत्रफल	12749	6.1
2. ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि	6844	3.3
3. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने लगी भूमि	17934	8.6
4. कृष्य बेकार भूमि	5725	2.6
5. चरागाह तथा अन्य वृक्ष, झाडियों आदि की भूमि	5013	2.4
6. वर्तमान परती एवं अन्य परती	18360	8.8
7. शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	142348	68.2
योग –	**208973**	**100**

स्रोत – सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश वर्ष 2006 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित पृष्ठ 102, 103

सारणी संख्या 21 से यह स्पष्ट है कि जनपद के प्रतिवेदित क्षेत्रफल में 142348 हेक्टेयर क्षेत्रफल शुद्ध बोया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद के 6.1 प्रतिशत भूमि जो 12749 हेक्टेयर है बनो से आच्छादित है, प्रतिवेदित क्षेत्रफल के 3.3 प्रतिशत या 6844 हेक्टेयर भूमि ऊसर और कृषि के अयोग्य घोषित की गयी है। इन सबके अतिरिक्त या शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के अतिरिक्त जनपद के प्रतिवेदित क्षेत्र का 8.6 प्रतिशत या 17934 हेक्टेयर भूमि कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगों में लगी हुई है। इसके अतिरिक्त जनपद की 2.6 प्रतिशत प्रतिवेदित भूमि जो 5725 हेक्टेयर कृष्य बेकार भूमि है, 2.4 प्रतिशत या 5013 हेक्टेयर प्रतिवेदित क्षेत्र का चरागाह तथा अन्य वृक्ष झाड़ियों आदि में लगा हुआ है। इन सब उपयोग के अतिरिक्त प्रतिवेदित क्षेत्र का 8.8 प्रतिशत या 18360 हेक्टेयर वर्तमान परती एवं अन्य परती भूमि है। इस प्रकार जनपद के प्रतिवेदित क्षेत्रफल में 160282 हेक्टेयर पर विभिन्न उत्पादन की क्रियायें की जाती हैं जो प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 76.8 प्रतिशत है। जिसमें कृषि उत्पादन का कार्य 68.2 प्रतिशत तथा अन्य उत्पादन की क्रियायें 8.6 प्रतिशत भूमि पर की जाती हैं।

जनसंख्या सम्बन्धी विशेषतायें : वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार कन्नौज जनपद की जनसंख्या 1387888 रही है। जो वर्ष 1991 में 1155847 थी। वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार पायी जाने वाली जनसंख्या में 744170 पुरुष व 644753 स्त्रियां हैं। इस आधार पर जनसंख्या में पुरुष स्त्री अनुपात 744170 : 644753 या 1 : 0.86 है। जनपद की जनसंख्या में 1156951 ग्रामीण जनसंख्या और 231972 नगरीय जनसंख्या है। इस आधार पर जनपद की जनसंख्या में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का अनुपात 1156951 : 231972 या 1 : 0.20 है। जनपद के उपरोक्त जनसंख्या में आय अर्जित करने वालों की संख्या या जिसे कार्यशील जनसंख्या कहा जा सकता है की संख्या 457591 और आश्रित जनसंख्या या जिन्हें कार्य न करने वालों की श्रेणी में रखा जा सकता है की संख्या 931332 है। इस प्रकार अर्जित संख्या 32.9 प्रतिशत व कार्य न करने वालों की संख्या 67.1 प्रतिशत है। जनपद का जनसंख्या घनत्व 664 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताओं को सारणी संख्या 22 द्वारा दर्शाया गया है।

सारणी संख्या–22

कन्नौज जनपद में जनसंख्या सम्बन्धी विशेषतायें (वर्ष 2001)

स्थिति	संख्या
1	2
1. जनपद की कुल जनसंख्या	1387888
2. (क) जनसंख्या में पुरुष स्त्री अनुपात	744170 : 644753
(ख) पुरुष स्त्री अनुपात	1 : 0.86
3. ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या	
(क) ग्रामीण जनसंख्या	1156951
(ख) नगरीय जनसंख्या	231972
4. ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का अनुपात	1 : 0.20
5. अर्जित एवं आश्रित जनसंख्या	
(क) अर्जित	457591
(ख) आश्रित	931332
(ग) अर्जित व आश्रित का अनुपात	1 : 2.03
6. जनसंख्या का घनत्व (व्यक्तिप्रति वर्ग किमी.)	664

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश वर्ष 2003 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित

कृषि की दशायें : कन्नौज जनपद में कृषि उत्पादन के अन्तर्गत गेहूं, मक्का, आलू, धान, दालें, लाही/सरसों, बाजरा, चना, ज्वार, तिलशुद्ध, मूंगफली व गन्ने आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। इन विभिन्न फसलों के अन्तर्गत जनपद के लगे हुये क्षेत्र व प्रति हेक्टेयर उत्पादन तथा औसत उत्पादन को क्रमशः सारणी संख्या 23 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–23

कन्नौज जनपद में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लगा क्षेत्र हेक्टेयर में (वर्ष 2001)

फसल का नाम	फसलों में लगा क्षेत्र	उत्पादन (मीट्रिक टन में)	औसत उत्पादन (हेक्टेयर प्रति कुन्तल)
1	2	3	4
1. गेहूं	76950	235689	30.63
2. मक्का	52842	103273	19.52
3. आलू	33061	886365	268.1
4. धान	22922	45047	19.65
5. दालें	11901	13122	11.03
6. लाही/सरसों	11884	13826	11.63
7. बाजरा	3664	3900	10.59
8. चना	2360	2877	12.19
9. ज्वार	1882	1758	9.34
10. तिलशुद्ध	1163	240	1.64
11. मूंगफली	928	779	8.39
12. गन्ना	539	28780	533.95

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश वर्ष 2003 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित

सारणी संख्या 23 से यह स्पष्ट है कि कन्नौज जनपद में सबसे बड़े क्षेत्रफल में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके पश्चात दूसरे क्रम पर मक्का का उत्पादन होता है तत्पश्चात आलू, धान, दालें व लाही/सरसों आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। जनपद की कृषि की जाने वाली भूमि में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 129265 हेक्टेयर है। जो कृषि की जाने वाली भूमि का 88.3 प्रतिशत है। जो जनपद में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लगे क्षेत्र का 58.7 प्रतिशत है।

इटावा जनपद :

कानपुर क्षेत्र का तीसरा जनपद इटावा है इस जनपद के अन्तर्गत 5 तहसील जो 8 विकास खण्डों में विभक्त है। इटावा जनपद की इटावा तहसील के अन्तर्गत बढ़पुरा व बसरेहर विकास खण्ड हैं, सैफई तहसील के अन्तर्गत सैफई विकास खण्ड, जसवन्त नगर तहसील के अन्तर्गत जसवन्त नगर विकास खण्ड है, भरथना तहसील में भरथना, महेवा व ताखा विकास खण्ड हैं तथा चकरनगर तहसील के अन्तर्गत चकरनगर विकास खण्ड है।

भूमि का उपयोग : इटावा जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 2311 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें 246152 हेक्टेयर प्रतिवेदित क्षेत्र है। जनपद का प्रतिवेदित क्षेत्र विभिन्न उपयोगों में लगा हुआ है जिसके विवरण को सारणी संख्या 24 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–24

इटावा जनपद में प्रतिवेदित भूमि का विवरण (वर्ष 2001–02)

मद	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिवेदित क्षेत्र के सापेक्ष प्रतिशत
1	2	3
1. वन	36103	14.7
2. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लगी भूमि	20362	8.3
3. ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि	12101	4.9
4. स्थाई चरागाह एवं अन्य चराई	634	0.2
5. अन्य वृक्ष झाड़ियों का क्षेत्र	2562	1.0
6. कृष्य बेकार भूमि	6554	2.7
7. वर्तमान परती एवं अन्य परती	18969	7.7
8. शुद्ध बोया गया क्षेत्र	148867	60.5
योग –	**246152**	**100**

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश वर्ष 2003 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित पृष्ठ संख्या 215–226

सारणी संख्या 24 से यह स्पष्ट है कि जनपद के प्रतिवेदित क्षेत्रफल में से 60.5 प्रतिशत या 148867 हेक्टेयर क्षेत्र पर खेती की जाती है। शेष में 14.7 प्रतिशत या 36103 हेक्टेयर प्रतिवेदित क्षेत्र वनों से आच्छादित है व 8.3 प्रतिशत या 20362 हेक्टेयर प्रतिवेदित क्षेत्र खेती के अतिरिक्त अन्य उत्पादन कार्य में लगा है, प्रतिवेदित क्षेत्र में से 4.9 प्रतिशत क्षेत्र ऊसर व खेती के अयोग्य है, 0.2 प्रतिशत स्थाई चरागाह एवं अन्य चराई की भूमि, 1.0 प्रतिशत प्रतिवेदित क्षेत्र का अन्य वृक्ष झाड़ियों में, प्रतिवेदित क्षेत्र का 2.7 प्रतिशत कृष्य बेकार भूमि व प्रतिवेदित क्षेत्र का 7.7 प्रतिशत वर्तमान परती व अन्य परती का क्षेत्र है।

कृषि की दशायें : इटावा जनपद में कृषि उत्पादन के अन्तर्गत गेहूं, धान, दालें, मक्का, चना, लाही/सरसों, ज्वार, आलू गन्ना, तिलशुद्ध, बाजरा व मूंगफली आदि की फसलें उगाई जाती हैं। जिसके विवरण को सारणी संख्या 25 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है–

सारणी संख्या–25

इटावा जनपद में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लगा क्षेत्र हेक्टेयर में (वर्ष 2001)

फसल का नाम	फसलों में लगा क्षेत्र	उत्पादन (मीट्रिक टन में)	औसत उत्पादन (हेक्टेयर प्रति कुन्तल)
1	2	3	4
1. गेहूं	87152	259933	29.83
2. धान	48308	106787	22.11
3. बाजरा	34864	45977	13.19
4. दालें	17763	21991	12.33
5. लाही/सरसों	15810	17428	11.02
6. मक्का	8196	16406	20.02
7. आलू	6610	163921	247.99
8. चना	6339	8300	13.09
9. गन्ना	973	51954	533.96
10. ज्वार	458	428	9.34
11. तिलशुद्ध	165	27	1.64
12. मूंगफली	36	30	8.39

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश वर्ष 2003 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित

सारणी संख्या 25 से यह स्पष्ट है कि इटावा जनपद में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत 226674 हेक्टेयर क्षेत्रफल लगा है जिसमें सबसे बड़े क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद धान, बाजरा, दालें व लाही/सरसों आदि का उत्पादन होता है। जनपद में कृषि की जाने वाली भूमि में से शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल जो शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का 79.5 प्रतिशत है सिंचित क्षेत्र है।

इटावा जनपद की जनसंख्या सम्बन्धी विशेषतायें : वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या 1338871 थी। जो वर्ष 1991 में 1130108 व वर्ष 1981 में 1742651, वर्ष 1971 में 1447702 तथा वर्ष 1961 में 1182202 रही है। जो इस बात को स्पष्ट करती है कि जनसंख्या में 1961 से 1981 तक वृद्धि तथा वर्ष 1991 में कमी तदोपरान्त 2001 में पुनः वृद्धि हुयी है। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार दी हुयी जनसंख्या में 785061 पुरुष व 679972 स्त्रियां हैं इस आधार पर जनसंख्या में पुरुष स्त्री अनुपात 785061 : 679972 या 1 : 0.86 का है। जनपद की जनसंख्या में 1156951 ग्रामीण व 308082 नगरीय जनसंख्या है इस प्रकार जनपद की जनसंख्या में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का अनुपात 1156951 : 308082 या 1 : 0.26 है। जनपद में उपरोक्त जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या या आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों की 368609 व काम न करने वालों की 970262 है। प्रतिशत के रूप में यदि देखा जाय तो कहा जा सकता है कि जनपद में कुल जनसंख्या का कार्यशील जनसंख्या 27.5 प्रतिशत व 72.5 प्रतिशत जनसंख्या कार्य न करने वालों की है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जनपद में आश्रितों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। जहां तक विकास का सवाल है जब तक कार्यशील जनसंख्या की अधिकता नहीं होगी तब तक सम्पूर्ण विकास की स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जनपद में आश्रित जनसंख्या की अधिकता होने का कारण यह भी है कि यहां पर 14 वर्ष से नीचे व 60 वर्ष से ऊपर व्यक्तियों की संख्या अधिक है जो अर्थ संख्या विभाग या सरकारी लेखे के अनुसार आश्रित जनसंख्या के अन्तर्गत आते हैं। जिनकी संख्या जनपद में अपेक्षाकृत अधिक है। इस कारण कार्यशील लोगों की संख्या कम है। और इस प्रकार यदि अनुपात के रूप में जनपद में कार्यशील व आश्रित व्यक्तियों की संख्या को देखा जाय तो कहा जा सकता है कि जनपद में 368609 : 970262 का अनुपात है। या 1 : 2.63 का अनुपात है। जनपद में जनसंख्या का घनत्व 580 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। जनपद की इस जनसंख्या सम्बन्धी समस्त विशेषताओं को सारणी संख्या 26 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–26

इटावा जनपद की जनसंख्या सम्बन्धी विशेषतायें (वर्ष 2001)

स्थिति	संख्या
1	2
1. जनपद की कुल जनसंख्या	1338871
2. (क) जनसंख्या में पुरुष स्त्री अनुपात	785061 : 679972
(ख) पुरुष स्त्री अनुपात	1 : 0.86
3. ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या	1156951 : 308032
(क) ग्रामीण जनसंख्या	1156951
(ख) नगरीय जनसंख्या	308032
4. ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का अनुपात	1 : 0.26
5. अर्जित एवं आश्रित जनसंख्या	368609 : 970262
(क) अर्जित	368609
(ख) आश्रित	970262
(ग) अर्जित व आश्रित का अनुपात	1 : 2.63
6. जनसंख्या का घनत्व (व्यक्तिप्रति वर्ग किमी.)	580

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश वर्ष 2003 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित

औरैया जनपद : कानपुर क्षेत्र का चौथा जनपद औरैया है। औरैया जनपद का सृजन वर्ष 1997 में हुआ है। इसके पहले यह जनपद इटावा जनपद की एक तहसील थी। जिसे वर्ष 1997 में एक अलग प्रशासनिक जनपद का रूप दिया गया। औरैया जनपद में 2 तहसीलें व 7 विकास खण्ड हैं। जो इन दोनों तहसीलों के अन्तर्गत स्थित है। जनपद में प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो दो तहसीलें हैं उनमें औरैया व विधूना हैं। औरैया तहसील के अन्तर्गत औरैया , अजीतमल व भाग्यनगर विकास खण्ड आते हैं तथा विधूना तहसील के अन्तर्गत विधूना, सहार, ऐरवा कटरा व अछल्दा विकास खण्ड आते हैं।

जनपद में भूमि का उपयोग :

औरैया जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 2015 वर्गकिलोमीटर है जिसमें 200239 हेक्टेयर प्रतिवेदित क्षेत्र है। जनपद का प्रतिवेदित क्षेत्र विभिन्न उपयोगों में लगा हुआ है। जिसके विवरण को सारणी संख्या 27 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–27

औरैया जनपद में प्रतिवेदित भूमि का विवरण (वर्ष 2001–02)

मद	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिवेदित क्षेत्र के सापेक्ष प्रतिशत
1	2	3
1. वन	2725	1.3
2. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लगी भूमि	16827	8.4
3. ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि	7994	4.0
4. स्थाई चरागाह एवं अन्य चराई	1322	0.7
5. अन्य वृक्ष झाड़ियों का क्षेत्र	5143	2.6
6. कृष्य बेकार भूमि	5991	3.0
7. वर्तमान परती एवं अन्य परती	20922	10.4
8. शुद्ध बोया गया क्षेत्र	139315	69.6
योग –	200239	100

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश वर्ष 2003 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित पृष्ठ संख्या 215–226

सारणी संख्या 27 से यह स्पष्ट है कि औरैया जनपद के प्रतिवेदित क्षेत्र में से 69.6 प्रतिशत या 139315 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है। जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, 1.3 प्रतिशत या 2725 हेक्टेयर प्रतिवेदित भू–भाग वनों से आच्छादित है, प्रतिवेदित क्षेत्र का 8.4 प्रतिशत या 16827 हेक्टेयर क्षेत्र खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लगा है, प्रतिवेदित क्षेत्र का 4.0 प्रतिशत या 7994 हेक्टेयर ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि, 0.7 प्रतिशत स्थाई चरागाह एवं अन्य

चराई की भूमि, 2.6 प्रतिशत अन्य वृक्ष झाड़ियों आदि में लगी है। तथा प्रतिवेदित क्षेत्र का 3.0 कृष्य बेकार एवं 10.4 प्रतिशत या 20922 हेक्टेयर प्रतिवेदित क्षेत्र वर्तमान परती एवं अन्य परती में पड़ा हुआ क्षेत्र है।

कृषि की दशायें : औरैया जनपद में कृषि उत्पादन के अन्तर्गत गेहूं, धान, दालें, मक्का, चना, लाही/सरसों, तिलशुद्ध, गन्ना, आलू, मूंगफली, बाजरा आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। इन विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्र व उत्पादन स्तर को सारणी संख्या 28 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–28

औरैया जनपद में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लगा क्षेत्र हेक्टेयर में (वर्ष 2001)

फसल का नाम	फसलों में लगा क्षेत्र	उत्पादन (मीट्रिक टन में)	औसत उत्पादन (हेक्टेयर प्रति कुन्तल)
1	2	3	4
1. गेहूं	88476	289048	32.67
2. धान	51471	125273	24.34
3. बाजरा	21902	29596	13.51
4. दालें	18371	21066	11.47
5. मक्का	13059	27643	21.17
6. लाही/सरसों	12739	15285	12.00
7. ज्वार	9796	2083	7.45
8. चना	8633	9035	10.47
9. आलू	2738	59475	217.22
10. गन्ना	1306	77985	597.13
11. मूंगफली	139	117	8.39
12. तिलशुद्ध	28	5	1.64
13. अलसी	04	2	4.20

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश वर्ष 2003 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित

सारणी संख्या 28 से यह स्पष्ट है कि औरैया जनपद में सबसे बड़े भू–भाग में गेहूं की खेती की जाती है। तत्पश्चात धान, बाजरा, दालें, मक्का द लाही/सरसों आदि फसलों का उत्पादन होता है। जनपद में कृषि की जाने वाली भूमि में से कुल सिंचित क्षेत्रफल 173101 हेक्टेयर है। जो कुल सिंचित क्षेत्रफल का सम्पूर्ण बोये गये क्षेत्र से 76.59 प्रतिशत या शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल 109303 हेक्टेयर का 78.5 प्रतिशत है।

जनसंख्या सम्बन्धी विशेषतायें : औरैया जनपद की जनसंख्या जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार 1179993 है, जिसमें 635762 पुरुष व 544231 स्त्रियां हैं। इस आधार पर जनपद में पुरुष स्त्री अनुपात 635762 : 544231 या 1 : 0.85 है। जनपद की जनसंख्या में 1011226 ग्रामीण व 168967 नगरीय जनसंख्या है। जिसमें ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का अनुपात 1011226 : 168967 या 1 : 0.16 का अनुपात है। जनपद के उपरोक्त जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 388260 व कार्य न करने वालों की संख्या 791733 है। आनुपातिक दृष्टि से 388260 : 791733 या 1 : 2.02 का अनुपात है। यदि प्रतिशत के रूप में कार्यशील व कार्य न करने वालों की जनसंख्या को देखा जाय तो कहा जा सकता है कि जनपद में 32.9 प्रतिशत व 67.1 प्रतिशत है। इस प्रकार औरैया जनपद में भी अन्य जनपदों की भांति आश्रित जनसंख्या की अधिकता है। इसका भी कारण यही है कि जनपद में 14 वर्ष से नीचे व 60 वर्ष से ऊपर उम्र के व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है जिस कारण आश्रित लोगों की जनसंख्या अधिक है जहां तक अन्य कार्यशील जनसंख्या कम होने के कारण है इसमें प्रमुख रूप से रोजगार की स्थिति का अभाव होना व तकनीकी शिक्षा का अभाव होना रहा है। जिस कारण जनपद में कार्य करने वालों या आय अर्जित करने वालों की संख्या कम है जिस कारण जनपद का पूर्ण विकास सम्भव नहीं हो सका है अतः विकास की गति को बढ़ाने के लिए जनपद में आवासरत संख्या को अधिकाधिक मात्रा में रोजगार की ओर प्रेरित करना आवश्यक है जिससे कि आश्रितों की संख्या में कमी आये और प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि के साथ–साथ राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो सके तथा उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जा सके। जनपद में जनसंख्या का घनत्व 586 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनपद में इस जनसंख्या विशेषताओं को सारणी संख्या 29 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या 28 से यह स्पष्ट है कि औरैया जनपद में सबसे बड़े भू–भाग में गेहूं की खेती की जाती है। तत्पश्चात धान, बाजरा, दालें, मक्का व लाही/सरसों आदि फसलों का उत्पादन होता है। जनपद में कृषि की जाने वाली भूमि में से कुल सिंचित क्षेत्रफल 173101 हेक्टेयर है। जो कुल सिंचित क्षेत्रफल का सम्पूर्ण बोये गये क्षेत्र से 76.59 प्रतिशत या शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल 109303 हेक्टेयर का 78.5 प्रतिशत है।

जनसंख्या सम्बन्धी विशेषतायें : औरैया जनपद की जनसंख्या जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार 1179993 है, जिसमें 635762 पुरुष व 544231 स्त्रियां हैं। इस आधार पर जनपद में पुरुष स्त्री अनुपात 635762 : 544231 या 1 : 0.85 है। जनपद की जनसंख्या में 1011226 ग्रामीण व 168967 नगरीय जनसंख्या है। जिसमें ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का अनुपात 1011226 : 168967 या 1 : 0.16 का अनुपात है। जनपद के उपरोक्त जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 388260 व कार्य न करने वालों की संख्या 791733 है। आनुपातिक दृष्टि से 388260 : 791733 या 1 : 2.02 का अनुपात है। यदि प्रतिशत के रूप में कार्यशील व कार्य न करने वालों की जनसंख्या को देखा जाय तो कहा जा सकता है कि जनपद में 32.9 प्रतिशत व 67.1 प्रतिशत है। इस प्रकार औरैया जनपद में भी अन्य जनपदों की भांति आश्रित जनसंख्या की अधिकता है। इसका भी कारण यही है कि जनपद में 14 वर्ष से नीचे व 60 वर्ष से ऊपर उम्र के व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है जिस कारण आश्रित लोगों की जनसंख्या अधिक है जहां तक अन्य कार्यशील जनसंख्या कम होने के कारण है इसमें प्रमुख रूप से रोजगार की स्थिति का अभाव होना व तकनीकी शिक्षा का अभाव होना रहा है। जिस कारण जनपद में कार्य करने वालों या आय अर्जित करने वालों की संख्या कम है जिस कारण जनपद का पूर्ण विकास सम्भव नहीं हो सका है अतः विकास की गति को बढ़ाने के लिए जनपद में आवासरत संख्या को अधिकाधिक मात्रा में रोजगार की ओर प्रेरित करना आवश्यक है जिससे कि आश्रितों की संख्या में कमी आये और प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि के साथ–साथ राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो सके तथा उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जा सके। जनपद में जनसंख्या का घनत्व 586 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनपद में इस जनसंख्या विशेषताओं को सारणी संख्या 29 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–29

औरैया जनपद की जनसंख्या सम्बन्धी विशेषतायें (वर्ष 2001)

स्थिति	संख्या
1	2
1. जनपद की कुल जनसंख्या	1179993
2. (क) जनसंख्या में पुरुष स्त्री अनुपात	635762 : 544231
(ख) पुरुष स्त्री अनुपात	1 : 0.82
3. ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या	1011226 : 168997
(क) ग्रामीण जनसंख्या	1011226
(ख) नगरीय जनसंख्या	168997
4. ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का अनुपात	1 : 0.16
5. अर्जित एवं आश्रित जनसंख्या	388260 : 791733
(क) अर्जित	388260
(ख) आश्रित	791733
(ग) अर्जित व आश्रित का अनुपात	1 : 2.02
6. जनसंख्या का घनत्व (व्यक्तिप्रति वर्ग किमी.)	586

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश वर्ष 2003 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित

सारणी संख्या 29 से यह स्पष्ट है कि औरैया जनपद में 1179993 जनसंख्या हैं जिसमें से केवल 388260 व्यक्ति ही आय अर्जित करने वाले हैं शेष व्यक्तियों की संख्या आश्रितों के अन्तर्गत आती है। जो किसी भी प्रकार के रोजगार अवसरों में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत नहीं है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जनपद में व्यक्तियों का जीवन स्तर आज भी निम्न बना हुआ है।

कानपुर जनपद : कानपुर क्षेत्र का नाम कानपुर जनपद के आधार पर रखा गया है। वर्तमान में कानपुर जनपद 2 प्रशासनिक जनपदों में विभक्त है। कानपुर नगर व कानपुर देहात जनपद का प्रशासनिक विभाजन सर्वप्रथम वर्ष 1978 में हुआ था किन्तु प्रशासनिक अवरोधों के कारण जनपदों का पुनः एक जनपद के रूप में विलय हो गया था किन्तु 12 अप्रैल 1981 को कानपुर जनपद का पूर्णरूप से विभाजन कर दिया गया। जो वर्तमान में कानपुर नगर व कानपुर देहात जनपद में विभक्त हैं। सर्वप्रथम यह आवश्यक हो जाता है कि संयुक्त रूप से कानपुर जनपद की विभाजन से पहले जनसंख्या सम्बन्धी स्थिति को स्पष्ट किया जाय। इसी को ध्यान में रखते हुये कानपुर जनपद में जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताओं को सारणी संख्या 30 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–30

कानपुर जनपद की विभिन्न जनगणना वर्षों के अनुसार जनसंख्या

जनगणना वर्ष	जनसंख्या	दशक परिवर्तन (प्रतिशत में)
1	2	3
1901	1258917	—
1911	1142332	− 9.2
1921	1148705	+ 0.6
1931	1212296	+ 5.5
1941	1556296	+ 28.4
1951	1939921	+ 24.6
1961	2381497	+ 22.8
1971	2996232	+ 25.1
1981	3742223	+ 24.9

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका वर्ष 2006 कानपुर नगर में दिये गये आंकड़ों पर आधारित पृष्ठ 38 व 39 के मध्य

सारणी संख्या 30 से स्पष्ट है कि वर्ष 1901 से 1981 के बीच कानपुर जनपद की जनसंख्या में वर्ष 1901 और वर्ष 1911 के बीच कमी हुयी है। तत्पश्चात 11 से 81 तक जनपद की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। इसके पश्चात क्योंकि जनपद का विभाजन दो वर्गों में हो गया इसलिए कानपुर जनपद के इन दोनों रूपों की भौगोलिक तथा आर्थिक परिस्थितियों पर प्रथक रूप से विचार किया जाना आवश्यक है इसलिए अगले पैराग्राफों में कानपुर नगर व कानपुर देहात की सामाजिक और आर्थिक दशाओं पर विचार किया जायेगा। इसी को ध्यान में रखते हुये सर्वप्रथम जनपद कानपुर नगर के संदर्भ में अध्ययन किया जाना है।

जनपद कानपुर नगर : कानपुर नगर जनपद के अन्तर्गत 3 तहसीलें हैं। जो 10 विकास खण्डों में विभाजित हैं। कानपुर नगर की कानपुर , बिल्हौर व घाटमपुर तहसील हैं। इन तहसीलों में कानपुर तहसील के अन्तर्गत सरसौल, कल्यानपुर व विधनू विकास खण्ड आते हैं, बिल्हौर तहसील के अन्तर्गत ककवन, शिवराजपुर, बिल्हौर व चौबेपुर विकास खण्ड कार्यरत हैं। व घाटमपुर तहसील के अन्तर्गत घाटमपुर, भीतर गाँव व पतारा विकास खण्ड हैं।

भूमि का उपयोग : कानपुर नगर का भौगोलिक क्षेत्रफल 3155 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें 296919 हेक्टेयर प्रतिवेदित क्षेत्रफल है। जनपद में यह पाये जाने वाला प्रतिवेदित क्षेत्र विभिन्न उपयोगों में लगा हुआ है। जिनमें क्रमशः वनों के अन्तर्गत लगा क्षेत्र, स्थाई चरागाह एवं अन्य चराई का क्षेत्र, उद्यान बाग, वृक्ष आदि का क्षेत्र, ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि, अन्य परती, कृषि योग्य बंजर भूमि, वर्तमान परती व शुद्ध बोया गया क्षेत्र आदि क्षेत्रफलों में प्रतिवेदित भू–भाग लगा हुआ है। जिसमें सबसे ज्यादा क्षेत्र शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का 63.3 प्रतिशत है। इसके पश्चात अन्य उपयोग की भूमि है। इस भूमि के अन्तर्गत तमाम सारे कल कारखाने, फर्म व अन्य तमाम प्रकार के उत्पादक एवं विकास परख कार्य सम्पादित किये जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ा भाग वर्तमान परती के रूप में पड़ हुआ है जिसको कि कृषि से सम्बन्धित आवश्यक संसाधनों को जुटाकर उत्पादन क्षेत्र में लाया जा सकता है। भूमि के उपयोग सम्बन्धित विश्लेषण को सारणी संख्या 31 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–31

कानपुर नगर जनपद में प्रतिवेदित भूमि का विवरण (वर्ष 2001–02)

मद	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिवेदित क्षेत्र के सापेक्ष प्रतिशत
1	2	3
1. चरागाह	376	0.2
2. उद्यान, बाग–वृक्ष	3177	1.0
3. अन्य उपयोग की भूमि	34759	11.7
4. ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि	10165	3.5
5. अन्य परती	8147	2.7
6. वन	5627	1.9
7. कृषि योग्य बंजर	17890	6.0
8. वर्तमान परती	28732	9.7
9. शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	188046	63.3
योग –	**296919**	**100**

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका वर्ष 2006 कानपुर नगर में दिये गये आंकड़ों पर आधारित पृष्ठ 45–46

सारणी संख्या 31 से यह स्पष्ट है कि कानपुर नगर जनपद के प्रतिवेदित क्षेत्र का 63.3 प्रतिशत या 188046 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कृषि की जाती है शेष में से 0.2 प्रतिशत प्रतिवेदित क्षेत्रफल चरागाह, 1.0 प्रतिशत प्रतिवेदित क्षेत्रफल उद्यान, बाग वृक्ष, 11.7 प्रतिशत प्रतिवेदित क्षेत्र पर अन्य उपयोग की भूमि, 2.7 प्रतिशत अन्य परती, 1.9 प्रतिशत भाग प्रतिवेदित क्षेत्र का वनो से आच्छादित है व 6.0 प्रतिशत कृषि योग्य बंजर भूमि तथा 9.7 प्रतिशत प्रतिवेदित क्षेत्र का वर्तमान परती की भूमि पड़ी हुई है।

कृषि की दशायें : कानपुर नगर जनपद में कृषि उत्पादन के अन्तर्गत गेहूं, धान, दालें, मक्का,चना लाही/सरसों, ज्वार, आलू, गन्ना, तिलशुद्ध, बाजरा, अलसी व मूंगफली आदि की

फसलें उगाई जाती हैं। इन विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्र व उत्पादन स्तर तथा औसत उत्पादन आदि के विवरण को सारणी संख्या 32 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–32

कानपुर नगर जनपद मे विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लगा क्षेत्र हेक्टेयर में (वर्ष 2001)

फसल का नाम	फसलों में लगा क्षेत्र	उत्पादन (मीट्रिक टन में)	औसत उत्पादन (हेक्टेयर प्रति कुन्तल)
1	2	3	4
1. गेहूं	102437	328246	32.04
2. धान	43450	78802	18.14
3. दालें	39314	39557	10.06
4. मक्का	18953	31705	16.73
5. चना	18100	16753	9.26
6. लाही/सरसों	17058	18638	10.93
7. ज्वार	15253	14004	9.18
8. आलू	9865	236671	239.91
9. गन्ना	4352	195353	448.88
10. तिलशुद्ध	2209	362	1.64
11. बाजरा	826	875	10.59
12. अलसी	320	134	4.20
13. मूंगफली	208	175	8.39

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश वर्ष 2003 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित

सारणी संख्या 31 से स्पष्ट है कि कानपुर जनपद के अन्तर्गत उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों में लगा कुल क्षेत्रफल 272345 हेक्टेयर है। जिसमें से सबसे अधिक क्षेत्रफल में गेंहू का उत्पादन किया जाता है। इसके पश्चात धान, दालें, मक्का, चना, लाही/सरसों आदि का उत्पादन होता है। जनपद में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लगे क्षेत्र में से शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 68.8 प्रतिशत है।

जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताये : वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या 4165999 रही है। जो वर्ष 1991 में 3253572 थी। और वर्ष 1981 में 3742223 थी जनसंख्या के इन आंकड़ों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 1981 की तुलना में वर्ष 1991 में जनसंख्या में कमी महसूस की गयी, जबकि 1991 की तुलना में वर्ष 2001 में जनसंख्या में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जनपद में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार दी हुयी जनसंख्या में 2247216 पुरुष व 1920783 स्त्रियां हैं। इस आधार पर जनपद में पुरुष स्त्रियों का अनुपात 2247216 : 1920783 या 1 : 0.85 का अनुपात है। जनपद की जनसंख्या में 1370488 ग्रामीण व 2795511 नगरीय जनसंख्या है। कानपुर क्षेत्र के अन्य जनपदों की तुलना में कानपुर नगर जनपद में नगरीय जनसंख्या की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अधिकता है। इस आधार पर जनपद की जनसंख्या में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के अनुपात को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। 1370488 : 2795511 या 1 : 2.03 का अनुपात है। जनपद में उपरोक्त जनसंख्या में आय अर्जित करने वालों की व कार्य न करने वालों की संख्या 1245833 व 2920166 है। इस प्रकार कार्य न करने वाले और कार्य करने वाले व्यक्तियों का अनुपात 1245833 : 2920116 या 1 : 2.34 का अनुपात है। और प्रतिशत के रूप में कह सकते हैं कि जनपद में आय अर्जित करने वाले व आश्रित व्यक्तियों का प्रतिशत 29.9 व 70.1 प्रतिशत है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कानपुर नगर जनपद में भी कार्य करने वालों की संख्या की अपेक्षा आश्रितों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। जिससे उत्पादन क्षेत्र से सम्बन्धित व विकास से सम्बन्धित तमाम सारे अवरोध उत्पन्न होते हैं जिसके कारण आज भी कानपुर नगर जनपद का पूर्णरूप से विकास हो पाना सम्भव नहीं हो सका है। अतः विकास की गति को बढ़ाने के लिए कार्यशील जनसंख्या व आश्रित जनसंख्या की स्थिति में परिवर्तन करना होगा। जनपद में जनसंख्या का घनत्व 1331 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो कि सम्पूर्ण उत्त. प्रदेश के जनसंख्या घनत्व के सापेक्ष अधिक है इसका कारण कानपुर नगर का एक विस्तृत क्षेत्र कानपुर महानगर का होना रहा है। जनपद में नगरीय क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन रहा है। जनपद का नगरीय जनसंख्या घनत्व 820 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जबकि ग्रामीण क्षेत्र 510 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या सम्बन्धी इन आंकड़ों को सारणी संख्या–32 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–32

कानपुर नगर जनपद की जनसंख्या सम्बन्धी विशेषतायें (वर्ष 2001)

स्थिति	संख्या
1	2
1. जनपद की कुल जनसंख्या	4165999
2. (क) जनसंख्या में पुरुष स्त्री अनुपात	2247216 : 1920783
(ख) पुरुष स्त्री अनुपात	1 : 0.85
3. ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या	1370488 : 2795511
(क) ग्रामीण जनसंख्या	1370488
(ख) नगरीय जनसंख्या	2795511
4. ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का अनुपात	1 : 2.03
5. अर्जित एवं आश्रित जनसंख्या	124588 : 2920166
(क) अर्जित	124588
(ख) आश्रित	2920166
(ग) अर्जित व आश्रित का अनुपात	1 : 2.34
6. जनसंख्या का घनत्व (व्यक्तिप्रति वर्ग किमी.)	1331
(क) ग्रामीण	510
(ख) नगरीय	820
7. जनसंख्या के घनत्व का अनुपात	510: 820 या 1 : 1.60

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश वर्ष 2003 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित

कानपुर देहात जनपद : कानपुर देहात जनपद का सृजन 25 अप्रैल 1981 को हुआ है। जनपद के अन्तर्गत 5 तहसीलें जो 10 विकास खण्डों में विभाजित हैं। जो निम्न हैं– अकबरपुर तहसील के अन्तर्गत अकबरपुर व मैथा विकास खण्ड हैं, डेरापुर तहसील में डेरापुर, सन्दलपुर व झींझक विकास खण्ड आते हैं, भोगनीपुर तहसील में अमरौधा व मलासा विकास खण्ड आते हैं, रसूलाबाद तहसील में रसूलाबाद विकास खण्ड व सिकन्दरा तहसील में सिकन्दरा व राजपुर विकास खण्ड आते हैं।

भूमि का उपयोग : कानपुर देहात जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 3021 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 314984 हेक्टेयर प्रतिवेदित क्षेत्रफल है। जनपद का प्रतिवेदित क्षेत्रफल विभिन्न उपयोगों में लगा हुआ है। जिसे सारणी संख्या 33 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–33

कानपुर देहात जनपद में प्रतिवेदित भूमि का विवरण (वर्ष 2001–02)

मद	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिवेदित क्षेत्र के सापेक्ष प्रतिशत
1	2	3
1. वन	9980	3.2
2. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लगी भूमि	22510	7.2
3. ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि	17479	5.5
4. स्थाई चरागाह एवं अन्य वृक्ष झाड़ियों का क्षेत्रफल	4090	1.3
5. वर्तमान परती एवं अन्य परती	34675	11.0
6. कृष्य बेकार भूमि	5087	1.6
7. शुद्ध बोया गया क्षेत्र	221163	70.2
योग –	**314984**	**100**

स्रोत – जनपद कानपुर देहात की सांख्यिकीय पत्रिका वर्ष 2005 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित

सारणी संख्या 33 से यह स्पष्ट है कि जनपद में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में से 70.2 प्रतिशत या 221163 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है। तथा 3.2 प्रतिशत या 9980 हेक्टेयर क्षेत्र वनों से आच्छादित है, 5.5 प्रतिशत प्रतिवेदित क्षेत्र या 17479 हेक्टेयर ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि है, 7.2 प्रतिशत या 22270 हेक्टेयर प्रतिवेदित क्षेत्र खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लगी है, 1.6 प्रतिशत कृष्य बेकार भूमि है, 1.3 प्रतिशत स्थाई चरागाह एवं अन्य चराई तथा अन्य वृक्ष झाड़ियों का क्षेत्र है व 11.0 प्रतिशत प्रतिवेदित क्षेत्र या 34675 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र वर्तमान परती एवं अन्य परती में लगा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध बोये गये क्षेत्र के बाद प्रतिवेदित क्षेत्र का बड़ा भाग परती भूमि के अन्तर्गत है जिसको कृषि संसाधनों को जुटाकर उपजाऊ भमि बनाया जा सकता है।

कृषि की दशायें : कानपुर देहात जनपद में कृषि उत्पादन के अन्तर्गत गेहूं, धान, दालें चना, लाही/सरसों, ज्वार, मक्का, बाजरा, गन्ना, आलू, तिलशुद्ध, अलसी व मूंगफली आदि की फसलें उगाई जाती हैं। जिसके विवरण को सारणी संख्या 34 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–34

कानपुर देहात जनपद में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लगा क्षेत्र हेक्टेयर में (वर्ष 2001)

फसल का नाम	फसलों में लगा क्षेत्र	उत्पादन (मीट्रिक टन में)	औसत उत्पादन (हेक्टेयर प्रति कुन्तल)
1	2	3	4
1. गेहूं	117350	394871	33.65
2. धान	52501	120615	20.37
3. दालें	50129	73317	14.43
4. चना	26412	37392	1416
5. लाही/सरसों	23713	58560	12.04
6. ज्वार	16723	17689	10.57
7. मक्का	16137	3100	19.27
8. बाजरा	11479	15020	13.08
9. गन्ना	2733	144507	528.75
10. आलू	1828	48711	265.02
11. तिलशुद्ध	1070	177	1.64
12. अलसी	73	31	4.20
13. मूंगफली	23	19	8.39

स्रोत – जनपद कानपुर देहात की सांख्यिकीय पत्रिका वर्ष 2005 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित

सारणी संख्या 34 से यह स्पष्ट है कि कुल 320178 हेक्टेयर प्रतिवेदित क्षेत्र में फसलें उगाई जाती हैं। इसमें सबसे बड़े भाग पर गेहूं की खेती की जाती है तत्पश्चात क्रमशः धान, दालें, चना, लाही/सरसों आदि फसलों का क्रम आता है। जनपद में कृषि की जाने वाली भूमि में शुद्ध बोये गये क्षेत्र में से शुद्ध सिंचित क्षेत्र 166685 हेक्टेयर या शुद्ध बोये गये क्षे का 52.2 प्रतिशत है। और सम्पूर्ण बोये गये क्षेत्र 215591 हेक्टेयर में से सम्पूर्ण सिंचित क्षेत्र 67.53 प्रतिशत है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जनपद में आज भी असिंचित फसल बड़े भू–भाग पर उगाई जाती है।

जनसंख्या सम्बन्धी विशेषतायें : कानपुर देहात जनपद में वर्ष 2001 की जनगणना आंकड़ों के आधार पर 1563336 जनसंख्या है जो वर्ष 1991 में केवल 1303232 थी। जो वर्ष 2001 की तुलना में कम थी जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनपद की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2001 में जनपद में 844139 पुरुष व 718997 स्त्रियां हैं। जनपद में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात 844139 अनुपात 718997 या 1 : 0.85 है। जनपद की जनसंख्या में 1455569 ग्रामीण व 107667 नगरीय जनसंख्या है। जनपद की जनसंख्या में ग्रामीण नगरीय अनुपात 1455569 : 107667 या 1 : 0.07 का अनुपात है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कानपुर देहात जनपद में नगरीय जनसंख्या का स्तर नगण्य है। अर्थात जनपद में निवास करने वाली अधिकतर जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करती है। जनपद की इस जनसंख्या में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 93.1 व 6.9 प्रतिशत है। उपरोक्त जनसंख्या में अर्जित जनसंख्या 513211 या 32.8 प्रतिशत तथा काम न करने वालों की जनसंख्या 1050125 या कुल जनसंख्या का 67.2 प्रतिशत है। यदि अर्जित व आश्रित जनसंख्या को अनुपात के रूप में देखा जाय तो कहा जा सकता है कि 513211 : 1050125 या 1 : 2.04 का अनुपात है। जनपद की आश्रित व अर्जित जनसंख्या को देखने से स्पष्ट होता है कि जनपद में आश्रित जनसंख्या की बहुलता है। जिसके कारण विकास के समस्त सोपानों को गति प्रदान नहीं की जा सकी है। जनपद में जनसंख्या का घनत्व 517 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उपरोक्त जनसंख्या सम्बन्धी समस्त आंकड़ों को सार गर्भित बनाने के लिए सारणी संख्या 35 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–35

कानपुर देहात जनपद की जनसंख्या सम्बन्धी विशेषतायें (वर्ष 2001)

स्थिति	संख्या
1	2
1. जनपद की कुल जनसंख्या	1563336
2. (क) जनसंख्या में पुरुष स्त्री अनुपात	844139 : 718997
(ख) पुरुष स्त्री अनुपात	1 : 0.85
3. ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या	1455569 : 107667
(क) ग्रामीण जनसंख्या	1455569
(ख) नगरीय जनसंख्या	107667
4. ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का अनुपात	1 : 0.07
5. अर्जित एवं आश्रित जनसंख्या	754560 : 808876
(क) अर्जित	754560
(ख) आश्रित	808876
(ग) अर्जित व आश्रित का अनुपात	1 : 1.07
6. अर्जित व आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत	48.3, 51.7
7. जनसंख्या का घनत्व (व्यक्तिप्रति वर्ग किमी.)	517

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश वर्ष 2003 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित

सारणी संख्या 36 से यह स्पष्ट होता है कि कानपुर देहात जनपद में आज भी ग्रामीण क्षेत्र में आवास करने वालों की संख्या बहुतायत मात्रा में है, जहां तक स्त्री पुरुष का सवाल है स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की प्रधानता है वहीं जनपद में आज भी अर्जित जनसंख्या की अपेक्षा आश्रित संख्या अधिकाधिक मात्रा में है जो विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं।

कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी जनपदों की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों को प्रथक–प्रथक विवेचना करने के पश्चात कानपुर क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक विशेषताओं को समस्त विशेषताओं के समस्त रूप को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों के क्रियाकलापों का विश्लेषण अगले अध्याय का विषय होगा जिसके अन्तर्गत अध्ययन के प्रारम्भ में स्पष्ट की गयी परिकल्पनाओं का परीक्षण व्यावसायिक बैंकों की कार्य प्रणाली क्रियाकलापों के आधार पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना असंगत नहीं होगा कि बैंकिंग व्यवस्था किसी अर्थव्यवस्था विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में एक अधो संरचना के रूप में सहायक होता है। जैसा कि श्री पी.जे. मेशराम ने अपने अध्ययन में इस बात को सिद्ध किया है। श्री मेशराम का अध्ययन महाराष्ट्र राज्य के भण्डारा जिले पर आधारित है।[13] इसी प्रकार वर्तमान अध्ययन के प्रारम्भ में स्पष्ट की गयी परिकल्पनाओं के परीक्षण के पश्चात इस बात को स्पष्ट किया जायेगा कि बैंकिंग व्यवस्था किस सीमा तक कृषि क्षेत्र को प्रभावित कर सकी है। और किन रूपों में किया है क्योंकि वर्तमान अध्ययन की पहली परिकल्पना यह है–

1. वाणिज्यिक बैंकों के वित्त प्रदान करने के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत वित्त का ढाँचा विस्तृत और मजबूत हो सका है।
2. वाणिज्यिक बैंको के माध्यम से किसानों को पर्याप्त मात्रा में वित्त प्राप्त होने के कारण कृषि के विकास में सहायता प्राप्त हुयी है।
3. कृषि के लिए आवश्यक वित्त प्रदान करने के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए उत्पादन के कार्य में आवश्यक संगठनात्मक ढाँचे का विकास एवं विस्तार हुआ है।
4. किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
5. किसानों को महाजनों के आर्थिक शोषण से बचाया जा सका है।

उपरोक्त परिकल्पनाओं के परीक्षण के सम्बन्ध में इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया जायेगा कि व्यवसायिक बेंकों के वित्त का कृषि अर्थव्यवस्था पर बर्हुमुखी प्रभाव हुआ है। इसके लिए कानपुर क्षेत्र को आधार बनाया गया है।

---

13. P.J. Meshram Institutional Credit in Rural India (Akash Study of Maharastra District)

निष्कर्ष : उपरोक्त अध्याय के निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कृषि साख के संगठित स्रोतों के अन्तर्गत उन संगठनों या स्रोतों को रखा गया है। जिन संगठनों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र के लिए वित्त या ऋण निम्न संस्थागत या संगठनों के माध्यम से प्राप्त होता है।

1. व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. सहकारी बैंकिंग व्यवस्था या बैंक
4. सरकार द्वारा

इन संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 में कृषि क्षेत्र में संस्थागत वित्त का लगभग 24.5 प्रतिशत सहकारी बैंकों द्वारा, 9.4 प्रतिशत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा व 66.3 प्रतिशत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किया गया था। कृषि क्षेत्र में कृषि आवश्यकता का इन संस्थागत स्रोतों से कृषि क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करने के कार्य में निरन्तर वृद्धि हुयी है इनके क्रियाकलापों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण केन्द्र एवं राज्य सरकार की कृषि नीति के अन्तर्गत कृषि विकास को प्राथमिकता प्रदान करना रहा है। कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक से अधिक वित्त प्रदान करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र का निर्धारण किया जाता रहा है। प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि, लघु उद्योग एवं समाज के कमजोर वर्ग को रखा गया है।

वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात इन बैंकों द्वारा अधिक से अधिक ऋण कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 1969 में इन बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋण का मात्र 3.6 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र को दिया गया था। राष्ट्रीयकरण के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का 15 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष वित्त या ऋण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसे वर्ष 1985 तक प्राप्त किया जाना था। इस लक्ष्य को बाद में बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया जिसे वर्ष 1987 तक प्राप्त करने का लक्ष्य था। वर्ष 1990 तक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अधिक से अधिक ऋण कृषि क्षेत्र को प्रदान किये गये थे। जो इन बैंकों में कृषकों के ऋण खातों की संख्या से स्पष्ट हैं। वर्ष 1969

में कृषि क्षेत्र के ऋण प्राप्तकर्ताओं के खातों की संख्या बैंकों के कुल खातों की संख्या में 8.1 प्रतिशत थी। जो वर्ष 1988 में बढ़कर 60.1 प्रतिशत हो गयी।

यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रदान किये गये वित्त/ऋणों की मात्रा में विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि वाणिज्यिक बैंकों के विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिये गये ऋणों में वृद्धि के साथ–साथ कृषि क्षेत्र के लिए दिये जाने वाले ऋणों में भी वृद्धि हुयी है।

इस बात का अनुमान बैंकों के कृषि क्षेत्र में लगे हुये ऋणों की रकम द्वारा लगाया जा सकता है। वर्ष 1969 में इन बैंकों का कुल 483.30 करोड़ रुपये का ऋण विभिन्न क्षेत्रों में लगा हुआ था। जो वर्ष 1988 में बढ़कर 28467.8 करोड़ रुपये हो गया। इस लगे हुये ऋण का लगभग 30 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र में लगा हुआ था।

राष्ट्रीकरण से पहले इन बैंकों द्वारा बड़े व मध्यम आकार के उद्योगों एवं थोक व्यापार के लिए 78 प्रतिशत ऋण दिया गया पर राष्ट्रीयकरण के पश्चात वर्ष 1988 में इन क्षेत्रों को प्राप्त ऋण कम होकर 41 प्रतिशत हो गया इसके विपरीत प्राथमिकता क्षेत्र को प्राप्त होने वाले ऋण में निरन्तर वृद्धि हुयी है।

वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीकरण के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में वित्त प्रदान करने को प्राथमिकता प्रदान की गयी जिन्हें राष्ट्रीयकरण के पहले वित्त नहीं प्र .ान किया जाता। इसके अन्तर्गत लघु ऋण प्राप्तकर्ताओं को वित्त प्रदान करने को प्राथमिकता प्रदान की गयी। इसके अन्तर्गत कृषि, लघु पैमाने के उद्योग, सड़क एवं जल परिवहन, फुटकर व्यापार और छोटे मोटे व्यवसायी वर्गों को ऋण प्रदान करने का कार्य किया गया। इन वर्गों को राष्ट्रीयकरण के पहले कोई महत्व नहीं प्रदान किया जाता था। वाणिज्यिक बैंकों के वित्त का बहुत छोटा भाग ही इन्हें प्राप्त हो पाता था।

परिणामस्वरूप वर्ष 1969 से 1988 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के लघु ऋण प्राप्तकर्ताओं के खातों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुयी है। इन ऋण प्राप्तकर्ताओं पर लगे हुये ऋण की मात्रा वर्ष 1969 में 441 करोड़ रुपये थी। जो वर्ष 1988 में बढ़कर 28468 करोड़ रुपये हो गयी थी।

वर्ष 1988 में कुल वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का 45.8 प्रतिशत ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया। राष्ट्रीयकरण के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समक्ष यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि इनके द्वारा दिये जाने वाले वित्त का 15 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को प्रदान किया जाये। इस लक्ष्य को वर्ष 1985 तक प्राप्त किया जाना था। बाद में इसको बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया। जिसे वर्ष 1989 तक प्राप्त किया जाना था। इस लक्ष्य के सन्दर्भ मे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपने कुल ऋण का 16.8 प्रतिशत ऋण वर्ष 1988 में दिया गया था।

नौंवी पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के समयावधि में कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्रों में 229000 करोड़ रुपये के ऋण दिये जाने के लक्ष्य का निर्धारण किया गया। जबकि वास्तविक रूप में 233700 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये गये। इसी प्रकार दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) में कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्रों में सभी बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से 736570 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये गये। जो नौवीं पंचवर्षीय योजना काल की तुलना में तीन गुना अधिक रहा है। वर्ष 2004–05) कृषि क्षेत्र को 115.2 हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया जो लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक था। जबकि लक्ष्य 105 हजार करोड़ रुपये का निर्धारित किया गया था। वर्ष 2005–06 में पिछले वर्षों की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक ऋण कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्रों में वितरित किया गया।

व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक : व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक से अभिप्राय उन सभी बैंकिंग संस्थाओं से लगाया जाता है जो किसी अर्थव्यवस्था में रुपये के लेन देन या व्यवसाय का कार्य करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर वाणिज्यिक बैंकों का कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ने

वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए उन सभी बैंकिंग संस्थाओं पर विचार किया गया है। जो कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए ऋण प्रदान करने का कार्य करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर सभी बैंकिंग संगठनों को व्यवसायिक बैंकों के अन्तर्गत रखा जाता है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत कुल 218 अनुसूचित (विदेशी बैंकों सहित) वाणिज्यिक बैंक हैं इनमें से 161 सार्वजनिक क्षेत्र के हैं जिनमें से 133 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर. आर. बी.) हैं, और ये सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि का 75.2 प्रतिशत एकत्र करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे ऋण प्राप्तकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए विशेष रूप से की गयी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा बाकी 28 बैंकों में 19 राष्ट्रीयकृत, एस.बी.आई. समूह के 8 व आई.बी.बी.आई. लिमिटेड हैं और ये सभी तरह का बैंकिंग व्यवसाय करते हैं।

कानपुर क्षेत्र : वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य 17 मण्डलों में विभक्त हैं। वर्तमान अध्ययन कानपुर क्षेत्र के सन्दर्भ में किया गया है। कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत 6 जनपद आते हैं। जो क्रमशः फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर व कानपुर देहात हैं। इन जनपदों में अलग–अलग मात्रा में प्रतिवेदित भूमि का वितरण रहा है। जिसका विस्तृत विवरण अध्याय में दिया गया है। भूमि के विभिन्न उपयोगों में सबसे अधिक भूमि कृषि कार्य में लगी हुयी है अतः व्यावसायिक बैंकों का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव को इसके सन्दर्भ में व्यक्त किया जायेगा।



अध्याय - तीन

अध्ययन क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक दशायें

अध्याय – तीन : अध्ययन क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक दशायें

अध्ययन क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक दशाओं को निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा सकता है।

1. **अर्थव्यवस्था का प्रारूप :** कानपुर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्यता कृषि प्रधान है। अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता को भूमि के उपयोग तथा क्षेत्र की लगी हुयी अधिकांश जनसंख्या के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। जहां तक भूमि के उपयोग का प्रश्न है क्षेत्र के प्रतिवेदित क्षेत्रफल 1489694 हेक्टेयर में से 1006208 हेक्टेयर क्षेत्र पर कृषि की जाती है जो प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 67.5 प्रतिशत है। इसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टिकोण से वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार क्षेत्र की जनसंख्या 11209520 रही है। इन पर विस्तृत रूप से अलग से विश्लेषण इसी अध्याय में किया गया है।

(क) भूमि का उपयोग : जैसा कि कहा जा चुका है कि कानपुर क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल 14776 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें से प्रतिवेदित क्षेत्रफल 1489694 हेक्टेयर है। यह प्रतिवेदित क्षेत्रफल विभिन्न मदों में विभाजित किया गया है। जो क्रमशः वन, ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि, खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लगी भूमि, कृष्य बेकार भूमि, चरागाह तथा अन्य वृक्ष झाड़ियों की भूमि, वर्तमान परती एवं अन्य परती व शुद्ध बोया गया क्षेत्र आदि क्षेत्रों में कानपुर क्षेत्र की प्रतिवेदित भूमि लगी हुयी है। जिसमें सबसे अधिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न फसलें उत्पादित की जाती हैं। जिसमें प्रमुख रूप से गेहूं, धान, चना, लाही/सरसों मक्का आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है वहीं कृषि के अतिरिक्त एक बड़ा भाग वर्तमान परती एवं अन्य परती के रूप में पड़ा हुआ है। जो कि कृषि के दृष्टिकोण से उपयुक्त होते हुये भी उपयोग में नहीं लगाया जा सका है जबकि विभिन्न कृषि संसाधनों को जुटाकर इस परती भूमि को कृषि के उपयोग में लाया जा सकता है जिससे कृषि क्षेत्र के उत्पादन आधार में वृद्धि हो सकती है। प्रतिवेदित भूमि के उपयोग सम्बन्धी इस समस्त विवरण को सारणी संख्या 36 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–36

कानपुर क्षेत्र में प्रतिवेदित भूमि का विवरण (वर्ष 2001–02)

मद	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिवेदित क्षेत्र के सापेक्ष प्रतिशत
1	2	3
1. वन	65810	4.4
2. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लगी भूमि	133610	9.5
3. ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि	81865	4.8
4. स्थाई चरागाह एवं अन्य वृक्ष झाड़ियों का क्षेत्रफल	27438	1.8
5. वर्तमान परती एवं अन्य परती	152658	10.2
6. कृष्य बेकार भूमि	38302	2.6
7. शुद्ध बोया गया क्षेत्र	994009	66.7
योग –	**1489694**	**100**

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश वर्ष 2003 एवं सांख्यिकीय डायरी 2006 तथा विभिन्न जनपदों की सांख्यिकीय पत्रिकाओं में दिये गये आंकड़ों पर आधारित

सारणी संख्या 36 से यह स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र के प्रतिवेदित क्षेत्रफल में सबसे अधिक भूमि कृषि क्षेत्र में लगी हुयी है। जो प्रतिवेदित क्षेत्र का 66.7 प्रतिशत है। इसके पश्चात 4.4 प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित है, 4.8 प्रतिशत भूमि ऊसर एवं खेती के अयोग्य भूमि है, 9.5 प्रतिशत कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगों में लगी हुयी है जो अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार को मजबूत बनाती है, 2.6 प्रतिशत कृष्य बेकार भूमि है, 1.8 प्रतिशत भूमि स्थाई चरागाह एवं अन्य वृक्ष झाड़ियों आदि क्षेत्रों के अन्तर्गत लगी हुयी है। तथा शेष 10.2 प्रतिशत प्रतिवेदित क्षेत्र का वर्तमान परती एवं अन्य परती क्षेत्र के रूप में पड़ी हुयी है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भूमि के उपयोग की दृष्टिकोण से कानपुर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है।

(ख) जनसंख्या : जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कानपुर क्षेत्र की जनसंख्या 11209520 थी। जिसमें से 1470990 जनसंख्या कृषि कार्यों में किसी न किसी रूप में लगी हुयी है जो कुल जनसंख्या का 13.1 प्रतिशत है। जनसंख्या के विभिन्न अंगों पर इसी अध्याय में अलग से विचार किया गया है।

2. **जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण :** जनसंख्या के आर्थिक वगीकरण का अर्थ जनसंख्या के उस वर्गीकरण से है जिसके अन्तर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगी हुयी जनसंख्या को वर्गीकृत किया जाता है। कानपुर क्षेत्र की जनसंख्या के विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगी हुयी कार्यशील जनसंख्या को या जनसंख्या के आर्थिक वर्गीकरण के स्वरूप को स्पष्ट करने से पहले क्षेत्र की जनसंख्या के विभिन्न अंगों को स्पष्ट किया जा सकता है।

कानपुर क्षेत्र की जनसंख्या जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार 11209520 रही है। जिसमें 60938446 पुरुष तथा 5167494 स्त्रियां हैं। इस आधार पर जनसंख्या में पुरुष स्त्री अनुपात 60938446 : 5167494 या 1 : 0.81 है। क्षेत्र की जनसंख्या में 7254 हजार ग्रामीण व 3955 हजार नगरीय जनसंख्या रही है। इस आधार पर ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का अनुपात 7254 : 3955 या 1 : 0.54 रहा है। तथा ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 64.7 एवं 35.3 प्रतिशत रहा है। उपरोक्त जनसंख्या में आय अर्जित करने वालों की जनसंख्या 3438357 या 30.7 प्रतिशत रही है और आश्रितों की संख्या 7771173 या 69.3 प्रतिशत रही है। आय अर्जित करने वाले व आश्रितों के बीच 3438557 : 7771173 या 1 : 2.26 का अनुपात रहा है। क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व 758.6 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर रहा है। क्षेत्र में साक्षर व्यक्तियों की संख्या जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार 6438211 रही है। जो कुल जनसंख्या का 57.4 प्रतिशत रही है।

कानपुर क्षेत्र की जनसंख्या के विभिन्न अंगों में आय अर्जित करने वाली जनसंख्या 3438357 रही है। इसी जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहा गया है। इसी कार्यशील

जनसंख्या का विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे होना जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण कहलाता है। कानपुर क्षेत्र की जनसंख्या के आर्थिक वर्गीकरण को सारणी संख्या 37 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–37

कानपुर क्षेत्र की कार्यशील जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण (वर्ष 2001)

आर्थिक क्रियायें	आर्थिक क्रियाओं में लगी जनसंख्या	कार्यशील जनसंख्या के सापेक्ष प्रतिशत
1	2	3
1. कृषक	1155511	33.6
2. कृषि श्रमिक	315479	9.2
3. पारिवारिक उद्योग में लगी जनसंख्या	116588	3.4
4. अन्य कर्मकर	1141664	33.2
5. कुल अन्य मुख्य कर्मकर	709105	20.6
योग –	**3438347**	**100**

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश वर्ष 2003 पर दिये गये आंकड़ों पर आधारित पृष्ठ 61, 62 व 63

सारणी संख्या 37 से स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र की कार्यशील जनसंख्या का 42.8 प्रतिशत कृषि कार्यों में किसी न किसी रूप में लगा हुआ है इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में कृषि कार्यों की प्रधानता है जो देश की अर्थव्यवस्था की विशेषता 'भारत एक कृषि प्रधान देश है ' की सार्थकता को सिद्ध कर देती है।

3. कृषि अर्थव्यवस्था : जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि कानपुर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है इसलिए क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था के स्वरूप को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। कानपुर क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत खाद्यांश, दलहन व तिलहन आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। जिसके अन्तर्गत धान, बाजरा, मक्का, गेहूं, चना, दालें,

मूंगफली, तिलशुद्ध, लाही/सरसों, अलसी, गन्ना व आलू आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। इन विभिन्न फसलों का उत्पादन भूमि के विभिन्न मात्रा में किया जाता है। इन फसलों के अन्तर्गत लगी हुयी भूमि, उत्पादन स्तर व औसत उत्पादन आदि को सारणी संख्या 38 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–38

कानपुर क्षेत्र की विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लगा क्षेत्र हेक्टेयर में (वर्ष 2001–02)

फसल का नाम	फसलों में लगा क्षेत्र	उत्पादन (मीट्रिक टन में)	औसत उत्पादन (हेक्टेयर प्रति कुन्तल)
1	2	3	4
1. धान	239658	506605	21.14
2. ज्वार	38753	37489	9.67
3. मक्का	154077	297609	19.32
4. गेहूं	549427	1769900	32.14
5. चना	63667	76580	12.03
6. दालें	146169	176949	13.11
7. मूंगफली	1443	1211	8.39
8. तिलशुद्ध	6163	1011	1.64
9. लाही/सरसों	90209	105650	11.71
10. अलसी	397	167	4.20
11. गन्ना	17386	928342	535.96
12. आलू	388552	9584545	246.62
13. बाजरा	76917	99774	12.97

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश वर्ष 2003 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित

सारणी संख्या 38 से यह स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र के विभिन्न कृषि उत्पादनों पर क्षेत्रफल की दृष्टि से विचार किया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके पश्चात आलू के अन्तर्गत लगा क्षेत्र है। उत्पादन की दृष्टिकोण से गेहूं का सबसे ऊपर स्थान है। इसी प्रकार प्रति हेक्टेयर विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है।

कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों की कृषि व्यवस्था में कुछ समानतायें हैं। जैसे उत्पादन की संरचना और कुल उत्पादन स्तर इत्यादि पर इन विभिन्न जनपदों के विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन मे भिन्नता रही है। इस भिन्नता का मुख्य कारण विभिन्न जनपदों में कृषि विकास की आवश्यक अधोसंरचना के विकास में विसमता का होना है। इसे सारणी संख्या 39 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–39

कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में फसलों का औसत उत्पादन स्तर (वर्ष 2001–02)

फसल का नाम	जनपदों के नाम एवं उत्पादन स्तर (उत्पादन कुन्तल प्रति हेक्टेयर में)						
	फर्रूखाबाद	कन्नौज	इटावा	औरैया	कानपुर नगर	कानपुर देहात	कानपुर क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1. चावल (धान)	21.03	19.65	22.11	24.34	18.14	20.37	21.14
2. ज्वार	9.34	9.34	9.34	7.45	9.18	10.57	9.67
3. मक्का	19.49	19.52	20.02	21.17	16.73	19.27	13.32
4. गेहूं	33.49	32.14	29.83	32.67	32.04	33.65	32.14
5. चना	21.19	12.19	13.09	10.47	9.26	14.16	12.03
6. दालें	10.34	1.03	12.33	11.47	10.06	14.43	12.11
7. मूंगफली	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39
8. तिलशुद्ध	–	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64
9. लाही/सरसों	13.23	11.63	11.02	12.00	10.93	12.04	11.71
10. अलसी	–	–	–	4.20	4.20	4.20	4.20
11. गन्ना	574.32	553.95	533.96	597.13	448.88	528.75	533.96
12. आलू	278.64	268.01	247.99	217.22	239.91	265.02	246.62
13. बाजरा	10.59	10.59	13.19	13.51	10.59	13.08	12.97

स्रोत: सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश वर्ष 2003 में दिये आंकड़ों पर आधारित पृष्ठ संख्या 236 से 255 तक

सारणी संख्या 39 से यह स्पष्ट है कि यदि कानपुर क्षेत्र में विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन की तुलना फर्रूखाबाद जनपद के विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन से की जाती है तो जनपद के कुछ फसलों का औसत उत्पादन कानपुर क्षेत्र की फसलों के औसत उत्पादन के लगभग समान रहा है। ऐसा मूंगफली के उत्पादन के सम्बन्ध में है। जबकि जनपद में धान, ज्वार, दालें, व गन्ना के सम्बन्ध में औसत उत्पादन कम रहा है। इसी प्रकार मक्का, गेहूं, चना, लाही/सरसों व आलू, आदि फसलों का औसत उत्पादन कानपुर क्षेत्र के औसत उत्पादन से ज्यादा रहा है।

इसी प्रकार यदि कन्नौज जनपद के विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन की तुलना कानपुर क्षेत्र के औसत उत्पादन से की जाय तो यह कहा जा सकता है कि तिलशुद्ध, गेहूं व मूंगफली का औसत उत्पादन कानपुर क्षेत्र में उत्पादित होने वाली इन फसलों के औसत उत्पादन के बराबर रहा है। इसी प्रकार धान, ज्वार, दालें, लाही/सरसों, बाजरा आदि फसलों का औसत उत्पादन कानपुर क्षेत्र में उत्पादित होने वाली इन फसलों के औसत उत्पादन से कम रहा है। जबकि मक्का, चना, गन्ना व आलू आदि फसलों का औसत उत्पादन कानपुर क्षेत्र में उत्पादित होने वाली इन फसलों के औसत उत्पादन से अधिक रहा है।

जहां तक इटावा जनपद के सम्बन्ध में विचार किया जाय तो कहा जा सकता है कि तिलशुद्ध, मूंगफली व गन्ने का औसत उत्पादन कानपुर क्षेत्र में उत्पादित होने वाली इन्हीं फसलों के औसत उत्पादन के बराबर रहा है। वहीं ज्वार, गेहूं व लाही/सरसों आदि फसलों का औसत उत्पादन कानपुर क्षेत्र में उत्पादित होने वाली इन्हीं फसलों के औसत उत्पादन से कम रहा है। जबकि धान, मक्का, दालें, चना, आलू, व बाजरा आदि फसलों का औसत उत्पादन कानपुर क्षेत्र में उत्पादित होने वाली इन्हीं फसलों के औसत उत्पादन से अधिक रहा है।

औरैया जनपद के अन्तर्गत तिलशुद्ध, अलसी, व मूंगफली आदि फसलों का औसत उत्पादन कानपुर क्षेत्र में उत्पादित होने वाली इन फसलों के औसत उत्पादन के बराबर रहा है। और ज्वार, चना, दालें व आलू आदि फसलों का औसत उत्पादन कानपुर क्षेत्र में उत्पादित होने वाली इन फसलों के औसत उत्पादन से कम रहा है, जबकि चावल, गन्ना, मक्का, गेहूं, लाही/

सरसों व बाजरा आदि फसलों का उत्पादन क्षेत्र में उत्पादित होने वाली इन फसलों के औसत उत्पादन से अधिक रहा है।

अन्य जनपदों की भांति कानपुर नगर जनपद की विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन में कानपुर क्षेत्र में उत्पादित फसलों के औसत उत्पादन की तुलना में असमानता रही है। क्योंकि जनपद में तिलशुद्ध, मूंगफली व अलसी का औसत उत्पादन क्षेत्र में उत्पादित फसलों के औसत उत्पादन के बराबर रहा है। वहीं धान, मक्का व गन्ना आदि फसलों का औसत उत्पादन क्षेत्र में उत्पादित होने वाली इन फसलों के औसत उत्पादन से कम रहा है जबकि ज्वार, गेहूं, चना, दालें, लाही/सरसों आलू व बाजरा आदि फसलों का औसत उत्पादन कानपुर क्षेत्र में उत्पादित होने वाली इन फसलों के औसत उत्पादन से अधिक रहा है।

कानपुर देहात जनपद के विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन की तुलना यदि हम कानपुर क्षेत्र के उत्पादित होने वाली विभिन्न फसलों से करे तो यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र और जनपद में उत्पादित होने वाली फसलों में असमानता व्याप्त है जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि तिलशुद्ध, मूंगफली व अलसी आदि फसलों का उत्पादन स्तर कानपुर क्षेत्र में उत्पादित होने वाले फसलों के औसत उत्पादन के बराबर रहा है जबकि धान, मक्का व गन्ना का औसत उत्पादन कानपुर क्षेत्र में होने वाली इन फसलों के औसत उत्पादन से कम रहा है लेकिन ज्वार गेहूं चना, दालें लाही/सरसों, आलू व बाजरा आदि फसलों का औसत उत्पादन कानपुर क्षेत्र में उत्पादित होने वाली फसलों के औसत उत्पादन से अधिक रहा है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कानपुर क्षेत्र का औसत उत्पादन कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के औसत उत्पादन से भिन्न रहा है जो कि इस अध्ययन से स्पष्ट होता है।

4. **कृषि आगतों की उपलब्धि एवं उपयोग :** औद्योगिक उत्पादन की भांति कृषि उत्पादन में भी विभिन्न आगतों की आवश्यकता होती है। यद्यपि कृषि उत्पादन अभी भी लगभग निजी स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कृषि उत्पादन फर्मों की संख्या बहुत कम है पर सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में सुधार तथा विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के

माध्यम से किसानों को कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक आगतों की आपूर्ति की जाती है। जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके और कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो सके कृषि आगतों की सुविधाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाओं को स्पष्ट किया जा सकता है।

(क) रासायनिक उर्वरकों का वितरण : सरकार द्वारा विभिन्न संयुक्त स्वामित्व वाले उपक्रमों में बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन कराके उसे कृषि क्षेत्र में आवश्यक संगठनों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है इस सुविधा के अन्तर्गत कानपुर क्षेत्र के किसानों को वित्तीय वर्ष 2001–02 में 205762 मीट्रिक टन रासायनिक खादों का वितरण किया गया है।

(ख) सिचाई की सुविधाओं का विकास : उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा नहरों का निर्माण किया गया। जिसके अन्तर्गत कानपुर क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में नहरों द्वारा 239609 हेक्टेयर क्षेत्र की सिचाई वित्तीय वर्ष 2003–04 में की जा सकी थी। इसके अलावा कानपुर क्षेत्र में निजी नलकूपों, सार्वजनिक नलकूपों आदि का विभिन्न संगठनों के माध्यम से विकास किया गया।

(ग) ट्रैक्टर एवं कृषि यन्त्रीकरण आदि : कानपुर क्षेत्र में विभिन्न सहकारी साख संस्थाओं के माध्यम से किसानों को कृषि उत्पादन आधार में निवेश के स्तर को बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर, अन्य कृषि यन्त्र आदि उपलब्ध कराये गये। जिससे कृषि तकनीकी का विकास के साथ–साथ प्रयोग सम्भव हो सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार द्वारा बीजों की व्यवस्था, कीटनाशक दवायें तथा उनके प्रयोग के लिए आवश्यक यन्त्र व खेतों की जुताई बुवाई के लिए हैरो व सीलड्रिल की व्यवस्था तथा सिचाई की समुचित व्यवस्था के लिए अनेकों प्रकार के साधन उपलब्ध कराये गये। जिससे कि कृषि क्षेत्र के विकास के साथ–साथ सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास सम्भव हो सके।

5. कृषि साख के स्रोत : कृषि साख के स्रोतों में उन स्रोतों को रखा जाता है जिनसे कृषि क्षेत्र के विभिन्न कार्यों के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण या आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। कृषि साख के स्रोत ग्रामीण साख के स्रोतों का एक अंग है। ग्रामीण साख के

स्रोतों के अन्तर्गत उन सभी स्रोतों को रखा जाता है जिनके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न आर्थिक क्रियाओं और कार्यक्रमों के लिए ऋण प्राप्त होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसके विकास के लिए वर्तमान में जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। उनमें प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम राशि 'जिसके अन्तर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कुछ वर्गों को ऋण प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाती है,' कमजोर वर्गों को ऋण, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को ऋण, विभेदी ब्याजदर योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) और कृषि के लिए ऋण इत्यादि कार्यक्रमों के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है।

कृषि क्षेत्र के लिए ऋण जैसा कि कहा जा चुका है दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है –

1. **कृषि साख के असंगठित स्रोत :** इसके अन्तर्गत उन व्यक्तियों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को रखा जाता है जिनके द्वारा किसानों को ऋण प्राप्त होता है।

2. **कृषि साख के संगठित स्रोत :** इन स्रोतों के अन्तर्गत उन संस्थाओं को रखा जाता है जिनके माध्यम से किसानों को ऋण प्राप्त होता है। इनमें निम्नलिखित संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है।
    1. सहकारी साख संस्थायें
    2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
    3. व्यावसायिक बैंक

वर्तमान अध्ययन का क्षेत्र वाणिज्यिक बैंकों तक सीमित है इसलिए वाणिज्यिक बैंकों के क्रियाकलापों पर अगले अध्यायों में विचार करके उनकी सफलताओं का आंकलन किया जायेगा। जिससे अध्ययन के प्रारम्भ में स्पष्ट की गई परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जा सके।

निष्कर्ष : 'अध्ययन क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक दशायें' के निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है।

1. **अर्थव्यवस्था का प्रारूप :** कानपुर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्यता कृषि प्रधान है। अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता को भूमि के उपयोग तथा क्षेत्र में लगी अधिकांश जनसंख्या के आधार पर स्पष्ट किया गया है। कानपुर क्षेत्र का प्रतिवेदित क्षेत्रफल 1489694 हेक्टेयर में से 1006208 हेक्टेयर क्षेत्र पर कृषि की जाती है जो प्रतिवेदित क्षेत्र का 67.5 प्रतिशत है इसी प्रकार जनसंख्या के दृष्टिकोण से वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार क्षेत्र की जनसंख्या 11209520 रही है।

(क) भूमि का उपयोग : कानपुर क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल 14776 वर्ग किलोमीटर है जिसमें प्रतिवेदित क्षेत्र 1489694 हेक्टेयर है यह प्रतिवेदित क्षेत्र विभिन्न उपयोगों में लगा हुआ है। जो निम्न हैं। वनों के अन्तर्गत लगी भूमि 65810 हेक्टेयर या प्रतिवेदित क्षेत्र का 4.4 प्रतिशत, खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लगी भूमि 133610 हेक्टेयर या प्रतिवेदित क्षेत्र का 9.5 प्रतिशत, ऊसर व खेती के अयोग्य भूमि 81665 हेक्टेयर या 4.8 प्रतिशत, कृष्य बेकार भूमि 38302 हेक्टेयर या प्रतिवेदित क्षेत्र का 2.6 प्रतिशत , चरागाह तथा अन्य वृक्ष झाड़ियों की भूमि 27438 हेक्टेयर या प्रतिवेदित क्षेत्र का 1.8 प्रतिशत, वर्तमान परती एवं अन्य परती 152658 हेक्टेयर या प्रतिवेदित क्षेत्र का 10.2 प्रतिशत तथा शेष शुद्ध बोया गया क्षेत्र 994009 हेक्टेयर या कुल रिपोर्ट की गयी भूमि का 66.7 प्रतिशत है।

(ख) जनसंख्या : क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुयी है। जनगणना वर्ष 2001 के आधार पर क्षेत्र की 11209520 जनसंख्या में 1470990 जनसंख्या कृषि कार्यों में किसी न किसी रूप में लगी हुयी है। जो कुल जनसंख्या का 13.1 प्रतिशत है और कार्यशील जनसंख्या का 42.8 प्रतिशत है जो कृषि कार्य करती है।

2. **जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण :** जनसंख्या के आर्थिक वर्गीकरण से आशय जनसंख्या के उस वर्गीकरण से है जिसके अन्तर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगी हुयी

जनसंख्या को वर्गीकृत किया गया है। कानपुर क्षेत्र की जनसंख्या में आय अर्जित करने वालों की संख्या 3438357 या कुल जनसंख्या का 30.7 प्रतिशत है। और आश्रितों की संख्या 7771173 या कुल जनसंख्या का 69.3 प्रतिशत है।

इसी आय अर्जित करने वाली जनसंख्या का विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगा होना जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण कहलाता है। इस दृष्टिकोण से कानपुर क्षेत्र की जनसंख्या में 33.6 प्रतिशत कृषक, 9.2 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 3.4 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग में लगी जनसंख्या, 33.2 प्रतिशत अन्य कर्मकर व 20.6 प्रतिशत अन्य मुख्य कर्मकर हैं।

3. **कृषि अर्थव्यवस्था :** कानपुर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के समान कृषि प्रधान है। कृषि के अन्तर्गत कानपुर क्षेत्र में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है जिसके अन्तर्गत गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, लाही/सरसों, तिलशुद्ध, मूंगफली, अलसी, दालें, चना, गन्ना व आलू आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है जिसका उत्पादन स्तर लगा क्षेत्रफल व प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन आदि को अध्याय की सारणी संख्या 38 में दर्शाया गया है इन विभिन्न फसलों में सबसे बड़े क्षेत्र में गेहूं की फसल उत्पादित की जाती है तत्पश्चात अन्य फसलों का उत्पादन होता है।

4. **कृषि आगतों की उपलब्धि एवं उपयोग :** औद्योगिक उत्पादन की भांति कृषि उत्पादन में विभिन्न आगतों की आवश्यकता होती है सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में सुधार तथा विकास के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से किसानों को कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक आगतों की आपूर्ति की जाती है। जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके और कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। कृषि आगतों की सुविधाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाओं को स्पष्ट किया जा सकता है जैसे– रासायनिक उर्वरकों का वितरण, सिचाई सुविधाओं का विकास, ट्रैक्टर एवं कृषि यन्त्रीकरण तथा अन्य तमाम प्रकार के यन्त्र क्लीनिक आदि।

5. **कृषि साख के स्रोत :** कृषि साख के स्रोतों में उन स्रोतों को रखा जाता है जिनके

माध्यम से कृषि क्षेत्र के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण या आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। कृषि साख के स्रोत ग्रामीण साख के स्रोत का एक अंग है। ग्रामीण साख के स्रोतों के अन्तर्गत उन सभी स्रोतों को रखा गया है। जिनके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न आर्थिक क्रियाओं और कार्यक्रमों के लिए ऋण प्राप्त होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसके विकास के लिए वर्तमान में जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनमें प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम राशि जिसके अन्तर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कुछ वर्गों को ऋण प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाती है। इसके तहत कमजोर वर्गों को ऋण, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को ऋण, व विभेदी ब्याज दर योजना तथा स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना और कृषि के लिए ऋण इत्यादि कार्यक्रमों के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। कृषि क्षेत्र के लिए ऋण मुख्यतया दो स्रोतों से प्राप्त होता है।

1. कृषि साख के असंगठित स्रोत
2. कृषि साख के संगठित स्रोत

कृषि साख के असंगठित स्रोतों के अन्तर्गत उन व्यक्तियों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को रखा गया है जिनके द्वारा किसानों को ऋण प्राप्त होता है तथा संगठित स्रोतों के अन्तर्गत उन स्रोतों को रखा गया है जिनके माध्यम से किसानों को ऋण सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा प्राप्त होता है। ये संस्थायें मुख्यरूप से तीन प्रकार की हैं।

1. सहकारी साख संस्थायें
2.. क्षेत्रीय ग्रार्म ग बैंक
3. वाणिज्यिक बैंक

वर्तमान अध्ययन का क्षेत्र वाणिज्यिक बैंकों के वित्त तक सीमित है इसलिए इस अध्ययन के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राप्त ऋण के विभिन्न अंगों व स्वरूपों पर भी विचार किया जायेगा।



अध्याय - चार

व्यापारिक बैंकों का विकास

अध्याय – चार : व्यापारिक बैंकों का विकास

भारतीय प्रबन्धन के अधीन पहला सीमित दायित्व वाला बैंक अवध कामर्शियल बैंक था जिसकी स्थापना वर्ष 1881 में की गयी थी। उसके बाद वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। वर्ष 1906 में शुरू हुये स्वदेशी आन्दोलन से कई वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना में प्रोत्साहन मिला। वर्ष 1913–1917 के दौरान बैंकिंग संकट तथा पांचवें दशक में विभिन्न राज्यों में 588 बैंकों के दिवालिया हो जाने से वाणिज्यिक बैंकों के नियमन और उन पर नियन्त्रण की आवश्यकता को बल मिला। बैंकिंग कम्पनी अधिनियम फरवरी 1949 में पारित हुआ। जिसे संशोधन के बाद 'बैंकिंग नियम अधिनियम 1949' के रूप में जाना गया। इस अधिनियम के जरिए बैंकिंग व्यवस्था पर नियमन का कानूनी अधिकार रिजर्व बैंक को मिल गया।

देश के सबसे बड़े बैंक 'इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया' का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1955 में किया गया और इसका नाम बदलकर 'स्टेट बैंक आफ इण्डिया' कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 1959 में इसके 7 सहयोगी बैंकों का गठन किया गया। निश्चित सामाजिक दायित्वों के साथ वाणिज्यिक बैंकों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का नियन्त्रण अपने हाथों में लेने के लिए 19 जुलाई 1969 में एक अध्यादेश जारी कर राष्ट्रीयकरण कर दिया, 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

8वें दशक के अन्त में बैंकिंग व्यवस्था में कुछ अनियमिततायें पायी गई। सरकार को लगा कि इन्हें दूर किया जाना चाहिए ताकि वित्तीय प्रणाली एक कुशल और स्पर्धापूर्ण अर्थव्यवस्था बनाने की अपनी भूमिका निभा सके। तदनुसार वित्तीय ढॉचे, संगठन, कामकाज और प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं की जांच के लिए श्री एम.नरसिम्हम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (सी.एफ.एस.) गठित की गई। समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1992–93 में बैंकिंग प्रणाली में व्यापक सुधार किये गये। भारत में बैंकिंग व्यवस्था में कुल 218 (विदेशी बैंकों

सहित) वाणिज्यिक बैंक हैं। इनमें से 161 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं जिनमें 133 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) हैं। और ये सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि का 75.2 प्रतिशत एकत्र करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे ऋण लेने वालों को और अधिक ऋण मुहैया कराने के लिए विशेष रूप से की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा बाकी 28 बैंकों में 19 राष्ट्रीयकृत, एस.बी.आई. समूह के 8 बैंक और आई.डी.बी.आई. लिमिटेड शामिल हैं और ये सभी तरह का बैंकिंग व्यवसाय करते हैं।[1]

भारत में व्यावसायिक बैंकों की प्रगति के सम्बन्ध में कुछ संकेतांकों को सारणी संख्या 40 में स्पष्ट किया गया है।

---

1. भारत वर्ष 2007 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित पृष्ठ 362

सारणी संख्या–40

भारत में व्यावसायिक बैंकों का विकास

वर्ष	वाणिज्यिक बैंकों की संख्या	(क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	(ग) गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	देश में बैंक कार्यालयों की संख्या	कार्यालय के अनुसार जनसंख्या (हजार में)	देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल डिपाजिट (करोड़ रुपये में)	देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल ऋण (करोड़ रुपये में)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रति व्यक्ति जमा (रुपये में)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया हुआ प्रति व्यक्ति ऋण	वर्तमान मूल्यों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि राष्ट्रीय आय के प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1969	39	73	—	16	8262	64	4646	3599	88	68	15.5
1973	83	74	—	9	15362	37	9165	6412	160	112	21.4
1975	83	74	—	9	18730	32	12545	8955	210	150	19.0
1976	100	92	19	8	21220	29	15178	11476	249	188	23.3
1977	126	119	47	7	24802	25	18903	13491	305	217	27.1
1978	128	122	48	6	28016	23	23312	15694	369	249	31.9
1979	136	131	56	5	30302	21	28671	19116	447	298	33.7
1980	154	149	74	5	32419	20	33283	22053	511	339	36.1
1981	187	183	102	4	35702	19	40549	26551	556	371	35.7
1982	206	202	121	4	39177	17	46128	30180	673	440	36.1
1983	226	222	142	4	42027	16	53386	35881	785	528	38.3
1984	247	243	162	4	45332	16	64620	43613	878	593	38.3
1985	268	264	183	4	51385	15	77075	50921	1026	678	41.5
1986	276	273	194	4	53265	14	91828	57229	1198	747	43.6
1987	279	275	196	4	53869	15	107345	63753	1374	816	47.6

1. वर्ष 1969 से 1980 तक इण्डिया 1981 के पृष्ठ संख्या 163 पर दिये आंकड़ों पर आधारित
2. वर्ष 1981 से 1983 तक इण्डिया 1984 के पृष्ठ संख्या 217 पर दिये आंकड़ों पर आधारित
3. वर्ष 1984 से 1987 तक इण्डिया 1988–89 के पृष्ठ संख्या 301 पर दिये आंकड़ों पर आधारित

नोट – समस्त आंकड़े 30 जून तक के हैं।

वर्ष	वाणिज्यिक बैंकों की संख्या	(क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	(ग) गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	देश में बैंक कार्यालयों की संख्या	कार्यालय के अनुसार जनसंख्या (हजार में)	देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल डिपाजिट (करोड़ रुपये में)	देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल ऋण (करोड़ रुपये में)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रति व्यक्ति जमा (रुपये में)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया हुआ प्रति व्यक्ति ऋण	वर्तमान मूल्यों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि राष्ट्रीय आय के प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1988	278	274	196	4	55410	14	126323	72436	1586	909	45.8
1989	278	274	196	4	57699	14	147854	89080	1821	1097	45.7
1997	299	297	196	2	63550	15	499763	278401	5261	2931	43.8
1998	300	299	196	1	64218	15	598485	324079	6170	3356	47.3
1999	303	302	196	1	64939	15	714025@	368837	7237	3738	49.8
2000	297	297	196	–	65412	15	851593@	454069	8498	4531	53.5
2001	301	296	196	5	65919	15	989141#	529272	9758	5221	58.9
2002	298	294	196	4	66190	16	1131187#	609053	10994	5921	60.7
2003	294	289	196	5	66535	16	1311761#	746432	12554	7143	66.0
2004	291	286	196	–	67188	16	1542284&	865594	14550	8166	68.5
2005	288	284	196	4	68355	16	1732858&	1124300	16091	10440	68.3

4. वर्ष 1988–89 इण्डिया 1991 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित
5. वर्ष 1997–2003 इण्डिया 2005 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित पृष्ठ संख्या 285–286
6. वर्ष 2004–05 इण्डिया 2007 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित पृष्ठ संख्या 362

नोट – आंकड़े 31 मार्च तक, @ - इसमें रिसर्जेन्ट इण्डिया बाण्ड (17945 करोड रुपये) शामिल हैं।
- इसमें रिसर्जेन्ट इण्डिया बाण्ड (17945 करोड़ रुपये) तथा इण्डिया मिलेनियम डिपाजिट्स (25662 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
& - इसमें इण्डिया मिलेनियम डिपाजिट्स (25662 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

उपरोक्त भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में प्रायः लगभग सभी प्रकार के व्यावसायिक बैंक कार्यरत हैं। जिसके विवरण को सारणी संख्या 41 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

उपरोक्त के विषय में कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न विकास खण्डों में कृषि क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करने वाले समस्त प्रकार के बैंकों को सारणी संख्या 41 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–41

कानपुर क्षेत्र में बैंकों का विकास (वर्ष 2006–07)

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4
1. फर्रूखाबाद	शमशाबाद	पंजाब नेशनल बैंक	शमसाबाद
		फर्रूखाबाद ग्रामीण बैंक	चौरसिया
			फैजबाग
			किसरौली
			मंझना
			रोशनाबाद
			शमशाबाद
			सकरूल्लापुर
			वरझाला
		जिला सहकारी बैंक	शमशाबाद
	कमालगंज	पंजाब नेशनल बैंक	कमालगंज
		फर्रूखाबाद ग्रामीण बैंक	कमालगंज
			रूनी बुरसई
			जहानगंज
			भोजपुर/कुटरा
			खुदागंज
			रजीपुर
			जरारी
			ताजपुरी
		जिला सहकारी बैंक	कमालगंज
			जहानगंज

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4
1. फर्रूखाबाद	नवाबगंज	बैंक आफ इण्डिया	भटासा
			गनीपुर जोगपुर
			चन्दुइंया
		फर्रूखाबाद ग्रामीण बैंक	अचरा खलवारा
			नवाबगंज
		जिला सहकारी बैंक	नवाबगंज
	मोहम्दाबाद	बैंक आफ इण्डिया	मोहम्दाबाद
		फर्रूखाबाद ग्रामीण बैंक	मोहम्दाबाद
			वीरपुर
			बिहार
			मदनपुर
			नीवकरोरी
			पिपरगाँव
			सिरौली (पुटरी)
			राजेन्द्र नगर
			मुरहास
			मेरापुर
			खिनसेपुर
		जिला सहकारी बैंक	मोहम्दाबाद
		भूमि विकास बैंक	मोहम्दाबाद
	बढ़पुर	बैंक आफ इण्डिया	फर्रूखाबाद
			फतेहगढ़
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	फर्रूखाबाद
			फतेहगढ़
			सचवाड़ा
		बैंक आफ बड़ौदा	सठगली
			फतेहगढ़
		सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	फर्रूखाबाद
			फतेहगढ़
		पंजाब नेशनल बैंक	फर्रूखाबाद
			फतेहगढ़

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4
1. फर्रूखाबाद	बढ़पुर	ओ0 बी0 सी0	फर्रूखाबाद
		यूनियन बैंक	फर्रूखाबाद
		यूको बैंक	फर्रूखाबाद
		इलाहाबाद बैंक	बढ़पुर
			चौक
		फर्रूखाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	फतेहगढ़
			फर्रूखाबाद
			घटियाघाट
			नारायनपुर
			यायातगंज
			आवास विकास
		जिला सहकारी बैंक	फतेहगढ़
			फर्रूखाबाद
		भूमि विकास बैंक	फतेहगढ़
	राजेपुर	बैंक आफ इण्डिया	बरखा
		फर्रूखाबाद ग्रामीण बैंक	राजेपुर
			अमृतपुर
			गांधी
			राजपुर
			सलेमपुर
		जिला सहकारी बैंक	राजेपुर
	कायमगंज	बैंक आफ इण्डिया	कायमगंज
			कम्पिल
			बरखेड़ा
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	कायमगंज
			ए.डी.बी. कायमगंज
		सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	कायमगंज
		फर्रूखाबाद ग्रामीण बैंक	अताईपुर (कायमगंज)

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4
1. फर्रूखाबाद	कायमगंज	फर्रूखाबाद ग्रामीण बैंक	उदायन
			विरसीयपुर
			शिवाराआस
			रामपुर चिनहट
		जिला सहकारी बैंक	कायमगंज
			कम्पिल
		भूमि विकास बैंक	कायमगंज
योग –	**7 (सात)**	**12 (बारह)**	**87 (सत्तासी)**

व्यावसायिक बैंक	–	29
फर्रूखाबाद ग्रामीण बैंक	–	45
जिला सहकारी बैंक	–	10
भूमि विकास बैंक	–	03
योग –		**87**

2. कन्नौज	छिबरामऊ	बैंक आफ इण्डिया	छिबरामऊ
			सिकन्दरपुर
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	छिबरामऊ
		बैंक आफ बड़ौदा	छिबरामऊ
		ओ0बी0सी0	छिबरामऊ
		सिन्डीकेट बैंक	छिबरामऊ
		आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	मण्डी समिति
			छिबरामऊ
			प्रेमपुर
			कसीबा
			सिकन्दरपुर
			विशुनगढ़
			अलीपुर

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4
2. कन्नौज	छिबरामऊ	जिला सहकारी बैंक	छिबरामऊ
		भूमि विकास बैंक	छिबरामऊ
	सौरिख	बैंक आफ इण्डिया	सौरिख
			दलौली
			चपुन्ना
		आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	खड़नी
			अलीपुर
			सकरावा
		जिला सहकारी बैंक	सौरिख
	हसेरन	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	हसेरन
			सत्तापुर
			नाडेमऊ
			मड़पुरा
			तरीन्द
			इन्दरगढ़
		जिला सहकारी बैंक	इन्दरगढ़
	तालग्राम	बैंक आफ इण्डिया	गुरसहायगंज
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	गुरसहायगंज
			सराय प्रयाग
			तालग्राम
		बैंक आफ बड़ौदा	गुरसहायगंज
		आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	समधन
			ताहपुर
			तालग्राम
			गुरसहायगंज
			जोगपुर

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4
2. कन्नौज	तालग्राम	जिला सहकारी बैंक	गुरसहायगंज
		भूमि विकास बैंक	गुरसहायगंज
	जलालाबाद	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	जलालाबाद
		आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	जसपुर सरैंया
			जलालपुर पनवारा
		जिला सहकारी बैंक	जलालाबाद
	गुगरापुर	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	फतेहपुर जशोदा
	कन्नौज	बैंक आफ इण्डिया	कन्नौज
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	कन्नौज
			कन्नौज सिटी
		इलाहाबाद बैंक	कन्नौज
		बैंक आफ बड़ौदा	कन्नौज
		सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	कन्नौज
		सिन्डीकेट बैंक	कन्नौज
		आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	कन्नौज
			नजरापुर
			मानीमऊ
			सरायमीरा
			नदसिया
		जिला सहकारी बैंक	कन्नौज
			मानीमऊ
		भूमि विकास बैंक	कन्नौज
	उमर्दा	बैंक आफ इण्डिया	तिर्वा
		इलाहाबाद बैंक	तिर्वा
			ठठिया
			रूरा
		आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	तिर्वा गंज
			तिर्वा खास
			उमर्दा/खानपुर

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4
2. कन्नौज	उमर्दा	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	औसेर
			अदौस
			ठठिया
			खैनीपुर
		जिला सहकारी बैंक	ठठिया
			तिर्वागंज
		भूमि विकास बैंक	तिर्वागंज
योग –	**8 (आठ)**	**9 (नौ)**	**75 (पचहत्तर)**

व्यावसायिक बैंक	–	26
आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	–	36
जिला सहकारी बैंक	–	9
भूमि विकास बैंक	–	4
योग –		**75**

3. इटावा	बढ़पुरा	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	बढ़पुरा
			इटावा मुख्य शाखा
			अनाज मण्डी इटावा
			तकिया आजागान
			के.के.डी. सी.
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	उदी
			इटावा मुख्य शाखा
			मण्डी इटावा
		इलाहाबाद बैंक	मुख्य शाखा इटावा
		बैंक आफ बड़ौदा	मुख्य शाखा इटावा
		यूनियन बैंक आफ इण्डिया	इटावा

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4
3. इटावा	बढ़पुरा	केनरा बैंक	इटावा
		इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	इटावा
			राजा का बाग
			चन्द्रपुर कला
			मानिकपुर मोहन
		जिला सहकारी बैंक	बढ़पुरा
			इटावा मुख्य शाखा
			सिटी वाच इटावा
		भूमि विकास बैंक	इटावा
	बसरेहर	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	अनाज मण्डी (बी)
			तकिया आजागान(बी)
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	रामनगर
			बसरेहर
			बरालोकपुर
			इटावा मुख्य शाखा
			मण्डी इटावा
		पंजाब नेशनल बैंक	सिविल लाइन्स इटावा
		बैंक आफ बड़ौदा	मुख्य शाखा इटावा (बी)
		बैंक आफ इण्डिया	मुख्य शाखा इटावा (बी)
		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बसरेहर
			चौपुला
			कुम्हावर (ए)
			कर्रीवीना (ए)
		जिला सहकारी बैंक	बसरेहर
			बरालोकपुर

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4
3. इटावा	सैफई	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	हैवरा
		इलाहाबाद बैंक	सैफई
		पंजाब नेशनल बैंक	सैफई
		बैंक आफ इण्डिया	सैफई
		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	हैवरा
			कुम्हावर (बी)
			करीवीना (बी)
			कुनैरा
		जिला सहकारी बैंक	सैफई
		भूमि विकास बैंक	सैफई
	जसवन्त नगर	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	जसवन्त नगर
			बाउथ
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	जसवन्त नगर
		इलाहाबाद बैंक	फ्रैन्ड्स कालोनी इटावा
		पंजाब नेशनल बैंक	साबितगंज
		बैंक आफ बड़ौदा	न्यू कालोनी सिविल लाइन्स
		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुनैरा (बी)
			भरवार
			मलाजनी
		जिला सहकारी बैंक	जसवन्त नगर
	चकरनगर	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	पिपरौली गढ़िया (चकरनगर)
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	चकरनगर
		जिला सहकारी बैंक	चकरनगर
		भूमि विकास बैंक	चकरनगर
	महेवा	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	अहेरीपुर
			बकेवर
			हनुमन्तपुर (लखना)
			इकदिल

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4
3. इटावा	महेवा	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	महेवा
			लखना
			लवेदी
			ददौरा
		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	महेवा
			बिजौली
			लुधियानी
			निवाड़ीकला
		जिला सहकारी बैंक	इकदिल
			लखना
			महेवा
			हनुमन्तपुर (लखना)
	भरथना	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	भरथना
			बहारपुर
			इकदिल (बी)
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	भरथना
		इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भरथना
			नारायनगंज (पाली खुर्द)
			साम्हो
			बिरौंधी
			उमरखड़ा
		जिला सहकारी बैंक	भरथना
		भूमि विकास बैंक	भरथना
	ताखा	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	सरसई नावा
		इलाहाबाद बैंक	चौपला (टकरपुरा)
		इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	नावर
			हिम्मतपुर
			ऊसराहार
			ताखा

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4
3. इटावा	ताखा	जिला सहकारी बैंक	ऊसराहार
योग –	**8 (आठ)**	**11 (ग्यारह)**	**86(छियासी)**

व्यावसायिक बैंक	–	42
इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–	25
जिला सहकारी बैंक	–	15
भूमि विकास बैंक	–	4
योग –		**86**

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
4. औरैया	औरैया	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	मिहौली
			मुरादगंज
			खानपुर (औरैया)
			कृषि उत्पादन मण्डी समिति
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	औरैया
		इलाहाबाद बैंक	औरैया
		पंजाब नेशनल बैंक	औरैया
		इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	औरैया
			बम्बुरीपुर
			मुढ़ी
			अयाना
		जिला सहकारी बैंक	औरैया
		भूमि विकास बैंक	औरैया
	अजीतमल	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	अजीतमल
			जनता महाविद्यालय अजीतमल
			मुरादगंज (बी)
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	अजीतमल
		पंजाब नेशनल बैंक	बहादुरपुर ऊँचा
		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	अनन्तरामपुर
			अटसू
			बाबरपुर
			भीखेपुर

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4
4. औरैया	अजीतमल	जिला सहकारी बैंक	अजीतमल
			मुरादगंज
	ऐरवा कटरा	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	ऐरवा कटरा
		पंजाब नेशनल बैंक	बहादुरपुर ऊँचा (बी)
		इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	ऐरवा कटरा
			बरौना कला
			कुदरकोट
			उमरैन
		जिला सहकारी बैंक	ऐरवा कटरा
	अछल्दा	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	अछल्दा
			घसारा
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	पाता
		इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	हरचन्दपुर
			मोहम्दाबाद
			नेबिलगंज
			पाता
			रुरूगंज
		जिला सहकारी बैंक	अछल्दा
	भाग्यनगर	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	भाग्यनगर
			कंचौसी बाजार
			बूढ़ा दाना
			दिबियापुर
			एनटीपीसी दिबियापुर
		पंजाब नेशनल बैंक	फफूंद
		इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	असैनी (दिबियापुर)
			ककोर
			फफूंद
		जिला सहकारी बैंक	दिबियापुर
			फफूंद
	विधूना	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	विधूना
			बेला
			भैंसऊ

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4
4. औरैया	विधूना	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	विधूना
		इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	विधूना
			बांधमऊ
		जिला सहकारी बैंक	विधूना
		भूमि विकास बैंक	विधूना
	सहार	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	सहार
			नौगवां
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	लहरापुर
		इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	याकूबपुर
			सहायल
			मल्हौसी
		जिला सहकारी बैंक	सहार
			याकूबपुर
			पूरवासुजान
योग –	**7(सात)**	**7(सात)**	**67(सरसठ)**

व्यावसायिक बैंक	–	28
इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–	25
जिला सहकारी बैंक	–	12
भूमि विकास बैंक	–	2
योग –		**67**

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
5. कानपुर नगर	कल्यानपुर	बैंक आफ बड़ौदा	किसाननगर
		भारतीय स्टेट बैंक	कल्यानपुर
			मन्धना
			भौंती
		सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	बिठूर
			सचेंडी
		बैंक आफ इण्डिया	मन्धना
		कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	नारामऊ
			कल्यानपुर
			भीमसेन

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4
5. कानपुर नगर	कल्यानपुर	जिला सहकारी बैंक	भौंती
	विधनू	बैंक आफ बड़ौदा	मंझावन टाउन
		पंजाब नेशनल बैंक	विधनू
		यूको बैंक	जामू
		कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	विधनू रमईपुर कठारा बिनगवां कठेरूआ इटारा बाजार
	सरसौल	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	सरसौल
		पंजाब नेशनल बैंक	नर्वल प्रेमपुर
		बैंक आफ इण्डिया	महाराजपुर नर्वल
		कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सरसौल रूमा पाली बौसर सिकठियापुरवा
		जिला सहकारी बैंक	सरसौल
		भूमि विकास बैंक	कानपुर
	घाटमपुर	पंजाब नेशनल बैंक	घाटमपुर रेउना
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	घाटमपुर बरीपाल
		कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	घाटमपुर सजेती परास कोरिया रामपुर मखौली बेंदा

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4
5. कानपुर नगर	घाटमपुर	जिला सहकारी बैंक	घाटमपुर
		भूमि विकास बैंक	सजेती
	पतारा	बैंक आफ बड़ौदा	पतारा
			पड़रीलालपुर
			रामसारी
			गिरसी
		कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	पतारा
			रठिगांव
			इटर्रा
		जिला सहकारी बैंक	पतारा
	भीतरगांव	बैंक आफ बड़ौदा	भीतरगाँव
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	नौरंगा
		कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	नौरंगा
			साढ़
			बरईगढ़
			भीतरगाँव
			कुड़नी
		जिला सहकारी बैंक	भीतरगाँव
	बिल्हौर	बैंक आफ बड़ौदा	मकनपुर
		सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	उत्तरीपुरा
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	बिल्हौर
		इलाहाबाद बैंक	अरौल
		कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	अरौल
			बिल्हौर
			कमसान
			बकोठी
			उत्तरीपुरा
		जिला सहकारी बैंक	बिल्हौर
			अरौल
		भूमि विकास बैंक	बिल्हौर
	ककवन	बैंक आफ बड़ौदा	ककवन
			अवरोतहारपुर
		कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	रहीमपुर विसधन
			ककवन

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4
5. कानपुर नगर	ककवन	जिला सहकारी बैंक	ककवन
	शिवराजपुर	बैंक आफ बड़ौदा	शिवराजपुर
		कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बर्राजपुर
			दिलीपनगर
			कासामऊ
			उत्तरी
			बीरामऊ
			सखरेज
		जिला सहकारी बैंक	शिवराजपुर
	चौबेपुर	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	चौबेपुर
			बैसठी
		कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	चौबेपुर
			गबड़ाहा
			सम्भलपुर
		जिला सहकारी बैंक	चौबेपुर
		भूमि विकास बैंक	चौबेपुर
योग –	**10(दस)**	**10(दस)**	**95(पन्चानबे)**

व्यावसायिक बैंक	–	34
कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–	45
जिला सहकारी बैंक	–	12
भूमि विकास बैंक	–	4
योग –		**95**

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
6. कानपुर देहात	अमरौधा	बैंक आफ बड़ौदा	पुखरायाँ
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	अमरौधा
			पुखरायाँ
			मूसानगर
			भोगनीपुर
		कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	अमरौधा
			पुखरायाँ
			शाहजहांपुर

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4
6. कानपुर देहात	अमरौधा	कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मूसानगर
			सरांय
			सट्टी
			चौरा स्टेशन
		जिला सहकारी बैंक	पुखरायाँ
		भूमि विकास बैंक	पुखरायाँ (भोगनीपुर)
	मलासा	बैंक आफ बड़ौदा	डीघ
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	मोहम्मदपुर
			शेरपुर
		कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मोहम्मदपुर
			बरौर
			अंगदपुर
		जिला सहकारी बैंक	बरौर
	राजपुर	बैंक आफ बड़ौदा	राजपुर
			सिकन्दरा
			रसधान
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	सिकन्दरा
		कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सिकन्दरा (नसीरपुर)
			काँधी
		जिला सहकारी बैंक	राजपुर
	अकबरपुर	बैंक आफ बड़ौदा	बारा
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	अकबरपुर
			रूरा
		कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	अकबरपुर
			रूरा
			लालपुर
			नबीपुर
			रूरा बहार
			मोहम्मदपुर खेड़ा
		जिला सहकारी बैंक	अकबरपुर
			रूरा
		भूमि विकास बैंक	अकबरपुर

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4
6. कानपुर देहात	मैथा	बैंक आफ बड़ौदा	मैथा
			काशीपुर
		पंजाब नेशनल बैंक	शिवली
		इलाहाबाद बैंक	शिवली
		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	शिवली
			जैतपुर
			बाघपुर
			गहलो
			वैरी सवाई
			औनहा
		जिला सहकारी बैंक	शिवली
	सरवनखेड़ा	बैंक आफ बड़ौदा	गजनेर
			सरवनखेड़ा
		इलाहाबाद बैंक	रनिया
		कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	रायपुर
			गोगूमऊ
			रनिया
			मोहना
		जिला सहाकरी बैंक	रनिया
			गजनेर
	डेरापुर	बैंक आफ बड़ौदा	डेरापुर
		कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	गलुआपुर
			मुंगीसापुर
			सिठमरा
			सरिगॉव बुजुर्ग
		जिला सहकारी बैंक	डेरापुर
		भूमि विकास बैंक	डेरापुर
	सन्दलपुर	बैंक आफ बड़ौदा	सन्दलपुर
		कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कौरू
			पिण्डार्थू
		जिला सहाकरी बैंक	सन्दलपुर
	झींझक	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	झींझक
		पंजाब नेशनल बैंक	झींझक
			बनीपारा महाराज
		कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	झींझक

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4
6. कानपुर देहात	झींझक	कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मंगलपुर
			खमैला
			बानबाजार
		जिला सहकारी बैंक	झींझक
		भूमि विकास बैंक	झींझक
	रसूलाबाद	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	रसूलाबाद
			सिसाही
		कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	रसूलाबाद
			असालतगंज
			कहिंजरी
			उसरी
			सिमरामऊ
			तिस्ती
		जिला सहकारी बैंक	रसूलाबाद
योग –	**10(दस)**	**8(आठ)**	**89(नवासी)**

व्यावसायिक बैंक	–	29
कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–	44
जिला सहकारी बैंक	–	12
भूमि विकास बैंक	–	4
योग –		**89**

स्रोत – कानपुर क्षेत्र के समस्त लीड बैंक कार्यालय से प्राप्त आंकड़े।

सारणी संख्या 41 से यह स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में कुल वित्तीय वर्ष 2006–07 तक 499 बैंक शाखाओं का विकास हुआ है। जिसमें 188 व्यावसायिक बैंक, 220 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व 91 सहकारी बैंक, संस्थाओं का विकास हुआ है। जिसमें से अध्ययन के लिए केवल व्यावसायिक बैंकों का चयन किया गया है। अतः व्यावसायिक बैंकों की ही कार्यप्रणालियों का आगे अध्ययन किया जाना निश्चित हुआ है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वर्तमान अध्ययन कानपुर क्षेत्र से सम्बन्धित है अतः सांख्यिकी विश्लेषण के दृष्टिकोण से इस अध्ययन की सम्पूर्ण इकाई यूनीवर्स (Universe) कानपुर क्षेत्र है। कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत 6 जनपद आते हैं जो कृमशः फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर व कानपुर देहात हैं। इन सभी जनपदों में कुल विकास खण्डों की संख्या 50 है। कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में विकास खण्ड के विवरण को सारणी संख्या 42 द्वारा स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–42

कानपुर क्षेत्र के जनपदों में विकास खण्ड का विवरण

जनपद का नाम	विकास खण्ड संख्या
1	2
1. फर्रूखाबाद	07
2. कन्नौज	08
3. इटावा	08
4. औरैया	07
5. कानपुर नगर	10
6. कानपुर देहात	10
योग –	**50**

स्रोत – कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में कार्यरत लीड बैंक कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित

सारणी संख्या 42 से यह स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र के समस्त जनपदों की अर्थव्यवस्था 50 विकास खण्डों में विभक्त है। अध्ययन को सम्पूर्ण इकाई का प्रतिनिधित्व करने के लिए अध्ययन के क्षेत्र को सभी विकास खण्डों तक विस्तृत किया गया है। जहां तक विकास खण्डों में अध्ययन की इकाइयों के चुनाव का प्रश्न है, तो जनपद में कार्यरत विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की शाखा संख्या के आधार पर किया गया है।

अध्ययन की इकाइयों का चुनाव रैण्डम सैम्पलिंग (Random Sampling)के आधार पर किया गया है क्योंकि कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में कुल बैंकों की

संख्या 499 है जिसके विवरण को सारणी संख्या 43 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–43

कानपुर क्षेत्र में कार्यरत बैंकों का विवरण (वित्तीय वर्ष 2006–07)

बैंकों के नाम	बैंक शाखाओं की संख्या
1	2
1. व्यावसायिक बैंक	188
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	220
3. जिला सहकारी बैंक	70
4. भूमि विकास बैंक	21
योग –	**499**

स्रोत – कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में कार्यरत लीड बैंक कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित

सारणी संख्या 43 में स्पष्ट की गई समस्त बैंक व शाखाओं में यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक व भूमि विकास बैंक को यदि कम कर दिया जाय तो व्यावसायिक बैंकों की संख्या 188 है। और सभी इकाइयों का अध्ययन सीमित समय और सीमित साधनों को ध्यान में रखकर अध्ययन करना सम्भव नहीं है। इसलिए अध्ययन की इकाइयों का चुनाव रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर की किया गया हैं। सांख्यिकी सिद्धान्तों के आधार पर किसी सम्पूर्ण इकाइयों के अध्ययन के लिए जो सैम्पल के आधार पर की जाती हैं। अध्ययन इकाई के कुल इकाइयों में 25 प्रतिशत इकाइयों के अध्ययन को उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। इस सिद्धान्त को ध्यान में रखकर अध्ययन के लिए 30 प्रतिशत इकाइयों का चुनाव किया गया है। सिद्धान्त के अनुसार 188 व्यावसायिक बैंकों में अध्ययन की आवश्यक इकाइयों या अध्ययन के लिए रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर चुने गये 57 बैंक शाखायें हैं। इन चयनित व्यावसायिक बैंकों को कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों की संख्या के आधार पर सैम्पल इकाइयों का चयन किया जायेगा। कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में कार्यरत विभिन्न व्यावसायिक बैंकों के विकास का विवरण निम्न प्रकार है। जिसको जनपदवार स्पष्ट किया जा सकता है।

1. फर्रूखाबाद जनपद : वर्तमान में फर्रूखाबाद जनपद में निम्नलिखित व्यावसायिक बैंक कार्यरत हैं जिनके द्वारा कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान किया जाता है।

1. बैंक आफ इण्डिया
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया
3. बैंक आफ बड़ौदा
4. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
5. पंजाब नेशनल बैंक
6. ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स
7. यूनियन बैंक आफ इण्डिया
8. यूको बैंक
9. इलाहाबाद बैंक

इन कार्यरत विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा पिछले कुछ वर्षों में दिये गये ऋण के विवरण को सारणी संख्या 44 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–44

फर्रूखाबाद जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षों में वितरित ऋण (स्थिति 31 मार्च)

वर्ष	वितरित ऋण (धनराशि करोड रुपये में)	वितरित ऋण में गत वर्ष की तुलना में होने वाली वृद्धि प्रतिशत में
1	2	3
1990	115.42	–
1992	128.12	11.00
1994	133.21	3.9
2000	246.13	84.7
2001	340.10	38.2
2002	193.40	–43.2
2003	245.40	26.8
2004	255.00	3.9
2005	293.00	14.9
2006	353.00	20.5
2007	470.00	33.1

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश व सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय वर्षों में दिये आंकड़ों पर आधारित

नोट– वितरित ऋण में व्यावसायिक बैंकों के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित ऋण भी सम्मिलित है।

सारणी संख्या 44 से यह स्पष्ट है कि फर्रूखाबाद जनपद में व्यवसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हुयी है। वर्ष 2001–02 में वितरित ऋण की मात्रा में कमी होने का कारण फर्रूखाबाद जनपद से कन्नौज जनपद का प्लान प्रथक हो जाना रहा है। अन्यथा की स्थिति में समस्त वित्तीय वर्षों में वितरित ऋण में वृद्धि स्पष्ट होती है। यदि पिछले 17 वर्षों के इन बैंकों के वितरित ऋण की वृद्धि पर विचार किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1990–91 में जो वितरित ऋण का स्तर था वह 2006–07 में बढ़कर 307.2 प्रतिशत हो गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनपद में वितरित ऋण में अनवरत वृद्धि हो रही है।

2. **कन्नौज जनपद :** कन्नौज जनपद में वर्तमान में कार्यरत विभिन्न व्यवसायिक बैंकों की संख्या निम्न प्रकार रही है।

1. बैंक आफ इण्डिया
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया
3. इलाहाबाद बैंक
4. ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स
5. बैंक आफ बड़ौदा
6. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया

जनपद में कार्यरत इन बैंक शाखाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2001–02 से वर्ष 2006–07 तक वितरित ऋण को सारणी संख्या 45 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–45

कन्नौज जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षों में वितरित ऋण (स्थिति 31 मार्च)

वर्ष	वितरित ऋण (धनराशि करोड रुपये में)	वितरित ऋण में गत वर्ष की तुलना में होने वाली वृद्धि प्रतिशत में
1	2	3
2001	115.00	–
2002	153.64	25.1
2003	170.02	10.7
2004	201.00	18.2
2005	258.00	28.4
2006	309.00	19.8
2007	371.07	20.1

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश व सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय वर्षों में दिये आंकड़ों पर आधारित

नोट– वितरित ऋण में व्यावसायिक बैंकों के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित ऋण भी सम्मिलित है।

सारणी संख्या 45 से यह स्पष्ट है कि कन्नौज जनपद में व्यावसायिक बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2001 में जो वितरित ऋण का स्तर था उसमें निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 से 2007 के बीच वितरित ऋण में 222.7 प्रतिशत की वृद्धि रही है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनपद में इन बैंक शाखाओं द्वारा वितरित ऋण में लगातार वृद्धि हो रही है।

3. इटावा जनपद : इटावा जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में कार्यरत बैंकों की संख्या निम्नलिखित रही है। जिनके द्वारा कृषि क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र को वित्तीय सहायतायें उपलब्ध की जा रही हैं।

1. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया
3. इलाहाबाद बैंक
4. पंजाब नेशनल बैंक
5. बैंक आफ इण्डिया
6. यूनियन बैंक
7. केनरा बैंक
8. बैंक आफ बड़ौदा

वर्तमान में इन बैंकों की 42 शाखायें कार्यरत हैं। जिनके द्वारा जनपद में ग्रामीण क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति हेतु ऋण का वितरण किया जा रहा है। जिसके विवरण को सारणी संख्या 46 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–46

इटावा जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षो में वितरित ऋण (स्थिति 31 मार्च)

वर्ष	वितरित ऋण (धनराशि करोड रुपये में)	वितरित ऋण में गत वर्ष की तुलना में होने वाली वृद्धि प्रतिशत में
1	2	3
1990	62.93	–
1992	74.65	18.6
1994	78.99	5.8
2000	141.39	79.0
2001	190.13	34.5
2002	129.21	–32.0
2003	146.09	13.1
2004	189.00	23.4
2005	240.00	27.0
2006	278.00	15.8
2007	359.38	29.3

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश व सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय वर्षों में दिये आंकड़ों पर आधारित

नोट– वितरित ऋण में व्यावसायिक बैंकों के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित ऋण भी सम्मिलित है।

सारणी संख्या 46 से यह स्पष्ट है कि इटावा जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2001–02 में वितरित ऋण में जो कमी स्पष्ट होती है वह औरैया जनपद का इटावा जनपद से अलग हो जाना रहा है। जिसके कारण वितरित ऋण में कमी स्पष्ट होती है। शेष वर्षों में निरन्तर वृद्धि हुई है जो कि इस बात से स्पष्ट है कि जनपद को वित्तीय वर्ष 1990 में वितरित ऋण की अपेक्षा वर्ष 2007 में वितरित ऋण में होने वाली 471.1 प्रतिशत की भारी वृद्धि से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

4. औरैया जनपद : औरैया जनपद का सृजन तो 1997 में हुआ किन्तु जनपद का वित्तीय ढांचे का विभाजन वर्ष 2001–02 से स्पष्ट होता है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में औरैया जनपद में विभिन्न बैंकें कार्यरत थीं जिनके विवरण को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

1. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया
3. इलाहाबाद बैंक
4. पंजाब नेशनल बैंक

इन विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2001–02 से 2006–07 तक वितरित ऋण को सारणी संख्या 47 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–47

औरैया जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षों में वितरित ऋण (स्थिति 31 मार्च)

वर्ष	वितरित ऋण (धनराशि करोड रुपये में)	वितरित ऋण में गत वर्ष की तुलना में होने वाली वृद्धि प्रतिशत में
1	2	3
2001	40.15	–
2002	53.51	33.3
2003	67.33	25.8
2004	86.00	27.7
2005	104.00	20.9
2006	126.00	21.2
2007	170.72	35.5

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश व सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय वर्षों में दिये आंकड़ों पर आधारित

नोट– वितरित ऋण में व्यावसायिक बैंकों के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित ऋण भी सम्मिलित है।

सारणी संख्या 47 से यह स्पष्ट है कि औरैया जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हुई है। वितरित ऋण की मात्रा में होने वाली यह वृद्धि इस बात से स्पष्ट है कि वर्ष 2001 में वितरित ऋण के सापेक्ष वर्ष 2007 में वितरित ऋण में 325.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो यह स्पष्ट करती है कि जनपद में वितरित ऋण में दिन–प्रतिदिन वृद्धि हो रही है।

5. **कानपुर नगर** : कानपुर नगर में निम्नलिखित व्यवसायिक बैंकों का विकास हुआ है। जो निम्न प्रकार हैं।

1. बैंक आफ बड़ौदा
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया
3. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
4. पंजाब नेशनल बैंक
5. बैंक आफ इण्डिया
6. इलाहाबाद बैंक
7. यूको बैंक

जनपद में कार्यरत इन विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षों में वितरित ऋण को सारणी संख्या 48 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–48

कानपुर नगर जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षों में वितरित ऋण (स्थिति 31 मार्च)

वर्ष	वितरित ऋण (धनराशि करोड रुपये में)	वितरित ऋण में गत वर्ष की तुलना में होने वाली वृद्धि प्रतिशत में
1	2	3
1998	72.67	–
1999	100.08	37.7
2000	109.07	9.0
2001	116.67	7.0
2002	133.45	14.4
2003	156.24	17.1
2004	185.61	18.8
2005	238.46	24.5
2006	355.24	49.0
2007	383.22	7.9

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश व सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय वर्षों में दिये आंकड़ों पर आधारित

नोट– वितरित ऋण में व्यावसायिक बैंकों के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित ऋण भी सम्मिलित है।

सारणी संख्या 48 से यह स्पष्ट है कि कानपुर नगर जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण में निरन्तर वृद्धि हो रही है जो कि इस बात से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 1998 में वितरित ऋण की अपेक्षा वर्ष 2007 में 427.3 प्रतिशत की वृद्धि स्पष्ट होती है जिससे यह बात सिद्ध हो जाती है।

6. कानपुर देहात : कानपुर देहात जनपद में विभिन्न व्यावसायिक बैंक कार्यरत हैं जो ग्रामीण क्षेत्र को आवश्यक साख उपलब्ध करा रहे हैं जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ढॉचें में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जनपद में कार्यरत इन बैंकों की संख्या निम्न प्रकार है।

1. बैंक आफ बड़ौदा
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया
3. पंजाब नेशनल बैंक
4. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
5. इलाहाबाद बैंक

जनपद में कार्यरत इन विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षों में वितरित ऋण को सारणी संख्या 49 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–49

कानपुर देहात जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षों में वितरित ऋण (स्थिति 31 मार्च)

वर्ष	वितरित ऋण (धनराशि करोड रुपये में)	वितरित ऋण में गत वर्ष की तुलना में होने वाली वृद्धि प्रतिशत में
1	2	3
1990	61.51	–
1992	80.55	31.0
1994	84.54	5.0
2000	149.13	70.4
2001	170.11	14.1
2002	194.08	14.1
2003	224.54	15.7
2004	304.00	35.4
2005	334.00	9.9
2006	432.00	39.3
2007	510.00	18.1

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश व सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय वर्षों में दिये आंकड़ों पर आधारित

नोट– वितरित ऋण में व्यावसायिक बैंकों के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित ऋण भी सम्मिलित है।

सारणी संख्या 49 से यह स्पष्ट है कि कानपुर देहात जनपद में विभिन्न वर्षों में वितरित ऋण में निरन्तर वृद्धि हुई है जो कि इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि वित्तीय वर्ष 1990 से वर्ष 2007 के बीच वितरित ऋण में 729.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

कानपुर क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों के ऋण का स्वरूप :

जहां तक कानपुर क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण के वितरण का प्रश्न है वह कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित ऋण के विवरण से स्पष्ट हो जाता है किन्तु फिर भी कानपुर क्षेत्र में विभिन्न जनपदों में जो विभिन्न वर्षों में वितरित ऋण रहा है उसके विवरण के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए सारणी संख्या 50 का सहारा लिया जा सकता है।

सारणी संख्या–50

कानपुर क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षों में वितरित ऋण (स्थिति 31 मार्च)

वर्ष	वितरित ऋण (धनराशि करोड रुपये में)	वितरित ऋण में गत वर्ष की तुलना में होने वाली वृद्धि प्रतिशत में
1	2	3
2001	972.16	–
2002	857.29	–11.8
2003	1009.62	17.8
2004	1220.61	20.9
2005	1467.46	20.2
2006	1853.00	26.3
2007	2264.39	22.2

सारणी संख्या 50 से यह स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में व्यावसायिक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वितरित ऋण में कुछ वर्षों को छोड़कर शेष समस्त वर्षों में वृद्धि ही स्पष्ट होती है। जो कि इस बात से सिद्ध होती है कि क्षेत्र में वर्ष 2001 में वितरित ऋण की अपेक्षा वर्ष 2007 में वितरित ऋण में 132.9 प्रतिशत की वृद्धि रही है से स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार विभिन्न व्यावसायिक बैंकों के द्वारा समय के परिवर्तन के साथ–साथ ऋण की मात्रा में भी परिवर्तन होता रहा है। जो कि कृषि अर्थव्यस्था में आवश्यक सुधार के लिए एक शुभ संकेत है।

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश व सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय वर्षों में दिये आंकड़ों पर आधारित

नोट– वितरित ऋण में व्यावसायिक बैंकों के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित ऋण भी सम्मिलित है।

बचत का गतिशीलन : व्यावसायिक बैंकों द्वारा न केवल अधिकाधिक मात्रा में अग्रिम प्रदान किये जाते रहे हैं बल्कि इसके अतिरिक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लोगों की जमा स्वीकार करके उनकी बचत को गतिशील बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विभिन्न जनपदों में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा स्वीकार की गई जमाओं को जनपद के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है।

1. फर्रूखाबाद जनपद : फर्रूखाबाद जनपद में व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमा की स्थिति को सारणी संख्या 51 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–51

फर्रूखाबाद जनपद में व्यावसायिक बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकार की गई जमायें
(स्थिति 31 मार्च)

वर्ष	जमा धनराशि (धनराशि करोड रुपये में)	स्वीकार की गई जमाओं में गत वर्ष की तुलना में होने वाली वृद्धि प्रतिशत में
1	2	3
1990	191.02	—
1992	245.78	28.7
1994	267.28	8.7
2000	8.8.68	202.1
2001	960.65	18.8
2002	694.09	–27.7
2003	729.92	5.2
2004	717.00	–1.8
2005	755.00	5.3
2006	843.00	11.6
2007	995.41	15.3

सारणी संख्या 51 से यह स्पष्ट है कि फर्रूखाबाद जनपद में व्यावसायिक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकार की गई जमाओं में लगभग वर्षों में वृद्धि ही स्पष्ट होती है जो इस बात से स्पष्ट है कि 1990–91 में स्वीकार की गई जमाओं के सापेक्ष वर्ष 2007 में 421.1 प्रतिशत की वृद्धि रही है, से स्पष्ट हो जाती है।

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश व सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय वर्षों में दिये आंकड़ों पर आधारित

कन्नौज जनपद : कन्नौज जनपद में व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षों में स्वीकार की गई जनता की जमाओं के विवरण को सारणी संख्या 52 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–52

कन्नौज जनपद में व्यावसायिक बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकार की गई जमायें (स्थिति 31 मार्च)

वर्ष	जमा धनराशि (धनराशि करोड रुपये में)	स्वीकार की गई जमाओं में गत वर्ष की तुलना में होने वाली वृद्धि प्रतिशत में
1	2	3
2001	410.30	–
2002	425.32	3.7
2003	463.32	9.0
2004	470.00	1.4
2005	501.00	6.6
2006	565.00	12.8
2007	687.99	21.8

सारणी संख्या 52 से यह स्पष्ट है कि कन्नौज जनपद में व्यावसायिक बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकार की गई जमाओं में लगभग वर्षों में वृद्धि ही स्पष्ट होती है जो इस बात से स्पष्ट है कि 2001 में स्वीकार की गई जमाओं के सापेक्ष वर्ष 2007 में 67.7 प्रतिशत की वृद्धि रही है, से स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार सारणी से यह स्पष्ट होता है कि जनपद में ग्रामीण क्षेत्र की जनता द्वारा स्वीकार की गई जमाओं से व्यक्तियों के बीच में बचत को गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिससे कि व्यक्तियों में बचत करने के प्रति उत्सुकता बढ़ी है निश्चित ही इस बचत करने की जिज्ञासा ही व्यक्ति को विकास की गति प्राप्त कराती है। क्योंकि व्यक्ति जब बचत करता है तो निश्चित ही वह व्यक्ति बचत की गई धनराशि को किसी क्षेत्र में निवेश करता है जिससे कि उस क्षेत्र में विकास के नये आयाम प्रखण्ड होते हैं। जिससे कि रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं और व्यक्तियों के आय स्तर में वृद्धि होती है और इस वृद्धि के साथ–साथ बचत में भी वृद्धि होती है जिससे निवेश के स्तर में और अधिक वृद्धि की सम्भावना प्रबल होती है। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सम्पूर्ण विकास सम्भव हो सकता है।

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश व सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय वर्षों में दिये आंकड़ों पर आधारित

इटावा जनपद : इटावा जनपद में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जनता के द्वारा स्वीकार्य की गई विभिन्न वित्तीय वर्षों में जमाओं को सारणी संख्या 53 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–53

इटावा जनपद में व्यावसायिक बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकार की गई जमायें (स्थिति 31 मार्च)

वर्ष	जमा धनराशि (धनराशि करोड रुपये में)	स्वीकार की गई जमाओं में गत वर्ष की तुलना में होने वाली वृद्धि प्रतिशत में
1	2	3
1990	155.76	–
1992	201.51	29.4
1994	212.67	5.5
2000	684.58	221.9
2001	605.40	–11.6
2002	540.94	–10.6
2003	598.43	10.6
2004	663.00	10.8
2005	746.00	12.5
2006	849.00	13.8
2007	1061.16	25.0

सारणी संख्या 53 से यह स्पष्ट है कि इटावा जनपद में व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकार्य की गई जमायें समय–समय पर परिवर्तित होती रही हैं। जैसा की सारणी से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 1990 से 2000 तक स्वीकार्य की गई जमाओं में निरन्तर तीव्र गति से वृद्धि हुई है जबकि 2001–02 में स्वीकार्य की गई जमाओं में कमी स्पष्ट होती है। किन्तु इसके पश्चात भी इन बैंकों द्वारा स्वीकार्य की गई जमाओं में निरन्तर वृद्धि स्पष्ट होती है। बैंकों द्वारा स्वीकार्य की गई जमाओं में वृद्धि होने से यह स्पष्ट होता है कि जनपद में बचत के गतिशीलन में वृद्धि हुई है जिससे कि व्यक्तियों में बचत के प्रति प्रेरणा जागृत हुई है और इस प्रेरणा से अत्यधिक बचत के स्तर को प्राप्त किया जा सका है जिससे कि लोगों के दिन प्रतिदिन बढ़ते हुये उत्पादन क्षेत्र में निवेश के स्तर में वृद्धि हो सकी है। जैसा कि सारणी से भी स्पष्ट है कि वर्ष 1990 में जो जमा का स्तर था वह 2007 में बढ़कर 581.3 प्रतिशत हो गया।

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश व सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय वर्षों में दिये आंकड़ों पर आधारित

औरैया जनपद : औरैया जनपद में व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जनता द्वारा स्वीकार्य की गई जमाओं के विवरण को सारणी संख्या 54 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–54

औरैया जनपद में व्यावसायिक बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकार की गई जमायें (स्थिति 31 मार्च)

वर्ष	जमा धनराशि (धनराशि करोड रुपये में)	स्वीकार की गई जमाओं में गत वर्ष की तुलना में होने वाली वृद्धि प्रतिशत में
1	2	3
2001	310.06	–
2002	339.27	9.4
2003	380.43	12.1
2004	393.00	3.3
2005	428.00	8.9
2006	462.00	7.9
2007	479.70	3.8

सारणी संख्या 54 से यह स्पष्ट है कि औरैया जनपद में व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकार्य की गई जनता की जमाओं में निरन्तर दिन–प्रतिदिन वृद्धि हुई है। जो कि वर्ष 2001 में स्वीकार्य की गई जमाओं की अपेक्षा वर्ष 2007 में स्वीकार्य की गई जमाओं में 60.5 प्रतिशत की वृद्धि से स्पष्ट है इस प्रकार कहा जा सकता है कि औरैया जनपद में इन बैंकों के द्वारा व्यक्तियों को बचत के प्रति प्रोत्साहित किया है। जिससे कि व्यक्ति बचत किये हुये धन को उत्पादक क्षेत्र में निवेश कर सके। जिससे प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ–साथ सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास सम्भव हो सके। अतः बचत के गतिशीलन में इन बैंक शाखाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया है। जो कि सारणी से स्पष्ट है।

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश व सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय वर्षो में दिये आंकड़ों पर आधारित

कानपुर नगर जनपद : कानपुर नगर जनपद में कार्यरत विभिन्न व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकार्य की गई जनता की जमाओं को विभिन्न वित्तीय वर्षों के आधार पर सारणी संख्या 55 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–55

कानपुर नगर जनपद में व्यावसायिक बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकार की गई जमायें (स्थिति 31 मार्च)

वर्ष	जमा धनराशि (धनराशि करोड रुपये में)	स्वीकार की गई जमाओं में गत वर्ष की तुलना में होने वाली वृद्धि प्रतिशत में
1	2	3
1998	265.29	–
1999	311.63	17.5
2000	395.11	26.8
2001	408.88	3.5
2002	480.46	17.5
2003	533.84	11.1
2004	553.84	3.7
2005	623.10	12.5
2006	729.60	17.1
2007	990.37	35.7

सारणी संख्या 55 से स्पष्ट है कि कानपुर नगर में कार्यरत व्यावसायिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जमा राशि में निरन्तर वृद्धि हुई है, परन्तु यह वृद्धि का स्तर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में परिवर्तित रहा है। और जमा राशि में होने वाली यह वृद्धि वर्ष 1998 की तुलना में वर्ष 2007 में 273.5 प्रतिशत अधिक रही हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनपद में इन बैंक शाखाओं में जमा राशि में निरन्तर वृद्धि हुई है। जहां तक बैंकों में होने वाली जमाओं में इस वृद्धि के महत्व की बात है तो निश्चित ही जब जमायें अधिक होंगी तो लोगों के बचत के स्तर में वृद्धि होगी जिससे बचत किया हुआ धन लोग उत्पादक कार्यों में निवेश कर सकेंगे। जिससे प्रति व्यक्ति आय के साथ–साथ सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास हो सकेगा।

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश व सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय वर्षों में दिये आंकड़ों पर आधारित

कानपुर देहात जनपद : कानपुर देहात जनपद में कार्यरत विभिन्न व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकार्य की गई जनता की जमाओं को विभिन्न वित्तीय वर्षों के आधार पर सारणी संख्या 56 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–56

कानपुर देहात जनपद में व्यावसायिक बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकार की गई जमायें (स्थिति 31 मार्च)

वर्ष	जमा धनराशि (धनराशि करोड रुपये में)	स्वीकार की गई जमाओं में गत वर्ष की तुलना में होने वाली वृद्धि प्रतिशत में
1	2	3
1990	105.90	–
1992	143.19	35.2
1994	154.40	7.8
2000	492.91	219.2
2001	324.22	–34.2
2002	641.71	97.9
2003	702.67	9.5
2004	751.00	6.9
2005	802.00	6.8
2006	848.00	5.7
2007	885.00	4.4

सारणी संख्या 56 से स्पष्ट है कि जनपद कानपुर देहात में व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकार्य की गई जमाओं में समय–समय पर परिवर्तन होता रहा है। वर्ष 1990 की तुलना में वर्ष 2007 में स्वीकार्य की गई जमा राशि में 735.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2001 में स्वीकार्य की गई जमा राशि में कमी हुई है, किन्तु शेष सभी वर्षों में वृद्धि ही स्पष्ट होती है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जनपद में बैंकों द्वारा जमा स्वीकार्य कर लोगों की बचत को गतिशील बनाया है। जिससे निवेश के स्तर में वृद्धि सम्भव हो सकती है।

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश व सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय वर्षों में दिये आंकड़ों पर आधारित

कानपुर क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जमा राशि का स्वरूप :

कानपुर क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा विभिन्न वर्षों में जनता की जमायें स्वीकार की गई है जो विभिन्न जनपदों में भिन्न–भिन्न रही हैं। इन सबका विचार करने के पश्चात् कानपुर क्षेत्र में इन बैंकों द्वारा स्वीकार की गई जमा धनराशि के विवरण को सारणी संख्या 57 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–57

कानपुर क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकार की गई जमायें (स्थिति 31 मार्च)

वर्ष	जमा धनराशि (धनराशि करोड रुपये में)	स्वीकार की गई जमाओं में गत वर्ष की तुलना में होने वाली वृद्धि प्रतिशत में
1	2	3
2001	3019.51	–
2002	3121.79	3.4
2003	3408.61	9.2
2004	3547.84	4.1
2005	3855.10	8.7
2006	4296.60	11.4
2007	5099.63	18.7

सारणी संख्या 57 से यह स्पष्ट है कि विभिन्न जनपदों की भांति सम्पूर्ण कानपुर क्षेत्र में भी व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकार की गई जमा राशि में निरन्तर वृद्धि हुई है किन्तु स्वीकार की गई जमा में होने वाली यह वृद्धि विभिन्न वित्तीय वर्षों में परिवर्तित रही है। जैसा की विभिन्न जनपदों में भी यही स्थिति थी। इन बैंकों द्वारा वर्ष 2001 में जो जमायें स्वीकार की गईं उसके सापेक्ष 2002 में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि 2002 के सापेक्ष 2003 में स्वीकार की गई जमाओं में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2003 के सापेक्ष स्वीकार जमाओं में वर्ष 2004 में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। और वर्ष 2004 के सापेक्ष 2005 में 8.7 प्रतिशत, 2005 के सापेक्ष 2006 में 11.7 प्रतिशत तथा वर्ष 2006 में स्वीकार की गई जमाओं के सापेक्ष वर्ष 2007 में स्वीकार की गई जमाओं में 18.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहीं वर्ष 2001 में स्वीकार की गई जमाओं के सापेक्ष वर्ष 2007 में स्वीकार की गई जमाओं में 69.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश व सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय वर्षों में दिये आंकड़ों पर आधारित

विभिन्न जनपदों के व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जनता से जमा के रूप में प्राप्त धन पिछले पांच वर्षों से क्रमशः बढ़ रहे हैं। यही बात कानपुर परिक्षेत्र के सम्पूर्ण दृष्टि से व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में सही उतरती है। इस प्रकार व्यावसायिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण जमा के रूप में उनकी बचत का गतिशीलन कर सके हैं। बचत के गतिशीलन के परिणामस्वरूप पूंजी निर्माण की गति में वृद्धि होती है और किसी देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी एक आवश्यक तथा अनिवार्य तत्व है जिसके बिना विकास की गति को बढ़ा पाना सम्भव नहीं है। अध्ययन के प्रारम्भ में स्पष्ट की गई परिकल्पनाओं में एक परिकल्पना यह भी है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा कृषकों को मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान किये जाने के परिणामस्वरूप उनके उत्पादन का ढॉचा मजबूत होगा। उत्पादन का ढांचा उस समय विस्तृत और मजबूत हो सकता है जब उसमें पर्याप्त मात्रा में निवेश किया जाय और निवेश बचत के साथ–साथ बचत के गतिशीलन पर निर्भर है। जहां तक बचत और बचत के गतिशीलन का प्रश्न है इस सम्बन्ध में व्यावसायिक बैंक सफल रहे हैं। क्योंकि इनके पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों से यह बात स्पष्ट होती है कि इनके द्वारा लोगों से अधिक से अधिक मात्रा में बचत प्राप्त करने में इन्हें सफलता प्राप्त हुई है। यदि जनपद स्तर पर कहा जाय तो फर्रूखाबाद जनपद के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1990 में जनता से प्राप्त जमा का जो भी स्तर रहा है उसमें 2 वर्षों में (1992 में) इस स्तर में 28.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वहीं वर्ष 2000 में वर्ष 1990 की तुलना में या एक दशक के पश्चात् इन बैंकों द्वारा जनसाधारण से प्राप्त की जाने वाली जमा में 323.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार 17 वर्ष के पश्चात वर्ष 2007 में 1990 की तुलना में यह वृद्धि 421.1 प्रतिशत रही है।

इसी प्रकार की स्थिति कन्नौज जनपद की रही है। वर्ष 2001 से वर्ष 2007 के बीच इन बैंकों से प्राप्त जमा में 67.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इटावा जनपद में वर्ष 1990 में इन बैंकों की बचत का जो स्तर था वह एक दशक या वर्ष 2000 में बढ़कर 339.5 प्रतिशत हो गया। वहीं वर्ष 2000 से वर्ष 2007 के बीच इन बैंकों द्वारा जनता से स्वीकार की गई जमाओं में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि वर्ष 1990 से 2007 तक के स्थिति पर विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि इन 17 वर्षों में जमा के रूप में प्राप्त धन में 581.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

औरैया जनपद में इन बैंकों द्वारा स्वीकार की गई जमाओं में वर्ष 2001 से वर्ष 2007 के बीच 60.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार कानपुर नगर जनपद में व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जमा के रूप में प्राप्त रकम में होने वाली वृद्धि वर्ष 1998 से वर्ष 2007 के बीच 273.5 प्रतिशत रही है।

जहाँ तक कानपुर देहात जनपद का प्रश्न है उसमें बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमा की रकम में 1990 और 2000 के बीच या एक दशक में 365.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। और यदि 17 वर्षों (1990–2007) के बीच की स्थिति पर विचार किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि इन बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमा रकम में 735.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इस प्रकार कानपुर क्षेत्र के विभिन्न व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जमा स्तर में वृद्धि इस बात को स्पष्ट करती है कि ये बैंक ग्रामीण जनता की बचत को गतिशील बनाने में सफल हुई है। बैंकों द्वारा प्राप्त जमा निवेश के लिए प्राप्त होती हैं। निवेश के परिणामस्वरूप उत्पादन के आधार में मजबूती और विस्तार होता है। निवेश की वृद्धि के परिणामस्वरूप किसी देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यदि कृषि क्षेत्र में उत्पादक निवेश के स्तर में वृद्धि होती है तो कृषि का विकास होगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की 'रीढ़' कही जाती है। कृषि विकास के परिणामस्वरूप देश के आर्थिक विकास में सहायता प्राप्त होगी। अतः अध्ययन के प्रारम्भ में स्पष्ट की गई तीसरी परिकल्पना की 'व्यापारिक बैंकों के वित्त के परिणामस्वरूप निजी निवेश स्तर में वृद्धि हुई है।' की सार्थकता सिद्ध होती है।

वर्ष 1990 से 2007 के बीच विभिन्न जनपदों के व्यावसायिक बैंकों में जमा होने वाली वृद्धि को सारणी संख्या 58 से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–58

कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में व्यावसायिक बैंकों की जमा राशि
(स्थिति 31 मार्च)

जनपद का नाम	वर्ष	जमा में वृद्धि प्रतिशत में
1	2	3
1. फर्रूखाबाद	1990–2007	421.1
2. इटावा	1990–2007	581.3
3. कानपुर देहात	1990–2007	735.7
4. कानपुर नगर	1998–2007	273.5
5. औरैया	2001–2007	60.5
6. कन्नौज	2001–2007	67.60

यदि क्षेत्र स्तर पर विचार किया जाये तो व्यावसायिक बैंकों की जमा में निरन्तर वृद्धि स्पष्ट होती है। जिसे सारणी संख्या 59 में स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–59

कानपुर क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों की जमा राशि
(स्थिति 31 मार्च)

वर्ष	जमा राशि (करोड़ रूपये में)		जमा में वृद्धि प्रतिशत में
1	2		3
1990–2000	1990	2000	1990–2000
(तीन जनपद)			
1. फर्रूखाबाद	191.02	808.68	323.3
2. इटावा	155.76	684.58	339.5
3. कानपुर देहात	105.90	492.91	365.4
योग –	**452.68**	**1986.17**	**338.7**

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश व सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय वर्षों में दिये आंकड़ों पर आधारित

नोट– जमा धनराशि में व्यावसायिक बैंकों के साथ–साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का भी जमा सम्मिलित है।

सारणी संख्या–60

कानपुर क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों की जमा राशि (स्थिति 31 मार्च)

वर्ष	जमा राशि (करोड़ रूपये में)		जमा में वृद्धि प्रतिशत में
1	2		3
2001–2007 (सभी जनपद)	2001	2007	2001–2007
1. फर्रूखाबाद	960.65	995.41	3.6
2. कन्नौज	410.30	687.99	67.7
3. इटावा	605.40	1061.16	75.3
4. औरैया	310.06	479.70	54.7
5. कानपुर नगर	408.88	990.37	142.2
6. कानपुर देहात	324.22	885.00	173.0
योग –	**3019.51**	**5099.63**	**68.9**

सारणी संख्या 60 से यह स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में वर्ष 1990 और वर्ष 2000 के दशक में व्यावसायिक बैंकों की जमा राशि में होने वाली दशक वृद्धि 338.7 प्रतिशत रही है। इसके पश्चात वर्ष 2001 से 2007 के बीच जमा राशि में होने वाली वृद्धि 68.9 प्रतिशत रही है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बचत को गतिशील बनाया जा सका है और इस बचत का उत्पादन के कार्यों में प्रयोग कर अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सकता है जिससे व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार के साथ–साथ आर्थिक मजबूती का स्तर भी कायम होगा।

ऋण जमा अनुपात : व्यावसायिक बैंकों के ऋण जमा अनुपात को सारणी संख्या 61 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश व सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय वर्षों में दिये आंकड़ों पर आधारित

नोट– जमा धनराशि में व्यावसायिक बैंकों के साथ–साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का भी जमा सम्मिलित है।

सारणी संख्या–61

कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में ऋण जमा अनुपात

वर्ष	फर्रूखाबाद	कन्नौज	इटावा	औरैया	कानपुर नगर	कानपुर देहात
1	2	3	4	5	6	7
1990	1 : 1.64	–	1 : 2.47	–	–	1 : 1.72
1992	1 : 1.91	–	1 : 2.69	–	–	1 : 1.77
1994	1 : 2.00	–	1 : 2.69	–	–	1 : 1.82
1998	–	–	–	–	1 : 3.65	–
1999	–	–	–	–	1 : 3.11	–
2000	1 : 3.28	–	1 : 4.84	–	1 : 3.62	1 : 3.50
2001	1 : 2.82	1 : 3.56	1 : 3.18	1 : 7.72	1 : 3.50	1 : 1.90
2002	1 : 3.58	1 : 2.76	1 : 4.18	1 : 6.34	1 : 3.60	1 : 3.30
2003	1 : 2.97	1 : 2.72	1 : 4.09	1 : 5.65	1 :3.41	1 : 3.12
2004	1 : 2.81	1 : 2.33	1 : 3.50	1 : 4.56	1 : 298	1 : 2.47
2005	1 : 2.57	1 : 1.94	1 : 3.10	1 : 4.11	1 : 2.61	1 : 2.40
2006	1 : 2.38	1 : 1.82	1 : 3.05	1 : 3.66	1 : 2.05	1 : 1.96
2007	1 : 2.11	1 : 1.85	1 : 2.95	1 : 2.80	1 : 2.58	1 : 1.73

सारणी संख्या 61 से यह स्पष्ट है कि इन बैंकों ने जितनी मात्रा मे ऋण दिया है उससे अधिक मात्रा में ग्रामीण जनता से जमा के रूप में उनकी बचत प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। इस ऋण जमा अनुपात द्वारा भी यह सिद्ध हो जाता है कि व्यावसायिक बैंक ग्रामीण क्षेत्र में ऋण देने के बजाय बचत को गतिशील बनाने में अधिक सफल हुये हैं। अतः अध्ययन के प्रारम्भ में स्पष्ट परिकल्पनाओं में यह परिकल्पना की कि इन बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में उत्पादन के आधार को अधिक मजबूत व विस्तृत बनाने में सहायता प्राप्त हुई है। सिद्ध होती है।

कानपुर क्षेत्र की स्थिति पर विचार किया जाय तो इन बैंकों की ऋण जमा

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश व सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय वर्षों में दिये आंकड़ों पर आधारित

नोट– ऋण जमा अनुपात में व्यावसायिक बैंकों के साथ–साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का भी योगदान सम्मिलित है।

अनुपात में निरन्तर कमी हुई है जिसे सारणी संख्या 62 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–62

कानपुर क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात (स्थिति 31 मार्च)

वर्ष	वितरित ऋण (करोड़ रूपये में)	जमा धनराशि (करोड़ रुपये में)	ऋण जमा अनुपात
1	2	3	4
2001	972.16	3019.51	1 : 3.10
2002	857.29	3121.79	1 : 3.64
2003	1009.62	3408.61	1 : 3.37
2004	1220.61	3547.84	1 : 2.90
2005	1467.46	3855.10	1 : 2.62
2006	1853.00	4296.60	1 : 2.31
2007	2264.39	5099.63	1 : 2.25

सारणी संख्या 62 के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि कानपुर क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों के ऋण जमा अनुपात में दशक 2001 से 2007 के बीच निरन्तर कमी हुई है। वर्ष 2001 में ऋण जमा अनुपात 1 : 3.10 रहा है। जो वर्ष 2007 में कम होकर 1 : 2.25 हो गया है। जो इस बात को स्पष्ट करता है कि इन बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकाधिक मात्रा में ऋण दिया जा रहा है जो ऋण जमा अनुपात के घटते हुये क्रम से स्पष्ट होता है कि इन बैंकों द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिकाधिक मात्रा मं ऋण दिया जा रहा है। जिन उद्देश्यों के लिए इनकी स्थापना की गई थी भले ही विभिन्न जनपदों की स्थिति अलग–अलग रही हो परन्तु इन बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ऋण वितरण अधिक मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र में वित्त प्रदान करके संस्थागत ढांचे का निर्माण करने में सहायता प्राप्त हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में साख के उपयुक्त संसाधनों के विकास न होने के कारण अधिकांश ग्रामीण साख असंगठित स्रोतों से प्राप्त होती थी। अब वह संगठित स्रोतों से प्राप्त होने लगी है। वर्ष 1951–52 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने यह पाया था कि कुल ग्रामीण साख का 92.7 प्रतिशत असंगठित स्रोतों से प्राप्त होता है जिनमें सगे सम्बन्धी, भू–स्वामी, कृषि महाजन, पेशेवर महाजन, व्यापारी एवं कमीशन एजेण्ट व अन्य व्यक्ति थे, और संगठित स्रोतों से ग्रामीण साख का प्राप्त होने वाला हिस्सा 7.3 प्रतिशत था जिनमें सरकार द्वारा, सहकारी

स्रोत – सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश व सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय वर्षों में दिये आंकड़ों पर आधारित

नोट– ऋण जमा अनुपात में व्यावसायिक बैंकों के साथ–साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का भी योगदान सम्मिलित है।

समितियों द्वारा व व्यापारिक बैंक आदि थे। वर्तमान में या अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी की रिपोर्ट के लगभग 5 दशकों के पश्चात इस स्थिति में परिवर्तन हुआ है। उस समय ग्रामीण साख में व्यावसायिक बैंक का हिस्सा 0.9 प्रतिशत था जिसमें अब निश्चित रूप से वृद्धि हुयी है। जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है।

अतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण साख की संरचना को संस्थागत बनाने में व्यावसायिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे अध्ययन के प्रारम्भ में स्पष्ट की गई परिकल्पना की इन बैंकों द्वारा ग्रामीण साख के संस्थागत स्वरूप को विकसित करने में सहायता प्राप्त हुई है। यह सिद्ध हो जाती है।

निष्कर्ष : भारतीय प्रबन्धन के अधीन पहला सीमित दायित्व वाला बैंक अवध कामर्शियल बैंक था जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। इसके बाद सन् 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। बैंकिंग कम्पनी अधिनियम फरवरी 1949 में पारित हुआ जिसे संशोधन के बाद बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के रूप में जाना गया। इस अधिनियम के जरिए बैंकिंग व्यवस्था पर नियमन का कानूनी अधिकार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को मिल गया।

देश के सबसे बड़े बैंक इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1955 में किया गया और इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक आफ इण्डिया कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 1959 में इसके 7 सहयोगी बैंकों का गठन किया गया। आर्थिक विकास में बैंकिंग व्यवस्था का योगदान सुनिश्चित करने के लिए 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश जारी किया गया। जिसके माध्यम से 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया गया और 15 अप्रैल 1990 को 6 अन्य प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

वर्तमान में बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत 218 अनुसूचित (विदेशी बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंक) है। इनमें से 161 सार्वजनिक क्षेत्र के हैं जिसमें 133 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और ये सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि का 75.2 प्रतिशत एकत्र करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे ऋण लेने वालों को और ऋण मुहैया कराने के लिए विशेष रूप से की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा बाकी 28 बैंकों में 19 राष्ट्रीयकृत हैं, 8 एस.बी.आई समूह के व 1 आई.डी.बी.आई. शामिल हैं। और ये सभी तरह का बैंकिंग व्यवसाय करते हैं।

कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में प्रायः लगभग सभी प्रकार के व्यावसायिक बैंक कार्यरत हैं जिनमें से कृषि क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करने का कार्य इन बैंकों की 188 शाखाओं द्वारा किया जा रहा है। सभी इकाइयों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना सीमित साधनों और समय मे सम्भव न होने के कारण इन बैंकों की शाखाओं का चुनाव रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर किया गया है।

वर्तमान अध्ययन में 30 प्रतिशत इकाइयों का रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर चयन किया जायेगा।

वर्तमान अध्ययन में व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 2001 से 2007 तक वितरित ऋण में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में कानपुर क्षेत्र में इन बैंकों द्वारा 972.16 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया था। जो वर्ष 2007 में बढ़कर 2264.39 करोड़ रुपये हो गया।

ऋण वितरण के अतिरिक्त इन बैंकों द्वारा ग्रामीण जनता की बचत भी स्वीकार की जाती हैं। इनके द्वारा स्वीकार की गई बचत में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में इन बैंकों में जनता की बचत की धनराशि 3019.51 करोड़ रुपये थी जो वर्ष 2007 में बढ़कर 5099.63 करोड़ रुपये हो गई।

इस समयावधि के बीच इन बैंकों में जमा धनराशि को सारणी संख्या 57 में स्पष्ट किया गया है। और इस सम्बन्ध में विभिन्न जनपदों की स्थिति को सारणी संख्या 51 से 56 तक स्पष्ट किया गया है।

यदि इन बैंकों के ऋण जमा अनुपात पर विचार किया जाय तो ऋण की तुलना में जमा का अनुपात वृद्धिमान रहा है। वर्ष 2001 में इसका ऋण जमा अनुपात 1 : 3.10 रहा है। जो वर्ष 2007 में कम होकर 1 : 2.25 हो गया है।

कानपुर क्षेत्र की स्थिति पर विचार किया जाय तो बैंकों के ऋण जमा अनुपात में निरन्तर कमी हुई है जिसे सारणी संख्या 62 से स्पष्ट किया गया है।

कानपुर क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण जमा अनुपात में दशक 2001 से 2007 के बीच निरन्तर कमी हुई है। वर्ष 2001 में 1 : 3.10 था। जो वर्ष 2007 में कम होकर 1 : 2.25 हो गया है। जो इस बात को स्पष्ट करता है कि इन बैंकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक ऋण दिया गया है। जो ऋण जमा अनुपात के बढ़ते हुये क्रम से स्पष्ट है।

इन बैंकों द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिकाधिक मात्रा में ऋण दिया जा

रहा है। जिन उद्देश्यों के लिए इनकी स्थापना की गई थी। भले ही विभिन्न जनपदों की स्थिति अलग–अलग रही है परन्तु कानपुर क्षेत्र के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से यह कहा जा सकता है कि इन बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ऋण वितरण अधिकाधिक मात्रा में किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में वित्त प्रदान करने के संस्थागत ढॉचे का निर्माण करने में ये बैंकें सहायक हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में साख में उपयुक्त संस्थाओं के विकास न होने के कारण अधिकांश ग्रामीण साख असंगठित स्रोतों से प्राप्त होती थी। जो अब संगठित स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होने लगी है। वर्ष 1951–52 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने यह पाया था कि कुल ग्रामीण साख का 92.7 प्रतिशत भाग असंगठित स्रोतों से प्राप्त होता है जिनसे सम्बन्धित भू–स्वामी, कृषि महाजन, पेशेवर महाजन, व्यापारी एवं कमीशन एजेण्ट एवं अन्य व्यक्ति थे जो ग्रामीण साख उपलब्ध कराते थे वहीं संगठित स्रोतों से ग्रामीण साख से प्राप्त होने वाला हिस्सा 7.3 प्रतिशत था। जिसमें सरकार, सहकारी समितियां , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व व्यापारिक बैंक शामिल थे। वर्तमान में अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण की रिपोर्ट के लगभग 5 दशकों के पश्चात इस स्थिति में परिवर्तन हुआ है। क्योंकि उस समय (1951–52) ग्रामीण साख में व्यावसायिक बैंक का हिस्सा मात्र 0.9 प्रतिशत था जिसमें अब निश्चित रूप से वृद्धि हुई है।

अतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण साख की संरचना को संस्थागत बनाने में व्यावसायिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें अध्ययन के प्रारम्भ में स्पष्ट की गई परिकल्पना की इन बैंकों द्वारा ग्रामीण साख के संस्थागत स्वरूप को विकसित करने में सहायता प्राप्त हुई है। यह सिद्ध हो जाती है।



अध्याय - पाँच

कृषि साख में व्यापारिक बैंकों का वित्त

अध्याय -पाँच : कृषि शाख में व्यापारिक बैंकों का वित्त

कृषि साख : कृषि साख से अभिप्राय उस साख या वित्त से है जिसके माध्यम से कृषि उत्पादन एवं कृषि से सम्बन्धित अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

ग्रामीण साख की आवश्यकता : ग्रामीण क्षेत्र में साख की आवश्यकता विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होती है। इन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न समयों के आधार पर विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्त प्रदान किया जा रहा है। जिसे निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

1. अल्पकालीन
2. मध्यकालीन
3. दीर्घकालीन

इन तीनों प्रकार के समयों पर आधारित व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण दिये जा रहे हैं। देश की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में देश के विकास के प्रयास किये जा रहे हैं। इसी प्रयास में देश की चौथी पंचवर्षीय योजना इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत देश की गरीबी निवारण के सम्बन्ध में विशिष्ट कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। और ऐसा अनुभव किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गरीबी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रित है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत रखा गया और व्यवसायिक बैंकों को इन क्षेत्रों में अधिकाधिक ऋण प्रदान किये जाने का निर्देश दिया गया। उसी समय से इन बैंकों द्वारा अपने दिये जाने वाले कुल ऋण मे प्राथमिकता क्षेत्र मे दिये जाने वाले ऋण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये कानपुर क्षेत्र के विभिन्न व्यावसायिक बैंकों के द्वारा जो ऋण वितरित किये जा रहे हैं उस ऋण के वितरण को द्वितीयक समंकों से प्राप्त आंकडों के आधार पर कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में विगत कुछ वर्षों में

वितरित ऋण एवं इस वितरित ऋण में होने वाली वार्षिक वृद्धि को बैंक व शाखा संख्याओं के आधार पर प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण को स्पष्ट किया जायेगा। जिसका जनपद के आधार पर क्रमवार विवरण को स्पष्ट किया जा सकता है।

1. फर्रूखाबाद जनपद : फर्रूखाबाद जनपद में कार्यरत बैंक संख्या व उनकी शाखाओं के आधार पर वर्ष 2001–02, 2004–05 व वर्ष 2006–07 में वितरित ऋण एवं वितरित ऋण में बैंक शाखावार प्रगति तथा कुल वितरित ऋण में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण को सारणी संख्या 63 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–63

फर्रूखाबाद जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण(2001–02) स्थिति 31 मार्च 2002 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में प्रति बैंक द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6
1. बैंक आफ इण्डिया	10	382039	328553	86%	36.4%
2. भारतीय स्टेट बैंक	05	266530	218554	82%	25.4%
3. इलाहाबाद बैंक	02	50356	30213	60%	4.8%
4. पंजाब नेशनल बैंक	04	101230	66811	66%	9.6%
5. बैंक आफ बड़ौदा	02	48981	43593	89%	4.7%
6. सेन्ट्रल बैंक	03	90259	78525	87%	8.6%
7. ओ0 बी0 सी0	01	47252	30242	64%	4.5%
8. यूको बैंक	01	25200	20160	80%	2.4%
9. यूनियन बैंक	01	38256	35578	93%	3.6%
योग– 09	**29**	**1050103**	**852229**	**81.2%**	**100%**

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय फतेहगढ़ फर्रूखाबाद द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2001–02

सारणी संख्या 63 से यह स्पष्ट है कि फर्रूखाबाद जनपद में वित्तीय वर्ष 2001–02 में व्यावसायिक बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा 1050103 हजार रुपये का ऋण वितरित किया इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंकों का 2.4 प्रतिशत से 36.4 प्रतिशत तक का योगदान रहा। और वितरित ऋण में से 852229 हजार रुपये प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किये गये। जो कुल वितरित ऋण का 81.2 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2004–05 में जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण को सारणी संख्या 64 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–64

फर्रूखाबाद जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण(2004–05)
स्थिति 31 मार्च 2002 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में प्रति बैंक द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में	वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि % में
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक आफ इण्डिया	10	716176	615405	86.0%	35.6%	87.5%
2. भारतीय स्टेट बैंक	05	543279	44617	81.8%	27.0%	103.8%
3. इलाहाबाद बैंक	02	81221	52947	62.7%	4.1%	61.3%
4. पंजाब नेशनल बैंक	04	185835	126524	68.1%	9.3%	83.6%
5. बैंक आफ बड़ौदा	02	117415	110123	93.8%	5.8%	139.7%
6. सेन्ट्रल बैंक	03	171237	146281	85.4%	8.5%	89.7%
7. ओ0 बी0 सी0	01	72378	47806	66.0%	3.6%	53.2%
8. यूको बैंक	01	41527	34092	82.1%	2.1%	64.8%
9. यूनियन बैंक	01	80161	77008	96.1%	4.0%	109.5%
योग– 09	**29**	**2009229**	**1652803**	**82.3%**	**100%**	**91.3%**

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय फतेहगढ़ फर्रूखाबाद द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2004–05

सारणी संख्या 64 से यह स्पष्ट है कि फर्रूखाबाद जनपद में वित्तीय वर्ष 2004–05 में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा 2009229 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये । इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंकों का 2.1 प्रतिशत से 35.6 प्रतिशत तक का योगदान है। और इस वितरित ऋण में 1652803 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र की आवश्यकता पूर्ति के लिए वितरित किये गये। जो जनपद में कुल वितरित ऋण का 82.3 प्रतिशत है तथा जनपद में वित्तीय वर्ष 2001–02 में वितरित ऋण की अपेक्षा इस वित्तीय वर्ष में वितरित ऋण में 91.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और प्रत्येक बैंक द्वारा वितरित ऋण में परिवर्तन के साथ वृद्धि हुई है।

जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में वितरित ऋण के विवरण को सारणी संख्या 65 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–65

फर्रूखाबाद जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण(2006–07)
स्थिति 31 मार्च 2002 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में प्रति बैंक द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में	वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि % में
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक आफ इण्डिया	10	1064491	933710	86.8%	35.7%	48.6%
2. भारतीय स्टेट बैंक	05	828962	639853	76.3%	28.1%	54.4%
3. पंजाब नेशनल बैंक	04	265627	208457	78.5%	8.9%	42.9%
4. सेन्ट्रल बैंक	03	262034	234337	89.4%	8.8%	53.0%
5. बैंक आफ बड़ौदा	02	127406	114851	90.1%	4.3%	8.5%
6. इलाहाबाद बैंक	02	191482	145550	76.0%	6.4%	135.7%
7. ओ0 बी0 सी0	01	92835	87597	94.4%	3.1%	28.3%
8. यूको बैंक	01	48648	45823	94.2%	1.6%	17.2%
9. यूनियन बैंक	01	92715	84433	91.1%	3.1%	15.7%
योग– 09	**29**	**2984200**	**2494608**	**83.4%**	**100%**	**48.5%**

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय फतेहगढ़ फर्रूखाबाद द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2006–07

सारणी संख्या 65 से यह स्पष्ट है कि फर्रूखाबाद जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा 2984200 हजार रुपये का ऋण वितरित किया गया। इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंकों का 1.6 प्रतिशत से 35.7 प्रतिशत तक का योगदान रहा है। समस्त बैंकों द्वारा वितरित ऋण में 2494608 हजार रुपये के ऋण या कुल वितरित ऋण का 83.4 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किये गये। और वित्तीय वर्ष 2004–05 में वितरित ऋण की अपेक्षा जनपद में इस वित्तीय वर्ष में वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि 48.5 प्रतिशत की रही है। जिसमें विभिन्न बैंक शाखाओं का अलग–अलग स्तर रहा है। वितरित ऋण में होने वाली यह वृद्धि यह सिद्ध करती है कि जनपद में वितरित ऋण में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

जनपद में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा जो ऋण वितरित किया जा रहा है। इस वितरित ऋण में से जो धनराशि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान की जा रही है वह विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वितरित की जा रही है। जिसमें कृषि क्षेत्र, लघु उद्योग व अन्य प्राथमिकता क्षेत्र प्रमुख रूप से हैं। इन सभी क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2006–07 में जनपद में कार्यरत विभिन्न व्यावसायिक बैंक संख्या व उनकी शाखाओं द्वारा जो ऋण वितरित किया जा रहा है। उसके वितरण के स्तर व प्राथमिकता प्राप्त के सापेक्ष कृषि क्षेत्र में प्रतिशत, लघु क्षेत्र में प्रतिशत व अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में क्या प्रतिशत रहा है इसके विवरण को तथा विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा वितरित ऋण में से किस बैंक शाखा द्वारा किस क्षेत्र को सबसे अधिक अपने वितरित ऋण का भाग दिया गया है। इसके विवरण को भी स्पष्ट किया जायेगा तथा यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि किस बैंक ने किस क्षेत्र में अपने वितरित ऋण का सबसे कम योगदान किया है। इन सबके विवरण को सारणी संख्या 66 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–66

फर्रूखाबाद जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का उद्देश्य के आधार पर वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र मे वितरि˜ ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %	कृषि क्षेत्र में से फसली ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %	लघु उद्योग में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. बैंक आफ इण्डिया	10	933710	734227	78.6%	370052	50.4%	80439	8.6%	119044	12.8%
2. भारतीय स्टेट बैंक	05	639853	385954	60.3%	87746	22.7%	62533	9.8%	191366	29.9%
3. पंजाब नेशनल बैंक	04	208454	92041	44.2%	26115	28.4%	76558	36.7%	39858	19.1%
4. सेन्ट्रल बैंक	03	234337	126488	54.0%	23006	18.2%	11335	4.8%	96514	41.2%
5. बैंक आफ बड़ौदा	02	114851	52064	45.3%	826	1.6%	20318	17.7%	42469	37.0%
6. इलाहाबाद बैंक	02	145550	74271	51.0%	19794	26.6%	6013	4.1%	65266	44.9%
7. यूनियन बैंक	01	84433	41133	48.7%	13780	33.5%	11200	13.3%	32100	38.0%
8. ओ0बी0सी0	01	87597	4888	5.6%	0	0	4950	5.6%	77759	88.8%
9. यूको	01	45823	6485	14.2%	2215	34.2%	3068	6.7%	36270	79.1%
योग– 09	**29**	**2494608**	**1517551**	**60.8%**	**543534**	**35.8%**	**276414**	**11.1%**	**700646**	**28.1%**

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय फतेहगढ़ फर्रूखाबाद द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2006–07

सारणी संख्या 66 से यह स्पष्ट है कि फर्रूखाबाद जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में 2494608 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। इस वितरित ऋण में से 1517551 हजार रुपये के ऋण कृषि क्षेत्र की आवश्यकता पूर्ति हेतु वितरित किये गये। जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 60.8 प्रतिशत है। और कृषि क्षेत्र में इस वितरित ऋण का 543534 हजार रुपये के फसली ऋण दिये गये जो कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का 35.8 प्रतिशत है तथा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में से 276414 हजार रुपये के ऋण लघु उद्योग क्षेत्र के आवश्यकता पूर्ति हेतु वितरित किये गये जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 11.1 प्रतिशत है। तथा शेष प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 700646 हजार रुपये अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वितरित ऋण का 28.1 प्रतिशत है। इस प्रकार प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित होने वाले ऋण में सबसे अधिक ऋण कृषि क्षेत्र की आवश्यकता पूर्ति हेतु वितरित किये गये। जो इस बात को स्पष्ट करता है कि वित्तीय वर्ष 1950–51 में जहां कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति असंगठित स्रोतों से होती थी आज वह स्थान संस्थागत स्रोतों ने ले लिया है। जिसमें व्यावसायिक बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा ही यह ऋण वितरित किये गये हैं। जनपद में वितरित इस ऋण में विभिन्न बैंक व उनकी शाखाओं का अलग–अलग स्तर रहा है। जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग कृषि क्षेत्र को अपने वितरित ऋण का बैंक आफ इण्डिया ने वितरित किया वहीं कृषि क्षेत्र में अपने वितरित ऋण का सबसे कम भाग ऋण का वितरण ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स द्वारा किया गया। कृषि क्षेत्र के अलावा जो लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण वितरित किये गये उसमें किसी बैंक द्वारा अपने प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का लघु उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक ऋण बैंक आफ बड़ौदा द्वारा वितरित किया गया। जो अन्य बैंकों के सापेक्ष अधिक रहा है। वहीं लघु उद्योग क्षेत्र में सबसे कम ऋण का वितरण इलाहाबाद बैंक द्वारा किया गया। इसके पश्चात् अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में सबसे अधिक ऋण का वितरण ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स द्वारा किया गया जबकि इसी क्षेत्र में सबसे कम ऋण का वितरण बैंक आफ इण्डिया द्वारा किया गया। इस प्रकार सारणी से यह स्पष्ट है कि फर्रूखाबाद जनपद में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वितरित ऋण का दूसरा बड़ा भाग अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को दिया गया जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का सहायक सिद्ध होता है।

2. कन्नौज जनपद : कन्नौज जनपद में वित्तीय वर्ष 2001–02, 2004–05 व 2006–07 में वितरित ऋण के विवरण व शाखा संख्या आदि का विश्लेषण विभिन्न सारणी के माध्यम से किया जायेगा। इसी को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2001–02 में कार्यरत बैंक संख्याओं व शाखा संख्याओं के आधार पर जनपद में वितरित ऋण व इस वितरित ऋण का प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण तथा कुल वितरित ऋण से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वितरित ऋण के प्रतिशत को सारणी संख्या 67 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–67

कन्नौज जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण(2001–02)
स्थिति 31 मार्च 2002 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में प्रति बैंक द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6
1. बैंक आफ इण्डिया	08	254300	223784	88.0%	38.4%
2. भारतीय स्टेट बैंक	07	269700	167760	80.0%	31.7%
3. इलाहाबाद बैंक	04	81200	77140	95.0%	12.3%
4. सेन्ट्रल बैंक	01	25600	23296	91.0%	3.9%
5. बैंक आफ बड़ौदा	03	48300	44919	93.0%	7.2%
6. ओ0बी0सी0	01	43200	49540	70.0%	6.5%
योग– 06	**24**	**662300**	**566439**	**85.5%**	**100%**

सारणी संख्या 67 से यह स्पष्ट है कि कन्नौज जनपद में वित्तीय वर्ष 2001–02 में व्यावसायिक बैंकों द्वारा 662300 हजार रुपये के ऋण वितरित किये। इस वितरित ऋण में 566439 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किये थे। इस सम्पूर्ण वितरित ऋण में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों का 3.9 प्रतिशत से 38.4 प्रतिशत तक का योगदान रहा है। तथा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण कुल ऋण का 85.5 प्रतिशत रहा है। जनपद में इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंक शाखाओं का अलग–अलग योगदान रहा है। जैसा कि सारणी से स्पष्ट है।

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय कन्नौज द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2001–02

कन्नौज जनपद में वित्तीय वर्ष 2004–05 में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण तथा वित्तीय वर्ष 2001–02 में वितरित ऋण के सापेक्ष इस वर्ष वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि को सारणी संख्या 68 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–68

कन्नौज जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण(2004–05) स्थिति 31 मार्च 2005 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में प्रति बैंक द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में	वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि % में
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक आफ इण्डिया	08	508000	452120	89%	36.4%	99.8%
2. भारतीय स्टेट बैंक	07	472000	382320	81%	33.8%	125.1%
3. इलाहाबाद बैंक	04	186500	177175	95%	13.4%	129.7%
4. सेन्ट्रल बैंक	01	53000	50350	95%	3.8%	107.0%
5. बैंक आफ बड़ौदा	03	78900	70221	89%	5.6%	63.4%
6. ओ0 बी0 सी0	01	98400	73800	75%	7.0%	127.8%
योग– 06	**24**	**1396800**	**1205986**	**86.3%**	**100%**	**110.9%**

सारणी संख्या 68 से यह स्पष्ट है कि कन्नौज जनपद में वित्तीय वर्ष 2004–05 में 1396800 हजार रुपये के व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण वितरित किये गये इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंकों का 3.8 प्रतिशत से 36.4 प्रतिशत का योगदान रहा है। और सम्पूर्ण वितरित ऋण में 1205986 हजार रुपये प्राथमिकता क्षेत्र की आवश्यकता पूर्ति हेतु वितरित किये गये जो कुल वितरित ऋण का 86.3 प्रतिशत है। और वित्तीय वर्ष 2001–02 में वितरित ऋण की अपेक्षा इस वर्ष वितरित ऋण में 110.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो इस बात का संकेत है कि जनपद में दिन–प्रतिदिन व्यावसायिक बैंकों द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वितरित ऋण में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जनपद में विभिन्न बैंकों द्वारा वितरित इस ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है। सभी बैंकों द्वारा एक समान ऋण का वितरण नहीं किया गया है जैसा की सारणी से स्पष्ट है।

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय कन्नौज द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2004–05

कन्नौज जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों द्वारा ग्रामीण वित्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु वितरित ऋण एवं वित्तीय वर्ष 2004–05 में वितरित ऋण के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष में वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि को सारणी संख्या 69 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–69

कन्नौज जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण(2006–07) स्थिति 31 मार्च 2007 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में प्रति बैंक द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में	वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि % में
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक आफ इण्डिया	08	1039400	915900	88%	38.4%	104.6%
2. भारतीय स्टेट बैंक	07	931000	783500	84%	34.5%	97.2%
3. इलाहाबाद बैंक	04	350800	343600	98%	12.9%	88.1%
4. सेन्ट्रल बैंक	01	81300	76800	94%	3.0%	53.4%
5. बैंक आफ बड़ौदा	03	159200	146400	92%	5.9%	101.8%
6. ओ0 बी0 सी0	01	90900	67000	74%	3.3%	–7.6%
7. सिन्डीकेट बैंक	02	56200	47100	84%	2.0%	–
योग– 07	**26**	**2708800**	**2380300**	**88%**	**100%**	**93.9%**

सारणी संख्या 69 के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि कन्नौज जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में 2708800 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंक शाखाओं का 2.0 प्रतिशत से 38.4 प्रतिशत तक वित्तीय योगदान रहा है। तथा इस वितरित ऋण में से 2380300 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र की आवश्यकता पूर्ति के लिए वितरित किये गये जो कुल वितरित ऋण का 88 प्रतिशत है। जनपद में वित्तीय वर्ष 2004–05 में वितरित ऋण के सापेक्ष इस वर्ष वितरित ऋण में 93.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो इस बात का संकेत है कि व्यावसायिक बैंकों के द्वारा कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय कन्नौज द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2006–07

जनपद में इस वितरित ऋण में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का अलग–अलग योगदान रहा है। इस वितरित ऋण में सबसे अधिक योगदान बैंक आफ इण्डिया का रहा है जिसने कुल वितरित ऋण का 38.4 प्रतिशत ऋण वितरण में योगदान किया। इसके बाद स्टेट बैंक आफ इण्डिया का क्रम है। जिसने कुल वितरित ऋण का 34.5 प्रतिशत वित्तीय योगदान दिया वहीं इन विभिन्न बैंको द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में इलाहाबाद बैंक द्वारा वितरित किया गया। जिसने अपने वितरित ऋण का 98 प्रतिशत भाग प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किया। इसके बाद सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया का स्थान है जिसने अपने वितरित ऋण का 94 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति हेतु ऋण वितरित किया। वहीं जनपद में वित्तीय वर्ष 2004–05 में वितरित ऋण की अपेक्षा सबसे ज्यादा वित्तीय वर्ष 2006–07 में वितरित ऋण में बैंक आफ इण्डिया का योगदान रहा है जिसने वर्ष 2004–05 में वितरित ऋण के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2006–07 में 104.6 प्रतिशत अधिक ऋण का वितरण किया वहीं दूसरे क्रम पर बैंक आफ बड़ौदा का स्थान है जिसने वर्ष 2004–05 में वितरित ऋण के सापेक्ष 101.8 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण वितरित किये जबकि ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स एक ऐसी बैंक है जिसने 2004–05 में जो ऋण वितरित किये थे उसके सापेक्ष 2006–07 में वितरित ऋण में कमी की है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न वर्षों में वितरित ऋण के स्तर में असमानता रही है किन्तु इतना अवश्य सत्य है कि इन बैंकों द्वारा वितरित ऋण में लगभग निरन्तर वृद्धि ही हो रही है। जिससे कि इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सार्थकता सिद्ध होती है।

कन्नौज जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में जो ऋण वितरित किया गया है उस वितरित ऋण से जो धनराशि प्राथमिकता क्षेत्र को दी गयी है वह विभिन्न उद्‌देश्यों को ध्यान में रखकर दी गई है जिसके अन्तर्गत प्रमुख रूप से कृषि क्षेत्र, लघु उद्योग, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आदि का स्थान है। इन सभी क्षेत्रों में जनपद में कार्यरत व्यवसायिक बैंको के द्वारा निरन्तर ऋण का वितरण किया जा रहा है। इनके द्वारा वितरित ऋण के विवरण व विभिन्न क्षेत्रों में दिये गय ऋण का कुल प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का हिस्सा प्रतिशत के रूप में स्पष्ट करने के लिए सारणी संख्या 70 का सहारा लिया जा सकता है।

सारणी संख्या–70

कन्नौज जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का उद्देश्य के आधार पर वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र मे वितरित ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %	कृषि क्षेत्र में से फसली ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %	लघु उद्योग में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. बैंक आफ इण्डिया	08	915900	603400	65.9%	301000	49.9%	118700	13.0%	193800	21.1
2. भारतीय स्टेट बैंक	07	783500	579000	73.9%	287000	49.6%	133200	17.0%	71300	9.1
3. इलाहाबाद बैंक	04	343600	302700	88.1%	150000	49.6%	16500	4.8%	24400	7.1
4. सेन्ट्रल बैंक	01	76800	64400	83.9%	42200	65.5%	5400	7.0%	7000	9.1
5. बैंक आफ बड़ौदा	03	146400	68500	46.8%	21000	30.7%	3900	2.7%	74000	50.5
6. ओ0बी0सी0	01	67000	36200	54.0%	17000	47.0%	2700	4.0%	28100	42.0
7. सिन्डीकेट	02	47100	33600	71.3%	11000	32.7%	1000	2.1%	12500	26.6
योग– 07	**26**	**3280300**	**1687800**	**70.9%**	**829200**	**49.1%**	**281400**	**11.8%**	**411100**	**17.3**

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय कन्नौज द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2006–07

सारणी संख्या 70 से यह स्पष्ट है कि कन्नौज जनपद में वित्तीय वर्ष 2006—07 में 2380300 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये। जो जनपद में कार्यरत 7 बैंकों की 26 शाखाओं द्वारा प्रदान किये गये हैं। इस वितरित ऋण में 1687800 हजार रुपये के ऋण कृषि क्षेत्र को उसकी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु दिये गये जिससे कि कृषि क्षेत्र में निवेश का स्तर बढ़ सके जिससे कृषि उत्पादन में ढांचागत सुधार के साथ—साथ नवीन तकनीक का प्रयोग किया जा सके इसके लिए व्यावसायिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को यह ऋण वितरित किये गये इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंकों द्वारा असमानता के आधार पर वित्तीय योगदान किया गया है। जिसमें सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का इलाहाबाद बैंक द्वारा दिया गया। जो इस बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का 88.1 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र को दिया गया। कृषि क्षेत्र में यह वितरित ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 70.9 प्रतिशत है। बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को जो ऋण वितरित किया गया है उसमें से 829200 हजार या कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का 49.1 प्रतिशत के फसली ऋण वितरित किये गये। विभिन्न बैंकों द्वारा वितरित कृषि ऋण से फसली ऋण में सबसे अधिक वित्तीय योगदान अपने वितरित ऋण का बैंक आफ इण्डिया का रहा है। जिसने कृषि क्षेत्र में अपने वितरित ऋण का 49.9 प्रतिशत के फसली ऋण दिये यह फसली ऋण कृषि क्षेत्र में तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ—साथ अन्य छोटे मोटे कार्यों को करने के लिए दिये गये हैं। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 281400 हजार रुपये के ऋण लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये। जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 11.8 प्रतिशत हैं इस वितरित ऋण में किसी बैंक द्वारा सबसे अधिक ऋण का वितरण 17 प्रतिशत स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को दिया गया। लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में सहायक के रूप में कार्य करते हैं, प्राथमिकता क्षेत्र का शेष भाग अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किया गया जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 17.3 प्रतिशत या 411100 हजार रुपये है। अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत भी कृषि क्षेत्र को दिये गये ऋण का अप्रत्यक्ष हिस्सा मानते हैं क्योंकि इसके अन्तर्गत जो ऋण वितरित किये गये हैं वह किसी न किसी रूप में कृषि क्षेत्र से ही सम्बद्ध हैं। अतः कहा जा सकता है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा जनपद में ग्रामीण शाख की उपलब्धता में निरन्तर बढ़ते हुये क्रम मे योगदान दिया है। जिससे कि असंगठित स्रोतों के शोषण से एक सीमा तक बचा जा सका है।

3. इटावा जनपद : इटावा जनपद में 8 व्यावसायिक बैंक कार्यरत हैं। जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को साख उपलब्ध कराया जा रहा है। जनपद में वित्तीय वर्ष 2001–02 में 31 मार्च तक विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा वितरित ऋण के विवरण को सारणी संख्या 71 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–71

इटावा जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण(2001–02)
स्थिति 31 मार्च 2002 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में प्रति बैंक द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6
1. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	15	640600	265257	41.4%	57.1%
2. सेन्ट्रल बैंक	13	215700	156979	72.8%	18.9%
3. बैंक आफ बड़ौदा	02	91400	24526	26.8%	8.1%
4. पंजाब नेशनल बैंक	02	41000	18336	44.7%	3.8%
5. इलाहाबाद बैंक	02	32000	19316	60.4%	2.9%
6. बैंक आफ इण्डिया	01	72700	25541	35.1%	6.6%
7. यूनियन बैंक	01	29400	4888	16.6%	2.6%
योग– 07	**36**	**1122800**	**514843**	**45.9%**	**100%**

सारणी संख्या 71 से यह स्पष्ट है कि इटावा जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2001–02 में 1122800 हजार रुपये के ऋण वितरित किये। इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंकों का 2.6 प्रतिशत से 57.1 प्रतिशत के बीच योगदान रहा है जिसमें सबसे अधिक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया का योगदान है। जिसके द्वारा कुल वितरित ऋण का 57.1 प्रतिशत ऋण वितरित किया गया। जनपद में वितरित इस ऋण से 514843 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये जो कुल वितरित ऋण का 45.9 प्रतिशत है। प्राथमिकता क्षेत्र में किसी बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग इलाहाबाद बैंक द्वारा 60.4 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को दिया गया।

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय इटावा द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2001–02

इटावा जनपद में वित्तीय वर्ष 2004–05 में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण एवं इस वितरित ऋण में वर्ष 2001–02 में वितरित ऋण के सापेक्ष होने वाली वृद्धि को सारणी संख्या 72 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–72

इटावा जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण(2004–05) स्थिति 31 मार्च 2005 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में प्रति बैंक द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में	वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि % में
1	2	3	4	5	6	7
1. सेन्ट्रल बैंक	14	450862	184870	41.0%	21.9%	109.0%
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	15	1039602	332378	32.0%	50.6%	62.3%
3. इलाहाबाद बैंक	03	127333	39564	31.2%	6.2%	297.9%
4. बैंक आफ इण्डिया	01	178036	81564	45.8%	8.6%	144.9%
5. बैंक आफ बड़ौदा	02	131455	27591	21.0%	6.4%	43.8%
6. पंजाब नेशनल बैंक	03	73939	16737	22.6%	3.6%	80.3%
7 यूनियन बैंक	01	50843	19762	38.9%	2.5%	72.9%
8.. केनरा बैंक	01	4106	165	4.0%	0.2%	–
योग– 08	**40**	**2056176**	**202631**	**34.3%**	**100%**	**83.1%**

सारणी संख्या 72 से यह स्पष्ट है कि इटावा जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 में 2056176 हजार रुपये के ऋण वितरित किये। इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंक। का 0.2 प्रतिशत से 50.6 प्रतिशत तक का वित्तीय योगदान रहा जिसमें सबसे अधिक ऋण का वितरण स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा किया गया। इस वितरित ऋण में से 702631 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किये गये। जो कुल वितरित ऋण का 34.3 प्रतिशत है। प्राथमिकता क्षेत्र में बैंक आफ इण्डिया द्वारा अपने वितरित ऋण का सर्वाधिक 45.8 प्रतिशत ऋण का वितरण किया गया। जबकि केनरा बैंक के द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे कम केवल 4 प्रतिशत धन का वितरण ही प्राथमिकता क्षेत्र को किया गया। यद्यपि बैंकों का

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय इटावा द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2004–05

राष्ट्रीयकरण इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया गया था कि ये बैंकें ज्यादा से ज्यादा अपने वितरित ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदान करें किन्तु इटावा जनपद में यह स्थिति सारणी के माध्यम से स्पष्ट नहीं होती है इसका कारण यह रहा है कि इटावा जनपद में कार्यरत बैंकों का एक बड़ा हिस्सा इटावा नगर में स्थित है जो प्राथमिकता क्षेत्र की अपेक्षा गैर प्राथमिकता क्षेत्र को ज्यादा मात्रा में ऋण प्रदान करता है क्योंकि समग्र बैंकों का एक साथ अध्ययन किया गया है। इसलिए जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण बैंकों द्वारा कुल वितरित ऋण का लगभग 40 प्रतिशत से कम भाग ही प्राप्त हो सका है। जनपद में वित्तीय वर्ष 2004–05 में जो ऋण वितरित किया गया है वह वित्तीय वर्ष 2001–02 में वितरित ऋण की अपेक्षा 83.1 प्रतिशत अधिक रहा है जो इस बात का संकेत है कि जनपद में वितरित ऋण में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण के विवरण को सारणी संख्या 73 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–73

इटावा जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण(2006–07)
स्थिति 31 मार्च 2007 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में प्रति बैंक द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में	वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि % में
1	2	3	4	5	6	7
1. सेन्ट्रल बैंक	14	677783	507887	74.9%	21.9%	50.3%
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	15	1437272	1168082	81.3%	46.4%	38.3%
3. इलाहाबाद बैंक	04	275274	223617	81.2%	8.9%	116.2%
4. बैंक आफ इण्डिया	02	277651	197733	71.2%	9.0%	56.0%
5. बैंक आफ बड़ौदा	02	215211	78580	36.5%	7.0%	63.7%
6. पंजाब नेशनल बैंक	03	109459	60310	55.0%	3.5%	48.0%
7 यूनियन बैंक	01	80172	75794	94.5%	2.6%	57.7%
8.. केनरा बैंक	01	21394	9862	46.1%	0.7%	421.0%
योग– 08	**42**	**3094216**	**2321865**	**75.1%**	**100%**	**50.5%**

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय इटावा द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2006–07

सारणी संख्या 73 से यह स्पष्ट है कि इटावा जनपद में वित्तीय वर्ष 2006—07 में व्यावसायिक बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा 3094216 हजार रुपये के ऋण वितरित किये। इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंकों का 0.7 प्रतिशत से 46.4 प्रतिशत तक का वित्तीय योगदान रहा है। इस वितरित ऋण में सबसे अधिक वित्तीय योगदान 46.4 प्रतिशत स्टेट बैंक आफ इण्डिया व 21.9 प्रतिशत सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया का रहा है। जनपद में वितरित इस ऋण में से 2321865 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए दिये गये। जो कुल वितरित ऋण का 75.1 प्रतिशत है। प्राथमिकता क्षेत्र में सबसे अधिक किसी बैंक के द्वारा अपने वितरित ऋण का 94.5 प्रतिशत यूनियन बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिया गया। इसके बाद 81.3 प्रतिशत स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिया गया। जनपद में वित्तीय वर्ष 2004—05 में वितरित ऋण के सापेक्ष इन बैंक संस्थाओं ने वित्तीय वर्ष 2006—07 में वितरित ऋण में 50.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जनपद में वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि इस बात को स्पष्ट करती है कि व्यवसायिक बैंकों द्वारा अपने वितरित ऋण में निरन्तर वृद्धि कर रहे हैं। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र की साख आवश्यकता की पूर्ति हो सके। वहीं यदि हम वर्ष 2001—02 में वितरित ऋण के सापेक्ष वर्ष 2006—07 में वितरित ऋण की तुलना करे तो कहा जा सकता है कि वर्ष 2001—02 से 2006—07 के बीच व्यावसायिक बैंकों द्वारा 175.6 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण वितरित किये गये। जो इस बात को स्पष्ट करता है कि वितरित ऋण में जनपद मे निरन्तर वृद्धि हो रही है।

इटावा जनपद में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा जो ऋण वितरित किये जा रहे हैं वह दो क्षेत्रों को ध्यान में रखकर दिये जा रहे हैं। जो गैर प्राथमिकता क्षेत्र व प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं क्योंकि अध्ययन के क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था/कृषि अर्थव्यवस्था होने के कारण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का अध्ययन किया जा रहा है। इसलिए जनपद में जो ऋण वितरित किया गया है उसमें से प्राथमिकता क्षेत्र को जितना ऋण वितरित किया गया है। उसके विवरण को विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सारणी संख्या 74 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–74

इटावा जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का उद्देश्य के आधार पर वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र मे वितरित ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %	कृषि क्षेत्र में से फसली ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %	लघु उद्योग में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. सेन्ट्रल बैंक	14	507887	367607	72.4%	62427	17.0%	24492	4.8%	115788	22.8%
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	15	1168.82	747071	64.0%	136679	18.3%	244255	20.9%	176756	15.1%
3. इलाहाबाद बैंक	04	22361⁷	191973	85.8%	20652	10.8%	5051	2.3%	26593	13.9%
4. बैंक आफ इण्डिया	02	197733	109914	55.6%	5669	5.2%	38393	19.4%	49426	25.1%
5. बैंक आफ बड़ौदा	02	78580	10239	13.0%	900	8.8%	19294	24.6%	49047	62.4%
6. पंजाब नेशनल बैंक	03	60310	22036	36.5%	3315	15.0%	10889	18.1%	27385	45.4%
7. यूनियन बैंक	01	75794	52863	69.8%	1329	2.5%	4113	5.4%	18881	24..9%
8. केनरा बैंक	01	9862	4964	50.3%	0	0	1067	10.8%	3831	38.9%
योग– 07	**42**	**2321865**	**1506667**	**64.9%**	**230971**	**15.3%**	**347554**	**15.0%**	**467644**	**20.1%**

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय इटावा द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2006–07

सारणी संख्या 74 से यह स्पष्ट है कि इटावा जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में व्यावसायिक बैंकों द्वारा 2321865 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किये गये इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंक शाखाओं का योगदान रहा है। यह वितरित ऋण विभिन्न वर्गों में विभक्त है। जिसमें 1506667 हजार रुपये कृषि क्षेत्र में जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 64.9 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण में किसी बैंक शाखा द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित अपने ऋण का 85.8 प्रतिशत ऋण का वितरण इलाहाबाद बैंक द्वारा दिया गया। इसके बाद सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा भी अपने प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 72.4 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र को दिया गया। जनपद में कृषि क्षेत्र में वितरित इस ऋण में से 230971 हजार रुपये के फसली ऋण दिये गये जो कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का 15.3 प्रतिशत है। फसली ऋण के रूप में किसी बैंक शाखा द्वारा कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण में से सबसे अधिक फसली ऋण स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा 18.3 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का फसली ऋण दिये गये। इसके बाद सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा 17 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का फसली ऋण दिया गया। जबकि केनरा बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण में कोई भी फसली ऋण नहीं दिये गये। जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का कृषि क्षेत्र के अलावा लघु उद्योग क्षेत्र में 347554 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 15 प्रतिशत है। लघु उद्योग क्षेत्र में वितरित इस ऋण में सबसे अधिक योगदान बैंक आफ बड़ौदा द्वारा 24.6 प्रतिशत दिया गया। जबकि दूसरे क्रम पर 20.9 प्रतिशत ऋण का योगदान सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा किया गया। जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में से शेष धनराशि 467644 हजार रुपये या प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 20.1 प्रतिशत भाग अन्य प्राथमिकता क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु वितरित किये गये। अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में बैंक आफ बड़ौदा द्वारा अपने वितरित ऋण का 62.4 प्रतिशत ऋण अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को दिया गया। इस प्रकार सारणी से यह स्पष्ट है कि इटावा जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में सबसे अधिक ऋण कृषि क्षेत्र को दिया गया। इसके बाद अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को दिया गया जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक धन्धे के रूप में कार्यरत हैं। और इसके बाद लघु एवं कुटीर उद्योग की आवश्यकता पूर्ति के लिए ऋण का वितरण किया गया। यह भी ऋण कृषि क्षेत्र या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ही अधीन आता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए निरन्तर ऋणों के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

4. औरैया जनपद : औरैया जनपद में विभिन्न बैंकों की 28 शाखायें कार्यरत हैं जिनके द्वारा ग्रामीण साख उपलब्ध कराया जा रहा है। इन विभिन्न कार्यरत व्यावसायिक बैंक शाखाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2001–02, 2004–05 व 2006–07 में वितरित ऋण एवं तुलनात्मक रूप से वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि को स्पष्ट किया जाना है। इसी को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2001 –02 में जनपद में कार्यरत बैंक शाखाओं के द्वारा वितरित ऋण के विवरण को सारणी संख्या 75 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–75

औरैया जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण(2001–02)
स्थिति 31 मार्च 2002 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में प्रति बैंक द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6
1. सेन्ट्रल बैंक	19	152532	111230	72.9%	41.4%
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	05	160325	90305	56.3%	43.5%
3. इलाहाबाद बैंक	01	25256	13256	52.5%	6.9%
4. पंजाब नेशनल बैंक	03	30210	9090	30.1%	8.2%
योग– 04	**28**	**368323**	**223881**	**60.8%**	**100%**

सारणी संख्या 75 से यह स्पष्ट है कि औरैया जनपद में वित्तीय वर्ष 2001–02 में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा 368323 हजार रुपये के ऋण वितरित किये, इस वितरित ऋण में विभिन्न बैकों का 6.9 प्रतिशत से 43.5 प्रतिशत तक का वित्तीय योगदान रहा है। जिसमें सबसे अधिक स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा कुल वितरित ऋण का 43.5 प्रतिशत ऋण दिया गया वहीं दूसरे क्रम पर कुल वितरित ऋण का 41.4 प्रतिशत ऋण सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिया गया। जनपद में वितरित इस ऋण में से 223881 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदान किये गये। जो कुल वितरित ऋण का 60.8 प्रतिशत है। विभिन्न बैंकों द्वारा कुल वितरित ऋण में से प्राथमिकता क्षेत्र में जो ऋण वितरित किये गये हैं उनमें से सबसे अधिक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा अपने वितरित ऋण का 72.9 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को दिया गया। जबकि सबसे कम पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का मात्र 30.1 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को दिया गया।

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय औरैया जनपद द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2001–02

जनपद में वित्तीय वर्ष 2004–05 में विभिन्न व्यावसायिक बैंको द्वारा वितरित ऋण के वितरण एवं वर्ष 2001 –02 में वितरित ऋण के सापेक्ष वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि को सारणी संख्या 76 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–76

औरैया जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण(2004–05) स्थिति 31 मार्च 2005 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में प्रति बैंक द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में	वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि % में
1	2	3	4	5	6	7
1. सेन्ट्रल बैंक	19	294454	182406	62.0%	41.0%	93.0%
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	05	307037	71884	23.4%	42.8%	91.5%
3. इलाहाबाद बैंक	01	51662	10951	21.4%	7.2%	104.6%
4. पंजाब नेशनल बैंक	03	64319	13114	20.4%	9.0%	112.9%
योग– 04	**28**	**717472**	**278355**	**38.8%**	**100%**	**94.8%**

सारणी संख्या 76 से स्पष्ट है कि औरैया जनपद में वित्तीय वर्ष 2004–05 में 717472 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। इस वितरित ऋण में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा 7.2 प्रतिशत से 42.8 प्रतिशत तक का वित्तीय योगदान रहा है। और इस वितरित ऋण में से 278355 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को वितरित किये गये। जो कुल वितरित ऋण का 38.8 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2001–02 में वितरित ऋण की अपेक्षा वित्तीय वर्ष 2004–05 में वितरित ऋण में 94.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वितरित ऋण में होने वाली यह वृद्धि इस बात को स्पष्ट करती है कि जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा निरन्तर ग्रामीण साख वितरण में वृद्धि हो रही है। जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सहायक हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण के विवरण एवं वित्तीय वर्ष 2004–05 में वितरित ऋण की अपेक्षा इस वित्तीय वर्ष में वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि को सारणी संख्या 77 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय औरैया जनपद द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2004–05

सारणी संख्या–77

औरैया जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण(वर्ष 2006–07) स्थिति 31 मार्च 2007 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में प्रति बैंक द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में	वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि % में
1	2	3	4	5	6	7
1. सेन्ट्रल बैंक	19	545891	259442	47.5%	44.5%	85.4%
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	05	506336	119897	23.7%	41.5%	64.9%
3. इलाहाबाद बैंक	01	94938	16123	17.0%	7.6%	83.8%
4. पंजाब नेशनल बैंक	03	80080	22245	27.8%	6.4%	24.5%
योग– 04	**28**	**1227245**	**417707**	**34.1%**	**100%**	**71.1%**

सारणी संख्या 77 से यह स्पष्ट है कि औरैया जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में 1227245 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये । इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंकों का 6.4 प्रतिशत से 44.5 प्रतिशत तक का वित्तीय योगदान रहा है। जिसमें कुल वितरित ऋण में सबसे अधिक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया का रहा है। जिसमें वितरित ऋण का 44.5 प्रतिशत ऋण वितरित किया। इसके बाद स्टेट बैंक आफ इण्डिया का क्रम है जिसने कुल वितरित ऋण का 41.5 प्रतिशत ऋण वितरित किया। जनपद में वितरित इस ऋण में से 417707 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किये गये जो कुल वितरित ऋण का 34.1 प्रतिशत है। इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंकों में सबसे ज्यादा अपने वितरित ऋण का 47.5 प्रतिशत सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण दिया गया। जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में वितरित ऋण वित्तीय वर्ष 2004–05 की अपेक्षा 71.1 प्रतिशत अधिक रहा है। यदि हम वित्तीय वर्ष 2001–02 में वितरित ऋण की स्थिति पर विचार करें तो निश्चित ही 2001–02 में व्यावसायिक बैंकों द्वारा जो ऋण वितरित किया गया था उसकी अपेक्षा वर्ष 2006–07 में 233.2 प्रतिशत अधिक ऋण वितरित किया गया। जो इस बात को स्पष्ट करता है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा ग्रामीण साख उपलब्धता में दिनो–दिन वृद्धि हो रही है। ग्रामीण साख में होने वाली यह वृद्धि इस बात को भी स्पष्ट करती है कि निश्चित ही असंगठित स्रोतों का दिनो–दिन कृषि साख में योगदान कम होता जा रहा है। औरैया जनपद में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में जो ऋण वितरित किये गये हैं उसमें से जो ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये हैं वह विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दिये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण के वितरण को सारणी संख्या 78 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय औरैया जनपद द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2006–07

सारणी संख्या–78

औरैया जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का उद्देश्य के आधार पर वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र मे वितरित ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %	कृषि क्षेत्र में से फसली ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %	लघु उद्योग में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. सेन्ट्रल बैंक	19	259442	203876	78.6%	151098	74.1%	19993	7.7%	35573	13.7%
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	05	119897	97783	81.6%	21520	22.0%	10248	8.5%	11866	9.9%
3. इलाहाबाद बैंक	01	16123	14395	89.3%	5064	35.2%	60	0.4%	1668	10.3%
4. पंजाब नेशनल बैंक	03	22245	15230	68.5%	7914	52.0%	2445	11.0%	4570	20.5%
योग– 04	**28**	**417707**	**331284**	**79.3%**	**185596**	**56.0%**	**32746**	**7.8%**	**53677**	**12.9%**

सारणी संख्या 78 से स्पष्ट है कि औरैया जनपद में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में 417707 हजार रुपये के ऋण वितरित किये इस वितरित ऋण में 331284 हजार रुपये कृषि क्षेत्र में वितरित किये जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 79.3 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में जो ऋण वितरित किये गये उसमें से 185596 हजार रुपये या कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का 56 प्रतिशत फसली ऋण दिये गये। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 7.8 प्रतिशत या 32746 हजार रुपये के ऋण लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये, प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण की शेष धनराशि 53677 हजार रुपये या प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 12.9 प्रतिशत भाग अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को दिया गया। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग कृषि क्षेत्र को दिया गया।

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय औरैया द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2006–07

5. **कानपुर नगर जनपद :** कानपुर नगर जनपद में 7 व्यावसायिक बैंकों की 34 शाखायें कार्यरत हैं। जिनके द्वारा ग्रामीण साख या कृषि साख उपलब्ध कराया जा रहा है। इन विभिन्न बैंकों व शाखाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2001–02, 2004–05 व 2006–07 में वितरित ऋण के विवरण को स्पष्ट किया जाना है। इसी को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2001–02 में जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण के विवरण को सारणी संख्या 79 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–79

कानपुर नगर जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण वर्ष (2001–02) स्थिति 31 मार्च 2002 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में प्रति बैंक द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6
1. बैंक आफ बड़ौदा	11	312609	290725	93%	36.8%
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	07	242792	165098	68%	28.6%
3. सेन्ट्रल बैंक	06	113641	76140	67%	13.4%
4. पंजाब नेशनल बैंक	05	65500	52300	80%	7.7%
5. बैंक आफ इण्डिया	03	97681	79389	81%	11.5%
6. इलाहाबाद बैंक	01	14535	12655	87%	1.7%
7. यूको बैंक	01	2848	1566	55%	0.3%
योग– 07	**34**	**849606**	**677873**	**79.8%**	**100%**

सारणी संख्या 79 से यह स्पष्ट है कि कानपुर नगर जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2001–02 में 849606 हजार रुपये के ऋण वितरित किये। इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंकों का 0.3 प्रतिशत से 36.8 प्रतिशत तक का वितरित ऋण में योगदान रहा है। जनपद में वितरित इस ऋण में से 677873 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किये गये। जो जनपद में वितरित ऋण का 79.8 प्रतिशत है। प्राथमिकता क्षेत्र में इस वितरित ऋण में सबसे अधिक किसी बैंक शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का 93 प्रतिशत भाग बैंक आफ बड़ौदा द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को दिया गया। इसके बाद इलाहाबाद बैंक ने 87 प्रतिशत व बैंक आफ इण्डिया ने 81 प्रतिशत अपने वितरित ऋण का प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किया।

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय औरैया जनपद द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2006–07

जनपद में वित्तीय वर्ष 2004–05 में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण के विवरण को व वित्तीय वर्ष 2001–02 में वितरित ऋण के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष में वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि के विवरण को सारणी संख्या 80 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या 80

कानपुर नगर जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण वर्ष (2004–05) स्थिति 31 मार्च 2005 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में प्रति बैंक द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में	वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि % में
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक आफ बड़ौदा	11	385619	352617	91.4%	25.3%	23.4%
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	07	594759	476740	80.2%	39.1%	145.0%
3. सेन्ट्रल बैंक	06	128292	110879	86.4%	8.4%	12.9%
4. पंजाब नेशनल बैंक	05	117832	97737	82.6%	7.7%	79.9%
5. बैंक आफ इण्डिया	03	183691	151626	82.5%	12.1%	88.1%
6. यूको बैंक	01	8954	7375	82.4%	0.6%	214.4%
7. इलाहाबाद बैंक	01	103400	100700	97.4%	6.8%	611.4%
योग– 07	**34**	**1522547**	**1297674**	**85.2%**	**100%**	**79.2%**

सारणी संख्या 80 से यह स्पष्ट है कि कानपुर नगर जनपद में वित्तीय वर्ष 2004–05 में विभिन्न व्यावसायिक बैंक शाखाओं द्वारा 1522547 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। इस वितरित ऋण में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का 0.6 प्रतिशत से 39.1 प्रतिशत तक का वितरित ऋण में वित्तीय योगदान रहा है। इस वितरित ऋण में सबसे अधिक योगदान स्टेट बैंक आफ इण्डिया का रहा है। जिसने जनपद में कुल वितरित ऋण का 39.1 प्रतिशत वित्तीय योगदान दिया वहीं दूसरे क्रम पर बैंक आफ बड़ौदा रही है। जिसने कुल वितरित ऋण का 25.3 प्रतिशत ऋण का वितरण किया। जबकि सबसे कम ऋण का वितरण यूको बैंक द्वारा किया गया जिसने कुल वितरित ऋण का मात्र 0.6 प्रतिशत ऋण का वितरण किया। जनपद में वितरित इस ऋण में से 1297674 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए वितरित किये जो कुल वितरित ऋण का 85.2 प्रतिशत है। प्राथमिकता क्षेत्र में किसी बैंक द्वारा अपने

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय कानपुर नगर जनपद द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2004–05

वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग इलाहाबाद बैंक द्वारा 97.4 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र में दिया गया। इसके बाद बैंक आफ बड़ौदा द्वारा अपने वितरित ऋण का 91.4 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरित किया गया। जनपद में वित्तीय वर्ष 2001–02 में जो भी ऋण वितरित किया गया था। उस वितरित ऋण के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2004–05 में 79.2 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण वितरित किये गये। हालांकि जनपद में इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न बैंकों द्वारा जो अतिरिक्त ऋण वितरित किये गये हैं उसमें बहुत ही असमानता की स्थिति रही है।

जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण के विवरण व वितरित ऋण में गत वर्ष 2004–05 की अपेक्षा होने वाली वृद्धि को सारणी संख्या 81 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–81

कानपुर नगर जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण वर्ष (2006–07) स्थिति 31 मार्च 2007 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में प्रति बैंक द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में	वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि % में
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक आफ बड़ौदा	11	610203	568998	93.3%	26.1%	58.2%
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	07	818002	632295	77.3%	35.0%	37.5%
3. पंजाब नेशनल बैंक	05	152478	138174	90.6%	6.5%	29.4%
4. सेन्ट्रल बैंक	06	185460	154933	83.5%	8.0%	44.6%
5. बैंक आफ इण्डिया	03	297500	261851	88.0%	12.7%	62.0%
6. इलाहाबाद बैंक	01	259206	254913	98.3%	11.2%	150.7%
7. यूको बैंक	01	11853	9973	84.1%	0.5%	32.4%
योग– 07	**34**	**2384702**	**2021137**	**86.6%**	**100%**	**53.3%**

सारणी संख्या 81 से यह स्पष्ट है कि कानपुर नगर जनपद की व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में 2334702 हजार रुपये के ऋण वितरित किये। इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंकों का 0.5 प्रतिशत से 35 प्रतिशत का वित्तीय योगदान रहा है। इस वितरित ऋण में सबसे अधिक

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय कानपुर नगर जनपद द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2006–07

योगदान स्टेट बैंक आफ इण्डिया का रहा है। जिसने कुल वितरित ऋण का 35 प्रतिशत का वित्तीय योगदान किया। जबकि सबसे कम ऋण वितरण में यूको बैंक का योगदान रहा जिसने कुल वितरित ऋण का 0.5 प्रतिशत योगदान दिया। जनपद में इस वितरित ऋण में से 2021137 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किये गये। जो जनपद में कुल वितरित ऋण का 86.6 प्रतिशत है। जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित इस ऋण में किसी बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग 98.3 प्रतिशत इलाहाबाद बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किया। वहीं दूसरे क्रम पर अपने वितरित ऋण का प्राथमिकता क्षेत्र में 93.3 प्रतिशत ऋण का वितरण बैंक आफ बड़ौदा द्वारा किया गया। जनपद में यह वितरित ऋण वित्तीय वर्ष 2004–05 में वितरित ऋण के सापेक्ष 53.3 प्रतिशत अधिक है। वहीं यदि वित्तीय वर्ष 2001–02 में वितरित ऋण के सापेक्ष देखा जाय तो कहा जा सकता है कि जनपद में वितरित ऋण में 174.8 प्रतिशत की वितरित ऋण में वृद्धि हुई है। जनपद में वितरित ऋण में होने वाली इस भारी वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिन–प्रतिदिन ग्रामीण साख उपलब्ध कराने में वृद्धि हो रही है। जैसा कि सारणी से स्पष्ट है।

नगर जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में जो ऋण वितरित किया गया है। यदि उसके विवरण पर विचार करें तो कहा जा सकता है कि यह वितरित ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को ध्यान में रखकर दिया गया है। और प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र, लघु उद्योग एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में इस ऋण को वितरित किया गया है। अतः कहा जा सकता है कि जनपद में जो प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण का वितरण हुआ है वह कितनी मात्रा में हुआ है। तथा जिन क्षेत्रों को प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण दिया गया है वह कितनी मात्रा में दिया गया है और उसमें विभिन्न बैंकों का क्या योगदान रहा है तथा प्राथमिकता क्षेत्र से वितरित ऋण का क्या प्रतिशत रहा है ? आदि प्रश्नों के उत्तर के लिए सारणी संख्या 82 का सहारा लिया जा सकता है।

सारणी संख्या–82

कानपुर नगर जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का उद्देश्य के आधार पर वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र मे वितरित ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %	कृषि क्षेत्र में से फसली ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %	लघु उद्योग में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. बैंक आफ बड़ौदा	11	568998	502158	88.3%	301294	60%	22356	3.9%	44484	7.8%
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	07	632295	512512	81.1%	358758	70%	12167	1.3%	107616	17.0%
3. पंजाब नेशनल बैंक	05	138174	123130	89.1%	115742	94%	740	0.5%	14304	10.3%
4. सेन्ट्रल बैंक	06	154933	103321	66.7%	58892	57%	17664	11.4%	33948	21.9%
5. बैंक आफ इण्डिया	03	261851	149017	56.9%	22352	15%	32796	12.5%	80038	30.6%
6. इलाहाबाद बैंक	01	254913	244900	96.1%	225308	92%	4997	2.0%	5113	1.9%
7. यूको बैंक	01	9973	7586	76.1%	4172	55%	0	0	2387	23.9%
योग– 07	**34**	**2021137**	**1642624**	**81.3%**	**1086518**	**61.1%**	**90623**	**4.5%**	**287890**	**14.2%**

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय कानपुर नगर जनपद द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2006–07

सारणी संख्या 82 से स्पष्ट है कि कानपुर नगर जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में 2021137 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। इस वितरित ऋण में से 1642624 हजार रुपये के ऋण कृषि क्षेत्र को दिये गये जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 81.3 प्रतिशत है। इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंकों द्वारा अपने वितरित ऋण में सबसे अधिक ऋण कृषि क्षेत्र को इलाहाबाद बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 96.1 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र को प्रदान किया। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने अपने वितरित ऋण का 89.1 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र से कृषि क्षेत्र को दिया। जनपद में कृषि क्षेत्र में वितरित इस ऋण में से 1086518 हजार रुपये के फसली ऋण दिये गये। जो कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का 66.1 प्रतिशत है। फसली ऋण के रूप में व्यावसायिक बैंक के किसी शाखा द्वारा अपने कृषि क्षेत्र में अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग 94 प्रतिशत पंजाब नेशनल बैंक द्वारा फसली ऋण दिये गये। इसके बाद इलाहाबाद बैंक द्वारा अपने कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का 92 प्रतिशत भाग फसली ऋण के रूप में दिया गया, जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण में से 90623 हजार रुपये के ऋण लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये। जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 4.5 प्रतिशत है। लघु उद्योग क्षेत्र में वितरित इस ऋण में से किसी बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का प्रथमिकता क्षेत्र में से लघु उद्योग को 12.5 प्रतिशत बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिया गया शेष बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को अपने वितरित ऋण का कम ही भाग दिया गया है, प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में से व्यावसायिक बैंक द्वारा 287890 हजार रुपये के ऋण अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये। जो जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत वितरित ऋण का 14.2 प्रतिशत है। जनपद में अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत किसी बैंक शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग 30.6 प्रतिशत बैंक आफ इण्डिया द्वारा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को दिया गया, जबकि शेष बैंकों द्वारा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में अपने वितरित ऋण का इससे कम ही भाग दिया गया है। इस प्रकार सारणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि कानपुर नगर जनपद में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत जो ऋण वितरित किया गया है उसमें से सबसे अधिक भाग कृषि क्षेत्र को प्रदान किया गया है। इसके बाद अन्य प्राथमिकता क्षेत्र व लघु एवं कुटीर उद्योग को दिया गया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत जो भी ऋण वितरित किया गया है वह किसी न किसी रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक हुआ है।

6. **कानपुर देहात जनपद :** जनपद कानपुर देहात में 5 व्यावसायिक बैंक कार्य कर रही हैं। जिनके द्वारा ग्रामीण साख उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यरत इन बैंकों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2001–02, 2004–05 व वित्तीय वर्ष 2006–07 में जो ग्रामीण क्षेत्र को साख उपलब्ध कराये गये हैं। उसके विस्तृत अध्ययन को स्पष्ट किया जाना है। इसी को ध्यान में रखते हुये जनपद में वित्तीय वर्ष 2001–02 में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण के विवरण को सारणी संख्या 83 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–83

कानपुर देहात जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण वर्ष (2001–02) स्थिति 31 मार्च 2002 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में प्रति बैंक द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6
1. बैंक आफ बड़ौदा	11	24754	183182	74%	38.1
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	10	328550	292410	89%	50.6
3. सेन्ट्रल बैंक	02	21792	18525	85%	3.4
4. पंजाब नेशनल बैंक	03	40200	34974	87%	6.2
5. इलाहाबाद बैंक	01	11211	10525	94%	1.7
योग– 05	**27**	**649297**	**539616**	**83.1%**	**100**

सारणी संख्या 83 से स्पष्ट है कि कानपुर देहात जनपद में वित्तीय वर्ष 2001–02 में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों के द्वारा 649297 हजार रुपये के ऋण वितरित किये। इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंकों का 1.7 प्रतिशत से 50.6 प्रतिशत तक का वितरित ऋण में वित्तीय योगदान रहा। जिसमें सबसे अधिक स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा कुल वितरित ऋण का 50.6 प्रतिशत व बैंक आफ बड़ौदा द्वारा कुल वितरित ऋण का 38.1 प्रतिशत ऋण वितरण में योगदान किया। जनपद में वितरित इस ऋण में से 539616 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किये गये जो जनपद में वितरित कुल ऋण का 83.1 प्रतिशत है। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित इस ऋण में किसी बैंक शाखा द्वारा अपने समस्त वितरित ऋण में से 94 प्रतिशत भाग इलाहाबाद बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को वितरित किया गया, व 89 प्रतिशत भाग अपने वितरित ऋण का स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिया गया।

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय कानपुर देहात जनपद द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2001–02

कानपुर देहात जनपद में वित्तीय वर्ष 2004–05 में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में वितरित ऋण के विवरण व वर्ष 2001–02 में वितरित ऋण के सापेक्ष वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि को सारणी संख्या 84 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–84

कानपुर देहात जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण वर्ष (2004–05) स्थिति 31 मार्च 2005 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में प्रति बैंक द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में	वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि % में
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक आफ बड़ौदा	11	325931	293036	89.9%	29.7%	31.7
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	10	620727	401905	64.8%	56.5%	88.9
3. पंजाब नेशनल बैंक	03	91594	48226	52.7%	8.2%	127.8
4. सेन्ट्रल बैंक	02	41841	35945	85.9%	3.7%	92.0
5. इलाहाबाद बैंक	01	21441	19711	91.9%	1.9%	91.3
योग– 05	**27**	**1098977**	**798823**	**72.7%**	**100%**	**69.3**

सारणी संख्या 84 से यह स्पष्ट है कि कानपुर देहात जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा 1098977 हजार रुपये के ऋण वितरित किये इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंकों का 1.9 प्रतिशत से 56.5 प्रतिशत तक का वितरित ऋण में योगदान रहा है। जिसमें सबसे अधिक ऋण का वितरण स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा किया गया। जनपद में वितरित इस ऋण में से 798823 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में दिये गये। जो कुल वितरित ऋण का 72.7 प्रतिशत है। और किसी बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग 91.9 प्रतिशत इलाहाबाद बैंक द्वारा दिया गया। इसके बाद 89.9 प्रतिशत बैंक आफ बड़ौदा द्वारा अपने वितरित ऋण का प्राथमिकता क्षेत्र को दिया गया। जनपद में वित्तीय वर्ष 2001–02 की अपेक्षा इस वर्ष वितरित ऋण में अपेक्षाकृत 69.3 प्रतिशत के अतिरिक्त ऋण वितरित किये गये जो इस बात को स्पष्ट करता है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में वितरित ऋण में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जिससे कि गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा वितरित ऋण में कमी हो सके और लोगों को असंगठित स्रोतों के शोषण से बचाया जा सके। जैसा कि सारणी से स्पष्ट है।

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय कानपुर देहात जनपद द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2004–05

जनपद कानपुर देहात में वित्तीय वर्ष 2006–07 में व्यावसायिक बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में वितरित ऋण के विवरण को व वित्तीय वर्ष 2004–05 में वितरित ऋण की अपेक्षा वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि को सारणी संख्या 85 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–85

कानपुर देहात जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण वर्ष (2006–07) स्थिति 31 मार्च 2007 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में प्रति बैंक द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में	वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि % में
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक आफ बड़ौदा	12	573325	539342	94.1%	34.2%	75.9%
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	10	917362	672521	73.3%	54.7%	47.8%
3. पंजाब नेशनल बैंक	03	65158	63855	98.0%	3.9%	–28.9%
4. सेन्ट्रल बैंक	02	67316	60965	90.6%	4.0%	37.8%
5. इलाहाबाद बैंक	02	55190	50538	91.6%	3.2%	157.4%
योग– 05	**29**	**1678351**	**1387221**	**82.7%**	**100%**	**52.7%**

सारणी संख्या 85 से यह स्पष्ट है कि जनपद कानपुर देहात में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में 1678351 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंकों का 3.2 प्रतिशत से 54.7 प्रतिशत तक वित्तीय योगदान रहा है। जिसमें सबसे अधिक 54.7 प्रतिशत कुल वितरित ऋण का स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा वितरित किया गया व 34.2 प्रतिशत कुल वितरित ऋण का बैंक आफ बड़ौदा द्वारा वित्तीय योगदान किया गया। जनपद में वितरित इस ऋण में से 82.7 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में दिया गया जो कुल वितरित ऋण का 1387221 हजार रुपये है। जनपद में वित्तीय वर्ष 2004–05 में वितरित ऋण की अपेक्षा 52.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि वर्ष 2001–02 में वितरित ऋण से 2006–07 में वितरित ऋण को देखा जाय तो कहा जा सकता है कि कुल वितरित ऋण में 158.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो इस बात को स्पष्ट करता है कि जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

कानपुर देहात जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय कानपुर देहात जनपद द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2006–07

सारणी संख्या–86

कानपुर देहात जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का उद्देश्य के आधार पर वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र मे वितरित ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %	कृषि क्षेत्र में से फसली ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %	लघु उद्योग में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. बैंक आफ बड़ौदा	12	539342	477269	88.5%	282030	59.1%	23017	4.3%	39066	7.2%
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	10	672521	626525	93.1%	27981	4.5%	20015	3.0%	25981	3.9%
3. पंजाब नेशनल बैंक	03	63855	61900	96.9%	35270	57.0%	925	1.4%	1030	1.7%
4. सेन्ट्रल बैंक	02	60965	39708	65.1%	24022	60.5%	8725	14.3%	12532	20.6%
5. इलाहाबाद बैंक	02	50538	45045	89.1%	25231	56.0%	1890	3.7%	3603	7.2%
योग– 05	**29**	**1387221**	**1250437**	**90.1%**	**394534**	**31.6%**	**54572**	**3.9%**	**82212**	**6.0%**

सारणी संख्या 86 से यह स्पष्ट है कि कानपुर देहात जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में 1387221 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये इस वितरित ऋण में 1250437 हजार रुपये के ऋण कृषि क्षेत्र को दिये गये जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 90.1 प्रतिशत है। इस वितरित ऋण में किसी बैंक शाखा द्वारा अपने प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में से कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण 96.9 प्रतिशत पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दिया गया, कृषि क्षेत्र में वितरित इस ऋण में से 394534 हजार रुपये के फसली ऋण दिये गये। जो कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का 31.6 प्रतिशत है। किसी बैंक शाखा द्वारा फसली ऋण के रूप में अपने कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण में से सबसे अधिक भाग 60.5 प्रतिशत सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिया गया, वहीं प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में से लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 54572 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये जो जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 3.9 प्रतिशत है व प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का शेष भाग 6.0 प्रतिशत या 82212 हजार रुपये के ऋण अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किये गये। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा ऋण कृषि क्षेत्र को दिये गये।

स्रोत – जिला अग्रणी बैंक कार्यालय कानपुर देहात जनपद द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना पत्रिका वर्ष 2006–07

कानपुर क्षेत्र के सम्पूर्ण जनपदों का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्त जनपदों की समस्त कार्यरत बैंकों के द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए एवं कृषि क्षेत्र में अधिकाधिक मात्रा में निवेश के स्तर को बढ़ाने के लिए व्यवसायिक बैंकों के द्वारा निरन्तर ऋण का वितरण किया जा रहा है जैसा कि विभिन्न जनपदों के अध्ययन से स्पष्ट होता है, चूंकि अध्ययन क्षेत्र सम्पूर्ण कानपुर क्षेत्र होने के कारण जनपदों का विश्लेषण करने के बावजूद भी कानपुर क्षेत्र की स्थिति पर विचार किया जाना आवश्यक हो जाता है अतः इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये कानपुर क्षेत्र में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2001–02, 2004–05 व वित्तीय वर्ष 2006–07 में वितरित ऋण के विवरण को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अतः कानपुर क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2001–02 में वितरित ऋण के विवरण को सारणी संख्या 87 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–87

कानपुर क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण वर्ष (2001–02)
स्थिति 31 मार्च 2002 (धनराशि हजार में)

जनपद का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में जनपद द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6
1. फर्रूखाबाद	29	1050103	852229	81.2%	22.3%
2. कन्नौज	24	662300	566439	85.5%	14.1%
3. इटावा	36	1122800	514843	49.9%	23.9%
4. औरैया	28	368323	223881	60.8%	7.8%
5. कानपुर नगर	34	849606	677873	79.8%	18.1%
6. कानपुर देहात	27	649297	539616	83.1%	13.8%
योग– 06	**178**	**4702429**	**3374881**	**71.8%**	**100%**

सारणी संख्या 87 से यह स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2001–02 में 4702429 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। इस वितरित ऋण में 7.8 प्रतिशत से 23.9 प्रतिशत तक विभिन्न जनपदों में कार्यरत बैंकों का योगदान रहा है। इस वितरित ऋण में सबसे अधिक ऋण का वितरण इटावा जनपद में किया गया जो कुल वितरित ऋण का 23. 9 प्रतिशत है। इसके बाद फर्रूखाबाद जनपद में कुल वितरित ऋण का 22.3 प्रतिशत ऋण

स्रोत – कानपुर क्षेत्र के समस्त जिला अग्रणी बैंक कार्यालयों से प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना रिपोर्ट वर्ष 2001–02 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित

वितरित किये गये। जबकि सबसे कम औरैया जनपद में कुल वितरित ऋण का 7.8 प्रतिशत ही ऋण वितरित किया गया। इस प्रकार सारणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि कानपुर क्षेत्र में विभिन्न जनपदों में वितरित ऋण में असमानता रही है। कानपुर क्षेत्र में वितरित इस ऋण में से 3374881 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किये गये। जो क्षेत्र में कुल वितरित ऋण का 71.8 प्रतिशत है। कानपुर क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण किसी जनपद द्वारा अपने वितरित समस्त ऋणों में से सबसे अधिक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में कन्नौज जनपद में किये गये जहां कुल वितरित ऋण का 85.5 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को दिया गया, वहीं इटावा जनपद में कुल वितरित ऋण का मात्र 49.9 प्रतिशत भाग ही प्राथमिकता क्षेत्र को दिया गया। इस प्रकार सारणी से यह भी स्पष्ट है कि प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में भी असमानता रही है।

कानपुर क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2004–05 में वितरित ऋण एवं वर्ष 2001–02 में वितरित ऋण के सापेक्ष होने वाली वृद्धि को सारणी संख्या 88 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–88

कानपुर क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण वर्ष (2004–05)
स्थिति 31 मार्च 2005 (धनराशि हजार में)

जनपद का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में जनपद द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में	वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि % में
1	2	3	4	5	6	7
1. फर्रुखाबाद	29	2009229	1652803	82.3%	22.7%	91.3%
2. कन्नौज	24	1396800	1205986	86.3%	15.9%	110.9%
3. इटावा	40	2056176	702631	34.3%	23.4%	83.1%
4. औरैया	28	717472	278355	38.8%	8.2%	94.8%
5. कानपुर नगर	34	1522547	1297674	85.2%	17.3%	79.2%
6. कानपुर देहात	27	1098977	798823	72.7%	12.5%	69.3%
योग– 06	**182**	**8801201**	**5936272**	**67.4%**	**100%**	**87.2%**

सारणी संख्या 88 से यह स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 में 8801201 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। इस वितरित ऋण में सबसे अधिक ऋण इटावा जनपद में वितरित किये गये। जिसमें कानपुर क्षेत्र में कुल वितरित ऋण का 23.4 प्रतिशत

स्रोत – कानपुर क्षेत्र के समस्त जिला अग्रणी बैंक कार्यालयों से प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना रिपोर्ट वर्ष 2004–05 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित

ऋण वितरित किये गये। इसके बाद कुल वितरित ऋण का 22.7 प्रतिशत ऋण फर्रूखाबाद जनपद में वितरित किया गया, जबकि सबसे कम क्षेत्र में वितरित ऋण का औरैया जनपद में मात्र 8.2 प्रतिशत भाग ही ऋण वितरित किया गया। इस प्रकार सारणी से यह स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत वितरित ऋण में विभिन्न जनपदों में परिवर्तन की स्थिति रही है। कानपुर क्षेत्र में वितरित इस ऋण में से 5936272 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किये गये, जो कुल वितरित ऋण का 67.4 प्रतिशत भाग है। प्राथमिकता क्षेत्र में भी विभिन्न जनपदों में असमानता की स्थिति रही है। इसके अन्तर्गत सबसे अधिक कन्नौज जनपद में अपने वितरित ऋण का 86.3 प्रतिशत ऋण तथा सबसे कम इटावा जनपद में अपने वितरित ऋण का 34.3 प्रतिशत भाग ही प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किया गया, जो कि सारणी से स्पष्ट है। कानपुर क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2001–02 में वितरित ऋण की अपेक्षा इस वर्ष वितरित ऋण में 87.2 प्रतिशत की वितरित ऋण में वृद्धि हुई है। जहां तक वितरित ऋण में वृद्धि का सवाल है इसमें भी कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में असमानता रही है। किन्तु एक बात अवश्य स्पष्ट होती है कि कानपुर क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में वित्तीय वर्ष 2001–02 की अपेक्षा वितरित ऋण में वृद्धि हुई है। जो इस बात का संकेत है कि व्यावसायिक बैंकों की भूमिका में दिनो–दिन वृद्धि हो रही है या यह कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में निवेश के स्तर में दिनो–दिन वृद्धि हो रही है।

कानपुर क्षेत्र में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में ग्रामीण क्षेत्र में वितरित ऋण के विवरण को व वित्तीय वर्ष 2004–05 में वितरित ऋण की अपेक्षा वर्ष 2006–07 में वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए तथा वित्तीय वर्ष 2001–02 से वित्तीय वर्ष 2006–07 के बीच वितरित ऋण में कानपुर क्षेत्र में होने वाली वृद्धि को सारणी संख्या 89 के माध्यम से इस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है कि व्यावसायिक बैंकों के द्वारा जो ऋण वितरित किया जा रहा है उसमें समय समय पर क्या परिवर्तन हो रहा है। इसके तहत यह स्पष्ट किया जायेगा कि क्या व्यावसायिक बैंक अपने उद्देश्यों में सफल रही हैं ? क्योंकि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित स्रोतों से उपलब्ध होने वाली साख में कमी लाने के लिए किया गया है। अतः यदि व्यावसायिक बैंकों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में ग्रामीण साख उपलब्ध कराया जा रहा है या उपलब्ध कराये जा रहे ऋण में निरन्तर वृद्धि हो रही है तो कह सकते हैं कि व्यावसायिक बैंक अपने कार्य में सफल हुये हैं इसी के विवरण को इस सारणी के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया जायेगा।

सारणी संख्या–89

कानपुर क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण वर्ष (2006–07) स्थिति 31 मार्च 2007 (धनराशि हजार में)

जनपद का नाम	शाखा संख्या	कुल वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कुल ऋण के सापेक्ष प्रतिशत	समस्त वितरित ऋण में जनपद द्वारा वितरित ऋण प्रतिशत में	वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि % में
1	2	3	4	5	6	7
1. फर्रूखाबाद	29	2984200	2488211	83.4%	21.3%	48.5%
2. कन्नौज	26	2708800	2380300	88.0%	19.3%	93.9%
3. इटावा	42	3094216	2321865	75.1%	22.1%	50.5%
4. औरैया	28	1227245	417707	34.1%	8.7%	71.1%
5. कानपुर नगर	34	2334702	2021137	86.6%	16.6%	53.3%
6. कानपुर देहात	29	1678351	1387221	82.7%	12.0%	52.7%
योग– 06	**188**	**14027514**	**11016441**	**78.5%**	**100%**	**59.4%**

सारणी संख्या 89 से यह स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में 14027514 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। इस वितरित ऋण में सबसे अधिक ऋण इटावा जनपद में वितरित किये गये। जिसमें कानपुर क्षेत्र में कुल वितरित ऋण का 22.1 प्रतिशत ऋण का वितरण किया गया। दूसरे क्रम पर फर्रूखाबाद जनपद का स्थान है जहां कानपुर क्षेत्र में वितरित ऋण में 21.3 प्रतिशत ऋण वितरित किया गया। वहीं सबसे कम ऋण का वितरण औरैया जनपद में किया गया जहाँ कानपुर क्षेत्र में वितरित ऋण का मात्र 8.7 प्रतिशत ऋण ही वितरित किया गया। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र के समस्त जनपदों में वितरित ऋण में असमानता रही है। क्षेत्र में वितरित इस ऋण में से 11016441 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किये गये जो क्षेत्र में वितरित कुल ऋण का 78.5 प्रतिशत है। कानपुर क्षेत्र में विभिन्न जनपदों में अपने वितरित ऋण में से सबसे अधिक प्राथमिकता क्षेत्र में कन्नौज जनपद द्वारा अपने वितरित ऋण का 88 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किया गया जबकि औरैया जनपद में अपने वितरित ऋण का मात्र 34.1 प्रतिशत ही प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण का वितरण किया गया। इस प्रकार सारणी से यह भी स्पष्ट है कि प्राथमिकता क्षेत्र में भी वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है। कानपुर क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2004–05 में वितरित ऋण की अपेक्षा इस वित्तीय वर्ष में 59.4 प्रतिशत अतिरिक्त ऋणों का वितरण किया गया। जहाँ तक

स्रोत – कानपुर क्षेत्र के समस्त जिला अग्रणी बैंक कार्यालयों से प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना रिपोर्ट वर्ष 2006–07 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित

कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में वितरित ऋण में होने वाली वृद्धि का सवाल है इसमें भी विभिन्न जनपदों में परिवर्तन की स्थिति रही है क्योंकि सबसे अधिक वृद्धि कन्नौज जनपद में वितरित ऋणों में रही है। जहाँ पर 93.9 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2004–05 की अपेक्षा अतिरिक्त ऋण वितरित किये गये वहीं फर्रूखाबाद जनपद में यह वृद्धि केवल 48.5 प्रतिशत की रही है जिससे यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न जनपदों में इस वित्तीय वर्ष में वितरित ऋण में वृद्धि का स्तर भी असमान रहा है। यदि हम वित्तीय वर्ष 2001–02 में वितरित ऋण के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2006–07 में वितरित ऋण से तुलना करें तो कहा जा सकता है कि 2001–02 की अपेक्षा वर्ष 2006--07 में वितरित ऋण में 198.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो यह स्पष्ट करती है कि कानपुर क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की ग्रामीण क्षेत्र के प्रति ग्रामीण साख उपलब्ध कराने में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जो यह स्पष्ट करती है कि व्यावासायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया था। उसमें कहीं हद तक सफल साबित हुई है जैसा की सारणी के माध्यम से स्पष्ट होता है।

कानपुर क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत जो ऋण वित्तीय वर्ष 2006–07 में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा वितरित किये गये है। वह विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दिये गये हैं। जिसके अन्तर्गत कृषि क्षेत्र, लधु उद्योग व अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये ही दिया गया है। जहाँ तक इन विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रश्न है तो कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत जो भी ऋण वितरित किये गये हैं वह कृषि के ढांचागत सुधार के साथ–साथ कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक का प्रयोग करने के लिए दिये गये हैं। जिससे कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जा सके और कृषि अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक इकाई बनाया जा सके क्योंकि जैसा पहले कहा जा चुका है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी आधे से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है और वह गांवों में रहकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है इसलिए कृषि क्षेत्र को भी एक आर्थिक इकाई के रूप में विकसित करना आवश्यक है। क्योंकि जब तक जनसंख्या का एक बड़े भाग का विकास नहीं होगा तब तक सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास की कल्पना करना निर्थक साबित होगी। इसी को ध्यान में रखकर व्यावसायिक बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि साख उपलब्ध कराये जा रहे हैं। अतः कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत इन बैंकों के द्वारा जो ऋण उपलब्ध कराये गये हैं उसके विवरण को जानने के लिए सारणी संख्या 90 का सहारा लिया जा सकता है।

सारणी संख्या–90

कानपुर क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का उद्देश्य के आधार पर वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

जनपद का नाम	शाखा संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र मे वितरित ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %	कृषि क्षेत्र में से फसली ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %	लघु उद्योग में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण के सापेक्ष %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. फर्रूखाबाद	29	2488211	1517551	61%	543534	35.8%	276414	11.0%	700646	28.0%
2. कन्नौज	26	2380300	1687800	70.9%	829200	49.1%	281400	11.8%	411100	17.3%
3. इटावा	42	2321865	1506667	64.9%	230971	15.3%	347554	15.0%	467644	20.1%
4. औरैया	28	417707	331284	79.3%	185596	56.0%	32746	7.8%	53677	12.9%
5. कानपुर नगर	34	2021137	1642624	81.3%	1086518	66.1%	90623	4.5%	287890	14.2%
6. कानपुर देहात	29	1387221	1250437	90.1%	394534	31.6%	54572	3.9%	82212	6.0%
योग– 06	**188**	**11016441**	**7936363**	**72.0%**	**3270353**	**41.2%**	**1083309**	**9.8%**	**2003169**	**18.2%**

सारणी संख्या 90 से यह स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में 11016441 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये इस वितरित ऋण में 7936363 हजार रुपये के ऋण कृषि क्षेत्र को दिये गये जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 72.0 प्रतिशत है।

स्रोत – कानपुर क्षेत्र के समस्त जिला अग्रणी बैंक कार्यालयों से प्रकाशित वार्षिक ऋण योजना रिपोर्ट वर्ष 2006–07 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित

इस वितरित ऋण में किसी जनपद द्वारा अपने कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग कानपुर देहात जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में कुल वितरित ऋण का 90.1 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र को दिया गया जबकि फर्रूखाबाद जनपद में अपने प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 61 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र को दिया गया। सारणी से यह स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण में कानपुर क्षेत्र के समस्त जनपदों में परिवर्तन की स्थिति रही है। कृषि क्षेत्र में वितरित इस ऋण में से 3270353 हजार रुपये के फसली ऋण दिये गये जो कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का 41.2 प्रतिशत है। विभिन्न जनपदों द्वारा कृषि क्षेत्र में वितरित अपने ऋण से सबसे अधिक फसली ऋण कानपुर नगर जनपद में दिये गये। जहां कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का 66.1 प्रतिशत भाग धनराशि के फसली ऋण दिये गये। वहीं इटावा जनपद में कृषि क्षेत्र में वितरित अपने ऋण में से मात्र 15.3 प्रतिशत भाग धनराशि ही फसली ऋण के लिए उपलब्ध कराई गई। कानपुर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 1083309 हजार रुपये लघु उद्योग क्षेत्र को दिया गया जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 9.8 प्रतिशत है। लघु उद्योग क्षेत्र में भी वितरित ऋण में विभिन्न जनपदों में असमानता की स्थिति रही है, 2003169 हजार रुपये के ऋण अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किये गये जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 18.2 प्रतिशत है। अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में भी अन्य उद्देश्यों की भांति कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में अपने वितरित ऋण में असमानता की स्थिति रही है। अतः सम्पूर्ण सारणी का विशलेषण करने के पश्चात् इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि कानपुर क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत जो ऋण वितरित किया गया है उसमें से सबसे अधिक भाग कृषि क्षेत्र को दिया गया है। जिससे कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन के साथ–साथ उत्पादकता स्तर को बढ़ाया जा सके। इसी को ध्यान में रखकर सबसे अधिक ऋण इस क्षेत्र को प्रदान किये गये हैं। कृषि क्षेत्र के अलावा जो ऋण लघु उद्योग या अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये हैं वह भी किसी न किसी रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक ही होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यावसायिक बैंकें अपने उद्देश्यों में सफल साबित हुई हैं।

निष्कर्ष : कृषि साख से अभिप्राय उस साख या वित्त से है जिसके माध्यम से कृषि उत्पादन एवं कृषि से सम्बन्धित अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में साख की आवश्यकता विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने की होती है। जिसमें कृषि एवं तत्सम्बन्धी क्रियाकलाप, लघु उद्योग एवं व्यापार व अन्य कृषि कार्य आदि इन सभी प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तीन प्रकार के समयों के आधार पर व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋणों का वितरण किया जाता है।

कानपुर क्षेत्र में कार्यरत व्यावसायिक बैंक व उनकी शाखाओं द्वारा राष्ट्रीयकरण के पश्चात से आज तक बैंकों के क्रियाकलापों में बहुत बड़ा अन्तर देखने को मिलता है। जहां राष्ट्रीयकरण के समय व उसके कुछ दशकों के पश्चात से आज व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। वहीं इन शाखाओं द्वारा अपने वितरित ऋण में निरन्तर वृद्धि हो रही है। और इनमें से भी जो ऋण का वितरण हो रहा है वह प्राथमिकता क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया जा रहा है क्योंकि विगत कुछ वर्षो में कानपुर क्षेत्र में कार्यरत बैंकों की शाखाओं द्वारा वितरित ऋण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कुल ऋण में से प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में दिन–प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। जहां तक कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न प्रशासनिक जनपदों के सन्दर्भ में विचार करें तो यह कहा जा सकता है कि विभिन्न जनपदों में से लगभग जनपदों में वर्ष 2001–02 की तुलना में शाखा विस्तार भी हुआ है और कुल वितरित ऋण में भी वृद्धि हुई है। तथा वितरित ऋण में से प्राथमिकंता क्षेत्र में वितरित ऋण में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि व्यावसायिक बैंकों को कृषि क्षेत्र में पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में कहीं हद तक सफलता प्राप्त हुई है। जो इस बात का संकेत है कि व्यावसायिक बैंकों का जो वर्ष 1967 में सामाजिक नियन्त्रण किया गया और उसके बाद इस बात को लेकर व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कि कृषि क्षेत्रों में जो सहकारी संगठन कृषि के तकनीकी विकास हेतु पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने में असफल रही हैं उसको व्यावसायिक बैंकों द्वारा सफल बनाया जा सकता है, के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीयकरण हुआ था। अतः यह कहा जा सकता है कि विभिन्न जनपदों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में व्यावसायिक बैंकें सफल सिद्ध हो रही हैं। इस प्रकार अध्ययन के प्रारम्भ में स्पष्ट की गई प्रथम परिकल्पना की वाणिज्यिक बैंकों के वित्त प्रदान करने के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ढांचा अधिक विस्तृत व मजबूत हो सका है इसकी पुष्टि हो जाती है।

दूसरी परिकल्पना कि वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से किसानों को पर्याप्त मात्रा में वित्त प्रदान होने के परिणामस्वरूप कृषि के विकास में सहायता प्राप्त हुई है। इसकी भी पुष्टि हो जाती है क्योंकि अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि कानपुर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर परिवर्तन व सुधार देखने में आया है जिसके पीछे व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण का योगदान प्रमुख रहा है क्योंकि अन्य वित्तीय संसाधन वित्त की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने में असफल या असमर्थ सिद्ध हुये हैं इसलिए व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण से कृषि क्षेत्र में विकास सम्भव हुआ है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण से कृषि क्षेत्र में व्यापक रूप से सुधार व विकास देखने को मिल रहा है।



अध्याय – छः

व्यापारिक बैंकों के वित्त का प्रारूप

अध्याय – छः व्यापारिक बैंकों के वित्त का प्रारूप

व्यापारिक बैंकों के वित्त के प्रारूप से आशय बैंकों द्वारा दिये जा रहे ऋणों के समयावधि से है। जहाँ तक समयावधि का प्रश्न है बैंकों द्वारा तीन समयावधियों को ध्यान में रखकर ऋण का वितरण किया जा रहा है।

1. अल्पकालीन
2. मध्यकालीन
3. दीर्घकालीन

1. **अल्पकालीन ऋण :** व्यापारिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में अल्पकालीन ऋण कृषि क्षेत्र में किसानों को उत्पादन सम्बन्धी कार्यशील पूँजी की पूर्ति के लिए दिया जाता है। कार्यशील पूँजी का अर्थ उन पूँजी उपकरणों से है। जिनका उपयोग किसानों द्वारा कृषि उत्पादन की दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है। इसके अन्तर्गत उत्तम बीज, खाद, सिचाई व्यय और लगान इत्यादि के लिए दिये गये ऋण से है।

2. **मध्यकालीन ऋण :** मध्यकालीन ऋण से आशय ऐसे उपयोगों के लिए प्राप्त होने वाले ऋणों से है जो कृषि के कार्यों में प्रयुक्त किये जाने वाले यन्त्रों, औजारों, सिचाई सुविधाओं के लिए डीप बोरिंग तथा कृषि से सम्बन्धित सहायक कार्य जैसे पशुपालन व सघन मिनी डेरी आदि कार्यों को पूरा करने के लिए दिया जाता है।

3. **दीर्घकालीन :** दीर्घकालीन ऋणों का सम्बन्ध कृषि उत्पादन में ऐसे किये जाने वाले निवेशों से है जिनका सम्बन्ध कृषि में उपयोग किये जाने वाले तकनीकी सम्बन्धी उपकरणों को क्रय करने के लिए दिया जाता है। इसके अन्तर्गत ट्रैक्टर, ट्यूवबेल, कटाई मशीन, भूमि का

समतलीकरण, भूमि क्रय करने एवं कोल्ड स्टोरेज तथा अनाज भण्डारण गृह निर्माण आदि कार्यों के लिए दिये जाने वाले ऋण से है।

जहाँ तक कानपुर क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण से प्रश्न है क्षेत्र में तीनों प्रकार के ऋणों का वितरण किया जा रहा है। जिसका विस्तृत से अध्ययन करने के लिए कानपुर क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा तीनों प्रकार के वितरित ऋणों का विभिन्न जनपदों में क्या स्थिति रही है ? इसको स्पष्ट किया जायेगा तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में तीनों अवधियों में कितना – कितना ऋण वितरित किया है, इसको भी स्पष्ट किया जायेगा। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2006–07 में इन अवधियों में जो ऋण वितरित किया गया है। इस वितरित ऋण को कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में विस्तृत से अध्ययन के लिए प्रत्येक जनपद में वितरित ऋण के विवरण को स्पष्ट किया जाना है।

1. फर्रूखाबाद जनपद : फर्रूखाबाद जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में 9 व्यावसायिक बैंकें कार्य कर रही थीं जिनकी 29 शाखायें कार्यरत हैं। जिनके द्वारा जनपद में ऋण का वितरण किया जा रहा है। इन बैंक शाखाओं द्वारा इस वित्तीय वर्ष में अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन समय के आधार पर जो ऋण वितरित किया गया है। उस ऋण में अल्पकाल में कितना प्रतिशत ऋण दिया गया, दीर्घकाल में कुल वितरित ऋण का कितना प्रतिशत ऋण मध्यकाल में कुल वितरित ऋण का कितना प्रतिशत ऋण दिया गया इसके विवरण के साथ–साथ यह भी स्पष्ट किया जाना है कि जनपद में कार्यरत विभिन्न व्यावसायिक बैंकों में किस बैंक ने अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग किस समय के लिए वितरित किया है। इसके विवरण को सारणी संख्या 91 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–91

फर्रूखबाद जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा समय के आधार पर वितरित ऋण का विवरण वर्ष 2006–07 स्थिति 31 मार्च 2007 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वितरित ऋण का वितरण					
			अल्पकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	मध्यकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	दीर्घकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. बैंक आफ इण्डिया	10	933710	370052	39.6%	199483	21.4%	364175	39.0%
2. स्टेट बैंक	05	639853	87746	13.7%	253899	39.7%	298208	46.6%
3. पंजाब नेशनल बैंक	04	208454	26115	12.5%	116416	55.9%	65926	31.6%
4. सेन्ट्रल बैंक	03	324337	23006	9.8%	107849	46.0%	103482	44.2%
5. बैंक आफ बड़ौदा	02	114851	826	0.7%	62787	54.7%	51238	44.6%
6. इलाहाबाद बैंक	02	145550	19794	13.6%	71279	49.0%	54477	37.4%
7. यूनियन बैंक	01	84433	1780	16.3%	43300	51.3%	27353	32.4%
8. ओ0बी0सी0	01	87597	0	0	82709	94.4%	4888	5.6%
9. यूको बैंक	01	45832	2215	4.8%	39338	85.9%	4270	9.3%
योग– 09	**29**	**2488211**	**543534**	**21.8%**	**977060**	**39.2%**	**974017**	**39.1%**

सारणी संख्या 91 से स्पष्ट है कि फर्रूखाबाद जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में 2488211 हजार रुपये के ऋण वितरित किये जिसमें जनपद में कार्यरत समस्त बैंक शाखाओं का योगदान रहा है। जनपद में वितरित इस ऋण में से 543534 हजार रुपये के ऋण अल्पकालीन समय की आवश्यकता पूर्ति के लिए दिये गये जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 21.8 प्रतिशत है। अल्पकालीन समय के लिए वितरित इस ऋण में सबसे अधिक ऋण बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिया गया। जिसने अपने वितरित ऋण का 39.6 प्रतिशत भाग अल्पकालीन समय के लिए दिया। जबकि ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स ने किसी प्रकार का अल्पकालीन ऋण नहीं दिया वहीं बैंक आफ बड़ौदा ने अपने वितरित ऋण का मात्र 0.7 प्रतिशत भाग ही अल्पकालीन समय के लिए ऋण वितरित किये, प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 977060 हजार रुपये के ऋण मध्यकालीन समय के लिए दिये गये। जो जनपद में प्राथमिकता

स्रोत – फर्रूखाबाद जनपद लीड बैंक कार्यालय से प्रकाशित वार्षिक ऋण पत्रिका वर्ष 2006–07 पर दिये गये आंकड़ों पर आधारित

क्षेत्र में वितरित ऋण का 39.2 प्रतिशत है। मध्यकालीन समय के लिए वितरित इस ऋण में कार्यरत् विभिन्न बैंक शाखाओं में अपने वितरित ऋण का किसी बैंक द्वारा सबसे अधिक भाग ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स ने 94.4 प्रतिशत भाग ऋण मध्यकालीन समय के लिए दिया। जबकि बैंक आफ इण्डिया ने अपने वितरित ऋण का मात्र 21.4 प्रतिशत भाग ही मध्यकालीन समय के लिए दिया, जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित इस ऋण का शेष भाग दीर्घकालीन समय के लिए दिया गया जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 39.1 प्रतिशत या 974017 हजार रुपये है। दीर्घकालीन समय के लिए वितरित इस ऋण में विभिन्न बैंकों का अलग–अलग योगदान रहा है, जिसमें किसी बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का 46.6 प्रतिशत भाग स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा दीर्घकाल को दिया गया। इसके अलावा 44.6 प्रतिशत भाग बैंक आफ बड़ौदा द्वारा अपने वितरित ऋण का दीर्घकालीन समय के लिए दिया गया। जबकि ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स द्वारा अपने वितरित ऋण का मात्र 5.6 प्रतिशत भाग ही दीर्घकाल समय को दिया गया। इस प्रकार सारणी से यह स्पष्ट है कि जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग मध्यकालीन समय व दीर्घकालीन समय के लिए दिया गया, जिसके अन्तर्गत वृहद् तकनीकी परिवर्तन व उत्पादन के क्षेत्र में अन्य व्यापक सुधारों हेतु ऋण का वितरण किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जनपद में जो दीर्घकाल व अल्पकाल समय के लिए अधिक मात्रा में ऋण दिये गये हैं वह व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों पर सफल साबित हुये हैं। क्योंकि व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण केवल इसी उद्देश्य के लिए ही किया गया था कि कृषि क्षेत्र को दीर्घकालीन ऋण नहीं प्राप्त हो पा रहे थे। क्योंकि सहकारी संगठनों के माध्यम से केवल अल्पकालीन व कुछ हद् तक मध्यकालीन ऋण ही दिये जा रहे थे। अतः दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता पूर्ति हेतु इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जो कहीं हद तक अपने कार्यों में सफल साबित हो रहे हैं। जहां तक बैंक शाखाओं का प्रश्न है, विभिन्न बैंकों द्वारा वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है। क्योंकि किसी बैंक द्वारा अल्पकालीन तो किसी द्वारा मध्यकालीन तथा किसी बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण अधिक मात्रा में दिये गये हैं। किन्तु औसत रूप में दीर्घकालीन व मध्यकालीन ऋण ही ज्यादा दिये गये हैं। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट हो जाता है कि बैंकों द्वारा अधिकाधिक मात्रा में प्रयास किया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर सुधार व विकास करने हेतु जो वित्तीय आवश्यकतायें उत्पन्न हो रही हैं उनकी पूर्ति की जाये।

2. **कन्नौज जनपद :** कन्नौज जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में 7 व्यावसायिक बैंके कार्य कर रही थीं। जिनकी कुल 26 शाखायें कार्यरत हैं जिनके द्वारा जनपद में ग्रामीण साख प्रदान किया जा रहा है। इन शाखाओं द्वारा इस वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता क्षेत्र में 2380300 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। इस वितरित ऋण को विभिन्न समयावधियों को ध्यान में रखकर वितरित किया गया। जिसके विवरण को सारणी संख्या 92 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–92

कन्नौज जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा समय के आधार पर वितरित ऋण का विवरण
वर्ष 2006–07 स्थिति 31 मार्च 2007 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वितरित ऋण का वितरण					
			अल्पकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	मध्यकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	दीर्घकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. बैंक आफ इण्डिया	08	915900	301000	32.9%	312500	34.1%	302400	33.1%
2. स्टेट बैंक	07	783500	287000	36.6%	204500	26.1%	292000	37.3%
3. इलाहाबाद बैंक	04	343600	150000	43.7%	40900	11.9%	152700	4.4%
4. सेन्ट्रल बैंक	01	76800	42200	54.9%	9400	12.2%	22200	28.9%
5. बैंक आफ बड़ौदा	03	146400	21000	14.3%	77900	53.3%	47500	32.4%
6. ओ0बी0सी0	01	67000	17000	25.3%	30800	46.0%	19200	28.7%
7. सिन्डीकेट बैंक	02	47100	11000	23.3%	13500	28.7%	22600	48.0%
योग– 07	**26**	**2380300**	**829200**	**34.8%**	**689500**	**29.0%**	**858600**	**36.2%**

सारणी संख्या 92 से यह स्पष्ट है कि कन्नौज जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में 2380300 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किये गये। जिसमें जनपद में कार्यरत समस्त बैंकों का योगदान रहा है। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण को समय के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जिसके अन्तर्गत 829200 हजार रुपये के ऋण अल्पकालीन समय के लिए दिये गये जो प्राथमिकता क्षेत्र मे वितरित ऋण का 34.8 प्रतिशत है। अल्पकालीन समय के लिए वितरित इस ऋण में विभिन्न बैंक शाखाओं का अलग–अलग

स्रोत – कन्नौज जनपद लीड बैंक कार्यालय से प्रकाशित वार्षिक ऋण पत्रिका वर्ष 2006–07 पर दिये गये आंकड़ों पर आधारित

योगदान रहा है। अल्पकाल समय के लिए किसी बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग 54.9 प्रतिशत सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिया गया। जबकि बैंक आफ बड़ौदा द्वारा अपने वितरित ऋण का मात्र 14.3 प्रतिशत भाग ही अल्पकाल समय के लिए दिया गया, जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित इस ऋण का दूसरा क्षेत्र मध्यकालीन समय रहा है जिसके अन्तर्गत 689500 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 29.0 प्रतिशत रहा है। मध्यकालीन समय में भी परिवर्तन की स्थिति रही है। जिसमें बैंक आफ बड़ौदा द्वारा अपने वितरित ऋण का 53.3 प्रतिशत भाग मध्यकालीन समय के लिए दिये गये। वहीं इलाहाबाद बैंक द्वारा मात्र 11.9 प्रतिशत भाग ही मध्यकालीन समय के लिए दिये गये। जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का तीसरा क्षेत्र दीर्घकालीन समय रहा है। इस दीर्घकालीन समय में 858600 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 36.2 प्रतिशत भाग है। दीर्घकालीन समय के लिए वितरित ऋण में भी परिवर्तन की स्थिति रही है जिसमें किसी बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग 48.0 प्रतिशत सिन्डीकेट बैंक द्वारा दीर्घकालीन समय के लिए दिया गया जबकि 28.7 प्रतिशत ऋण अपने वितरित ऋण का ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स द्वारा दीर्घकालीन समय के लिए दिया गया। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में कार्यरत समस्त बैंकों में परिवर्तन की स्थिति देखने को मिली है क्योंकि किसी बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग अल्पकालीन समय के लिए दिया गया तो किसी बैंक द्वारा दीर्घकालीन व किसी के द्वारा मध्यकालीन ऋणों का अधिक मात्रा में वितरण किया गया है जैसा कि सारणी से स्पष्ट है। किन्तु निष्कर्ष के रूप में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जनपद में औसत रूप से सबसे अधिक ऋण दीर्घकालीन समय के लिए दिये गये जो पूँजी निवेश का एक बड़ा हिस्सा है। अतः कहा जा सकता है कि कन्नौज जनपद में व्यावसायिक बैंक अपने उद्देश्य में किसी सीमा तक सफल ही साबित होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण अन्य संगठित इकाइयों के माध्यम से भी प्राप्त हो जाते थे। किन्तु दीर्घकालीन ऋण अन्य इकाइयों द्वारा नहीं प्राप्त हो पा रहे थे। इन दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति के लिए ही इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिसमें ये बैंकें सफल साबित होती दिखाई दे रही हैं। अतः कहा जा सकता है कि व्यावसायिक बैंकों के द्वारा जनपद में जो दीर्घकाल समय के लिए ऋण का वितरण किया जा रहा है उससे कृषि क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन करना सम्भव हो सका है।

3. **इटावा जनपद :** इटावा जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में कुल 8 व्यावसयिक बैंक कार्यरत थे जिनकी 42 शाखायें कार्य कर रही थीं। इनके द्वारा जनपद में कृषि शाख प्रदान किया जा रहा है। इनके द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 2321865 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किये गये। जो विभिन्न समयावधियों को ध्यान में रखकर वितरित किये गये। इसके विवरण को सारणी संख्या 93 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–93

इटावा जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा समय के आधार पर वितरित ऋण का विवरण
वर्ष 2006–07 स्थिति 31 मार्च 2007 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वितरित ऋण का वितरण					
			अल्पकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	मध्यकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	दीर्घकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. सेन्ट्रल बैंक	14	507887	62427	12.3%	140280	27.6%	305180	60.1%
2. स्टेट बैंक	15	1168082	136679	11.7%	421011	36.0%	610392	52.3%
3. इलाहाबाद बैंक	04	223617	20652	9.2%	31644	14.2%	171321	76.6%
4. बैंक आफ इण्डिया	02	197733	5669	2.9%	87819	44.4%	104245	52.7%
5. बैंक आफ बड़ौदा	02	78580	900	1.2%	68341	87.0%	9339	11.8%
6. पंजाब नेशनल बैंक	03	60310	3315	5.5%	38274	63.5%	18721	31.0%
7 यूनियन बैंक	01	75794	1329	1.8%	22994	30.2%	51534	68.0%
8.. केनरा बैंक	01	9862	0	0	4898	49.7%	4964	50.3%
योग– 08	**42**	**2321865**	**230971**	**10.0%**	**815261**	**35.1%**	**1275696**	**54.9%**

सारणी संख्या 93 से यह स्पष्ट है कि इटावा जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में कुल व्यावसायिक बैंकों की संख्या 8 है जिनकी 42 शाखाओं के द्वारा जनपद में 2321865 हजार रुपये के प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरित किये गये। इस वितरित ऋण में 230971 हजार रुपये या प्राथमिकता क्षेत्र मे वितरित ऋण का 10 प्रतिशत भाग अल्पकालीन समयावधि के लिए ऋण दिये गये। इस अल्पकालीन समयावधि के लिए दिये गये ऋण में जनपद में कार्यरत किसी बैंक द्वारा अपने प्राथमिकता क्षेत्र में दिये गये ऋण का 12.3 प्रतिशत भाग सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिया

स्रोत – इटावा जनपद लीड बैंक कार्यालय से प्रकाशित वार्षिक ऋण पत्रिका वर्ष 2006–07 पर दिये गये आंकड़ों पर आधारित

गया। जो जनपद में अन्य बैंकों की तुलना में अपने वितरित ऋण का अल्पकालीन समय के लिए सबसे अधिक ऋण है। जबकि इसके बाद स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने अपने कुल वितरित ऋण का अल्पकालीन समय के लिए 11.7 प्रतिशत ऋण अल्पकालीन समय के लिए वितरित किया। वहीं इसी समय के लिए केनरा बैंक द्वारा कोई ऋण नहीं वितरित किये गये। इस प्रकार सारणी से यह स्पष्ट है कि प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अल्पकालीन समय के लिए जनपद में कार्यरत विभिन्न बैंकों के ऋण वितरण में परिवर्तन की स्थिति रही है। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण के तहत 815261 हजार रुपये या प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 35.1 प्रतिशत भाग मध्यकालीन समयावधि के लिए दिया गया। मध्यकालीन समयावधि के लिए किसी बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग बैंक आफ बड़ौदा द्वारा 87 प्रतिशत इस समय के लिए दिया गया। इसके बाद 63.5 प्रतिशत भाग अपने वितरित ऋण का पंजाब नेशनल बैंक द्वारा मध्यकालीन समय के लिए दिया गया जबकि इलाहाबाद बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का केवल 14.2 प्रतिशत भाग ही मध्यकालीन समय के लिए दिया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मध्यकालीन समय के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा वितरित ऋण में भी असमानता या परिवर्तन की स्थिति रही है। प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वितरित ऋण में से 1275696 हजार रुपये के ऋण या प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 54.9 प्रतिशत ऋण दीर्घकालीन समय के लिए दिये गये। दीर्घकालीन समय के लिए जनपद में विभिन्न बैंकों द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे ज्यादा भाग इलाहाबाद बैंक द्वारा 76.6 प्रतिशत भाग दीर्घकाल समय के लिए दिया गया। इसके बाद यूनियन बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का 68 प्रतिशत ऋण दीर्घ काल के लिए दिया गया। इसके बाद सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा अपने वितरित ऋण का 60.1 प्रतिशत ऋण दीर्घकाल के लिए दिया गया, जबकि बैंक आफ बड़ौदा द्वारा वितरित अपने ऋण का केवल 11.8 प्रतिशत ऋण ही दीर्घकाल समय के लिए दिया गया। इस प्रकार जनपद में दीर्घकाल समय के लिए वितरित इस ऋण में भी परिवर्तन की स्थिति रही है। सारणी से यह स्पष्ट होता है कि जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत जो ऋण वितरित हुआ है उस वितरित ऋण में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में पूंजीगत निवेश के स्तर को बढ़ाने के लिए या यह कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करने के लिए सबसे ज्यादा ऋण दिये गये। चूंकि तकनीकी साधनों के प्रयोग के लिए अधिक वित्त की आवश्यकता होती है जिसकी बहुत कम समय में अदायगी कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है इसलिए इस ऋण को अधिक समय के लिए दिया जाता है। जो जनपद में दिये गये हैं। इससे

कि जनपद में कृषि क्षेत्र में सुधार या परिवर्तन के लिए अधिक ऋण वितरित किये गये। इसके बाद मध्यम समय के लिए भी अधिक मात्रा में ऋण वितरित किये गये, चूंकि इस समय के लिए भी वितरित ऋण की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक ही रहती है क्योंकि इस समय के लिए जो ऋण वितरित किया जाता है वह भी कृषि क्षेत्र में छोटे स्तर पर तकनीकी परिवर्तन के लिए ही किया जाता है। जिसकी अदायगी कम समय में सम्भव नहीं हो पाती है। इसलिए इस ऋण को भी दीर्घकाल न सही तो मध्यम समय के लिए दिया जाता है। जो दिये भी गये। जनपद में सबसे कम ऋण अल्पकालीन समय के लिए दिये गये। जो इस बात का संकेत है कि व्यावसायिक बैंकों का गठन दीर्घकाल व मध्यकाल ऋण अधिक मात्रा में वितरण के लिए हुआ है न कि अल्पकाल, क्योंकि अल्पकाल के लिए ऋण सहकारी संगठनों के माध्यम से आज भी उपलब्ध हो रहा है। क्योंकि इसके अन्तर्गत कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है जो दैनिक कार्यों में काम आती है। जहां तक दैनिक कार्यों का प्रश्न है व्यक्ति की बहुत लम्बी आवश्यकतायें नहीं होती हैं इसलिए इस ऋण को कम समय के रहते हुये भी अदायगी की जा सकती है इसलिए इस प्रकार के ऋण को अल्पकालीन समय के लिए ही दिया जाता है। जो दिया भी गया।

4. औरैया जनपद : औरैया जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में कुल चार व्यावसायिक बैंकों की 28 शाखायें कार्यरत थीं जिनके द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में 417707 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित यह ऋण विभिन्न समयावधियों के लिए दिये गये जिसके विवरण को सारणी संख्या 94 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–94

औरैया जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा समय के आधार पर वितरित ऋण का विवरण वर्ष 2006–07 स्थिति 31 मार्च 2007 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वितरित ऋण का वितरण					
			अल्पकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	मध्यकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	दीर्घकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. सेन्ट्रल बैंक	19	259442	151098	58.2%	55566	21.4%	52778	20.4%
2. स्टेट बैंक	05	119897	21520	17.9%	22144	18.5%	76263	63.6%
3. इलाहाबाद बैंक	01	16123	5064	31.4%	1728	10.7%	9331	57.9%
4. पंजाब नेशनल बैंक	03	22245	7914	35.6%	7015	31.5%	6316	32.9%
योग– 04	**28**	**417707**	**185596**	**4.4%**	**86423**	**20.7%**	**145688**	**34.9%**

स्रोत – औरैया जनपद लीड बैंक कार्यालय से प्रकाशित वार्षिक ऋण पत्रिका वर्ष 2006–07 पर दिये गये आंकड़ों पर आधारित

सारणी संख्या 94 से यह स्पष्ट है कि औरैया जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में 417707 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किये, प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित इस ऋण में से 185596 हजार रुपये के ऋण या प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 44.4 प्रतिशत ऋण अल्पकाल के लिए दिया गया। अल्पकाल के लिए वितरित इस ऋण में विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग 58.2 प्रतिशत सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा अपने वितरित ऋण का अल्पकाल समय के लिए दिया गया। उसके बाद 35.6 प्रतिशत भाग पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का अल्पकाल के लिए दिया गया, जबकि सबसे कम 17.9 प्रतिशत अपने वितरित ऋण का स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा इस समय के लिए दिया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनपद में अल्पकाल के लिए वितरित ऋण में विभिन्न बैंकों में परिवर्तन की स्थिति रही है। प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वितरित ऋण में 86423 हजार रुपये के ऋण या प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 20.7 प्रतिशत भाग मध्यकालीन समय के लिए दिये गये। मध्यकालीन समय के लिए वितरित इस ऋण में विभिन्न बैंकों द्वारा अपने ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है। क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का 31.5 प्रतिशत ऋण मध्यकाल के लिए जबकि इलाहाबाद बैंक द्वारा केवल अपने वितरित ऋण का 10.7 प्रतिशत भाग ही दिया गया। जो इस बात को स्पष्ट करता है कि जनपद में मध्यकाल में वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है। इसके बाद जनपद में पूंजीगत निवेश के लिए दीर्घकाल समय के लिए 145688 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 24.9 प्रतिशत भाग है। दीर्घकाल के लिए वितरित इस ऋण में भी विभिन्न बैंकों द्वारा अपने वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है, जो इस बात से स्पष्ट होती है कि दीर्घकाल समय के लिए अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग 63.6 प्रतिशत भाग स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिया गया। जबकि सेन्ट्रल बैंक द्वारा केवल 20.4 प्रतिशत भाग ही अपने वितरित ऋण का दीर्घकाल समय के लिए दिया गया जो इस बात की पुष्टि है।

सारणी से यह स्पष्ट होता है कि जनपद में औसत रूप से वितरित ऋण में सबसे अधिक ऋण अल्पकाल व इसके बाद दीर्घकाल समय के लिए दिये गये। तत्पश्चात् मध्यकाल समय के लिए ऋणों का वितरण किया गया।

5. कानपुर नगर जनपद : कानपुर नगर जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में 7 व्यावसायिक बैंकों की 34 शाखायें कार्यरत थीं। जिनके द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में 2021137 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। यह वितरित ऋण विभिन्न समयावधियों को ध्यान में रखकर दिये गये। जिसके विवरण को सारणी संख्या 95 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–95

कानपुर नगर जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा समय के आधार पर वितरित ऋण का विवरण वर्ष 2006–07 स्थिति 31 मार्च 2007 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वितरित ऋण का वितरण					
			अल्पकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	मध्यकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	दीर्घकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. बैंक आफ बड़ौदा	11	568998	301294	52.9%	66840	11.8%	200864	35.3%
2. स्टेट बैंक	07	632295	358758	56.7%	119783	18.9%	153754	24.4%
3. पंजाब नेशनल बैंक	05	138174	115742	83.8%	15044	10.9%	7388	5.3%
4. सेन्ट्रल बैंक	06	154933	58892	38.0%	51612	33.3%	44429	28.7%
5. बैंक आफ इण्डिया	03	261851	22352	8.5%	112834	43.1%	126665	48.4%
6. इलाहाबाद बैंक	01	254913	225308	88.3%	10110	4.0%	19592	7.7%
7 यूको बैंक	01	9973	4172	41.8%	2387	23.9%	3414	34.3%
योग– 07	**34**	**2021137**	**1086518**	**53.8%**	**378610**	**18.7%**	**556106**	**27.5%**

सारणी संख्या 95 से यह स्पष्ट है कि कानपुर नगर जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में 2021137 हजार रुपये के प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरित किये गये। इस वितरित ऋण में से 1086518 हजार रुपये के ऋण अल्पकाल के लिए वितरित किये गये। अल्पकाल के लिए विभिन्न बैंकों के द्वारा अपने वितरित ऋण की स्थिति इस प्रकार रही है। इलाहाबाद बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का 88.3 प्रतिशत, पंजाब नेशनल बैंक का 83.8 प्रतिशत व स्टेट बैंक आफ इण्डिया का 56.7 प्रतिशत भाग अपने वितरित ऋण का अल्पकाल समय के लिए दिया गया वहीं अपने वितरित ऋण का केवल 8.5 प्रतिशत भाग बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिया गया, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि जनपद में अल्पकाल समय के लिए वितरित ऋण में परिवर्तन की

स्रोत – कानपुर नगर जनपद लीड बैंक कार्यालय से प्रकाशित वार्षिक ऋण पत्रिका वर्ष 2006–07 पर दिये गये आंकड़ों पर आधारित

की स्थिति रही है। जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 378610 हजार रुपये के ऋण या प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 18.7 प्रतिशत भाग मध्यकाल समय के लिए दिया गया। इस समय के लिए भी विभिन्न बैंकों द्वारा वितरिण ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है, क्योंकि जहां बैंक आफ इण्डिया द्वारा अपने वितरित ऋण का 43.1 प्रतिशत भाग मध्यकाल समय के लिए दिया गया वहीं इलाहाबाद बैंक द्वारा मात्र 4 प्रतिशत भाग अपने वितरित ऋण का मध्यकाल समय के लिए दिया गया जो इस बात की पुष्टि कर देता है। जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र के तहत शेष ऋण 566106 हजार रुपये या प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 27.5 प्रतिशत भाग दीर्घकाल समय के लिए दिया गया। दीर्घकाल समय में भी विभिन्न बैंकों द्वारा वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति स्पष्ट होती है क्योंकि जहां एक ओर बैंक आफ इण्डिया द्वारा अपने वितरित ऋण का 48.4 प्रतिशत भाग दीर्घकाल के लिए दिया गया वहीं पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का मात्र 5.3 प्रतिशत भाग ही दीर्घकाल समय के लिए दिया गया। जो यह स्पष्ट कर देता है कि जनपद में वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है।

इस प्रकार सारणी से यह स्पष्ट होता है कि जनपद में अपेक्षाकृत पूंजीगत निवेश अन्य धनराशि की तुलना में कम मात्रा में वितरित किये गये हैं जो कि कृषि क्षेत्र में विकास के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता क्योंकि जब तक पूंजीगत निवेश अधिक नहीं होगा तब तक कृषि क्षेत्र में एक बदलाव की स्थिति को नहीं लाया जा सकता, क्योंकि कृषि क्षेत्र में बदलाव की स्थिति तब आयेगी जबकि कृषि क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर नवीन तकनीकी का प्रयोग किया जायेगा। इस नवीन तकनीक के अन्तर्गत कृषि यन्त्र, उपकरण, औजार, सिचाई की सुविधायें, भूमि का समतलीकरण, अच्छे बीज दवाओं का प्रयोग व भूमि का परीक्षण आदि सम्मिलित है जिसके लिए अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है जो कि अल्पकाल समय के लिए दी गई पूंजी के माध्यम से सम्भव नहीं है। क्योंकि अल्पकाल में पूंजी की अदायगी अतिशीघ्र करनी होती है ऐसी स्थिति में कृषक अक्षम साबित होते हैं। अतः बैंकों को चाहिए वह सबसे अधिक मात्रा में पूंजीगत निवेश ही वितरित करें जो कि दीर्घकाल समय में प्रदत्त पूंजी के तहत आते हैं। जनपद में सबसे अधिक अल्पकाल समय के लिए ऋण का वितरण किया गया है। जो कुल वितरित ऋण का 53.8 प्रतिशत है जो धनराशि कार्यशील पूंजी के अन्तर्गत आती है जो दैनिक कार्यों को पूरा करने या कृषि क्षेत्र में सिचाई कर व खाद बीज आदि के प्रयोग करने के काम आती है।

6. कानपुर देहात जनपद : कानपुर देहात जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में 5 व्यावसायिक बैंकों की 29 शाखायें कार्यरत थीं। जिनके द्वारा देहात जनपद में 1387221 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किये गये। यह वितरित ऋण विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न समयावधियों को ध्यान में रखकर दिये गये। अतः प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित इस ऋण को सारणी संख्या 96 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–96

कानपुर देहात जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा समय के आधार पर वितरित ऋण का विवरण वर्ष 2006–07 स्थिति 31 मार्च 2007 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वितरित ऋण का वितरण					
			अल्पकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	मध्यकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	दीर्घकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. बैंक आफ बड़ौदा	12	539342	282030	52.3%	62083	11.5%	195229	36.2%
2. स्टेट बैंक	10	672521	27981	4.2%	45996	6.8%	598544	89.0%
3. पंजाब नेशनल बैंक	03	63855	35270	55.2%	1955	3.1%	26630	41.7%
4. सेन्ट्रल बैंक	02	60965	24022	39.4%	21257	34.9%	15686	25.7%
5. इलाहाबाद बैंक	02	50538	25231	49.9%	5493	10.9%	19814	39.2%
योग– 05	**29**	**1387221**	**394534**	**28.4%**	**196784**	**9.9%**	**855903**	**61.7%**

सारणी संख्या 96 से यह स्पष्ट है कि कानपुर देहात जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में व्यावसायिक बैंकों द्वारा 1387221 हजार रुपये के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किये गये। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित इस ऋण में से 394534 हजार रुपये के ऋण या प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 28.4 प्रतिशत भाग अल्पकालीन समय के लिए दिये गये। अल्पकालीन समय के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा वितरित ऋण में सबसे अधिक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का 55.2 प्रतिशत भाग अल्पकालीन समय के लिए दिया गया। इसके बाद 52.3 प्रतिशत भाग अपने वितरित ऋण का बैंक आफ बड़ौदा द्वारा दिया गया, जबकि स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा अपने वितरित ऋण का मात्र 4.2 प्रतिशत भाग ही अल्पकाल समय के लिए दिया गया जो इस बात को स्पष्ट करता है कि विभिन्न बैंकों द्वारा अल्पकाल समय के लिए अपने वितरित ऋण में

स्रोत – कानपुर देहात जनपद लीड बैंक कार्यालय से प्रकाशित वार्षिक ऋण पत्रिका वर्ष 2006–07 पर दिये गये आंकड़ों पर आधारित

परिवर्तन की स्थिति रही है। 136784 हजार रुपये के ऋण या प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 9.9 प्रतिशत भाग मध्यकालीन ऋण के रुप में दिये गये। मध्यकालीन ऋण के रूप में विभिन्न बैंकों द्वारा अपने वितरित ऋण में सबसे अधिक 34.9 प्रतिशत भाग सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिया गया। इसके बाद बैंक आफ बड़ौदा द्वारा अपने वितरित ऋण का 11.5 प्रतिशत भाग मध्यकालीन ऋण के रूप में दिये गये। जबकि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा मात्र 3.1 प्रतिशत ऋण ही मध्यकालीन समय के लिए दिये गये, जो इस बात की पुष्टि करता है, कि जनपद में विभिन्न बैंकों द्वारा मध्यकालीन समय के लिए वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का शेष भाग 855903 हजार रुपये के ऋण या प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 61.7 प्रतिशत भाग दीर्घकालीन ऋण के रूप में दिये गये। दीर्घकालीन ऋण के रूप में जनपद में कार्यरत विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 89 प्रतिशत भाग दीर्घकाल ऋण के रूप में दिया गया। जबकि सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा मात्र अपने वितरित ऋण का 25.7 प्रतिशत भाग ऋण ही दीर्घकाल ऋण के रूप में दिया गया। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट हो जाता है कि दीर्घकाल ऋण के रूप में विभिन्न बैंकों द्वारा वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है।

जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग दीर्घकालीन ऋण के रूप में 61.7 प्रतिशत भाग दिया गया। जो पूंजीगत निवेश के लिए दिया गया। इससे कृषि अर्थव्यवस्था में व्यापक पैमाने पर सुधार व कृषि यन्त्रीकरण का प्रयोग सम्भव हो सका, जबकि इसके बाद व्यावसायिक बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण के रूप में 28.4 प्रतिशत भाग दिया गया जो कार्यशील पूंजी के रूप में दी गई। कार्यशील पूंजी के अन्तर्गत कृषि उत्पादन से सम्बन्धित समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये ऋण दिये गये। जबकि मध्यकालीन समय के लिए जनपद में सबसे कम मात्र 9.9 प्रतिशत भाग के ऋण ही दिये गये। मध्यकालीन समय के लिए दिये गये ये ऋण लघु पूंजीगत निवेश के रूप में जाने जाते हैं जो कृषि क्षेत्र में छोटे स्तर पर कृषि यन्त्रीकरण का प्रयोग व कृषि से सम्बन्धित अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिये गये हैं।

कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों के द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण के समयावधियों के आधार पर वितरण को प्रत्येक जनपद का अलग–अलग अध्ययन करने के पश्चात् यह बात स्पष्ट होती है कि चूंकि अध्ययन का स्तर सम्पूर्ण क्षेत्र होने के कारण अब सम्पूर्ण क्षेत्र का एक साथ अध्ययन किया जाना अनिवार्य हो जाता है इसी को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2006–07 में कानपुर क्षेत्र में कार्यरत 188 व्यवसायिक बैंक शाखाओं के द्वारा 11016441 हजार रुपये के प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण का वितरण किया गया। जो विभिन्न समयावधियों को ध्यान में रखकर किया गया। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित इस ऋण के सम्पूर्ण विवरण को सारणी संख्या 97 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–97

कानपुर क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों द्वारा समय के आधार पर वितरित ऋण का विवरण
वर्ष 2006–07 स्थिति 31 मार्च 2007 (धनराशि हजार में)

जनपद का नाम	शाखा संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वितरित ऋण का वितरण					
			अल्पकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	मध्यकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	दीर्घकालीन ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. फर्रूखाबाद	29	2488211	543534	21.8%	977060	39.2%	974017	39.1%
2. कन्नौज	26	280300	829200	34.8%	689500	29.0%	858600	36.1%
3. इटावा	42	2321865	230971	10.0%	815261	35.1%	1275696	54.9%
4. औरैया	28	417707	185596	44.4%	86423	20.7%	145688	34.9%
5. कानपुर नगर	34	2021137	1086518	53.8%	378610	18.7%	556106	27.5%
6. कानपुर देहात	29	1387221	394534	28.4%	136784	9.9%	855903	61.7%
योग– 06	**188**	**11016441**	**3270353**	**29.7%**	**3083638**	**28.0%**	**4666010**	**42.3%**

सारणी संख्या 97 से यह स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2006–07 में कार्यरत 188 बैंक शाखाओं के द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में 11016441 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। इस वितरित ऋण में से 3270353 हजार रुपये के ऋण अल्पकालीन ऋण के रूप में दिये गये। जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 29.7 प्रतिशत है। अल्पकालीन ऋण के रूप में वितरित इस ऋण में विभिन्न जनपदों में कार्यरत विभिन्न व्यावसायिक बैंकों व उनकी शाखाओं का अलग–

स्रोत – कानपुर क्षेत्र के समस्त जनपदों में कार्यरत लीड बैंक कार्यालयों से वर्ष2006–07 में प्रकाशित होने वाली वार्षिक ऋण पत्रिका में दिये गये आंकड़ों पर आधारित

अलग स्तर रहा है। क्योंकि विभिन्न जनपदों में अल्पकालीन ऋण के रूप में जो ऋण दिया गया है वह प्रत्येक जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में अपने वितरित ऋण का स्तर इस प्रकार रहा है। कानपुर नगर जनपद में अपने वितरित ऋण का 53.8 प्रतिशत ऋण अल्पकाल ऋण के रूप में दिये गये। जबकि इटावा जनपद में अपने समस्त वितरित ऋण का केवल 10 प्रतिशत भाग ही अल्पकालीन ऋण के रूप में दिये गये। जो इस बात को स्पष्ट करता है कि अल्पकालीन ऋण के रूप में वितरित ऋण में विभिन्न जनपदों में परिवर्तन की स्थिति रही है। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में से 3086638 हजार रुपये के ऋण मध्यकालीन समय के लिये दिये गये। जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 28 प्रतिशत है। मध्यकालीन ऋण के रूप में भी विभिन्न जनपदों में अपने वितरित ऋण में असमानता की स्थिति रही है क्योंकि जहां एक ओर फर्रूखाबाद जनपद द्वारा अपने वितरित ऋण का 39.2 प्रतिशत भाग मध्यकालीन ऋण के रूप में दिये गये। वहीं कानपुर देहात जनपद द्वारा मात्र अपने वितरित ऋण का 9.9 प्रतिशत भाग ही मध्यकालीन ऋण के रूप में दिये गये। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि मध्यकालीन ऋण के वितरण में विभिन्न जनपदों में परिवर्तन की स्थिति रही है। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में से 4666010 हजार रुपये के ऋण दीर्घकालीन ऋण के रूप में दिये गये जो कानपुर क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 42.3 प्रतिशत है। प्राथमिकता क्षेत्र में से दीर्घकालीन ऋण के रूप में विभिन्न जनपदों में वितरण की असमानता की स्थिति रही है। क्योंकि जहां एक ओर कानपुर देहात जनपद द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग 61.7 प्रतिशत ऋण दीर्घकालीन ऋण के रूप में दिये गये वहीं कानपुर नगर जनपद द्वारा मात्र अपने वितरित ऋण का 27.5 प्रतिशत भाग ही दीर्घकालीन ऋण के रूप में वितरित किये गये। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण की तरह दीर्घकालीन ऋण में भी विभिन्न जनपदों में अपने वितरित ऋण में असमानता की स्थिति पाई गई।

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में जो ऋण वितरित किया गया था। उसमें से सबसे अधिक भाग दीर्घकालीन ऋण के रूप में दिया गया। इसके बाद अल्पकाल व मध्यकाल ऋण दिये गये। कहा जा सकता है कि कानपुर क्षेत्र में अपने वितरित ऋण में सबसे अधिक भाग दीर्घकालीन ऋण के रूप में देने क कारण व्यावसायिक बैंकें अपने उद्देश्यों में सफल साबित होती हैं। क्योंकि इन बैंकों का

सृजन दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के रूप में ही हुआ था। क्योंकि दीर्घकाल समय के लिए जो ऋण दिया जाता है उस ऋण के रकम की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हुआ करती है। धनराशि की मात्रा अधिक होने के कारण ही सहकारी संघ इस क्षेत्र में वित्तीय अभाव के कारण असफल साबित हुई थीं जिससे कृषि क्षेत्र में पूंजीगत ढाँचे के निवेश में वृद्धि नहीं हो सकी थी। अतः पूंजीगत निवेश में वृद्धि करने के लिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये बैंकें आज अपने लक्ष्य में सफल साबित होती दिखाई दे रही हैं।

निष्कर्ष : व्यावसायिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में विभिन्न समयावधियों को ध्यान में रखकर ऋण दिये जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में दिन प्रतिदिन के उत्पादन की आवश्यकताओं के लिए अल्पकालीन ऋण दिये जाते हैं। जिनकी अवधि 9 महीने से 15 महीनों तक की होती है। व्यावसायिक बैंकों द्वारा 3270353 हजार रुपये के ऋण कृषि उत्पादन की अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिये गये, मध्यकालीन ऋण की आवश्यकता पूंजी निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत होती है इसके अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण का समय 15 महीने से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। इस समयावधि के लिए कानपुर क्षेत्र में 3083638 हजार रुपये के ऋण दिये गये। कृषि उत्पादन में पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। क्योंकि कृषि उत्पादन के लिए पूंजीगत संसाधन एकत्र करने के लिए एक बड़ी मात्रा में पूंजी के निवेश की आवश्यकता होती है जो व्यावसायिक बैंकों द्वारा ही सम्भव होता है। इन बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋण में से 466010 हजार रुपये के ऋण इस समय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दिये गये।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा इन तीनों प्रकार के ऋणों में मुख्यतया अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्धकालीन ऋण दिये जा रहे हैं। जिसमें कानपुर क्षेत्र में सबसे अधिक दीर्घकालीन ऋण दिये जा रहे हैं। इसके पश्चात् अल्पकाल व मध्यकाल का नम्बर आता है। इन बैंकों द्वारा दिये जाने वाले दीर्घकालीन ऋण को अधिकाधिक मात्रा में प्रोत्सहित किया जाना चाहिए क्योंकि दीर्घकालीन ऋणों से किसान अपने उत्पादन कार्य के लिए आवश्यक पूंजी का प्रबन्ध करने के लिए समर्थ होगा। अतः कृषि को आर्थिक इकाई बनाने के लिए अर्थशास्त्रियों को दो दृष्टिकोण से विचार करना होगा।

प्रथम भूमि सुधार–जिसके लिए हमारे देश की सरकारें प्रयत्नशील हैं पर अर्थशास्त्रियों को यह देखना होगा कि भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है या नहीं। दूसरी ओर किसानों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का प्रबन्ध जिससे किसान अपनी उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ऐसा माना जाता है कि वित्त के संस्थागत स्रोतों के माध्यम से उसे उपयुक्त मात्रा में उचित शर्तों पर ऋण प्राप्त हो सकेगा। जिसके लिए व्यावसायिक बैंक कार्यरत हैं।



अध्याय - सात

व्यापारिक बैंकों से प्राप्त साख के लाभार्थियों का विश्लेषण

अध्याय – सात : व्यापारिक बैंकों से प्राप्त साख के लाभार्थियों का विश्लेषण

वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत प्राथमिक समंकों का प्रयोग कर अध्ययन के लिए 30 प्रतिशत इकाइयों चयन रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर किया गया है। इसके अन्तर्गत कानपुर क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक बैंक की 30 प्रतिशत शाखाओं का अध्ययन के लिए चयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में वितरित ऋण व लाभार्थियों की संख्या तथा साख प्राप्त लाभार्थियों की संख्या का 25 प्रतिशत रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर चयन कर उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को स्पष्ट किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुये सर्वप्रथम जनपद में कार्यरत बैंक संख्या के आधार पर चयनित बैंकों को सारणी संख्या 98 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–98

कानपुर क्षेत्र में अध्ययन के लिए चयनित बैंकिंग इकाइयों का विवरण वर्ष (2006–07)

जनपद का नाम	बैंक का नाम	शाखा संख्या	अध्ययन के लिए चयनित बैंक व शाखा संख्या
1	2	3	4
1. फर्रूखाबाद	बैंक आफ इण्डिया	10	03
	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	05	02
	पंजाब नेशनल बैंक	04	01
	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	03	01
	बैंक आफ बड़ौदा	02	01
	इलाहाबाद बैंक	02	01
	यूनियन बैंक	01	0
	ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स	01	0
	यूको बैंक	01	0
योग :–	**09**	**29**	**09**

जनपद का नाम	बैंक का नाम	शाखा संख्या	अध्ययन के लिए चयनित बैंक व शाखा संख्या
1	2	3	4
2. कन्नौज जनपद	बैंक आफ इण्डिया	08	02
	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	07	02
	इलाहाबाद बैंक	04	01
	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	01	0
	बैंक आफ बड़ौदा	03	01
	ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स	01	01
	सिन्डीकेट बैंक	02	01
योग :–	**07**	**26**	**08**
3. इटावा जनपद	सेन्ट्रल बैंक	14	04
	स्टेट बैंक	15	04
	इलाहाबाद बैंक	04	01
	बैंक आफ इण्डिया	02	01
	बैंक आफ बड़ौदा	02	01
	पंजाब नेशनल बैंक	03	01
	यूनियन बैंक	01	01
	केनरा बैंक	01	0
योग :–	**08**	**42**	**13**
4. औरैया जनपद	सेन्ट्रल बैंक	19	06
	स्टेट बैंक	05	01
	इलाहाबाद बैंक	01	0
	पंजाब नेशनल बैंक	03	01
योग :–	**04**	**28**	**08**

जनपद का नाम	बैंक का नाम	शाखा संख्या	अध्ययन के लिए चयनित बैंक व शाखा संख्या
1	2	3	4
5. कानपुर नगर जनपद	बैंक आफ बड़ौदा	11	03
	स्टेट बैंक	07	02
	पंजाब नेशनल बैंक	05	01
	सेन्ट्रल बैक	06	02
	बैंक आफ इण्डिया	03	01
	इलाहाबाद बैंक	01	01
	यूको बैंक	01	0
योग :–	**07**	**34**	**10**
6. कानपुर देहात जनपद	बैंक आफ बड़ौदा	12	03
	स्टेट बैंक	10	03
	पंजाब नेशनल बैंक	02	01
	सेन्ट्रल बैंक	02	01
	इलाहाबाद बैंक	02	01
योग :–	**05**	**29**	**09**

सारणी संख्या 98 से यह स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की 188 शाखायें कार्यरत हैं। इन कार्यरत 188 शाखाओं में से अध्ययन के लिए 30 प्रतिशत इकाइयों का चयन किया गया है। इन चयनित इकाइयों की संख्या 57 है। जो विभिन्न जनपदों में इस प्रकार है। फर्रूखाबाद जनपद 9, कन्नौज जनपद 8, इटावा जनपद 13, औरैया जनपद 8, कानपुर नगर जनपद 10 वकानपुर देहात जनपद में 9 बैंक शाखाओं का अध्ययन के लिये चयन किया गया है। कानपुर क्षेत्र में कुछ बैंकें ऐसी रही हैं जिनका अध्ययन के लिए चयन नहीं हो सका है उसका कारण यह रहा है या तो उनकी एक ही शाखा जनपद स्तर पर कार्यरत है या फिर बैंक का प्रारम्भिक विकास इन्हीं वर्षों में हुआ है जिसके कारण अध्ययन के लिए चयन से वंचित रहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में इन चयनित बैंकों के द्वारा कानपुर क्षेत्र में वितरित ऋण के विवरण को स्पष्ट करने के लिए क्षेत्र के विभिन्न जनपदों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुये कानपुर क्षेत्र के समस्त जनपदों का अलग–अलग अध्ययन किया जा रहा है।

1. फर्रूखाबाद जनपद : फर्रूखाबाद जनपद में 9 व्यावसायिक बैंकों की 29 शाखायें कार्यरत हैं जिनमें अध्ययन के लिए 9 शाखाओं का चयन किया गया है। इन चयनित शाखाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण के विवरण व साख प्राप्त व्यक्तियों की संख्या को सारणी संख्या 99 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–99
फर्रूखाबाद जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैंकों के द्वारा वितरित ऋण का विवरण वर्ष 2006–07 (धनराशि हजार रुपये में)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	विकास खण्ड का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	साख प्राप्त व्यकितयों की संख्या
1	2	3	4	5
1. बैंक आफ इण्डिया	1. बरखा	राजेपुर	85810	780
	2. चन्दुईयां	नवाबगंज	90768	955
	3. मोहम्दाबाद	मोहम्मदाबाद	103272	1053
2. स्टेट बैंक आफ	1. सचवाड़ा	बढ़पुर	110382	883
इण्डिया	2. कायमगंज	कायमगंज	138042	1061
3. पंजाब नेशनल बैंक	1. शमसाबाद	शमसाबाद	55730	640
4. सेन्ट्रल बैंक	1. फतेहगढ़	बढ़पुर	62310	958
5. बैंक आफ बड़ौदा	1. सठगली	बढ़पुर	61315	340
6. इलाहाबाद बैंक	1. बढ़पुर	बढ़पुर	80625	701
योग :– 06	**09**	**06**	**788257**	**7371**

सारणी संख्या 99 से यह स्पष्ट है कि फर्रूखाबाद जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में अध्ययन के लिए चयनित 9 बैंक शाखाओं द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में 7371 व्यक्तियों को 788257 हजार रुपये के

स्रोत – उपरोक्त समस्त बैंक कार्यालयों के फाइल एल.बी.आर–2 में दिये गये आंकडों पर आधारित

गये। इस वितरित ऋण में सबसे अधिक ऋण स्टेट बैंक की कायमगंज शाखा द्वारा 1061 व्यदित्तयों को 138042 हजार रुपये के ऋण दिये गये जबकि सबसे कम पंजाब नेशनल बैंक की शमसाबाद शाखा 55730 हजार रुपये के ऋण 640 व्यक्तियों के मध्य दिये गये। किन्तु बैंक आफ बड़ौदा की शाखा सठगली द्वारा सबसे कम 340 व्यक्तियों को 61315 हजार रुपये के ऋण दिये गये। इस प्रकार सारणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि जनपद में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों द्वारा परिवर्तन की स्थिति में ऋण का वितरण किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि जनपद की व्यावसायिक बैंक शाखाओं में किसी शाखा द्वारा बहुत अधिक ऋण दिया गया, जबकि किसी बैंक शाखा द्वारा काफी कम मात्रा में ऋण का वितरण किया गया है। जनपद में वितरित यह ऋण विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिया गया। अतः इस वितरित ऋण को विभिन्न समयावधियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2006–07 में वितरित ऋण के विवरण को सारणी संख्या 100 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–100

फर्रूखाबाद जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैंकिंग इकाइयों द्वारा समय के आधार पर ऋण का वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	लाभार्थियों की संख्या	अल्पकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	मध्यकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	दीर्घकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. बैंक आफ इण्डिया	वरखा	85810	780	28317	32.9%	410	31017	36.2%	242	26476	30.9%	128
	चन्दुइयां	90768	955	27230	30%	485	29954	33%	253	33584	37%	219
	मोहम्दाबाद	103272	1053	28917	28%	506	30982	30%	233	43373	42%	314
2. स्टेट बैंक	सचवाड़ा	110382	883	41954	38%	598	26492	24%	121	41936	38%	164
	कायमगंज	138042	1061	38634	28%	600	44173	32%	259	55235	40%	202
3. पंजाब ने0बैं0	शमशाबाद	55730	640	10589	19%	341	32324	58%	152	12817	23%	147
4. सेन्ट्रल बैंक	फतेहगढ़	62310	958	6231	10%	497	24924	40%	223	31155	50%	238
5. बैंक आफ बड़ौदा	सठगली	61315	340	3065	05%	103	37386	61%	137	20864	34%	100
6. इलाहाबाद बैंक	बढ़पुर	80628	701	12094	15%	363	36283	45%	166	32251	40%	172
योग– 06	**09**	**788257**	**7371**	**317031**	**25%**	**3903**	**293535**	**37.2%**	**1786**	**297691**	**37.8%**	**1682**

स्रोत – फर्रूखाबाद जनपद में अध्ययन के लिए उपरोक्त समस्त बैंक शाखाओं के एल.बी.आर. फाइल–2 में दिये गये आंकडों पर आधारित।

सारणी संख्या 100 से यह स्पष्ट है कि फर्रूखाबाद जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में अध्ययन के लिए चयनित 9 बैंक शाखाओं द्वारा 7371 व्यक्तियों को 788257 हजार रुपये के ऋण दिये गये। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित इस ऋण में से 25 प्रतिशत ऋण 3903 व्यक्तियों को अल्पकालीन ऋण के रूप में 197031 हजार रुपये के ऋण दिये। अल्पकाल समय में दिये गये इस ऋण में विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग स्टेट बैंक आफ इण्डिया की सचवाड़ा शाखा द्वारा 38 प्रतिशत ऋण अल्पकाल समय के लिए दिये गये जबकि बैंक आफ बड़ौदा की सठगली शाखा द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में अपने वितरित ऋण का मात्र 5 प्रतिशत भाग ही अल्पकाल समय के लिए दिया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अल्पकाल समय में वितरित ऋण में विभिन्न शाखाओं में परिवर्तन की स्थिति रही है। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 37.2 प्रतिशत ऋण 1786 व्यक्तियों के मध्य 293535 हजार रुपये के ऋण मध्यकाल समय के लिए दिये गये। मध्यकाल समय में वितरित इस ऋण में जनपद के विभिन्न बैंक शाखाओं का स्तर भी अलग–अलग रहा है। जिसमें बैंक आफ बड़ौदा द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में अपने वितरित ऋण का 61 प्रतिशत भाग मध्यकालीन समय के लिए दिये गये। जबकि स्टेट बैंक आफ इण्डिया की सचवाड़ा शाखा द्वारा मात्र 24 प्रतिशत भाग ही मध्यकाल समय के लिए दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकाल समय में भी वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 37.8 प्रतिशत ऋण 1682 व्यक्तियों को 297691 हजार रुपये के ऋण दीर्घकाल समय के लिए वितरित किये गये। दीर्घकाल समय में वितरित इस ऋण में भी विभिन्न बैंक शाखाओं के मध्य वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है क्योंकि सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की फतेहगढ़ शाखा द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में अपने वितरित ऋण का 50 प्रतिशत भाग दीर्घकाल समय के लिए वितरित किया गया जबकि पंजाब नेशनल बैंक की शमशाबाद शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का मात्र 23 प्रतिशत ऋण ही दीर्घकाल समय के लिए वितरित किया गया। इस प्रकार सारणी से यह स्पष्ट है कि जनपद में विभिन्न बैंक शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग ऋण दीर्घकाल समय के लिए दिया गया। जबकि सबसे कम ऋण भाग अल्पकाल समय के लिए दिया गया। किन्तु यदि हम लाभार्थियों की संख्या की दृष्टिकोण से देखें तो इसके ठीक विपरीत की स्थिति रही है। क्योंकि सबसे अधिक व्यक्तियों को अल्पकाल समय के लिए ऋण प्राप्त हो सका है जबकि सबसे कम व्यक्तियों को दीर्घकाल समय के लिए ऋण प्राप्त हो सका है।

जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में जो ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किया गया है वह विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दिया गया है अतः उद्देश्यों के आधार पर वितरित इस ऋण के विवरण को सारणी संख्या 101 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–101

फर्रूखाबाद जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैंकिंग इकाइयों द्वारा उद्देश्य के आधार पर ऋण का वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का विभिन्न क्षेत्रों में वितरण								लघु क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	अन्य प्रा0प्रा0 क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या
						ट्रैक्टर एवं कृषि यन्त्र	लाभार्थी संख्या	लघु सिंचाई	लाभार्थी संख्या	फसली ऋण	लाभार्थी संख्या	अन्य कृषि ऋण	लाभार्थी संख्या						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. बैंक आफ इण्डिया	वरखाा	85810	54793	63.9%	538	12691	47	10271	20	28317	410	3514	61	10804	12.5%	83	20213	23.6%	159
	चन्दुइयां	90768	60784	67%	704	23800	70	7320	12	27230	485	2464	137	11217	12.4%	49	18737	20.6%	170
	मोहम्दाबाद	103272	72290	70%	820	26720	82	12130	43	28917	506	4523	189	14913	14.4%	87	16069	15.6%	146
2. स्टेट बैंक	सचवाड़ा	110382	83890	76%	762	20915	43	12210	28	41954	598	8811	93	7167	6.5%	30	19325	17.5%	91
	कायमगंज	138042	93869	68%	802	38634	90	9595	34	38634	600	7006	78	12256	8.9%	93	31917	23.1%	166
3. पंजाब ने0बैं0	शमशाबाद	55730	23406	42%	488	9088	30	1110	15	10589	341	2619	102	20510	36.8%	86	11814	21.2%	66
4. सेन्ट्रल बैंक	फतेहगढ़	62310	37386	60%	735	21318	45	585	08	6231	497	9252	185	9025	14.5%	42	15899	25.5%	181
5. बैंक आफ बड़ौदा	सठगली	61315	23929	39%	203	10252	29	4035	19	3065	103	6577	52	15676	25.6%	38	21710	35.4%	.99
6. इलाहाबाद बैंक	बढ़पुर	80628	44345	55%	535	19715	45	4330	30	12094	363	8206	97	12510	15.5%	29	23773	29.5%	137
योग– 06	**09**	**788257**	**494692**	**62.8%**	**5587**	**183123**	**481**	**61586**	**209**	**197031**	**3903**	**52972**	**994**	**114078**	**14.4%**	**537**	**179455**	**22.8%**	**1215**

स्रोत – फर्रूखाबाद जनपद में अध्ययन के लिए उपरोक्त समस्त बैंक शाखाओं के एल.बी.आर. फाइल–2 में दिये गये आंकडों पर आधारित।

सारणी संख्या 101 से यह स्पष्ट है कि फर्रूखाबाद जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में व्यावसायिक बैंक की 9 शाखाओं द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में 788257 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। यह वितरित ऋण विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दिये गये। जिसके अन्तर्गत 5587 व्यक्तियों को 494692 हजार रुपये के कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण का वितरण किया गया। कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत वितरित यह ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 62.8 प्रतिशत है। विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में अपने वितरित ऋण में से कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का स्तर असमान रहा है। क्योंकि प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत वितरित ऋण का स्टेट बैंक आफ इण्डिया की सचवाड़ा शाखा द्वारा 76 प्रतिशत ऋण को कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए दिया गया, जो किसी बैंक द्वारा वितरित अपने ऋण का सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में दिया गया ऋण है जबकि अपने वितरित ऋण का सबसे कम भाग कृषि क्षेत्र में वितरित करने वाली बैंक शाखा बैंक आफ बड़ौदा की शाखा सठगली द्वारा दिया गया। जिसके द्वारा अपने वितरित ऋण का 39 प्रतिशत भाग मात्र ही कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए दिया गया। इससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण में असमानता रही है।

जनपद में कृषि क्षेत्र में वितरित यह ऋण विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दिया गया जैसे ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण क्रय करना। इसके लिए जनपद में 481 व्यक्तियों को 183123 हजार रुपये के ऋण दिये गये। जिसमें विभिन्न बैंकों में सबसे ज्यादा स्टेट बैंक आफ इण्डिया की कायमगंज शाखा द्वारा व्यक्तियों को दिया गया। जहां 90 व्यक्तियों को 38634 हजार रुपये के ऋण ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यन्त्र/उपकरण क्रय करने के लिए दिये गये। जबकि इन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक की शमशाबाद शाखा द्वारा केवल 30 व्यक्तियों को 9088 हजार रुपये के ऋण दिये गये। इस प्रकार इन यन्त्रों के क्रय करने में भी विभिन्न बैंकों द्वारा असमानता की स्थिति प्रकट होती हैं, 209 व्यक्तियों को 61586 हजार रुपये के ऋण लघु सिचाई की व्यवस्था करने के लिए ऋण उपलब्ध कराये गये। जिसमें सबसे अधिक बैंक आफ इण्डिया की मोहम्दाबाद शाखा द्वारा ऋण दिये गये जबकि सबसे कम सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की फतेहगढ़ शाखा द्वारा केवल 585 हजार रुपये के ऋण ही दिये गये, 3903 व्यक्तियों को 197031 हजार रुपये के फसली ऋण दिये गये। यह ऋण विभिन्न बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी के रूप में दिये गये व 994 व्यक्तियों को 52972 हजार रुपये के विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा अन्य कृषि कार्य करने के लिए ऋण वितरित किये गये थे। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण इन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिये गये, कृषि क्षेत्र के अलावा 537 व्यक्तियों को 114078 हजार रुपये के लघु एवं कुटीर उद्योग संचालित करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 14.4 प्रतिशत ऋण दिये गये तथा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का शेष भाग 1215 व्यक्तियों को 179455

हजार रुपये के अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कार्यों को पूरा करने के लिए ऋण दिये गये। यह प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत वितरित ऋण का 22.8 प्रतिशत है। इसमें भी विभिन्न बैंकों के द्वारा अपने वितरित ऋण में से अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में असमानता की स्थिति रही है।

इस प्रकार सारणी से यह स्पष्ट है कि जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत जो भी ऋण वितरित किये गये हैं उसमें से सबसे अधिक भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र को दिये गये हैं जबकि इसके अलावा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को व लघु उद्योग तथा सेवा एवं फुटकर व्यापार आदि कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा ऋणों का वितरण किया गया।

2. **कन्नौज जनपद :** कन्नौज जनपद में कुल 7 बैंकों की 26 शाखायें विभिन्न विकास खण्डों में कार्यरत हैं जिनके द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋणों का वितरण किया जा रहा है। इन विभिन्न शाखाओं में से जनपद में अध्ययन के लिए 6 बैंकों की 8 शाखाओं का 6 विकास खण्डों के अन्तर्गत चयन किया गया है। इन चयनित बैंक शाखाओं को सैम्पल इकाई कहा गया है। इन सैम्पल इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में जनपद में वितरित ऋण एवं लाभार्थियों की संख्या को सारणी संख्या 102 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–102

कन्नौज जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैंकों के द्वारा वितरित ऋण का विवरण

वर्ष 2006–07 (धनराशि हजार रुपये में)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	विकास खण्ड का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	साख प्राप्त व्यकितयों की संख्या
1	2	3	4	5
1. बैंक आफ इण्डिया	1. सौरिख	सौरिख	121040	703
	2. कन्नौज	कन्नौज	90987	492
2. स्टेट बैंक आफ	1. जलालाबाद	जलालाबाद	128950	636
इण्डिया	2. छिबरामऊ	छिबरामऊ	103215	572
3. इलाहाबाद बैंक	1. तिर्वा	उमर्दा	87965	549
4. बैंक आफ बड़ौदा	1. गुरसहायगंज	तालग्राम	39725	305
5. ओ0बी0सी0	1. छिबरामऊ	छिबरामऊ	67000	411
6. सिन्डीकेट बैंक	1. कन्नौज	कन्नौज	20921	190
योग :– 06	**08**	**06**	**659803**	**3858**

स्रोत – उपरोक्त समस्त बैंक कार्यालयों के फाइल एल.बी.आर–2 में दिये गये आंकडों पर आधारित

सारणी संख्या 102 से यह स्पष्ट है कि कन्नौज जनपद में 6 बैंकों की 8 शाखाओं द्वारा 3858 व्यक्तियों को 659803 हजार रुपये के वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरित किये। इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंक शाखाओं का अलग–अलग योगदान रहा है। जिसमें स्टेट बैंक आफ इण्डिया की जलालाबाद बैंक शाखा द्वारा 128950 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये जबकि सबसे कम सिन्डीकेट बैंक की कन्नौज शाखा द्वारा मात्र 20921 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। जनपद में सबसे अधिक व्यक्तियों को बैंक आफ इण्डिया की सौरिख शाखा द्वारा 703 व्यक्तियों को ऋण दिये गये, जबकि सबसे कम 190 व्यक्तियों को सिन्डीकेट बैंक की कन्नौज शाखा द्वारा दिये गये।

प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित यह ऋण विभिन्न समयाविधियों को ध्यान में रखकर दिये गये। अतः जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण को विभिन्न समयावधियों के आधार पर वितरण को सारणी संख्या 103 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–103

कन्नौज जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैंकिंग इकाइयों द्वारा समय के आधार पर ऋण का वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	लाभार्थियों की संख्या	अल्पकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	मध्यकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	दीर्घकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. बैंक आफ इण्डिया	सौरिख	121040	703	39943	33%	325	41154	34%	290	39943	33%	88
	कन्नौज	90987	492	27296	30%	237	32755	36%	145	30936	34%	110
2. स्टेट बैंक	जलालाबाद	128950	636	45133	35%	334	28369	22%	210	55448	43%	92
	छिबरामऊ	103215	572	29932	29%	256	30965	30%	158	42318	41%	158
3. इलाहाबाद बैंक	तिर्वा	87965	549	39584	45%	384	13195	15%	125	35186	40%	40
4. बैंक आफ बड़ौदा	गुरसहायगंज	39725	305	4370	11%	95	19863	50%	173	15492	39%	37
5. ओ0बी0सी0	छिबरामऊ	67000	411	17000	25.3%	175	30800	46%	139	19200	28.7%	97
6. सिन्डीकेट	कन्नौज	20921	190	6276	30%	85	6276	30%	90	8369	40%	15
योग– 06	08	659803	3858	209534	31.8%	1891	203377	30.8%	1330	246892	37.4%	637

स्रोत – कन्नौज जनपद में अध्ययन के लिए उपरोक्त समस्त बैंक शाखाओं के एल.बी.आर. फाइल–2 में दिये गये आंकडों पर आधारित।

सारणी संख्या 103 से यह स्पष्ट है कि कन्नौज जनपद में 6 बैंकों की 8 शाखाओं द्वारा 3858 व्यक्तियों को 659803 हजार रुपये के वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरित किये। इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंक शाखाओं का अलग–अलग योगदान रहा है। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित इस ऋण में से 1891 व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 31.8 प्रतिशत या 209534 हजार रुपये के ऋण अल्पकालीन समय के लिए दिये गये। अल्पकालीन समय के लिए वितरित इस ऋण में किसी बैंक शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग इलाहाबाद बैंक की तिर्वा शाखा द्वारा 39584 हजार रुपये या प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 45 प्रतिशत भाग 384 व्यक्तियों को अल्पकाल समय के लिए दिये गये। जबकि जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का सबसे कम भाग बैंक आफ बड़ौदा की गुरसहायगंज शाखा द्वारा 4370 हजार रुपये या प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का मात्र 11 प्रतिशत भाग 95 व्यक्तियों को अल्पकाल समय के लिए ऋण दिये गये इससे यह स्पष्ट होता है कि अल्पकाल समय के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 30.8 प्रतिशत या 203377 हजार रुपये के ऋण 1330 व्यक्तियों को मध्यकालीन समय के लिए दिये गये। मध्यकालीन समय के लिए जनपद में वितरित इस ऋण में भी विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा अपने वितरित ऋण में असमानता की स्थिति रही है क्योंकि बैंक आफ बड़ौदा की गुरसहायगंज शाखा द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में अपने वितरित ऋण का 50 प्रतिशत भाग ऋण 173 व्यक्तियों को 19863 हजार रुपये के ऋण दिये गये। जबकि इलाहाबाद बैंक तिर्वा शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का मात्र 15 प्रतिशत भाग 125 व्यक्तियों को 13195 हजार रुपये के ऋण दिये गये। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनपद में विभिन्न शाखाओं द्वारा अपने वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 37.4 प्रतिशत भाग 637 व्यक्तियों को 246892 हजार रुपये के ऋण दीर्घकालीन समय के लिए दिये गये। दीर्घकालीन समय के लिए वितरित इस ऋण में भी जनपद की विभिन्न शाखाओं द्वारा इस समय के लिए वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है क्योंकि स्टेट बैंक आफ इण्डिया की जलालाबाद शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का 43 प्रतिशत भाग 92 व्यक्तियों को 5448 हजार रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिये गये। जो किसी बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का दीर्धकाल समय के लिए सबसे अधिक भाग है। जबकि ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स की छिबरामऊ शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का मात्र 28.7 प्रतिशत भाग ही 97 व्यक्तियों को 19200 हजार रुपये के ऋण दिये गये जो किसी बैंक द्वारा दिये गये ऋण का सबसे कम भाग है। जो यह स्पष्ट करता है कि जनपद में दीर्घकाल समय के लिए वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग दीर्घकाल समय के लिए दिया गया जो इस बात का संकेत है कि जनपद में सबसे अधिक पूंजी निवेश एक बड़े क्षेत्र में किया गया। इसके बाद अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण दिये गये। जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में यह वितरित ऋण विभिन्न उद्‌देश्यों को ध्यान में रखकर दिये गये हैं जिसके विवरण को सारणी संख्या 104 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–104

कन्नौज जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैंकिंग इकाइयों द्वारा उद्देश्य के आधार पर ऋण का वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का विभिन्न क्षेत्रों में वितरण								लघु क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	अन्य प्रा0प्रा0 क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या
						ट्रैक्टर एवं कृषि यन्त्र	लाभार्थी संख्या	लघु सिचाई	लाभार्थी संख्या	फसली ऋण	लाभार्थी संख्या	अन्य कृषि ऋण	लाभार्थी संख्या						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. बैंक आफ इण्डिया	सौरिख	121040	79886	66%	413	18545	43	10125	15	39943	325	11273	30	17253	14.3%	125	23901	19.7%	165
	कन्नौज	90987	58232	64%	347	24262	57	5010	13	27296	237	1664	40	12510	13.8%	65	20245	22.2%	80
2. स्टेट बैंक	जलालाबाद	128950	100581	78%	426	33236	48	8096	10	45133	334	14116	34	10185	7.9%	85	18184	14.1%	125
	छिबरामऊ	103215	72250	70%	414	30067	58	4590	25	29932	256	7661	75	10776	10.4%	64	20189	19.6%	94
3. इलाहाबाद बैंक	तिर्वा	87965	74770	85%	424	25156	20	4268	11	39584	384	5762	09	4592	5.2%	48	8603	9.8%	77
4. बैंक आफ बड़ौदा	गुरसहायगंज	39725	19862	50%	132	10971	15	2023	07	4370	95	2498	15	8213	20.7%	65	11650	29.3%	108
5. ओ0बी0सी0	छिबरामऊ	67000	36200	54%	272	10983	18	3510	19	17000	175	4707	60	2700	4.1%	43	28100	41.9%	96
6. सिन्डीकेट	कन्नौज	20921	14645	70%	100	7010	10	359	02	6276	85	1000	03	983	4.7%	20	5293	25.3%	70
योग– 06	08	659803	456426	69.2%	2528	160230	269	37981	102	209534	1891	48681	266	67212	10.2%	515	136165	20.6%	815

स्रोत – कन्नौज जनपद में अध्ययन के लिए उपरोक्त समस्त बैंक शाखाओं के एल.बी.आर. फाइल–2 में दिये गये आंकडों पर आधारित।

सारणी संख्या 104 से यह स्पष्ट है कि कन्नौज जनपद में 6 बैंकों की 8 शाखाओं द्वारा 659803 हजार रुपये के प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरित किये गये। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित यह ऋण विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दिये गये। जिसके अन्तर्गत 2528 लाभार्थियों को 456426 हजार रुपये के ऋण या प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 69.2 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए दिये गये। विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में से कृषि क्षेत्र में ऋण का वितरण सबसे अधिक इलाहाबाद बैंक की तिर्वा शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का 85 प्रतिशत स्टेट बैंक आफ इण्डिया की जलालाबाद शाखा द्वारा 78 प्रतिशत जबकि बैंक आफ बड़ौदा की गुरसहायगंज शाखा द्वारा 50 प्रतिशत भाग ही अपने वितरित ऋण का कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया गया। कृषि क्षेत्र में यह वितरित ऋण विभिन्न उद्देश्यों या विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया गया। जिसके अन्तर्गत 269 व्यक्तियों को 160230 हजार रुपये के ऋण ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यन्त्र उपकरण क्रय करने के लिए दिये गये। ट्रैक्टर एवं कृषि यन्त्र उपकरण क्रय करने के लिए भी विभिन्न बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में परिवर्तन रहा है, 102 व्यक्तियों को 37981 हजार रुपये के ऋण सिचाई सुविधाओं की आपूर्ति के लिए दिये गये। जिसके अन्तर्गत पम्प सेट क्रय करना, विद्युत मोटर क्रय करना, डीप बोरिंग, समरसेबिल बोरिंग, तालाब भराई आदि कार्यों के लिए दिये गये। इस कार्य के लिए भी विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा दिये गये ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है, 1891 व्यक्तियों को 209534 हजार रुपये के फसली ऋण दिये गये। जिसको कार्यशील पूंजी कहते हैं इस ऋण के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में दिन–प्रतिदिन आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्त प्रदान किये गये जिसके अन्तर्गत खाद, बीज, रासायनिक दबायें, कीटनाशक छिड़काव मशीन, लगान व अन्य रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वित्त प्रदान किये गये व 266 व्यक्तियों को 48681 हजार रुपये के अन्य कृषि कार्य करने के लिए वित्त प्रदान किये गये। अन्य कृषि कार्य के अन्तर्गत कृषि से सम्बन्धित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के क्षेत्र आते हैं। जो कृषि क्षेत्र में सहायक आय के स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं। जनपद में इस प्रकार के ऋण वितरण में भी विभिन्न बैंक शाखाओं में परिवर्तन की स्थिति देखो गयी।

जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में से 515 व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 10.2 प्रतिशत या 67212 हजार रुपये के ऋण लघु एवं कुटीर उद्योग में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिये गये। इसके अन्तर्गत मशीनों को क्रय करने, कच्चे माल क्रय करने, विद्युत बिल भुगतान करने व अन्य तमाम सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण दिये गये। लघु उद्योग क्षेत्र में वितरित इस ऋण में भी अन्य क्षेत्रों की तरह व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए बैंक आफ बड़ौदा की गुरसहायगंज शाखा द्वारा 65 व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 20.5 प्रतिशत ऋण लघु उद्योग के लिए दिया, जो किसी बैंक शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग है वहीं ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स की छिबरामऊ शाखा द्वारा 43 व्यक्तियों को प्राथमिकता

क्षेत्र में वितरित ऋण का मात्र 4.1 प्रतिशत भाग ही दिया गया, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि जनपद में लघु उद्योग क्षेत्र में विभिन्न बैंकों द्वारा वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है।

प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में से 815 व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 20.6 प्रतिशत या 136155 हजार रुपये के ऋण अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिये गये। अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि सम्बन्धित सहायक क्षेत्र आते हैं। जैसे– सघन मिनी डेरी, अन्य दुधारू पशु व अन्य पालतू पशु क्रय करने व उनके रख–रखाव के लिए दान–चारा इत्यादि की व्यवस्था करने तथा उनके आवास की व्यवस्था करने के लिए भवन निर्माण आदि के लिए दिये जाने वाले ऋण व इससे हटकर मतस्य पालन, मुर्गी पालन आदि क्षेत्रों के लिए दिये जाने वाले ऋण से है। इस क्षेत्र के लिए भी जनपद में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है, क्योंकि विभिन्न बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में अपने वितरित ऋण में से 41.9 प्रतिशत भाग ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स की छिबरामऊ शाखा द्वारा 96 व्यक्तियों को अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण दिये गये जो किसी भी बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में दिये गये ऋण में सबसे अधिक भाग है। वहीं इलाहाबाद बैंक की तिर्वा शाखा द्वारा 77 व्यक्तियों को अपने वितरित ऋण का मात्र 9.8 प्रतिशत भाग ही अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को दिया गया जो किसी बैंक द्वारा इस क्षेत्र को दिये गये अपने ऋण का सबसे कम भाग है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि निशचित तौर पर अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में सबसे अधिक भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए दिया गया, जबकि इसके बाद कृषि क्षेत्र में ही सहायक क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए जैसे अन्य प्राथमिकता क्षेत्र व लघु उद्योग क्षेत्र आदि क्षेत्रों में ऋण का वितरण किया गया।

3. इटावा जनपद : इटावा जनपद में 8 व्यावसायिक बैंकों की 42 शाखायें कार्यरत हैं। जिनके द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण का वितरण किया जा रहा है। इटावा जनपद में इन कार्यरत बैंकों व उनकी शाखाओं में से विस्तृत अध्ययन के लिए 7 बैंकों की 13 शाखाओं का अध्ययन के लिए चयन किया गया है। जिनके द्वारा वितरित ऋण व लाभार्थियों की संख्या आदि को स्पष्ट किया जाना है इसी के तहत वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण व लाभार्थियों की संख्या को सारणी संख्या 105 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या –105

इटावा जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैंकों के द्वारा वितरित ऋण का विवरण

वर्ष 2006–07 (धनराशि हजार रुपये में)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	विकास खण्ड का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	साख प्राप्त व्यकितयों की संख्या
1	2	3	4	5
1. सेन्ट्रल बैंक	1. बकेवर	महेबा	15524	513
	2. भरथना	भरथना	14887	487
	3. पिपरौली गढ़िया	चकरनगर	10555	208
	4. जसवन्त नगर	जसवन्त नगर	113999	1428
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	1. लखना	महेबा	82120	1353
	2. सरसई नावर	ताखा	34983	1089
	3. बसरेहर	बसरेहर	80599	1309
	4. जसवन्त नगर	जसवन्त नगर	107020	1674
3. इलाहाबाद बैंक	1. चौपला (टकरपुरा)	ताखा	120502	2220
4. बैंक आफ इण्डिया	1. इटावा	सैफई	197733	746
5. बैंक आफ बड़ौदा	1. इटावा	बढ़पुरा	49001	259
6. पंजाब नेशनल बैंक	1. इटावा कचहरी रोड	बसरेहर	21506	321
7. यूनियन बैंक	1. इटावा	बढ़पुरा	75794	566
योग :– 07	**13**	**08**	**924223**	**12173**

सारणी संख्या 105 से यह स्पष्ट है कि इटावा जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में कार्यरत 7 व्यावसायिक बैंकों की 13 शाखाओं द्वारा 8 विकास खण्डों में 12173 व्यक्तियों को 924223 हजार रुपये के प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरित किये। यह ऋण विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिये गये। जनपद में वितरित इस ऋण में सबसे अधिक योगदान बैंक आफ इण्डिया की इटावा शाखा द्वारा 197733 हजार रुपये के 746 व्यक्तियों को ऋण दिये गये जबकि इस वितरित ऋण में सबसे कम योगदान पंजाब नेशनल बैंक की इटावा शाखा द्वारा 321 व्यक्तियों को 21506 हजार रुपये के ऋण दिये गये। बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में इस भारी मात्रा परिवर्तन की स्थिति रही है। जनपद में वितरित यह ऋण विभिन्न समयों के लिए दिया गया। जिसको सारणी संख्या 106 से स्पष्ट किया जा सकता है।

स्रोत – उपरोक्त समस्त बैंक कार्यालयों के फाइल एल.बी.आर–2 में दिये गये आंकडों पर आधारित

सारणी संख्या–106

इटावा जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैंकिंग इकाइयों द्वारा समय के आधार पर ऋण का वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	लाभार्थियों की संख्या	अल्पकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	मध्यकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	दीर्घकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. सेन्ट्रल बैंक	बकेवर	15524	513	5894	38%	334	4041	26%	83	5589	36%	96
	भरथना	14887	487	2375	16%	149	2359	15.8%	48	10153	68.2%	278
	पिपरौली (गढ़िया)	10555	208	2658	25.2%	118	233	2.2%	08	7664	72.6%	92
	जसवन्त नगर	113999	1428	16613	14.6%	689	19854	17.4%	294	77552	68%	346
2. स्टेट बैंक आफ	लखना	82120	1353	18659	22.7%	731	15695	19.1%	208	47766	58.2%	414
इण्डिया	सरसई नावा	34983	1089	12826	36.7%	730	2030	5.8%	153	20077	57.5%	230
	वसरेहर	80599	1309	18444	22.9%	1057	0	0	0	62155	77.1%	252
	जसवन्त नगर	107020	1674	26263	24.5%	1011	13545	12.7%	142	67212	62.8%	521
3. इलाहाबाद बैंक	चौपला (टकपुरा)	120502	2220	39490	32.8%	1206	6593	5.5%	272	74419	61.8%	742
4. बैंक आफ इण्डिया	इटावा	197733	746	8037	4.1%	243	87819	44.4%	410	101877	51.5%	101
5. बैंक आफ बड़ौदा	इटावा	49001	259	0	0	0	40577	82.8%	248	8424	17.2%	11
6. पंजाब ने0 बैंक	इटावा (क.रोड)	21506	321	5740	26.7%	110	15766	73.3%	212	0	0	0
7. यूनियन बैंक	इटावा	75794	566	5470	7.2%	113	22931	30.3%	247	47393	62.5%	206
योग– 07	13	924223	12173	162469	17.6%	6491	231443	25%	2325	530281	57.4%	3289

स्रोत – इटावा जनपद में अध्ययन के लिए उपरोक्त समस्त बैंक शाखाओं के एल.बी.आर. फाइल–2 में दिये गये आंकडों पर आधारित।

सारणी संख्या 106 से यह स्पष्ट है कि इटावा जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में कार्यरत 7 व्यावसायिक बैंकों की 13 शाखाओं द्वारा जनपद में 12173 व्यक्तियों को 924223 हजार रुपये के प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरित किये गये। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित इस ऋण में से 6491 व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 17.6 प्रतिशत या 162469 हजार रुपये के अल्पकालीन समय की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण वितरित किये गये। जनपद में विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा अल्पकालीन समय के लिए अपने वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है, क्योंकि सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की बकेवर शाखा द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में अपने वितरित ऋण का 38 प्रतिशत भाग अल्पकालीन समय के लिए 334 व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया गया। जो जनपद में किसी बैंक शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का अल्पकालीन समय में सबसे अधिक भाग है वहीं अपने वितरित ऋण का सबसे कम भाग बैंक आफ बड़ौदा की इटावा मुख्य शाखा द्वारा अल्पकालीन समय के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई ऋण नहीं दिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनपद में अल्पकालीन समय के लिए वितरित ऋण में बैंकों के मध्य परिवर्तन की स्थिति रही है।

प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 2325 व्यक्तियों को 25 प्रतिशत या 231443 हजार रुपये के ऋण मध्यकालीन समय की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए दिये गये। मध्यकालीन समय में जनपद में वितरित इस ऋण में विभिन्न बैंकों का अलग–अलग योगदान रहा है, क्योंकि जनपद में किसी बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का इस समय के लिए सर्वाधिक ऋण बैंक आफ बड़ौदा की इटावा मुख्य शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का 82.8 प्रतिशत ऋण 248 व्यक्तियों को दिया गया वहीं इसी समयावधि के लिए सबसे कम अपने वितरित ऋण का स्टेट बैंक की वसरेहर शाखा द्वारा दिया गया जहां पर किसी भी व्यक्ति को मध्यकालीन ऋण नहीं दिये गये। जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनपद में मध्यकालीन ऋण वितरण में परिवर्तन की स्थिति रही है।

जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 57.4 प्रतिशत भाग ऋण 3289 व्यक्तियों को 530281 हजार रुपये के दीर्घकालीन समयावधि की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति हेतु ऋण का वितरण किया गया। दीर्घकालीन समयावधि के लिए वितरित इस ऋण में विभिन्न बैंकों द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग 72.6 प्रतिशत भाग सेन्ट्रल बैंक की पिपरौली (गढ़िया) शाखा द्वारा दिया गया, जबकि पंजाब नेशनल बैंक की इटावा शाखा द्वारा इस समय के

लिये किसी प्रकार के ऋण का वितरण नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि दीर्घकालीन समय के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा जो ऋण वितरित किया गया है। उसमें परिवर्तन की स्थिति रही है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जनपद में इन अध्ययन के लिए चयनित बैंक शाखाओं द्वार वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में जो ऋण वितरित किया गया है। उसमें से सबसे अधिक ऋण दीर्घकाल समय के लिए दिये गये हैं। दीर्घकाल समय के लिए जो भी ऋण दिये गये हैं वह कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधार या बृहद् पैमाने पर कृषि निवेश के लिए दिये गये हैं, क्योंकि जनपद में कृषि क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ है। जिसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। यह निवेश कृषि क्षेत्र में कृषि यन्त्रीकरण, भूमि समतलीकरण, सिचाई सुविधा व ऊसर बंजर सुधार आदि क्षेत्रों के लिए वित्त की आवश्यकता है। इन्हीं क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए दीर्घकालीन ऋण दिये गये हैं। दीर्घकालीन ऋण के अलावा जनपद में मध्यकालीन व अल्पकालीन समयावधि के लिए ऋण दिये गये हैं।

इटावा जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में इन अध्ययन के लिए चयनित बैंक शाखाओं द्वारा जो ऋण दिये गये हैं वह विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दिये गये हैं जैसे – कृषि क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र व अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जिसमें कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत ट्रैक्टर क्रय करना, मध्यम व वृहद् प्रकार के कृषि उपकरण को क्रय करना, कोल्ड स्टोरेज खोलना, अनाज भण्डार गृह निर्माण, लघु सिचाई, फसली ऋण व अन्य तमाम प्रकार की कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए दिये गये वित्त या साख से है। जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में इन विभिन्न उद्देश्यों की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋण के विवरण व साख प्राप्त लाभार्थियों की संख्या को सारणी संख्या 107 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–107

इटावा जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैंकिंग इकाइयों द्वारा उद्देश्य के आधार पर ऋण का वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का विभिन्न क्षेत्रों में वितरण								लघु क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	अन्य प्रा0प्रा0 क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या
						ट्रैक्टर एवं कृषि यन्त्र	लाभार्थी संख्या	लघु सिचाई	लाभार्थी संख्या	फसली ऋण	लाभार्थी संख्या	अन्य कृषि ऋण	लाभार्थी संख्या						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. सेन्ट्रल बैंक	बकेवर	15524	11483	74%	430	2740	09	–	–	5894	324	2849	87	–	–	–	4041	26%	83
	भरथना	14887	12528	84.2%	429	3858	18	350	08	2375	149	5945	254	1266	8.5%	09	1093	7.3%	49
	पिपरौली (गढ़िया)	10555	10322	97.8%	200	7120	59	–	–	2658	118	544	23	–	–	–	233	2.2%	08
	जसवन्त नगर	113999	94145	82.6%	1035	51286	136	–	–	16613	689	26246	210	913	0.8%	14	18941	16.6%	280
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	लखना	82120	66925	80.9%	1145	37181	83	713	18	18659	731	7872	313	1804	2.2%	21	13891	16.9%	187
	सरसई नावा	34983	32903	94.2%	930	18796	158	248	13	12826	730	1033	29	107	0.3%	02	1973	5.6%	151
	वसरेहर	80599	80599	100%	1309	56945	210	–	–	18444	1057	5210	42	–	–	–	–	–	–
	जसवन्त नगर	107020	93475	87.3%	1532	48180	276	2034	27	26263	1011	16998	218	5320	05%	35	8225	7.7%	107
3. इलाहाबाद बैंक	चौपला (टकपुरा)	120502	113909	94.6%	1948	21682	97	470	20	39490	1206	52267	625	2080	1.7%	25	4513	3.8%	247
4. बैंक आफ इण्डिया	इटावा	197733	109914	55.6%	344	2416	14	106	01	8037	243	99355	86	38393	19.4%	91	49426	25%	311
5. बैंक आफ बड़ौदा	इटावा	49001	8424	17.2%	11	–	–	–	–	–		8424	11	15556	31.7%	35	25021	51%	213
6. पंजाब ने0 बैंक	इटावा (क.रोड)	21506	5740	26.7%	110	–	–	–	–	5740	110	–	–	1390	6.5%	02	14376	66.8%	210
7. यूनियन बैंक	इटावा	75794	52863	69.7%	319	39164	167	–	–	5470	113	1133	38	4113	5.4%	30	18818	24.8%	217
योग– 07	13	924223	693230	75%	9742	289368	1227	3921	87	162469	6491	229876	1936	70942	7.7%	264	160551	17.4%	2063

स्रोत – इटावा जनपद में अध्ययन के लिए उपरोक्त समस्त बैंक शाखाओं के एल.बी.आर. फाइल–2 में दिये गये आंकडों पर आधारित।

सारणी संख्या 107 से यह स्पष्ट है कि इटावा जनपद में कार्यरत 7 व्यावसायिक बैंकों की 13 शाखाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में 924223 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। इस वितरित ऋण में 9742 व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 75 प्रतिशत या 693230 हजार रुपये के कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए ऋण वितरित किये। कृषि क्षेत्र में वित्तीय आवश्कताओं की पूर्ति के लिए जनपद में वितरित इस ऋण में विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा जो भी योगदान है उसमें जनपद की विभिन्न बैंकों द्वारा अपने वितरित ऋण में से कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक भाग स्टेट बैंक आफ इण्डिया की वसरेहर शाखा द्वारा 1309 व्यक्तियों को 100 प्रतिशत ऋण वितरित किये अर्थात् कह सकते हैं कि वसरेहर शाखा द्वारा केवल कृषि क्षेत्र को ही ऋण दिये गये। वहीं इसके बाद सेन्ट्रल बैंक की पिपरौली शाखा द्वारा 97.8 प्रतिशत, इलाहाबाद बैंक की चौपला (टकपुरा) शाखा द्वारा 94.6 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया गया, वहीं बैंक आफ बड़ौदा की इटावा मुख्य शाखा द्वारा अपने तितरित ऋण का 17.2 प्रतिशत व पंजाब नेशनल बैंक की इटावा शाखा द्वारा 26.7 प्रतिशत ऋण ही कृषि क्षेत्र को दिया गया। कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित इस ऋण में परिवर्तन की स्थिति दिखाई दे रही है इससे यही स्पष्ट होता है कि बैंकों द्वारा अलग–अलग स्तर पर ऋण का वितरण किया गया है। जनपद में कृषि क्षेत्र में वितरित इस ऋण को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसके अन्तर्गत 1227 व्यक्तियों को 289368 हजार रुपये के ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि उपकरण/यन्त्र क्रय करने के लिए ऋण का वितरण किया गया। इस ऋण वितरण में भी विभिन्न बैंकों द्वारा कम ज्यादा व्यक्तियों को ऋण दिया गया और ऋण की मात्रा भी असमान रही है, जनपद में 87 व्यक्तियों को 3921 हजार रुपये के सिचाई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वित्त प्रदान किये गये। सिचाई आवश्यकताओं की पूर्ति में भी जनपद की विभिन्न शाखाओं द्वारा वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है क्योंकि किसी बैंक शाखा द्वारा लघु सिचाई के लिए ऋण का वितरण किया ही नहीं गया, जबकि किसी बैंक शाखा द्वारा काफी व्यक्तियों को ऋण दिये गये, जनपद में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत 6491 व्यक्तियों को कार्यशील पूंजी के रूप में 162469 हजार रुपये के फसली ऋण दिये गये। इस फसली ऋण के अन्तर्गत रोजमर्रा के तमाम वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण दिये गये। इस वितरित ऋण में भी विभिन्न बैंकों द्वारा वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है क्योंकि जहां एक ओर इलाहाबाद बैंक की चौपला (टकपुरा) शाखा द्वारा 1206 व्यक्तियों को फसली ऋण दिये गये वहीं बैंक आफ बड़ौदा की मुख्य शाखा द्वारा किसी भी व्यक्ति को फसली ऋण नहीं दिये गये। जिससे यह स्पष्ट है कि जनपद

में विभिन्न व्यावसायिक बैंक शाखाओं द्वारा इस क्षेत्र के लिए वितरित साख में परिवर्तन की स्थिति रही है व जनपद में 1936 व्यक्तियों को 229876 हजार रुपये के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अन्य कृषि कार्य करने के लिए साख का वितरण किया गया। इस क्षेत्र में वितरित ऋण में भी परिवर्तन की स्थिति स्पष्ट होती है क्योंकि जहां एक ओर इलाहाबाद बैंक की चौपला (टकपुरा) शाखा द्वारा 625 व्यक्तियों को ऋण दिये गये वहीं पंजाब नेशनल बैंक इलाहाबाद शाखा द्वारा इस क्षेत्र के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए साख प्रदान नहीं की गई। जिससे परिवर्तन की स्थिति स्पष्ट होती है।

जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में से 7.7 प्रतिशत साख 264 व्यक्तियों को 70942 हजार रुपये के लघु एवं कुटीर उद्योगों की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु ऋण का वितरण किया गया। इस क्षेत्र के लिए वितरित ऋण में किसी बैंक शाखा द्वारा अपने प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग बैंक आफ बड़ौदा की इटावा मुख्य शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का 31.7 प्रतिशत भाग लघु एवं कुटीर उद्योग की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए दिया गया जो किसी बैंक शाखा द्वारा लघु उद्योग के लिए अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग है। वहीं सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की भरथना शाखा, बकेवर शाखा व स्टेट बैंक आफ इण्डिया की सरसई नावा शाखा द्वारा इस क्षेत्र के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई ऋण नहीं दिया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में अपने वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति देखने में आई है।

जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में से शेष भाग अन्य प्राथमिकता क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए दिया गया जो प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 17.4 प्रतिशत है जो 2063 व्यक्तियों को 160551 हजार रुपये के ऋण दिये गये। इस ऋण में किसी बैंक द्वारा अपने वितरित ऋण का 66.8 प्रतिशत भाग 210 व्यक्तियों को पंजाब नेशनल बैंक की इटावा शाखा द्वारा दिया गया। जो किसी बैंक द्वारा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग है वहीं स्टेट बैंक आफ इण्डिया की बसरेहर शाखा द्वारा इस क्षेत्र के लिए किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया गया। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग कृषि क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए ऋण का वितरण किया गया। इसके बाद अन्य प्राथमिकता क्षेत्र व लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति हेतु ऋणों का वितरण किया गया।

4. औरैया जनपद : औरैया जनपद में 4 व्यावसायिक बैंकों की 28 शाखायें कार्यरत हैं जो विभिन्न क्षेत्रों को साख उपलब्ध करा रही हैं। जनपद में कार्यरत इन बैंकों की विभिन्न शाखाओं में से अध्ययन के लिए 3 बैंकों की 8 शाखाओं का चयन किया गया है। जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण के विवरण व इस क्षेत्र में साख प्राप्त लाभार्थियों की संख्या को सारणी संख्या 108 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–108

औरैया जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैंकों के द्वारा वितरित ऋण का विवरण

वर्ष 2006–07 (धनराशि हजार रुपये में)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	विकास खण्ड का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	साख प्राप्त व्यकितयों की संख्या
1	2	3	4	5
1. सेन्ट्रल बैंक	1. खानपुर	औरैया	12986	300
	2. अछल्दा	अछल्दा	14221	370
	3. अजीतमल	अजीतमल	13242	265
	4. भाग्यनगर	भाग्यनगर	14530	532
	5. सहार	सहार	12932	213
	6. ऐरवा कटरा	ऐरवा कटरा	11981	406
2. स्टेट बैंक	1. विधूना	विधूना	25768	396
3. पंजाब नेशनल बैंक	1. औरैया	औरैया	9035	192
योग :– 03	**08**	**07**	**114705**	**2674**

सारणी संख्या 108 से यह स्पष्ट है कि औरैया जनपद में अध्ययन के लिए चयनित इन 3 बैंकों की 8 शाखाओं द्वारा जो जनपद के सभी 7 विकास खण्डों तक कार्यरत हैं इनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में 2674 व्यक्तियों को 114705 हजार रुपये के प्राथमिकता क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण वितरित किये। प्राथमिकता क्षेत्र में इस वितरित ऋण में जनपद में कार्यरत विभिन्न बैंक शाखाओं में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की विधूना शाखा द्वारा 25768 हजार रुपये के 396 व्यक्तियों को साख प्रदत्त किये गये, जबकि पंजाब नेशनल बैंक की औरैया शाखा द्वारा 192 व्यक्तियों को 9035 हजार रुपये के ही ऋण वितरित किये गये। जनपद में सबसे अधिक व्यक्तियों को सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की भाग्यनगर शाखा द्वारा 532 व्यक्तियों को व

स्रोत – उपरोक्त समस्त बैंक कार्यालयों के फाइल एल.बी.आर–2 में दिये गये आंकडों पर आधारित

इसी बैंक की ऐरवा कटरा शाखा द्वारा 406 व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण वितरित किये गये। इस प्रकार विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जनपद में विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में दिये गये वित्तीय योगदान व व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन की स्थिति रही है।

जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में जो ऋण नितरित किये गये हैं वह विभिन्न समयावधियों को ध्यान में रखकर दिये गये हैं, क्योंकि विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा जो भी ऋण दिये जाते हैं वह मुख्यतयः तीन अवधियों के लिए दिये जाते हैं जिसमें अल्पकाल जिसकी वित्त अदायगी का समय 15 महीने तक होता है, मध्यकाल जिसके अन्तर्गत वित्त अदायगी का समय 15 माह से 5 वर्ष के मध्य होता है व दीघकाल जिसके अन्तर्गत वित्त अदायगी का समय 5 वर्ष से 15 या 18 वर्ष तक का होता है। इन विभिन्न समयावधियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में वितरित ऋण एवं साख प्राप्त लाभार्थियों की संख्या तथा इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंक शाखाओं के योगदान या विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के वितरित ऋण में से विभिन्न समयों के लिए दिये गये ऋण की मात्रा को प्रतिशत के रूप में जानने के लिए सारणी संख्या 109 के माध्यम स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–109

औरैया जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैंकिंग इकाइयों द्वारा समय के आधार पर ऋण का वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	लाभार्थियों की संख्या	अल्पकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	मध्यकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	दीर्घकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. सेन्ट्रल बैंक	1. खानपुर	12986	300	7532	58%	185	2065	15.9%	65	3389	26.1%	50
	2. अछल्दा	14231	370	6404	45%	203	1025	7.2%	25	6802	47.8%	142
	3. अजीतमल	13242	265	7061	53.3%	113	1856	14%	40	4325	32.7%	112
	4. भाग्यनगर	14530	532	4736	32.6%	268	4078	28.1%	19	5716	39.3%	245
	5. सहार	12932	213	8121	62.8%	120	1942	15%	38	2869	22.2%	55
	6. ऐरवा कटरा	11981	406	2995	25%	195	1518	12.7%	65	7468	62.3%	146
2. स्टेट बैंक	1. विधूना	25768	396	5153	20%	200	4030	15.6%	88	16585	64.4%	108
3. पंजाब नेशनल बैंक	1. औरैया	9035	192	2530	28%	90	3035	33.6%	32	3470	38.4%	70
योग– 03	**08**	**114705**	**2674**	**44532**	**38.8%**	**1374**	**19548**	**17.3%**	**372**	**50624**	**44.1%**	**928**

स्रोत – औरैया जनपद में अध्ययन के लिए उपरोक्त समस्त बैंक शाखाओं के एल.बी.आर. फाइल–2 में दिये गये आंकडों पर आधारित।

सारणी संख्या 109 से स्पष्ट है कि औरैया जनपद में अध्ययन के लिए चयनित 3 व्यावसायिक बैंकों की 8 शाखाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में 2674 व्यक्तियों को 114705 हजार रुपये के प्राथमिकता क्षेत्र में वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण वितरित किये गये। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित इस ऋण में 38.8 प्रतिशत ऋण 1374 व्यक्तियों को 4532 हजार रुपये अल्पकालीन समय के लिए दिये गये। अल्पकालीन समय में जनपद में विभिन्न बैंकों द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग सेन्ट्रल बैक आफ इण्डिया की सहार शाखा द्वारा 62.8 प्रतिशत, खानपुर शाखा द्वारा 58 प्रतिशत व अजीतमल शाखा द्वारा 53.3 प्रतिशत ऋण अल्पकाल समय के लिए दिये गये। वहीं जनपद में सबसे कम प्राथमिकता क्षेत्र में अपने वितरित ऋण का स्टेट बैंक आफ इण्डिया की विधूना शाखा द्वारा 20 प्रतिशत भाग ही अल्पकाल समय के लिए दिया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि अल्पकाल समय के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा दिये गये अपने ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है।

प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में 17.3 प्रतिशत 372 व्यक्तियों को 19548 हजार रुपये के मध्यकाल समय के लिए ऋण का वितरण किया गया इस समय के लिए वितरित ऋण में विभिन्न बैंकों द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग पंजाब नेशनल बैंक की औरैया शाखा द्वारा 33.6 प्रतिशत व सेन्ट्रल बैंक की भाग्यनगर शाखा द्वारा 28.1 प्रतिशत भाग अल्पकाल समय के लिए दिया गया। वहीं जनपद में अपने वितरित ऋण का सबसे कम भाम सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की अछल्दा शाखा द्वारा मात्र 7.2 प्रतिशत ही मध्यकाल समय के लिए दिये गये। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में अपने वितरित ऋण में विभिन्न शाखाओं में परिवर्तन की स्थिति रही है।

जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 44.1 प्रतिशत भाग 928 व्यक्तियों को 50624 हजार रुपये के दीर्घकाल समय के लिए ऋण वितरित किये गये। इस वितरित ऋण में भी अन्य क्षेत्रों की तरह व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपने वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है जैसा कि सारणी से स्पष्ट है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जनपद में सबसे अधिक ऋण दीर्घकाल समय के लिए वितरित किये गये। इसके बाद अल्पकाल व मध्यकाल ऋण का क्रम है। जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में यह वितरित ऋण विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिया गया है। जिसके विवरण को सारणी संख्या 110 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–110

औरैया जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैंकिंग इकाइयों द्वारा उद्देश्य के आधार पर ऋण का वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का विभिन्न क्षेत्रों में वितरण								लघु क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	अन्य प्रा0प्रा0 क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या
						ट्रैक्टर एवं कृषि यन्त्र	लाभार्थी संख्या	लघु सिंचाई	लाभार्थी संख्या	फसली ऋण	लाभार्थी संख्या	अन्य कृषि ऋण	लाभार्थी संख्या						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. सेन्ट्रल बैंक	खानपुर	12986	10921	84.1%	235	2015	13	103	02	7532	185	1271	35	702	5.4%	06	1363	10.5%	60
	अछल्दा	14231	13206	92.8%	345	3513	20	468	06	6404	203	2821	116	115	0.8%	01	910	6.4%	24
	अजीतमल	13242	11386	86%	225	3910	28	–	–	7061	113	415	84	–	–	–	1856	14%	40
	भाग्यनगर	14530	10452	71.9%	513	2510	18	510	04	4736	268	2696	223	980	6.7%	04	3098	21.3%	15
	सहार	12932	10970	85%	175	2013	20	–	–	8121	120	856	35	242	1.2%	02	1700	13.1%	36
	ऐरवा कटरा	11981	10463	87.3%	341	4800	37	503	03	2995	195	2165	106	200	1.7%	01	1318	11%	64
2. स्टेट बैंक	विधूना	25768	21738	84.4%	308	9065	53	510	02	5153	200	7010	53	1100	4.3%	10	2930	11.4%	78
3. पंजाब नेशनल बैंक	औरैया	9035	6000	66.4%	160	2038	21	–	–	2530	90	1432	49	510	5.6%	03	2525	28%	29
योग– 03	**08**	**114705**	**95156**	**83%**	**2302**	**29864**	**210**	**2094**	**17**	**44532**	**1374**	**18666**	**701**	**3849**	**3.4%**	**27**	**15700**	**13.6%**	**346**

स्रोत – औरैया जनपद में अध्ययन के लिए उपरोक्त समस्त बैंक शाखाओं के एल.बी.आर. फाइल–2 में दिये गये आंकडों पर आधारित।

सारणी संख्या 110 से यह स्पष्ट है कि औरैया जनपद में 3 व्यावसायिक बैंकों की 8 शाखाओं द्वारा 114705 हजार रुपये के वित्तीय वर्ष 2006–07 के प्राथमिकता क्षेत्र में जो ऋण वितरित किये गये उसमें से 2302 व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 83 प्रतिशत या 95156 हजार रुपये के ऋण कृषि क्षेत्र की विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिये गये। कृषि क्षेत्र में वितरित यह ऋण विभिन्न शाखाओं द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में अपने वितरित ऋण में सबसे अधिक भाग सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की अछल्दा शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का 92.8 प्रतिशत ऋण 345 व्यक्तियों को दिया गया। इसके बाद इसी बैंक के ऐरवा कटरा शाखा व सहार शाखा द्वारा कृषि क्षेत्र को अपने वितरित ऋण की अधिकाधिक मात्रा कृषि क्षेत्र में दी गई जबकि पंजाब नेशनल बैंक की औरैया शाखा द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में अपने वितरित ऋण का 66.4 प्रतिशत भाग ही कृषि क्षेत्र को दिया गया। जनपद में कृषि क्षेत्र में वितरित इस ऋण को कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किया गया। जिसके अन्तर्गत 210 व्यक्तियों को 29864 हजार रुपये के ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि उपकरण/यन्त्र क्रय करने के लिए वित्त प्रदान किये गये, 17 व्यक्तियों को 2094 हजार रुपये के ऋण सिचाई से सम्बन्धित आवश्कताओं की पूर्ति के लिए दिये गये, 1374 व्यक्तियों को 44532 हजार रुपये के रोजमर्रा की आवश्यकता या कार्यशील पूंजी के रूप में फसली ऋण दिये गये व 701 व्यक्तियों को 18666 हजार रुपये के अन्य कृषि कार्य करने के लिए साख उपलब्ध कराये गये।

जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 3.4 प्रतिशत या 3849 हजार रुपये के ऋण 27 व्यक्तियों के लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण वितरित किये गये। लघु उद्योग क्षेत्र में वितरित इस ऋण में विभिन्न बैंकों द्वारा अपने वितरित ऋण का 6.7 प्रतिशत सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की भाग्यनगर शाखा द्वारा व 5.6 प्रतिशत भाग पंजाब नेशनल बैंक की औरैया शाखा द्वारा इस क्षेत्र के लिए ऋण का वितरण किया गया, जबकि दूसरी ओर सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की अजीतमल शाखा द्वारा इस क्षेत्र के लिए किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया गया। जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का शेष भाग या प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 13.6 प्रतिशत या 15700 हजार रुपये के 346 व्यक्तियों के अन्य प्राथमिकता क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण का वितरण किया गया इस क्षेत्र के लिए विभिन्न बैंकों में से सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की भाग्यनगर शाखा द्वारा 21.3 प्रतिशत व पंजाब नेशनल बैंक की औरैया शाखा द्वारा इस क्षेत्र का सबसे अधिक 28 प्रतिशत ऋण का

वितरण अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में साख प्रदान किया गया, जबकि दूसरी ओर सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की अछल्दा शाखा द्वारा मात्र 6.4 प्रतिशत व खानपुर शाखा द्वारा 10.5 प्रतिशत अपने वितरित ऋण का भाग ही अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया गया। इस प्रकार सारणी के सम्पूर्ण विश्लेषण से एक बात उभर कर आती है कि विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो ऋण का वितरण किया गया है उसमें परिवर्तन की स्थिति स्पष्ट होती है।

औरैया जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में जो ऋण वितरित किया गया है। उस वितरित ऋण में सबसे अधिक भाग कृषि क्षेत्र की विभिन्न वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिये प्रत्यक्ष ऋण दिये गये, जबकि इसके बाद अन्य प्राथमिकता क्षेत्र व लघु उद्योग क्षेत्र में ऋण का वितरण किया गया।

5. कानपुर नगर : कानपुर नगर जनपद में 7 व्यावसायिक बैंकों की 34 शाखायें कार्यरत हैं जिनके द्वारा जनपद में विभिन्न प्रकार के साख उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इनके द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे साखों में से अध्ययन के लिए 6 व्यावसायिक बैंकों की 10 शाखाओं का चयन किया गया है। जो जनपद के सभी 10 विकास खण्डों में कार्यरत हैं। इन अध्ययन के लिए चयनित बैंकों उनकी शाखाओं एवं स्थित विकास खण्डों तथा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण व लाभार्थियों की संख्या को वित्तीय वर्ष 2006–07 के आधार पर दिये गये विवरण को सारणी संख्या 111 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–111

कानपुर नगर जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैंकों के द्वारा वितरित ऋण का विवरण वर्ष 2006–07 (धनराशि हजार रुपये में)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	विकास खण्ड का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	साख प्राप्त व्यकितयों की संख्या
1	2	3	4	5
1. बैंक आफ बड़ौदा	1. ककवन	ककवन	62310	556
	2. गिरसी	पतारा	50130	511
	3. शिवराजपुर	शिवराजपुर	47250	600
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	1. घाटमपुर	घाटमपुर	98932	907
	2. भीतरगांव	भीतरगांव	85710	832
3. पंजाब नेशनल बैंक	1. विधनू	विधनू	25921	293
4. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	1. चौबेपुर	चौबेपुर	24227	432
	2. सचेंडी	कल्यानपुर	26180	227
5. बैंक आफ इण्डिया	1. महाराजपुर	सरसौल	82510	667
6. इलाहाबाद बैंक	1. अरौल	बिल्हौर	254913	1620
योग :– 06	**10**	**10**	**758083**	**6645**

सारणी संख्या 111 से यह स्पष्ट है कि कानपुर नगर जनपद में अध्ययन के लिए चयनित 6 व्यावसायिक बैंकों की 10 शाखाओं द्वारा जनपद के सभी विकासखण्डों में 6645 व्यक्तियों को 758083 हजार रुपये के वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरित किये। इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंक शाखाओं का अलग–अलग योगदान रहा है। जिसमें सबसे अधिक इलाहाबाद बैंक की अरौल शाखा का रहा है, जिसने सबसे ज्यादा व्यक्तियों को भी ऋण वितरित किये, वहीं इस वितरित ऋण में सबसे कम सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की चौबेपुर शाखा का रहा है। लेकिन सबसे कम व्यक्तियों को ऋण इसी बैंक की सचेंडी शाखा द्वारा दिया गया है। जनपद में यह वितरित ऋण विभिन्न समयों को ध्यान में रखकर दिया गया। जिसके अन्तर्गत अल्पकाल, मध्यकाल व दीर्घकाल समय आते हैं। इन सभी प्रकार के समयों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण की मात्रा व लाभार्थियों की संख्या को सारणी संख्या 112 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

स्रोत – उपरोक्त समस्त बैंक कार्यालयों के फाइल एल.बी.आर–2 में दिये गये आंकडों पर आधारित

सारणी संख्या–112

कानपुर नगर जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैंकिंग इकाइयों द्वारा समय के आधार पर ऋण का वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	लाभार्थियों की संख्या	अल्पकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	मध्यकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	दीर्घकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. बैंक आफ बड़ौदा	1. ककवन	62310	556	34271	55%	439	6231	10%	35	21808	35%	82
	2. गिरसी	50130	511	22559	45%	382	6016	12%	27	21555	43%	102
	3. शिवराजपुर	47250	600	23153	49%	479	7088	15%	56	17009	36%	65
2. स्टेट बैंक	1. घाटमपुर	98932	907	46498	47%	698	19786	20%	94	32648	33%	115
	2. भीतरगांव	85710	832	49712	58%	687	12857	15%	70	23141	27%	75
3. पंजाब नेशनल बैंक	1. विधनू	25921	293	19441	75%	258	3369	13%	20	3111	12%	15
4. सेन्ट्रल बैंक	1. चौबेपुर	24227	432	6299	26%	355	7753	32%	42	10175	42%	35
	2. सचेंडी	26180	227	8378	32%	107	9163	35%	81	8639	33%	39
5. बैंक आफ इण्डिया	1. महाराजपुर	82510	667	7426	09%	347	33004	40%	170	42080	51%	150
6. इलाहाबाद बैंक	1. अरौल	254913	1620	225308	88.3%	1484	10110	04%	75	19495	7.7%	61
योग– 06	**10**	**758083**	**6645**	**443045**	**58.4%**	**5236**	**115377**	**15.2%**	**670**	**199661**	**26.4%**	**739**

स्रोत – कानपुर नगर जनपद में अध्ययन के लिए उपरोक्त समस्त बैंक शाखाओं के एल.बी.आर. फाइल–2 में दिये गये आंकडों पर आधारित।

सारणी संख्या 112 से यह स्पष्ट है कि कानपुर नगर जनपद में अध्ययन के लिए चयनित 6 व्यावसायिक बैंकों की 10 शाखाओं द्वारा जनपद के सभी विकासखण्डों में 6645 व्यक्तियों को 758083 हजार रुपये के वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरित किये। इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंक शाखाओं का अलग–अलग योगदान रहा है। जनपद में यह वितरित ऋण विभिन्न समयावधि को ध्यान में रखकर दिया गया। जिसके अन्तर्गत 5236 व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 58.4 प्रतिशत या 443045 हजार रुपये के ऋण अल्पकालीन समय के लिए दिये गये। इस समय के लिए जो ऋण वितरित किये गये हैं उसमें विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा अपने वितरित ऋण में इस क्षेत्र के लिए वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है क्योंकि जहां एक ओर इलाहाबाद बैंक की अरौल शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का अल्पकालीन समय के लिए 88.3 प्रतिशत भाग ऋण वितरित किया, वहीं बैंक आफ इण्डिया की महाराजपुर शाखा द्वारा मात्र 9 प्रतिशत भाग ऋण ही इस समय के लिए दिया गया, जनपद में 670 व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 15.2 प्रतिशत या 115377 हजार रुपये के ऋण मध्यकाल समय के लिए दिये गये। इस वितरित ऋण में भी विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा अपने वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है क्योंकि जहां बैंक आफ इण्डिया की महाराजपुर बैंक शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का 40 प्रतिशत भाग मध्यकालीन समय के लिए दिया गया वहीं इलाहाबाद बैंक की अरौल शाखा द्वारा मात्र 4 प्रतिशत भाग ऋण ही इस समय के लिए दिये गये व जनपद में 739 व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 26.4 प्रतिशत या 199661 हजार रुपये के ऋण दीर्घकाल समय के लिए दिये गये। दीर्घकाल समय के लिए भी विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है क्योंकि जहां एक ओर बैंक आफ इण्डिया की महाराजपुर शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का 51 प्रतिशत भाग ऋण इस समय के लिए दिये गये वहीं इलाहाबाद बैंक की अरौल शाखा द्वारा मात्र 7.7 प्रतिशत भाग ऋण इस समय के लिए दिया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कानपुर नगर जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग मध्यकालीन समय के लिए तत्पश्चात् अल्पकाल व दीर्घकाल समय के लिए ऋणों का वितरण किया गया। जनपद में इन विभिन्न समयों के लिए जो ऋण वितरित किये गये हैं वह विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दिये गये हैं। उद्देश्यों के आधार पर जनपद में ऋण के वितरण व लाभार्थियों की संख्या को सारणी संख्या 113 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–113

कानपुर नगर जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैंकिंग इकाइयों द्वारा उद्देश्य के आधार पर ऋण का वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा० क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का विभिन्न क्षेत्रों में वितरण								लघु क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा० क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	अन्य प्रा०प्रा० क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा० क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या
						ट्रैक्टर एवं कृषि यन्त्र	लाभार्थी संख्या	लघु सिचाई	लाभार्थी संख्या	फसली ऋण	लाभार्थी संख्या	अन्य कृषि ऋण	लाभार्थी संख्या						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. बैंक आफ बड़ौदा	ककवन	62310	56079	90%	611	5256	18	1850	10	34271	439	14702	54	2715	4.4%	08	3516	5.6%	27
	गिरसी	50130	44114	88%	484	6750	30	1470	07	22559	382	13335	65	–	–	–	6013	12%	27
	शिवराजपुर	47250	40162	85%	544	8820	35	1025	05	23153	479	7164	35	2010	4.3%	02	5078	10.7%	54
2. स्टेट बैंक	घाटमपुर	98932	79146	80%	813	18550	53	5120	20	46498	698	8978	42	3095	3.1%	19	16691	16.9%	75
	भीतरगांव	85710	72853	85%	762	8505	27	4260	20	49712	687	10376	28	2015	2.4%	10	10842	12.6%	60
3. पंजाब नेशनल बैंक	विधनू	25921	22552	87%	273	2065	07	560	02	19441	258	486	06	–	–	–	3369	13%	20
4. सेन्ट्रल बैंक	चौबेपुर	24227	16474	68%	390	6210	18	780	05	6299	355	3185	12	1025	2.3%	09	6728	27.7%	31
	सचेंडी	26180	17017	55%	146	2915	11	1050	05	8378	107	4674	23	2510	9.6%	13	6653	25.4%	68
5. बैंक आफ इण्डिया	महाराजपुर	82510	49506	60%	497	10640	28	7525	35	7426	347	18165	87	1065	1.3%	05	31939	38.7%	165
6. इलाहाबाद बैंक	अरौल	254913	244900	96%	1545	9450	30	1125	05	225308	1484	9017	26	4997	02%	22	5113	02%	53
योग– 06	**10**	**758083**	**642803**	**84.8%**	**5975**	**79161**	**257**	**24765**	**114**	**443045**	**5236**	**90082**	**378**	**19435**	**2.6%**	**88**	**95942**	**12.6%**	**580**

स्रोत –कानपुर नगर जनपद में अध्ययन के लिए उपरोक्त समस्त बैंक शाखाओं के एल.बी.आर. फाइल–2 में दिये गये आंकडों पर आधारित।

सारणी संख्या 113 से यह स्पष्ट है कि कानपुर नगर जनपद में अध्ययन के लिए चयनित 6 व्यावसायिक बैंकों की 10 शाखाओं द्वारा जनपद के सभी विकासखण्डों में 6645 व्यक्तियों को 758083 हजार रुपये के वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरित किये। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित इस ऋण में से 84.8 प्रतिशत या 642803 हजार रुपये के ऋण कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 5975 व्यक्तियों को ऋण वितरित किये गये। जनपद में इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंक शाखाओं का अलग–अलग योगदान रहा है। जनपद में किसी बैंक शाखा द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में अपने वितरित ऋण में से 96 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को इलाहाबाद बैंक की अरौल शाखा द्वारा सबसे अधिक भाग ऋण प्रदान किया गया। इसके बाद बैंक आफ बड़ौदा की ककवन शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का 90 प्रतिशत भाग व इसी बैंक की गिरसी शाखा द्वारा 88 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिये गये, वहीं सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की चौबेपुर शाखा द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में अपने वितरित ऋण का मात्र 55 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति हेतु ऋण का वितरण किया गया। जनपद में कृषि क्षेत्र में जो ऋण प्रदान किया गया वह विभिन्न क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए दिया गया हैं जिसके अन्तर्गत 257 व्यक्तियों को 79161 हजार रुपये के ऋण ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि उपकरण/यन्त्र क्रय करने के लिए दिये गये। इस प्रकार के यन्त्रों/उपकरणों को क्रय करने के लिए विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा अलग–अलग स्तर पर ऋण का वितरण किया गया है, 114 व्यक्तियों को 24765 हजार रुपये के व्यावसायिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में सिचाई आवश्यकता की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए ऋण दिये गये, 5236 व्यक्तियों को 443045 हजार रुपये के फसली ऋण दिये गये। जिसको हम कार्यशील पूंजी कह सकते हैं यह ऋण दिन प्रतिदिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिये गये व जनपद में कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का शेष भाग 378 व्यक्तियों को 90082 हजार रुपये के अन्य कृषि कार्य करने के लिए ऋण वितरित किये गये। इसके अन्तर्गत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के ऋण दिये गये।

जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 88 व्यक्तियों को 2.6 प्रतिशत या 19435 हजार रुपये के लघु एवं कुटीर उद्योग की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए ऋण वितरित किये गये। इस क्षेत्र के लिए विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है क्योंकि जहां एक ओर लघु उद्योग क्षेत्र में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा अपने वितरित ऋण का 9.6 प्रतिशत भाग इस क्षेत्र के लिए दिया गया वहीं बैंक आफ बड़ौदा की गिरसी शाखा व पंजाब

नेशनल बैंक की विधनू शाखा द्वारा इस क्षेत्र के लिए कोई ऋण नहीं दिया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा इस क्षेत्र में दिये गये ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है।

जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 580 व्यक्तियों को 12.6 प्रतिशत या 95942 हजार रुपये के अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए ऋण वितरित किये गये। इस क्षेत्र के लिए विभिन्न बैंक शाखा द्वारा वितरित ऋण में भी परिवर्तन की स्थिति रही है क्योंकि जहां एक ओर बैंक आफ इण्डिया की महाराजपुर शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का 38.7 प्रतिशत ऋण इस क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए दिये गये। वहीं इलाहाबाद बैंक की अरौल शाखा द्वारा इस क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए मात्र अपने वितरित ऋण का 2 प्रतिशत ऋण ही इस क्षेत्र को दिया गया। इस परिवर्तन की स्थिति से यह स्पष्ट है कि जनपद में अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए जो ऋण वितरित किये गये हैं। वह परिवर्तित रहे हैं।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में जो ऋण वितरित किये गये हैं उसका एक बड़ा भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए दिया गया। इसके बाद अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र व लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण का वितरण किया गया।

6. **कानपुर देहात जनपद :** जनपद कानपुर देहात में 5 व्यावसायिक बैंकों की 29 शाखायें कार्यरत हैं जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु समय–समय पर वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कराई जा रही है। इसी को ध्यान में रखकर जनपद में कार्यरत इन बैंक शाखाओं में से अध्ययन के लिए 9 बैंक शाखाओं का चयन किया गया, और इन बैंक शाखाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में जनपद में जो ऋण वितरित किये गये, उसके विवरण व लाभार्थियों की संख्या को सारणी संख्या 114 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–114

कानपुर देहात जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैंकों के द्वारा वितरित ऋण का विवरण वर्ष 2006–07 (धनराशि हजार रुपये में)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	विकास खण्ड का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	साख प्राप्त व्यकितयों की संख्या
1	2	3	4	5
1. बैंक आफ बड़ौदा	1. राजपुर	राजपुर	55310	335
	2. सन्दलपुर	सन्दलपुर	62270	461
	3. बारा	अकबरपुर	41210	329
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	1. झींझक	झींझक	75365	486
	2. मोहम्मदपुर	मलासा	60230	474
	3. पुखरायाँ	अमरौधा	80310	524
3. पंजाब नेशनल बैंक	1. शिवली	मैथा	23256	240
4. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	1. रसूलाबाद	रसूलाबाद	35270	282
5. इलाहाबाद बैंक	1. रनियां	सरवनखेड़ा	38546	350
योग :– 05	**09**	**09**	**471767**	**3481**

सारणी संख्या 114 से यह स्पष्ट है कि जनपद कानपुर देहात में वित्तीय वर्ष 2006–07 में अध्ययन के लिए चयनित 9 बैंक शाखाओं द्वारा 3481 व्यक्तियों को 471767 हजार रुपये के प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरित किये गये। जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में इस वितरित ऋण में विभिन्न बैंक शाखाओं का अलग–अलग योगदान रहा है। इस वितरित ऋण में सबसे अधिक ऋण का वितरण स्टेट बैंक आफ इण्डिया की पुखरायाँ शाखा द्वारा दिया गया। जबकि सबसे कम ऋण वितरण में योगदान पंजाब नेशनल बैंक की शिवली शाखा का रहा है। जनपद में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की पुखरायाँ शाखा द्वारा सबसे अधिक व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया गया। जबकि पंजाब नेशनल बैंक की शिवली शाखा द्वारा सबसे कम व्यक्तियों को वित्तीय योगदान किया गया।

जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित यह ऋण विभिन्न समयावधियों को ध्यान में रखकर दिया गया है। विभिन्न समयावधियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2006–07 में वितरित ऋण व शाख प्राप्त लाभार्थियों की संख्या को सारणी संख्या 115 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

स्रोत – उपरोक्त समस्त बैंक कार्यालयों के फाइल एल.बी.आर–2 में दिये गये आंकडों पर आधारित

सारणी संख्या–115

कानपुर देहात जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैंकिंग इकाइयों द्वारा समय के आधार पर ऋण का वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	लाभार्थियों की संख्या	अल्पकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	मध्यकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	दीर्घकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. बैंक आफ बड़ौदा	1. राजपुर	55310	335	27655	50%	180	8296	15%	42	19359	35%	113
	2. सन्दलपुर	62270	461	34449	55%	210	6227	10%	38	21594	35%	213
	3. बारा	41210	329	18984	46%	175	7418	18%	45	14808	36%	109
2. स्टेट बैंक	1. झींझक	75365	486	5276	07%	268	6029	08%	100	64060	85%	118
	2. मोहम्मदपुर	60230	474	9035	15%	300	6625	11%	68	44570	74%	106
	3. पुखरायाँ	80310	524	8031	10%	325	4016	05%	95	68263	85%	104
3. पंजाब नेशनल बैंक	1. शिवली	23256	240	10233	44%	165	1396	06%	28	11627	50%	47
4. सेन्ट्रल बैंक	1. रसूलाबाद	35270	282	14108	40%	175	12345	35%	37	8817	25%	70
5. इलाहाबाद बैंक	1. रनियां	38546	350	16189	42%	195	5782	15%	50	16575	43%	105
योग 05	**09**	**471767**	**3481**	**143960**	**30.5%**	**1993**	**58134**	**12.3%**	**503**	**269673**	**57.2%**	**985**

स्रोत – कानपुर देहात जनपद में अध्ययन के लिए उपरोक्त समस्त बैंक शाखाओं के एल.बी.आर. फाइल–2 में दिये गये आंकडों पर आधारित।

सारणी संख्या 115 से यह स्पष्ट है कि जनपद कानपुर देहात में वित्तीय वर्ष 2006–07 में अध्ययन के लिए चयनित 9 बैंक शाखाओं द्वारा 3481 व्यक्तियों को 471767 हजार रुपये के प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरित किये गये। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित इस ऋण में से 1993 व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 30.5 प्रतिशत या 143960 हजार रुपये के अल्पकालीन ऋण दिये गये। जनपद में इस समय के लिए दिये गये ऋण में विभिन्न बैंक शाखाओं का अलग–अलग योगदान रहा है और अपने वितरित ऋण में से इस समय के लिए सबसे अधिक ऋण बैंक आफ बड़ौदा की सन्दलपुर शाखा द्वारा 55 प्रतिशत भाग व इसी बैंक की राजपुर शाखा द्वारा 50 प्रतिशत भाग ऋण इस समय के लिए दिये गये वहीं स्टेट बैंक आफ इण्डिया की झींझक शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का इस समय के लिए मात्र 7 प्रतिशत भाग ऋण ही वितरित किया गया। जनपद में इस समय के लिए सबसे अधिक व्यक्तियों को स्टेट बैंक आफ इण्डिया की पुखरायाँ शाखा द्वारा ऋण प्रदान किये गये, जनपद में 503 व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 12.5 प्रतिशत या 58134 हजार रुपये के ऋण मध्यकालीन समय के लिए दिये गये। इस समय के लिए जनपद में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा अपने वितरित ऋण का 35 प्रतिशत भाग ऋण दिया गया। जनपद में किसी बैंक शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग इसी बैंक द्वारा दिये गये, वहीं स्टेट बैंक आफ इण्डिया की मोहम्मदपुर शाखा द्वारा इस समय के लिए अपने वितरित ऋण का सबसे कम भाग ऋण दिया गया, व जनपद में 985 व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 57.2 प्रतिशत या 269673 हजार रुपये के ऋण दीर्घकालीन समय के लिए दिये गये। दीर्घकालीन समय के लिए जनपद में विभिन्न व्यावसायिक बैंक शाखाओं द्वारा दिये गये ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है क्योंकि जहां एक ओर स्टेट बैंक आफ इण्डिया की झींझक व पुखरायाँ शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का 85–85 प्रतिशत भाग ऋण इस समय के लिए दिया गया वहीं सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की रसूलाबाद शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का मात्र 25 प्रतिशत भाग ऋण ही इस (दीर्घकाल) समय के लिए दिये गये।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में सबसे अधिक ऋण दीर्घकालीन समय के लिए दिये गये। जो कि कृषि क्षेत्र में बढ़ते हुये पूंजी निवेश के स्तर को दर्शाता है। इसके बाद अल्पकाल व मध्यकाल ऋण दिये गये। जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में जो ऋण वितरित किये गये हैं वह विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दिये गये हैं अतः जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर वितरित ऋण के विवरण को सारणी संख्या 116 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–116

कानपुर देहात जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैंकिंग इकाइयों द्वारा उद्देश्य के आधार पर ऋण का वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का विभिन्न क्षेत्रों में वितरण: ट्रैक्टर एवं कृषि यन्त्र	लाभार्थी संख्या	लघु सिचाई	लाभार्थी संख्या	फसली ऋण	लाभार्थी संख्या	अन्य कृषि ऋण	लाभार्थी संख्या	लघु क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	अन्य प्रा0प्रा0 क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. बैंक आफ बड़ौदा	राजपुर	55310	47014	85%	293	10360	35	3230	23	27655	180	5769	55	3028	5.5%	10	5268	9.5%	32
	सन्दलपुर	62270	56043	90%	423	18320	92	1012	10	34449	210	2262	111	2512	04%	09	3715	06%	29
	बारा	41210	33792	82%	284	8600	40	2510	25	18984	175	3698	44	3022	7.3%	15	4396	10.7%	30
2. स्टेट बैंक	झींझक	75365	69336	92%	386	14625	45	1013	03	5276	268	48422	70	3068	4.1%	40	2961	3.9%	60
	मोहम्मदपुर	60230	53605	89%	406	15660	28	14200	23	9035	300	14710	55	1013	1.7%	15	5612	9.3%	53
	पुखरायाँ	80310	76294	95%	429	16520	40	20210	28	8031	325	31533	36	1216	1.5%	30	2800	3.5%	65
3. पंजाब ने0 बैंक	शिवली	23256	21860	94%	212	9093	17	1310	13	10233	165	1224	17	268	1.2%	04	1128	4.8%	24
4. सेन्ट्रल बैंक	रसूलाबाद	35270	22925	65%	245	4300	20	1013	07	14108	175	3504	41	4500	12.8%	10	7845	22.2%	27
5. इलाहाबाद बैंक	रनियां	38546	32764	85%	300	12960	35	830	10	16189	195	2785	60	3030	7.9%	20	2752	7.1%	30
योग 05	**09**	**471767**	**413633**	**87.7%**	**2978**	**110438**	**352**	**45328**	**142**	**143960**	**1993**	**113907**	**491**	**21657**	**4.6%**	**153**	**36477**	**7.7%**	**350**

स्रोत –कानपुर देहात जनपद में अध्ययन के लिए उपरोक्त समस्त बैंक शाखाओं के एल.बी.आर. फाइल–2 में दिये गये आंकडों पर आधारित।

सारणी संख्या 116 से यह स्पष्ट है कि जनपद कानपुर देहात में वित्तीय वर्ष 2006–07 में अध्ययन के लिए चयनित 9 बैंक शाखाओं द्वारा 3481 व्यक्तियों को 471767 हजार रुपये के प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरित किये गये। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित इस ऋण में से 413633 हजार रुपये के ऋण 2978 व्यक्तियों को उनकी वित्तीय आवश्यकता पूर्ति हेतु कृषि क्षेत्र में दिये गये। कृषि क्षेत्र में वितरित यह ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 87.7 प्रतिशत है। विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा इस क्षेत्र में वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है जहां एक ओर स्टेट बैंक आफ इण्डिया की पुखरायां शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का 95 प्रतिशत व पंजाब नेशनल बैंक की शिवली शाखा द्वारा 94 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिया गया है। वहीं सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की रसूलाबाद शाखा द्वारा 65 प्रतिशत ऋण ही कृषि क्षेत्र को दिया गया। कृषि क्षेत्र में वितरित यह ऋण विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत दिया गया। जिसके तहत 352 व्यक्तियों को 110438 हजार रुपये के ऋण ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि उपकरण/यन्त्र क्रय करने के लिए दिये गये, 142 व्यक्तियों को 45328 हजार रुपये के ऋण सिचाई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, 1993 व्यक्तियों को 143960 हजार रुपये के ऋण फसली ऋण के रूप में जिसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं व 491 व्यक्तियों को 113907 हजार रुपये के ऋण अन्य कृषि कार्य करने के लिए दिये गये।

प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 4.6 प्रतिशत या 21657 हजार रुपये के ऋण 153 व्यक्तियों को लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए दिये गये। जनपद में इस क्षेत्र के लिए विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा अलग–अलग वित्तीय योगदान किया गया। क्योंकि जहां एक ओर सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की रसूलाबाद शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का 12.8 प्रतिशत भाग ऋण इस क्षेत्र के लिए दिया गया वहीं पंजाब नेशनल बैंक की शिवली शाखा द्वारा मात्र 1.2 प्रतिशत इस क्षेत्र को दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है। जनपद में शेष प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 7.7 प्रतिशत भाग या 36477 हजार रुपये के ऋण अन्य प्राथमिकता क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए 350 व्यक्तियों को दिये गये। इस क्षेत्र में भी विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है क्योंकि जहां एक ओर सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की रसूलाबाद शाखा द्वारा अपने वितरित ऋण का 22.2 प्रतिशत भाग इस क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए दिया गया वहीं स्टेट बैंक आफ इण्डिया की पुखरायां शाखा द्वारा इस क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए मात्र 3.5 प्रतिशत ऋण ही प्रदान किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति

रही है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का सबसे अधिक भाग कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए दिया गया। सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में ऋण वितरित होने का कारण भी निश्चित है क्योंकि कानपुर देहात जनपद की आधे से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में आवास करती है और ग्रामीण क्षेत्र में रहकर जीविकोपार्जन के साधन के रूप में प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और जनपद की कृषि अर्थव्यवस्था आज भी पिछड़ी हुई है क्योंकि आज भी पर्याप्त मात्रा में न तो सिचाई के साधन ही उपलब्ध हैं और न ही नवीन तकनीकी का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग हो पा रहा है। इन दोनों ही स्थिति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सम्पूर्ण विकास करने के लिए पर्याप्त मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है जो व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से सम्भव है। अतः इसी को ध्यान में रखते हुये ही देहात जनपद की बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान कर इस क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रयास है। जनपद में कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र व लघु उद्योग क्षेत्र को भी व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्त प्रदान किया जा रहा है जिससे यह क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के सहायक क्षेत्र के रूप में विकसित होकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आवास कर रहे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें इसके लिए एक प्रयास है।

कानपुर क्षेत्र के सम्पूर्ण जनपदों का अलग–अलग अध्ययन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कानपुर क्षेत्र में जो 188 व्यावसायिक बैंके कार्यरत हैं उनके द्वारा कृषि क्षेत्र में विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो वित्त प्रदान किया जा रहा है उसमें से अध्ययन के लिए जिन 30 प्रतिशत (57 बैंक शाखायें) शाखाओं का अध्ययन के लिए चयन किया गया है। उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में कुल प्राथमिकता क्षेत्र में 36202 व्यक्तियों को 3716838 हजार रुपये के ऋण दिये गये। जिन व्यक्तियों को व्यावसायिक बैंक के द्वारा ये ऋण दिये गये हैं वह विभिन्न समयावधियों को ध्यान में रखते हुये दिये गये हैं अतः कानपुर क्षेत्र में विभिन्न समयावधियों में इन 57 बैंक शाखाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में वितरित ऋण के विवरण को सारणी संख्या 117 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–117

कानपुर क्षेत्र में अध्ययन के लिए चयनित बैंकिंग इकाइयों द्वारा समय के आधार पर ऋण का वितरण
स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

जनपद का नाम	शाखा संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	लाभार्थियों की संख्या	अल्पकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	मध्यकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	दीर्घकालीन ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. फर्रूखाबाद	09	788257	7371	197031	25%	3903	293535	37.2%	1786	297691	37.8%	1682
2. कन्नौज	08	659803	3858	209534	31.8%	1891	203377	30.8%	1330	246892	37.4%	637
3. इटावा	13	924223	12173	162469	17.6%	6491	231443	25%	2325	530281	57.4%	3289
4. औरैया	08	114705	2674	44532	38.8%	1374	19548	17.3%	372	50624	44.1%	928
5. कानपुर नगर	10	758083	6645	443045	58.4%	5236	115377	15.2%	670	199661	26.4%	739
6. कानपुर देहात	09	471767	3481	143960	30.5%	1993	58134	12.3%	503	269673	57.2%	785
योग 06	57	3716838	36292	1200571	32.3%	20868	921414	24.8%	6986	1594822	42.9%	8260

स्रोत – कानपुर क्षेत्र में अध्ययन के लिए चयनित की गई समस्त बैंक शाखाओं से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित ।

सारणी संख्या 117 से यह स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों में से 57 बैंक शाखाओं द्वारा कानपुर क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र में 3716838 हजार रुपये के 36202 व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरित किये। इस वितरित ऋण में कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी 6 जनपदों में सबसे अधिक ऋण का वितरण इटावा जनपद में हुआ है। जबकि सबसे कम ऋण का वितरण इटावा जनपद से अलग–अलग हुये औरैया जनपद में हुआ है इस प्रकार विश्लेषण से स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित किये गये ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है। कानपुर क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र में जो ऋण वितरित किया गया है। इस वितरित ऋण में से 1200571 हजार रुपये के ऋण 20868 व्यक्तियों को दिये गये। कानपुर क्षेत्र में यह वितरित ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 32.3 प्रतिशत भाग है। यह ऋण अल्पकालीन समय के लिए दिया गया। अल्पकालीन समय के लिए दिये गये इस ऋण में कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में कार्यरत बैंक शाखाओं द्वारा वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है जहां एक ओर अल्पकालीन समय के लिए कानपुर नगर की व्यावसायिक बैंक शाखाओं द्वारा अपने वितरित ऋण का 58.4 प्रतिशत भाग इस समय के लिए दिया वहीं इटावा जनपद में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपने वितरित ऋण का मात्र 17.6 प्रतिशत भाग ही इस समय के लिए वितरित किया गया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्र में वितरित होने वाले ऋण में परिवर्तन की स्थिति स्पष्ट होती है, कानपुर क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 24.8 प्रतिशत भाग या 921414 हजार रुपये के ऋण मध्यकालीन समय के लिए दिये गये। इस समय के लिए 6986 व्यक्तियों को ये ऋण दिये गये। क्षेत्र में मध्यकालीन समय के लिए वितरित इस ऋण में भी परिवर्तन की स्थिति रही है क्योंकि जहां एक ओर फर्रूखाबाद जनपद में कार्यरत व्यावसायिक बैंक शाखाओं द्वारा अपने वितरित ऋण का 37.2 प्रतिशत भाग इस समय के लिए दिया गया, वहीं कानपुर देहात जनपद में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों द्वारा मध्यकालीन समय के लिए अपने वितरित ऋण का 12.3 प्रतिशत भाग ऋण ही इस समय के लिए दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में मध्यकालीन समय के लिए वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति पाई गयी है व कानपुर क्षेत्र में वितरित ऋण का शेष भाग या 42.9 प्रतिशत ऋण 8260 व्यक्तियों को दीर्घकाल समय के लिए दिया गया। दीर्घकाल समय के लिए वितरित यह राशि 1593822 हजार रुपये है। इस वितरित धनराशि में यह कह सकते हैं कि विभिन्न जनपदों का योगदान या विभिन्न जनपदों की व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपने वितरित ऋण का इस समय के लिए सबसे अधिक ऋण का वितरण इटावा जनपद में कार्यरत बैंकों द्वारा 57.4 प्रतिशत भाग इस समय के लिए दिया गया है। वहीं कानपुर नगर जनपद में कार्यरत बैंकों द्वारा दीर्घकालीन समय के लिए अपने वितरित ऋण का

मात्र 26.4 प्रतिशत भाग ही इस समय के लिए दिया गया। इससे यह स्पष्ट है कि दीर्घकाल समय के लिए वितरित ऋण में विभिन्न जनपदो में परिवर्तन की स्थिति रही है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में कार्यरत जिन 57 बैंक शाखाओ का अध्ययन किया गया है। उनके द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो साख उपलब्ध कराये गये हैं उसका एक बड़ा भाग या उसमें से सबसे अधिक साख दीर्घकाल समय के लिए दिये गये। जो इस बात को स्पष्ट करता है कि कानपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश को महत्व प्रदान किया गया। चूंकि जहां तक पूंजी निवेश का प्रश्न है कानपुर क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रधान क्षेत्र है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोगों का प्रमुख जीविकोपार्जन का साधन कृषि अर्थव्यवस्था है और कृषि अर्थव्यवस्था आज भी असंगठित संगठनों या निजी स्वामित्व के हाथ में है। जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय आज भी निम्न है इसलिए व्यक्तियों को कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधार के लिए पर्याप्त वित्त जुटा पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है इसलिए व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से वित्त प्राप्त करके कृषि क्षेत्र को एक आर्थिक इकाई बनाने के लिए व्यापक पैमाने पर सुधार करने की आवश्यकता है। व्यापक पैमाने पर सुधार से आशय कृषि क्षेत्र में व्याप्त तमाम प्रकार की आव्यवस्थाओं को दूर कर इस क्षेत्र को तकनीकी क्षेत्र से जोड़ने से है चूंकि कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रयोग करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। और बड़े पैमाने पर निवेश तब सम्भव है जब कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा अधिकाधिक मात्रा में दीर्घकाल समय के लिए वित्त उपलब्ध कराये जायें। बड़े पैमाने पर परिवर्तन के लिए दीर्घकालीन वित्त की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि जब तक अधिक समय के लिए वित्त नहीं उपलब्ध कराया जायेगा तब तक विकास नहीं हो सकता क्योंकि यदि पाप्त वित्त की अदायगी बहुत जल्दी करनी होती है तो अर्थव्यवस्था की स्थिति गड़बड़ा जाती है जिसके कारण बड़े पैमाने पर निवेश कर पाना सम्भव नहीं हो पाता इसी को ध्यान में रखते हुये ही कानपुर क्षेत्र में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों के द्वारा अपने वितरित ऋण का एक बड़ा भाग दीर्घकाल समय के लिए दिया गया इसके बाद अल्पकाल व मध्यकाल ऋण भी वितरित किये गये।

कानपुर क्षेत्र में अध्ययन के लिए चयनित इन बैंक शाखाओ द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में जो ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में दिया गया है वह विभिन्न उद्देश्यों/क्षेत्रों को ध्यान में रखकर दिया गया है। क्षेत्र में दिये गये उद्देश्यों के आधार पर ऋण के विवरण को सारणी संख्या 118 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–118

कानपुर क्षेत्र में अध्ययन के लिए चयनित बैंकिंग इकाइयों द्वारा उद्देश्य के आधार पर ऋण का वितरण

स्थिति 31 मार्च 2006–07 (धनराशि हजार में)

जनपद का नाम	शाखा संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का विभिन्न क्षेत्रों में वितरण								लघु क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या	अन्य प्रा0प्रा0 क्षेत्र में वितरित ऋण	प्रा0 क्षेत्र के सापेक्ष %	लाभार्थियों की संख्या
						ट्रैक्टर एवं कृषि यन्त्र	लाभार्थी संख्या	लघु सिचाई	लाभार्थी संख्या	फसली ऋण	लाभार्थी संख्या	अन्य कृषि ऋण	लाभार्थी संख्या						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. फर्रूखाबाद	09	788257	494692	62.8%	5587	183123	421	61586	209	197031	3903	52972	994	114078	14.5%	537	179455	22.7%	1215
2. कन्नौज	08	659803	456426	69.2%	2528	160230	269	37981	102	209534	1891	48681	266	67212	10.2%	515	136165	20.6%	815
3. इटावा	13	924223	693230	75%	9742	289368	1227	3921	87	162469	6491	229876	1936	70942	7.7%	264	160551	17.4%	2063
4. औरैया	08	114705	95156	83%	2302	29864	210	2094	17	44532	1374	18666	701	3849	3.4%	27	15700	13.6%	346
5. कानपुर नगर	10	758083	642803	84.8%	5975	79161	257	24765	114	443045	5236	90082	378	19435	2.6%	88	95942	12.6%	580
6. कानपुर देहात	09	471767	413633	87.7%	2978	110438	352	45328	142	143960	1993	113907	491	21657	4.6%	153	36477	7.7%	350
योग 06	**57**	**3716838**	**2795940**	**75.2%**	**29113**	**852184**	**2796**	**175675**	**671**	**1200571**	**20888**	**554184**	**4766**	**297173**	**08%**	**1584**	**624290**	**16.8%**	**5369**

स्रोत –कानपुर क्षेत्र में अध्ययन के लिए चयनित समस्त बैंक शाखाओं की फाइल एल0बी0आर0–2 में दिये गये आंकड़ों पर आधारित

सारणी संख्या 118 से यह स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2006–07 में अध्ययन के लिए चयनित 57 बैंक शाखाओं द्वारा क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में प्राथमिकता क्षेत्र में 3716838 हजार रुपये के ऋण वितरित किये। प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित इस ऋण में से 2795940 हजार या प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 75.2 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 29113 व्यक्तियों को वित्त प्रदान किये गये। क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में वितरित यह ऋण विभिन्न जनपदों में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में से कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है क्योंकि जहां एक ओर कानपुर देहात जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 87.7 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र को दिया गया, वहीं फर्रूखाबाद जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 62.8 प्रतिशत ऋण ही कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिया गया। क्षेत्र में वितरित ऋण में इस कम ज्यादा मात्रा से स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में से कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है। कानपुर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में जो भी ऋण वितरित किये गये वह विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत वितरित किये गये। जिसके तहत 2796 व्यक्तियों को 852184 हजार रुपये के ट्रैक्टर एवं कृषि यन्त्र/उपकरणों को क्रय करने के लिए वित्त प्रदान किये गये, 671 व्यक्तियों को 175675 हजार रुपये के कृषि क्षेत्र में सिचाई की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक संसाधनों को क्रय करने या उनके विकास करने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा वित्त प्रदान किया गया, कानपुर क्षेत्र में 20888 व्यक्तियों को 1200571 हजार रुपये के फसली ऋण दिये गये। व कानपुर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत वितरित होने वाले शेष ऋण 554184 हजार रुपये 4766 व्यक्तियों को अन्य कृषि कार्य करने के लिए विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा वित्त प्रदान किये गये।

कानपुर क्षेत्र के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत वितरित ऋण में से कृषि क्षेत्र के अलावा 1584 व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 8 प्रतिशत या 297173 हजार रुपये के लघु उद्योग क्षेत्र को विकसित करने के लिए वित्त प्रदान किये गये। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपने वितरित ऋण का वितरण अलग–अलग रहा है क्योंकि जहां एक ओर फर्रूखाबाद जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 14.5 प्रतिशत भाग लघु उद्योग क्षेत्र को दिया गया वहीं कानपुर नगर जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में अपने वितरित ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत ऋण ही लघु उद्योग क्षेत्र को दिया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि जनपद में इस क्षेत्र के लिए वितरित होने वाले ऋण में परिवर्तन की स्थिति स्पष्ट होती है।

कानपुर क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत वितरित ऋण का शेष 16.8 प्रतिशत ऋण 5369 व्यक्तियों को अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए 624290 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वितरित होने वाले ऋण में परिवर्तन की स्थिति रही है, क्योंकि जहां एक ओर फर्रूखाबाद जनपद में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वितरित होने वाले 22.7 प्रतिशत भाग अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए दिया गया है वहीं कानपुर देहात जनपद में अपने वितरित ऋण का मात्र 7.7 प्रतिशत ऋण ही अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में इस उद्देश्य के लिए दिये जाने वाले ऋणों में परिवर्तन की स्थिति रही है।

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि कानपुर क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों की जिन 57 शाखाओं द्वारा ऋण का वितरण किया गया है उसमें से सबसे अधिक भाग कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए दिया गया है। इसके बाद अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र व लघु उद्योग क्षेत्र को वित्त प्रदान किया गया।

कानपुर क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को इन 57 बैंक शाखाओं द्वारा ऋण प्राप्त हुआ है। उसमें से लाभार्थियों के विस्तृत अध्ययन के लिए प्रत्येक बैंक शाखा से साख प्राप्त लाभार्थियों का 25 प्रतिशत अध्ययन के लिए चयन कर विभिन्न बैंक शाखाओं से साख प्राप्त लाभार्थियों की जानकारी प्राप्त कर उनसे प्रश्नावली के माध्यम से व्यक्तिगत सम्पर्क करके उनके द्वारा प्राप्त ऋण एवं ऋण का समय तथा ऋण के उद्देश्य व ऋण के प्रकार आदि को स्पष्ट किया जायेगा। इसी को ध्यान में रखते हुये सर्वप्रथम कानपुर क्षेत्र के समस्त जनपदों के विभिन्न विकास खण्डों में साख प्राप्त लाभार्थियों की संख्या को जिनका विस्तृत अध्ययन के लिए चयन किया गया है उनको सारणी संख्या 119 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–119
कानपुर क्षेत्र में अध्ययन के लिए चयनित साख प्राप्त लाभार्थियों की संख्या
वर्ष 2006–07

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	अध्ययन के लिए चयनित साख प्राप्त लाभार्थियों की संख्या
1	2	3
1. फर्रूखाबाद	1. राजेपुर	195
	2. नवाबगंज	239
	3. मोहम्मदाबाद	263
	4. कायमगंज	265
	5. शमशाबाद	160
	6. बढ़पुर	720
योग :	**06**	**1842**
2. कन्नौज	1. सौरिख	175
	2. कन्नौज	171
	3. जलालाबाद	159
	4. छिबरामऊ	246
	5. उमर्दा	137
	6. तालग्राम	76
योग :	**06**	**964**
3. इटावा	1. महेबा	466
	2. भरथना	122
	3. चकरनगर	52
	4. जसवन्त नगर	775
	5. ताखा	827
	6. बसरेहर	407
	7. सैफई	186
	8. बढ़पुरा	206
योग :	**08**	**3041**
4. औरैया	1. औरैया	123
	2. अछल्दा	92
	3. अजीतमल	66
	4. भाग्यनगर	133
	5. सहार	53
	6. ऐरवाकटरा	101
	7. विधूना	99
योग :	**07**	**667**

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	अध्ययन के लिए चयनित साख प्राप्त लाभार्थियों की संख्या
1	2	3
5. कानपुर नगर	1. कल्यानपुर	57
	2. ककवन	139
	3. पतारा	128
	4. शिवराजपुर	150
	5. घाटमपुर	227
	6. भीतरगांव	208
	7. विधनू	73
	8. चौबेपुर	108
	9. सरसौल	167
	10. बिल्हौर	405
योग :	**10**	**1662**
6. कानपुर देहात	1. अमरौधा	131
	2. मलासा	118
	3. राजपुर	84
	4. सन्दलपुर	115
	5. अकबरपुर	82
	6. झींझक	121
	7. सरवनखेड़ा	87
	8. रसूलाबाद	70
	9. मैथा	60
योग :	**09**	**868**
महा योग :	**46**	**9044**

सारणी संख्या 119 से यह स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में अध्ययन के लिए 46 विकास खण्डों में कार्यरत 57 बैंक शाखाओं का अध्ययन के लिए चयन किया गया। जिनके द्वारा प्राप्त साख लाभार्थियों के 25 प्रतिशत जनसंख्या 9044 है। कानपुर क्षेत्र में इन व्यक्तियों को क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न बैंकों द्वारा वित्त प्राप्त हुआ है। ये विभिन्न बैंकें विभिन्न विकास खण्डों में कार्यरत हैं। वैसे तो कानपुर क्षेत्र में 50 विकास खण्ड हैं किन्तु अध्ययन के लिए केवल 46 विकास खण्डों का चयन किया गया है। जिन चार विकास खण्डों का चयन नहीं किया गया है। उनमें व्यावसायिक बैंकों की इतनी शाखायें कार्यरत नहीं थी कि उनका अध्ययन के लिए लाटरी प्रणाली के आधार पर चयन किया जा सकता अतः ये चार विकास खण्ड अध्ययन से अछूते रह गये हैं शेष समस्त विकास खण्डों में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं द्वारा वितरित

ऋण के विवरण व साख प्राप्त लाभार्थियों का अध्ययन किया गया है। कानपुर क्षेत्र में कार्यरत इन बैंक शाखाओं के द्वारा जिन व्यक्तियों को साख प्राप्त हुआ है उनका रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर अध्ययन के लिए चुनाव किया गया है। इन अध्ययन के लिए चयनित व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया है। जिन व्यक्तियों से सम्पर्क किया गया है। उन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति क्या रही है व उनके द्वारा कितना ऋण प्राप्त किया गया है तथा उस ऋण के उपयोग का क्या स्तर रहा है आदि का विश्लेषण किया जाना है।

कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में वित्तीय वर्ष 2006–07 में साख प्राप्त लाभार्थियों में से प्रत्येक विकास खण्ड से 25 प्रतिशत लाभार्थियों का विश्लेषण करने के लिए रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर चयन किया गया है इन साख प्राप्त लाभार्थियों की प्रश्नावली भरकर इनके द्वारा ली गई बैंक शाखा से रकम व रकम के वापसी का समय तथा इन साख प्राप्त लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति व साख प्राप्त लाभार्थियों की साख प्राप्त होने के पश्चात् आर्थिक स्थिति में पड़ने वाले प्रभाव आदि का विश्लेषण किया जाना है। इन विभिन्न बिन्दुओं के विश्लेषण के लिए कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में जिन साख प्राप्त लाभार्थियों का चयन किया गया है। उनकी आर्थिक स्थितियों पर सर्वप्रथम विचार किया जाना आवश्यक है। इसके लिए जनपद स्तर पर साख प्राप्त लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति पर विचार किया जा सकता है।

साख प्राप्त लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति पर विचार करने के लिए जनपद स्तर पर साख प्राप्त लाभार्थियों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है।

1. निम्न आय वर्ग के लाभार्थी
2. मध्यम आय वर्ग के लाभार्थी
3. उच्च आय वर्ग के लाभार्थी

इन तीनों ही प्रकार के लाभार्थियों की स्थिति पर विचार करने के लिए सर्वप्रथम तीनों वर्गों के आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना आवश्यक है इसी के तहत सर्वप्रथम निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत किन व्यक्तियों को रखा गया है, मध्यम वर्ग आय के अन्तर्गत किन परिवारों को रखा गया है व उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत किन परिवारों को रखा गया है। इसका स्पष्टीकरण करना अनिवार्य है। इसी को ध्यान में रखते हुये क्रमशः इनका स्पष्टीकरण किया जा सकता है।

1. निम्न आय वर्ग के लाभार्थी : निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत उन लाभार्थियों या व्यक्तियों को रखा गया है जिनकी वार्षिक आय चल व अचल सम्पत्तियों के माध्यम से 20,000 रुपये तक है या जिनके पास भू–राजस्व लेखे के अनुसार 5 बीघे तक सिंचित भूमि है। उन व्यक्तियों को निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत रखा जाता है जिन्हें हम गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की श्रेणी में रख सकते हैं।

इस वर्ग के लाभार्थियों द्वारा कानपुर क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कितने–कितने व्यक्तियों को किस–किस समय के लिए कितनी–कितनी वित्त की मात्रा प्रदान की गई है। इसके विश्लेषण को विभिन्न सारणियों के माध्यम से स्पष्ट किया जायेगा।

2. मध्यम आय वर्ग के लाभार्थी : मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत उन लाभार्थियों/व्यक्तियों को रखा गया है जिनकी चल व अचल किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के माध्यम से वार्षिक आय 21,000 रुपये से लेकर 1,00000 रुपये तक आय है या जिनके पास 6 बीघे से लेकर 25 बीघे तक भू–राजस्व लेखे में सिंचित भूमि पाई जाती है। उन परिवारों को मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत या गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के अन्तर्गत रखा गया है।

मध्यम आय वर्ग के लाभर्थियों द्वारा कानपुर क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में कार्यरत व्यावसायिक बैंक से कितने व्यक्तियों को वित्त प्राप्त हुआ है और कितने समय के लिए व कितनी मात्रा में वित्त प्राप्त हुआ है। तथा इन साख प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा उस वित्त का किस प्रकार से उपयोग किया गया है आदि के विश्लेषण को विभिन्न सारणियों के माध्यम से स्पष्ट किया जायेगा।

3. उच्च आय वर्ग के लाभार्थी : उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत उन व्यक्तियों या लाभार्थियों को रखा गया है। जिनकी चल व अचल किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के माध्यम से वार्षिक आय 1,00000 रुपये से अधिक है और अधिकतम सीमा में कोई प्रतिबन्ध नहीं या जिनके पास भू–राजस्व लेखे में 25 बीघे से अधिक सिंचित भूमि है। इस प्रकार के व्यक्तियों को उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत रखा गया है या यह कहा जा सकता है कि जिन व्यक्तियों के द्वारा आयकर दिया जाता है। वह व्यक्ति उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कानपुर क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों द्वारा विभिन्न

व्यावसायिक बैंकों के द्वारा कितने व्यक्तियों को ऋण प्राप्त हुआ है व इन ऋण प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा उस ऋण का क्या उपयोग किया गया है व कितने समय के लिए ऋण प्राप्त किया गया है आदि के विश्लेषण को विभिन्न सारणियों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

कानपुर क्षेत्र के साख प्राप्त लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति पर विचार करने के पश्चात् इन व्यक्तियों द्वारा क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में कार्यरत विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से जो साख प्राप्त किया गया है। उसके आय वर्ग के आधार पर विवरण व लाभार्थियों की संख्या को तथा इन लाभार्थियों द्वारा प्राप्त ऋण की समय सीमा को विभिन्न जनपदों के आधार पर क्रमशः विश्लेषित किया जाना है। इसी के तहत सर्वप्रथम कानपुर क्षेत्र के फर्रूखाबाद जनपद में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों के द्वारा वितरित ऋण, लाभार्थियों की संख्या आदि को स्पष्ट कियाा जा सकता है।

1. फर्रूखाबाद जनपद : फर्रूखाबाद जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैंको के द्वारा जिन व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया गया है उन व्यक्तियों में से 25 प्रतिशत व्यक्तियों की विभिन्न शाखाओं से नामावली प्राप्त कर उनसे व्यक्तिगत प्रश्नावली भरकर विचार ज्ञात किये गये। इन चयनित व्यक्तियों द्वारा जनपद की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त साख की मात्रा व लाभार्थियों की संख्या तथा ऋण की समयावधि को सारणी संख्या 120 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–120

फर्रूखाबाद जनपद में अध्ययन के लिए चयनित आर्थिक स्थिति के आधार पर साख प्राप्त लाभार्थियों का विवरण (वर्ष 2006–07) धनराशि हजार में

आर्थिक स्थिति	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	लाभार्थी संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का समयावधि के आधार पर वितरण					
			अल्पकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या	मध्यकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या	दीर्घकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. निम्न आय वर्ग	5065	340	523	65	4233	263	309	12
2. मध्यम आय वर्ग	112513	1085	26170	503	43785	417	42558	165
3. उच्च आय वर्ग	89655	417	43785	283	16460	76	29410	58
योग–	**207233**	**1842**	**70478**	**851**	**64478**	**756**	**72277**	**235**

सारणी संख्या 120 से यह स्पष्ट है कि जनपद में अध्ययन के लिए चयनित किये गये 25 प्रतिशत व्यक्तियों जिनकी संख्या 1842 है। इन व्यक्तियों के द्वारा फर्रूखाबाद जनपद की विभिन्न बैंक

शाखाओं से 207233 हजार रुपये के ऋण प्राप्त किये गये। जिन व्यक्तियों ने जनपद की विभिन्न शाखाओं से ऋण प्राप्त किये हैं उन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति निम्न प्रकार रही है जिसके तहत निम्न आय वर्ग के 340 व्यक्तियों को 5065 हजार रुपये के ऋण दिये गये, 1085 मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को 112513 हजार रुपये के ऋण दिये गये व 417 उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को 89655 हजार रुपये के ऋण दिये गये। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में सबसे ज्यादा इन 25 प्रतिशत लाभार्थियों को मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को बैंकों से ऋण प्राप्त हुये हैं। जबकि इसके बाद उच्च आय वर्ग व निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण प्राप्त हो सके हैं। जनपद में जिन व्यक्तियों को ऋण प्राप्त हुये है उनको विभिन्न समयावधियों के आधार पर ऋण दिये गये हैं जिसके तहत 851 व्यक्तियों को 70478 हजार रुपये के अल्पकाल समय के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त हुये हैं। अल्पकाल समय के लिए इन ऋण प्राप्त व्यक्तियों में से 65 व्यक्ति निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत आते हैं जिनको 523 हजार रुपये के ऋण दिये गये, 503 मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को 26170 हजार रुपये के ऋण दिये गये व 283 व्यक्तियों को 43785 हजार रुपये के अल्पकालीन समय के लिए ऋण दिये गये। इस प्रकार सरणी से स्पष्ट है कि जनपद में अल्पकालीन समय के लिए सबसे अधिक मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण दिये गये। जनपद में मध्यकालीन समय के लिए 756 व्यक्तियों को 64478 हजार रुपये के ऋण दिये गये। मध्यकालीन समय के लिए वितरित इस ऋण में 263 निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को 4233 हजार रुपये के मध्यकालीन ऋण दिये गये, 417 मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को 43785 हजार रुपये के मध्यकालीन ऋण दिये गये व जनपद में 76 उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को 16460 हजार रुपये के मध्यकालीन ऋण दिये गये इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में सबसे अधिक मध्यम आय वर्ग के व निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को मध्यकालीन ऋण दिये गये। तथा जनपद में 235 व्यक्तियों को 72277 हजार रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिये गये। जनपद में इस वितरित ऋण में 12 निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को 309 हजार रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिये गये, 165 मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को 42558 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये तथा 58 उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को 29410 हजार रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिये गये। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि दीर्घकालीन समय के लिए सबसे ज्यादा मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण दिये गये।

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जनपद में सबसे अधिक व्यक्तियों को अल्पकालीन तत्पश्चात् मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण दिये गये।

फर्रूखाबाद जनपद में साख प्राप्त लाभार्थियों द्वारा प्राप्त साख का उपयोग :

फर्रूखाबाद जनपद में 1842 विभिन्न व्यावसायिक बैंको से साख प्राप्त व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके उनके द्वारा प्राप्त साख व साख के उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। जानकारी के उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि जिन लाभार्थियों को व्यावसायिक बैंक शाखाओं द्वारा विभिन्न समयावधियों के लिए विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो ऋण दिया गया है उस ऋण का विभिन्न आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त साख का उपयोग परिवर्तित रूप में रहा है जिसके विवरण को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है।

1. निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों द्वारा प्राप्त साख का उपयोग : जनपद में निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 340 व्यक्तियों को ऋण दिया गया है जिसमें से अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि अल्पकाल समय के लिए जिन व्यक्तियों को ऋण प्राप्त हुआ है उनमें से 68.2 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिन्होंने वास्तविक रूप में जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया है उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस ऋण का उपयोग भी किया है जिससे कि उनके द्वारा प्राप्त साख का सदुपयोग हो सका है शेष में 10.3 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने उत्पादन के दूसरे क्षेत्रों में धन का उपयोग किया और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जबकि शेष 21.5 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिन्होंने बैंकों से प्राप्त अल्पकालीन समय के लिए साख को गैर उत्पादक कार्यों में लगाया जिसके अन्तर्गत खाद्यांश पदार्थ क्रय करना व अन्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करना तथा इसके अलावा कुछ व्यक्ति ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने बैंकों से लिये ऋण को महाजनों द्वारा लिये गये ऋण के भुगतान या उसके ब्याज भुगतान में व्यय कर दिया। जिससे कि इन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सका है और बजाय आर्थिक वृद्धि के इतना अवश्य सम्भव हुआ कि ये व्यक्ति बैंकों के भी ऋणी हो गये।

मध्यकाल समय के लिए जनपद में निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 263 व्यक्तियों को ऋण दिया गया था जिसमें से 48.7 प्रतिशत साख प्राप्त व्यक्तियों में जिस कार्य के लिए ऋण लिया था। वास्तविकता में उसी क्षेत्र में लगाया और अपनी निश्चित आय में वृद्धि की। जबकि 22.3 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिन्होंने बैंक से किसी कार्य के लिए ऋण लिया लेकिन लगाया किसी अन्य कार्य में जबकि शेष 29 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे रहे है जिन्होंने मध्यकाल समय में प्राप्त की गई धनराशि का सदुपयोग न करके उसको अन्य कार्यों में लगा दिया जैसे– उत्सव, विवाह, खाद्य पदार्थ क्रय करने व इससे हटकर अन्य बेफिजूल के कार्यों में भी धन को लगाया गया जिससे इन

व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन देखने में नहीं आया।

दीर्घकाल समय के लिए जनपद में निम्न आय वर्ग के 12 व्यक्तियों को ऋण दिया गया। इन साख प्राप्त व्यक्तियों में केवल 7 व्यक्ति ऐसे निकले जिन्होंने धन को उत्पादक कार्यों में लगाकर उत्पादन स्तर को बढ़ाया और अपनी आर्थिक प्रगति की जबकि 4 व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने बैंकों द्वारा प्राप्त साख को पुराने कर को अदा करने में धनराशि को व्यय कर दिया। जबकि शेष 2 व्यक्तियों ने बैंकों द्वारा प्राप्त साख को अपने पारिवारिक खर्चों में व्यय किया। इस व्यय में उनके पुत्र व पुत्रियों का शिक्षा व्यय आदि भी शामिल है। जिन व्यक्तियों ने इस प्रकार के क्षेत्र में अपना धन व्यय किया है उनकी आर्थिक स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जनपद में निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत तीनों ही समयावधियों में लिये गये ऋण का एक बड़ा भाग अनुत्पादक कार्यों में लगाया गया। जिससे कि व्यक्तियों की आर्थिक स्थितियों में बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन नहीं हो सका।

2. मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों द्वारा प्राप्त साख का उपयोग : मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत जनपद की विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा 1085 व्यक्तियों को साख प्रदान किया गया। इन साख प्राप्त लाभार्थियों में 503 व्यक्तियों को अल्पकाल समय के लिए ऋण प्राप्त हो सका। अल्पकाल समय के लिए साख प्राप्त इन व्यक्तियों में 83 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे रहे हैं। जिन्होंने बैंकों से प्राप्त साख को जिस उद्देश्य के लिए लिया था उसी उद्देश्य में लगाया भी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन भी हुआ। जबकि 7 प्रतिशत व्यक्तियों ने अल्पकाल समय के लिए प्राप्त साख को पारिवारिक सदस्यों के रोटी कपड़ों से लेकर शिक्षा तक में व्यय किया, जबकि शेष 10 प्रतिशत व्यक्तियों ने बैंकों द्वारा प्राप्त साख को भवन निर्माण, उत्सव व अन्य कार्य करने के लिए धन का उपयोग किया जिससे इन व्यक्तियों की इन तमाम सारी आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो गई परन्तु जिस उद्देश्य के लिए इन्होंने बैंकों से वित्त प्राप्त किया था उस उद्देश्य में न लगाकर अपने आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सके।

मध्यवर्गीय व्यक्तियों में 417 व्यक्तियों को मध्यकाल समय के लिए विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से साख प्राप्त हुआ। मध्यवर्गीय व्यक्तियों के द्वारा जो मध्यकाल समय के लिए साख प्राप्त हुआ है उसमें से 67 प्रतिशत व्यक्तियों ने तो धन को उत्पादक कार्यों में लगाया जिससे इन व्यक्तियों के उत्पादन स्तर में परिवर्तन हुआ और जिससे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति भी

परिवर्तित हुई, किन्तु 33 प्रतिशत व्यक्तियों ने बैंकों द्वारा प्राप्त साख को या तो अनुत्पादक कार्यों में लगाया या फिर अन्य बेफिजूल के खर्चों में व्यय कर दिया जिससे कि बैंकों द्वारा साख प्राप्त होने के बावजूद भी उनके आर्थिक जीवन में कोई सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं होता है।

दीर्घकाल समय के लिए मध्य आय वर्ग के अन्तर्गत 153 व्यक्तियों को ऋण दिया गया जिसमें से इस ऋण का लगभग भाग जिस उद्देश्य के लिए दिया गया था उसी में लगाया गया, लेकिन उचित प्रशिक्षण व ज्ञान न होने के अभाव में कुछ व्यक्तियों द्वारा इस ऋण से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। जबकि शेष व्यक्तियों के आर्थिक स्थिति में परिवर्तन देखने में आया है।

3. उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों द्वारा प्राप्त साख का उपयोग : जनपद में 417 उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को विभिन्न बैंक शाखाओं से वित्त प्राप्त हुआ है। इन वित्त प्राप्त लाभार्थियों में 283 व्यक्तियों को अल्पकाल समय के लिए व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त हो सके हैं जिन व्यक्तियों को अल्पकाल समय के लिए ऋण प्राप्त हुये हैं उन व्यक्तियों में से 90 प्रतिशत व्यक्तियों ने इस धन का सदुपयोग किया क्योंकि इन व्यक्तियों ने जिस उद्देश्य के लिए धन को लिया था उसी उद्देश्य में लगाकर उत्पादन स्तर को बढ़ाया जिससे इन व्यक्तियों के आर्थिक स्तर में वृद्धि हुई है। जबकि 10 प्रतिशत व्यक्तियों ने साख प्राप्त करने के बावजूद भी आर्थिक परिवर्तन नहीं हुआ। इसका कारण यह रहा कि इन लोगों ने जो भी साख प्राप्त किया उसको अनुत्पादक कार्यों में व्यय किया जिससे इनके जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो सका।

जनपद में उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत मध्यकाल समय के लिए 76 व्यक्तियों को व्यवसायिक बैंक शाखाओं द्वारा ऋण दिया गया जिसका व्यक्तियों के द्वारा बताई गई सूचनाओं के आधार पर सभी व्यक्तियों ने बैंकों द्वारा प्राप्त ऋण को उत्पादक कार्यों में लगाया और उससे उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है।

जनपद में उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा दीर्घकाल समय के लिए 58 व्यक्तियों को ऋण दिया गया जिसमें से लगभग सभी व्यक्तियों ने जिस कार्य के लिए वित्त प्राप्त किया था लगभग उसी कार्य में सम्पूर्ण धनराशि को लगाया जिससे इन व्यक्तियों के उत्पादन स्तर में वृद्धि हुई और जिससे इनकी आय में वृद्धि हो सकी।

जैसा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा जिस भी व्यक्ति को ऋण दिया गया है उसके द्वारा लगभग तौर पर धन को उसी क्षेत्र में लगाया गया है। जिसके लिए बैंकों से साख प्राप्त हुआ है। हालांकि यह स्थिति उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों में मध्यम आय वर्ग व निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक रही है। जबकि निम्न आय वर्ग के द्वारा विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त साख की एक बड़ी मात्रा अनुत्पादक कार्यों में भी व्यय की गई जिससे उच्च आय वर्ग की तुलना में इस आय वर्ग के व्यक्तियों के जीवन स्तर में कम परिवर्तन हो सका है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इनके जीवन स्तर में कुछ बदलाव ही नहीं हुआ।

जनपद में व्यावसायिक बैंकों के साख प्राप्त लाभार्थियों द्वारा प्रकट किये गये विचार :

फर्रूखाबाद जनपद में जिन व्यक्तियों को व्यावसायिक बैंको के द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण दिया गया उनके द्वारा बैंकों की कार्यप्रणाली से लेकर धन के उपयोग के सम्बन्ध तक निम्नलिखित विचार प्रकट किये गये।

1. व्यावसायिक बैंकों के सृजन से ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त ऋणग्रस्तता में कमी आई है।
2. व्यावसायिक बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण का वितरण किया जा रहा है उससे कृषि क्षेत्र में कार्यशील पूंजी व पूंजीगत वित्त की समस्या से निजात मिली है।
3. कम ब्याज स्तर पर ऋण प्राप्त होने से जो आय का निश्चित भाग ब्याज भुगतान में खर्च होता था उसमें कमी आई है।
4. व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्राप्त ऋण से कृषि क्षेत्र के उत्पादन स्तर में वृद्धि हो सकी है।
5. हम लोगों (किसानों) का ढाँचा विस्तृत व मजबूत हो सका है।
6. बैंकों से प्राप्त ऋण से कृषि के सहायक क्षेत्रों का विकास हुआ है। जिससे कृषि कार्य को देखने के साथ–साथ हम लोगों की अतिरिक्त आय में वृद्धि हो सकी है।
7. व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख प्राप्त होने से सिचाई के साधनों का विकास हो सका है। जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है।
8. व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्राप्त साख से कृषि यन्त्रीकरण में वृद्धि हुई है जिससे फसल को समय से तैयार कर सुरक्षित घरों तक ले जाने में सहायता प्राप्त हुई है।
9. व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त ऋण द्वारा गांवों में ट्रैक्टरों की मात्रा में वृद्धि हुई है जिससे कृषि कार्य करना आसान हो सका है व मण्डियों तक अपने उत्पादित फसल के अतिरेक को ले जाने में सहायता प्राप्त हुई है जिससे व्यापारियों एवं मध्यस्थों से बचा जा सका है और अपनी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हुई है।

10. व्यावसायिक बैंकों के विकास होने से बचत किये हुये धन को सुरक्षित रखने में सहायता प्राप्त हुई है व बचत करने को विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से प्रोत्साहन मिला है।

फर्रूखाबाद जनपद में साख प्राप्त व्यक्तियों से सम्पर्क करने पर जहां एक ओर अधिकाधिक व्यक्तियों ने बैंकों की कार्यप्रणाली पर सन्तोष जाहिर कर उनकी विशेषताओं को उजागर करने की कोशिश की वहीं पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा व्यावसायिक बैंकों की कार्यप्रणाली पर असन्तोष जाहिर कर उनकी आलोचनायें समस्या के रूप में प्रकट की जिनको निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

1. पर्याप्त मात्रा में ऋण प्राप्त न हो पाना, जिससे कि अतिरिक्त उत्पादन स्तर को न प्राप्त कर सकना या अतिरिक्त आय न अर्जित कर पाना।
2. ऋण प्राप्त करने में व्यावसायिक बैंकों द्वारा काफी कठिन शर्तों को लागू करना जिससे या तो कम मात्रा में ऋण प्राप्त होता है या फिर ऋण प्राप्त कर पाना लगभग असम्भव सा हो जाता है।
3. ऋण अदायगी की किश्तों के दिनों में कम अन्तर होना जिससे समय पर ऋण की किश्त न पहुंच पाना और परिणामस्वरूप अधिक ब्याज वसूल किया जाता है।
4. बैंकों से सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकास परक योजनाओं की समय से सूचना न देना व प्रशिक्षण आदि का अभाव होना जिससे जिन व्यक्तियों को योजना का लाभ भी मिलता है वह उस लाभ का उचित उपयोग नहीं कर पाते हैं जिससे इस प्रकार के व्यक्तियों की आर्थिक स्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो पाता।
5. ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में अनेक आवश्यक कागजातों की पूर्ति करनी होती है जो कम समय में कर पाना सम्भव नहीं हो पाता जिससे समय पर ऋण प्राप्त नहीं हो सकता जिससे समय से ऋण का उपयोग नहीं हो सकता जिससे उत्पादन स्तर में गिरावट आती है। और जिसका परिणाम यह निकलता है कि औसत रूप से होने वाली वार्षिक आय में वृद्धि कम मात्रा में हो पाती है।

उपरोक्त दोनों प्रकार की स्थितियों पर विचार करने के पश्चात् इस स्थिति पर पहुचा जा सका है कि निश्चित ही व्यावसायिक बैंकों के विकास होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय समस्याओं से एक सीमा तक निपटा जा सका है। जिससे कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधार किये जा सके हैं जिससे इस क्षेत्र के उत्पादन स्तर में वृद्धि हुई है।

2. कन्नौज जनपद : कन्नौज जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में व्यावसायिक बैंकों द्वारा जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में वितरित ऋण में से साख प्राप्त लाभार्थियों में 25 प्रतिशत लाभार्थियों की संख्या 964 रही है। जिन व्यक्तियों को अध्ययन के लिए चयन किया गया है। उन व्यक्तियों की विभिन्न बैंकों से नामावली लेकर इनके द्वारा प्राप्त साख तथा साख के उपयोग के सम्बन्ध में व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया और इनके द्वारा साख के उपयोग से लेकर व्यावसायिक बैंकों के वित्त का इनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी स्पष्ट किया गया है। अतः कन्नौज जनपद में इन साख प्राप्त व्यक्तियों के विश्लेषण को सारणी संख्या 121 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–121

कन्नौज जनपद में अध्ययन के लिए चयनित आर्थिक स्थिति के आधार पर साख प्राप्त लाभार्थियों का विवरण (वर्ष 2006–07) धनराशि हजार रु0 में

आर्थिक स्थिति	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	लाभार्थी संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का समयावधि के आधार पर वितरण					
			अल्पकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या	मध्यकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या	दीर्घकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. निम्न आय वर्ग	9320	185	3255	93	5330	82	735	07
2. मध्यम आय वर्ग	131075	627	58375	380	37000	200	35700	47
3. उच्च आय वर्ग	56058	155	16275	52	6240	70	33543	33
योग–	**196453**	**964**	**77905**	**525**	**48570**	**352**	**69978**	**87**

सारणी संख्या 121 से यह स्पष्ट है कि जनपद में अध्ययन के लिए चयनित किये गये 25 प्रतिशत व्यक्तियों जिनकी संख्या 964 है। इन व्यक्तियों के द्वारा कन्नौज जनपद की विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा 196453 हजार रुपये के ऋण प्राप्त किये। ऋण प्राप्त इन व्यक्तियों में से 182 व्यक्ति निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत आते हैं जिनको प्राथमिकता क्षेत्र में 9320 हजार रुपये के ऋण दिये गये, 627 मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को 131075 हजार रुपये के ऋण दिये गये, व 155 उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को 56058 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। इस प्रकार सारणी से यह स्पष्ट है कि जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में सबसे अधिक मध्य आय वर्गीय व्यक्तियों को ऋण दिये गये। इसके बाद निम्न आय वर्ग व उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण दिये गये। जनपद में जिन व्यक्तियों को ये ऋण प्राप्त हुये हैं उनको विभिन्न समयावधियों के आधार पर यह ऋण दिये गये हैं जिसके तहत 525 व्यक्तियों को 77905 हजार रुपये के

अल्पकालीन समय के लिए ऋण दिये गये। अल्पकालीन समय के लिए निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 93 व्यक्तियों को 3255 हजार रुपये के ऋण दिये गये, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 380 व्यक्तियों को 58375 हजार रुपये के अल्पकालीन ऋण दिये गये व जनपद में उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत 52 व्यक्तियों को 16275 हजार रुपये के ऋण दिये गये। जनपद में 352 व्यक्तियों को 48570 हजार रुपये के मध्यकालीन समय के ऋण दिये गये। मध्यकालीन समय के लिए जनपद में यह ऋण निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 82 व्यक्तियों को 5330 हजार रुपये के ऋण दिये गये, 200 मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों को 37000 हजार रुपये के मध्यकालीन ऋण दिये गये व जनपद में 70 उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को 6240 हजार रुपये के मध्यकालीन ऋण दिये गये। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में सबसे अधिक मध्यवर्ग के व्यक्तियों को मध्यकालीन ऋण दिये गये। इसके बाद निम्न आय वर्ग व उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को इस समय के लिए ऋण दिये गये। जनपद में 87 व्यक्तियों को 69978 हजार रुपये के दीर्घकालीन समय के लिए ऋण वितरित किये गये। दीर्घकालीन समय के लिए इस वितरित ऋण में 7 निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को 735 हजार रुपये के ऋण दिये गये, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 47 व्यक्तियों को 35700 हजार रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिये गये व जनपद में 33 उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को 33543 हजार रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिये गये। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में सबसे अधिक मध्यम वर्ग आय के व्यक्तियों को तत्पश्चात् उच्च व निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को दीर्घकालीन ऋण दिये गये।

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जनपद में सबसे अधिक अल्पकाल समय में व्यक्तियों को ऋण दिये गये, तत्पश्चात मध्यकाल व दीर्घकाल समय के लिए ऋण का वितरण किया गया, किन्तु जहां तक औसत ऋण वितरण के सम्बन्ध में प्रश्न है तो सबसे अधिक दीर्घकाल समय में ऋण का वितरण किया गया। जनपद में जिन व्यक्तियों को यह ऋण प्राप्त हुये हैं उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क करके उनके कुछ विचार जाने गये व उनके द्वारा ऋण के उपयोग क सम्बन्ध में भी प्रश्नावली भरकर उनके द्वारा व्यक्त किये गये सभी विचार व समस्याओं को प्रकट किया गया है।

कन्नौज जनपद में साख प्राप्त व्यक्तियों द्वारा ऋण का उपयोग : कन्नौज जनपद में विभिन्न आय वर्ग के व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके यह ज्ञात हुआ है कि विभिन्न बैंक शाखाओं के द्वारा विभिन्न समयावधियों के लिये प्राप्त धनराशि का उद्देश्यों के आधार पर जो

जहां तक धनराशि के उचित उपयोग का प्रश्न है सबसे ज्यादा जनपद में उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा धन का उपयोग किया गया है क्योंकि इस वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया गया है उसी उद्देश्य में लगभग व्यक्तियों के द्वारा धन को अधिकाधिक मात्रा में लगाया भी गया है। जिससे इस वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन स्तर को बढ़ाकर अधिकाधिक मात्रा में लाभ अर्जित किया गया है। जिससे यह कहा जा सकता है कि व्यावसायिक बैंकों के वित्त का सबसे अधिक प्रभाव उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के ऊपर पड़ा है क्योंकि इस वर्ग के व्यक्तियों ने जो भी साख प्राप्त की है उसकी अधिकाधिक मात्रा उत्पादक कार्यों में लगाई है। जिससे इन व्यक्तियों के उत्पादन स्तर में दिन–प्रतिदिन वृद्धि हुई है जिससे इन लोगों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन सम्भव हो सका है। जबकि सबसे कम निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त साख का जनपद में सदुपयोग किया गया है। इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों में लगभग 60–70 प्रतिशत तक लोगों द्वारा प्राप्त साख का ही सदुपयोग किया जा सका है। बाकी व्यक्तियों के द्वारा व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त धनराशि का अनुत्पादक कार्यों में लगाया जाना रहा है जिससे इस वर्ग के व्यक्तियों की आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन हो पाना सम्भव नहीं हो पाया है और जिन व्यक्तियों के द्वारा धन का सदुपयोग भी किया गया है ऐसा संज्ञान में आया है कि उन व्यक्तियों की भी अपेक्षाकृत अन्य आय वर्ग की तुलना में कम ही मात्रा में आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई है इस सम्बन्ध में जब व्यक्तियों से पूछा गया तो ज्ञात हुआ कि हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में ऋण ही नहीं प्राप्त हो पाता जिससे आवश्यकता के अनुरूप ऋण न मिलने के कारण हम लोगों के द्वारा आवश्यक वित्त न जुटा पाने की स्थिति में उत्पादन स्तर में एक छोटे पैमाने पर ही वृद्धि हो सकी है। जिससे हम लोगों के जीवन स्तर में व्यावसायिक बैंकों के वित्त का अपेक्षाकृत अन्य वर्गों की तुलना में कम प्रभाव पड़ा है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा इसके अन्य भी कारण भी बताये गये हैं लेकिन इतना भी सत्य है कि इस वर्ग के व्यक्तियों का जीवन स्तर आज भी बहुत सुदृढ़ नहीं हो सका है।

जनपद में मध्य आय वर्गीय व्यक्तियों के द्वारा व्यावसायिक बैंक शाखाओं से प्राप्त ऋण का लगभग 80–90 प्रतिशत तक धन का सदुपयोग किया गया है जिससे इनके जीवन स्तर में अपेक्षाकृत सुधार की स्थिति देखने में आयी है क्योंकि जिन व्यक्तियों से सम्पर्क किया गया है उनके द्वारा यह जानकारी दी गई है चूंकि हम लोगों के पास वित्तीय अभाव होने के कारण कृषि क्षेत्र में पर्याप्त निवेश कर पाना सम्भव नहीं था जिसके कारण कृषि क्षेत्र पिछड़ा हुआ था जिससे हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं थी, किन्तु आज व्यावसायिक बैंकों का

विकास होने के पश्चात् हम लोगों को बैंकों से वित्त प्राप्त हुआ जिससे हम लोगों ने कृषि क्षेत्र में निवेश के स्तर को बढ़ाया जिससे कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक एवं कृषि यन्त्रों का प्रयोग किया जा सका जिससे कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जा सका। कृषि क्षेत्र में उत्पादन के स्तर में वृद्धि होने से हम लोगों की अतिरिक्त आय में वृद्धि हुई जिससे हम लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ अतः कह सकते हैं कि व्यावसायिक बैंकों का हम लोगों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। लेकिन जिन 15–20 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा साख प्राप्त होने के बावजूद उनके जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ उनसे बदलाव न होने के कारण जानने चाहे तो पता चला कि व्यावसायिक बैंकों के द्वारा वित्त तो प्रदान किया गया लेकिन हमें उचित जानकारी नहीं थी जिसके कारण हम धन का सदुपयोग नहीं कर सके। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों के द्वारा आर्थिक रूप से साहूकारों, महाजनों, सगे–सम्बन्धियों एवं अन्य व्यक्तियों का ऋणी होने के कारण बैंकों से जो भी वित्त प्राप्त हुआ उसका एक बड़ा भाग इन लोगों की रकम वापसी के लिए दे दिया गया जिससे हमारे पास पुनः धनाभाव हो गया। जिस कारण हम लोग बैंकों से प्राप्त वित्त का कोई लाभ नहीं ले सके। और इन व्यक्तियों के द्वारा कोई लाभ न ले पाने के कारण इनके आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

कन्नौज जनपद में उपरोक्त तीनों प्रकार के आय वर्ग के लाभार्थियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके यह ज्ञात हुआ कि व्यावसायिक बैंकों के वित्त का प्रभाव सबसे अधिक उच्च्य आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों पर पड़ा क्योंकि इन व्यक्तियों ने प्राप्त साख का सदुपयोग कर कृषि क्षेत्र का विकास किया व इसके साथ–साथ जिस कार्य के लिए ऋण प्राप्त किया उससे अतिरिक्त आय प्राप्त कर अपना विकास किया। जबकि निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा अपेक्षाकृत उच्च्य व मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों की तुलना में बहुत कम मात्रा में व्यावसायिक बैंकों से साख प्राप्त होने के बावजूद भी अपने जीवन स्तर को बहुत ऊँचा नहीं कर सके।

कन्नौज जनपद में साख प्राप्त व्यक्तियों के विचार : कन्नौज जनपद में अध्ययन के लिए चयनित 964 व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके उनके विचारों को सुना गया तथा उनके द्वारा व्यावसायिक बैंकों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न विचार प्रकट किये गये।

1. व्यावसायिक बैंकों के द्वारा ऋण प्राप्त होने से आर्थिक ऋण ग्रस्तता में कमी आई है।
2. व्यावसायिक बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण प्राप्त होने से कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधार किये जा सके हैं।

3. इन बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में अपेक्षाकृत अन्य बैंकिंग संस्थाओं से प्राप्त होने वाले ऋण से कम मात्रा में ब्याज का भुगतान करना पड़ता है जिससे ब्याज के भुगतान में दी जाने वाली अतिरिक्त राशि में बचत हुई है।
4. व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त ऋण से स्वरोजगार के क्षेत्र में वृद्धि हुई है।
5. व्यावसायिक बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी करने से किसी भी समय वित्त प्राप्त किया जा सकता है जिससे किसी भी प्रकार की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है या आकस्मिक समस्याओं से निपटा जा सकता है।

समस्यायें : कन्नौज जनपद में एक ओर जहां साख प्राप्त लाभार्थियों द्वारा व्यावसायिक बैंकों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में सन्तोष जाहिर किया गया वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनकी कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में कुछ समस्यायें भी प्रकट की गयी और उन समस्याओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था में परिवर्तन के लिए व्यक्तियों के द्वारा कुछ सुझाव भी दिये गये। जो निम्नलिखित हैं :–

1. व्यावसायिक बैंकों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऋण की प्राप्ति न हो पाना ।
2. ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न हो पाना।
3. आवश्यक कागजातों की समय से उपलब्धता न हो पाना जिससे समय पर ऋण प्राप्त न हो पाना।
4. आवश्यक शर्तों को पूरा न कर पाना, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऋण लेने से वंचित रह जाना।
5. ऋण अदायगी की किश्तों का समय से भुगतान न होने की स्थिति में अतिरिक्त ब्याज वसूल करना।
6. सेवा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य बैंक से ऋण प्राप्त करने पर सेवा क्षेत्र की बैंक द्वारा ऋण की उपलब्धता न करा पाना आदि बिन्दुओं पर विभिन्न साख प्राप्त लाभार्थियों द्वारा समस्यायें प्रकट की गयी और यह कहा गया कि एक सुदृढ़ बैंकिंग सुविधा तभी सम्भव है जबकि इन बैंकों के द्वारा इन अवगत कराई गई समस्याओं का निराकरण किया जाये। इस प्रकार कन्नौज जनपद के साख प्राप्त लाभार्थियों द्वारा बैंकिंग प्रणाली के सम्बन्ध में अपने सुझाव भी प्रकट किये गये। संक्षेप रूप में कहा जा सकता है कि व्यावसायिक बैंकों से वित्त प्राप्त होने के उपरान्त कृषि अर्थव्यवस्था सहित अन्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता प्राप्त हुई है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

3. इटावा जनपद : इटावा जनपद में अध्ययन के लिए जिन बैंक शाखाओं का चयन किया गया है उनके द्वारा जितने भी व्यक्तियों को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्त प्रदान किया गया है उसमें से 25 प्रतिशत व्यक्तियों का अध्ययन के लिए चयन किया गया और इन 25 प्रतिशत व्यक्तियों से प्रश्नावली के माध्यम से व्यक्तिगत साक्षात्कार किया गया। व्यक्तिगत साक्षात्कार करके उनके द्वारा विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त रकम की मात्रा व उस रकम के उपयोग तथा उस रकम के उपयोग से इन व्यक्तियों के जीवन स्तर में पड़ने वाले प्रभाव तथा बैंकिंग कार्यप्रणाली के ढाँचे के सम्बन्ध में भी इन साख प्राप्त व्यक्तियों से चर्चा की गई तथा उनके विचारों को जाना गया। इटावा जनपद में वित्तीय वर्ष 2006–07 में 25 प्रतिशत लाभार्थियों की संख्या 3041 रही है। इनके द्वारा 221721 हजार रुपये के ऋण प्राप्त किये गये हैं। इन व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त ऋण एवं उसकी समयावधि तथा इन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को सारणी संख्या 122 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–122

इटावा जनपद में अध्ययन के लिए चयनित आर्थिक स्थिति के आधार पर साख प्राप्त लाभार्थियों का विवरण (वर्ष 2006–07) धनराशि हजार रु0 में

आर्थिक स्थिति	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	लाभार्थी संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का समयावधि के आधार पर वितरण					
			अल्पकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या	मध्यकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या	दीर्घकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. निम्न आय वर्ग	20460	756	7560	400	5600	310	7300	46
2. मध्यम आय वर्ग	80976	1687	15660	870	18750	625	46566	192
3. उच्च आय वर्ग	120285	598	32260	276	35805	217	52220	105
योग–	**221721**	**3041**	**55480**	**1546**	**60155**	**1152**	**106086**	**343**

सारणी संख्या 122 से यह स्पष्ट है कि इटावा जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत अध्ययन के लिए जिन 3041 व्यक्तियों का चयन किया गया है उनके द्वारा 221721 हजार रुपये के विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त किये गये हैं। ऋण प्राप्त इन व्यक्तियों में 756 निम्न आय वर्ग के व्यक्ति जिनको 20460 हजार रुपये के ऋण व्यावसायिक बैंको द्वारा दिये गये, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 1687 व्यक्तियों को 80976 हजार रुपये के ऋण दिये गये व जनपद में 598 उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को 120285 हजार रुपये के ऋण दिये गये। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में सबसे अधिक मध्यम आय वर्ग के लोगों को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किये गये तत्पश्चात्

निम्न व उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण दिये गये। जनपद में इस वितरित ऋण में से 1546 व्यक्तियों को 55480 हजार रुपये के ऋण अल्पकालीन समय के लिए दिये गये। जनपद में इस समय के लिए निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 400 व्यक्तियों को 7560 हजार रुपये के अल्पकालीन ऋण दिये गये, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 870 व्यक्तियों को 15660 हजार रुपये के ऋण दिये गये व 276 व्यक्तियों को 32260 हजार रुपये के अल्पकालीन ऋण दिये गये। जनपद में 1152 व्यक्तियों को 60155 हजार रुपये के मध्यकालीन ऋण दिये गये। इस समय के लिए जनपद में निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 310 व्यक्तियों को 5600 हजार रुपये के ऋण दिये गये, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 625 व्यक्तियों को 18750 हजार रुपये के ऋण दिये व 217 व्यक्तियों को 35805 हजार रुपये के उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को मध्यकालीन ऋण दिये गये। जनपद में 343 व्यक्तियों को 106086 हजार रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिये गये। जनपद में इस समय के लिए निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 46 व्यक्तियों को 7300 हजार रुपये दिये गये, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 192 व्यक्तियों को 46566 हजार रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिये व 105 उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को 52220 हजार रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिये गये। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में सबसे अधिक मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण प्रदान किये गये। तत्पश्चात् उच्च आय वर्ग व निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को बैंकों द्वारा वित्त प्राप्त हुये।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जनपद में सबसे अधिक अल्पकालीन समय के लिए व्यक्तियों को ऋण दिये तत्पश्चातृ मध्यकाल व दीर्घकाल समय के लिए व्यक्तियों को ऋण दिये किन्तु औसत ऋण वितरण सबसे अधिक दीर्घकाल तत्पश्चात् मध्यकाल व अल्पकाल समय का रहा। इस प्रकार कह सकते हैं कि दीर्घकाल समय के लिए व्यक्तियों को तो कम ऋण दिया गया परन्तु ऋण की मात्रा औसत रूप से ज्यादा रही।

इटावा जनपद में व्यावसायिक बैंकों से साख प्राप्त व्यक्तियों द्वारा ऋण का उपयोग :

इटावा जनपद में विभिन्न आय वर्ग के व्यक्तियों द्वारा व्यावसायिक बैंक शाखाओं से विभिन्न समयावधि के लिए जो वित्त प्राप्त किया है यह वित्त जिन भी व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त किया गया है उन व्यक्तियों से जब व्यक्तिगत तौर पर जानकारी ली गई तो पता चला कि इन विभिन्न वर्गों में सबसे अधिक ऋण का सदुपयोग या जिस कार्य के लिए बैंकों से वित्त प्राप्त किया गया था। उसी कार्य में ऋण का उपयोग मध्य आय वर्गीय व उच्च आय वर्गीय परिवारों द्वारा ऋण का उपयोग किया गया। क्योंकि जानकारी से यह स्पष्ट हुआ है कि जो विभिन्न समयावधियों के

लिए ऋण प्राप्त किया गया था। उसमें से मध्य आय वर्गीय परिवरों द्वारा अल्पकाल समय के लिए प्राप्त वित्त व मध्यकाल समय के लिए जो भी वित्त जिन भी व्यक्तियों ने प्राप्त किया है उसमें से लगभग 80 प्रतिशत व्यक्तियों ने धन का सदुपयोग ही किया है, क्योंकि सर्वे के माध्यम से यह बात स्पष्ट हुई है कि इन वर्ग के परिवारों की ऋण लेने से पहले और ऋण लेने के बाद की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन स्पष्ट होता है। जो इस बात को सिद्ध करता है कि इन व्यक्तियों ने बैंकों से प्राप्त वित्त का सदुपयोग कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है, जबकि शेष लगभग 20 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा यह बताया गया कि हम लोगों को बैंक शाखाओं से वित्त तो प्राप्त हुआ लेकिन हम लोगों के व्यक्तिगत समस्याओं के कारण वित्त का सदुपयोग नहीं कर सके जिससे हमारी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सका। इस प्रकार की जानकारी देने वालों में दो प्रकार के सदस्य देखे गये। जहां एक वर्ग द्वारा यह बताया गया कि हम लोगों की माली हालत पहले से ही ठीक नहीं थी, क्योंकि हम लोग बैंकों से वित्त लेने से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवास कर रहे अपने ही सगे सम्बन्धियों के ऋणी थे। जिससे हम लोगों के द्वारा बैंकों से जो वित्त प्राप्त किया गया था उसका एक मात्र उद्देश्य सगे–सम्बन्धियों की ऋण की अदायगी था अतः हम अपने उद्देश्य में तो सफल हुये लेकिन बैंकों ने जिस उद्देश्य से हमें ऋण दिया था उस उद्देश्य में बैंकों के दृष्टिकोण में हम असफल साबित हुये, जबकि दूसरा वर्ग ऐसा था जिसमें धन के सदुपयोग न कर पाने के कारणों में पारिवारिक स्थिति में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से परिवर्तन होने को बताया जिसके तहत इस वर्ग के द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया था उसका किंचित मात्र भाग भी उस कार्य में न लगाकर दूरदर्शिता की ओर अग्रसर होते हुये हमने अपने परिवार के सदस्यों को उचित शिक्षा दिलाने में महत्ता दी जिसके कारण वर्तमान में हमारी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन इन बैंकों के द्वारा जो हमें वर्तमान में वित्त प्राप्त हुआ है उसका भविष्य में अवश्य असर दिखाई देगा। वहीं उच्च आय वर्ग के परिवारों द्वारा जो विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त किया गया है उसका लगभग–लगभग उपयोग ही हुआ है, क्योंकि सर्वे में एक बात पायी गई है कि जो उच्च आय वर्ग के परिवार हैं वह ज्यादातर शिक्षित व जागरूक हैं जिसके कारण इन व्यक्तियों के द्वारा अनावश्यक रूप से अपने ऊपर बैंकों से वित्त प्राप्त कर बोझ नहीं लिया गया बल्कि प्राप्त वित्त का सदुपयोग कर अपने आर्थिक स्थिति में व्यापक पैमाने पर परिवर्तन किया, क्योंकि इस वर्ग के जितने भी व्यक्तियों से सम्पर्क किया गया उनमें से लगभग 95 प्रतिशत व्यक्तियों का एक जैसा विचार रहा और बैंकों से प्राप्त वित्त के उपयोग के सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय दिखाई दिये। तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि इस वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा धन का उपयोग कर आर्थिक स्थिति में परिवर्तन

किया गया। जबकि निम्न आय वर्ग के परिवारों द्वारा भी बैंकों से विभिन्न समयावधियों के लिए ऋण प्राप्त किया गया। इन व्यक्तियों से सम्पर्क करने में एक बात उभर कर आई है कि इस वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा जो दीर्घकालिक समय के लिए ऋण लिया गया है उसका तो लगभग 80 प्रतिशत सदुपयोग किया गया है लेकिन उससे हटकर जो अल्पकालीन व मध्यकालीन समय के लिए ऋण प्राप्त किये गये हैं उसके एक बड़े भाग धन का उपयोग नहीं हो पाया। इस धन के उपयोग न हो पाने के कारणों पर जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि यह धन जिन भी व्यक्तियों को प्राप्त हुये है उनकी माली हालत ठीक नहीं है कि वह दो जून की रोटी भी आराम से प्राप्त नहीं कर पाते जो धन को उत्पादक कार्यों में लगा सकें यानि कह सकते हैं कि इन लोगों के पास मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के ही साधन सुलभ नहीं थे जिससे कि इन व्यक्तियों के द्वारा जो भी बैंकिंग वित्त प्राप्त हुआ उसका ज्यादातर लोगों के द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही व्यय किया गया जिससे जहां एक ओर उनको मूलभूत वस्तुओं की तो प्राप्ति हो गई लेकिन किसी भी प्रकार की दीर्घकालिक समय के लिए आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सके इस वर्ग के व्यक्तियों में लगभग 35–40 प्रतिशत व्यक्ति ही ऐसे पाये गये जिनके द्वारा धन का सदुपयोग कर आर्थिक स्थिति में परिवर्तन किया गया।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि इटावा जनपद में उच्च आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा बैंकों से जो वित्त प्राप्त हुआ है उसका अधिकाधिक उपयोग कर विभिन्न क्षेत्रों का विकास किया गया जबकि निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त वित्त का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग नहीं हो सका है जिससे इनके द्वारा किसी विशेष क्षेत्र का भी विकास नहीं किया जा सका है इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि व्यावसायिक बैंकों के वित्त का उच्च आय वर्ग व मध्य आय वर्ग पर तो अनुकूल प्रभाव पड़ा है लेकिन निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति बहुत ठीक न होने के कारण इस आय वर्ग के लोगों पर इन बैंकों के वित्त का प्रभाव नहीं हो सका।

साख प्राप्त व्यक्तियों द्वारा प्रकट किये गये विचार : इटावा जनपद में जिन व्यक्तियों के द्वारा व्यावसायिक बैंकों की विभिन्न शाखाओं से जो वित्त प्राप्त हुआ है उसके सम्बन्ध में तथा बैंकों की कार्यप्रणाली व बैंकों के वित्त का दैनिक जीवन पर होने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में लगभग व्यक्तियों के द्वारा एक जैसे विचार प्रकट किये गये हैं। इनमें से ज्यादातर व्यक्तियों के द्वारा यह बताया गया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निश्चित रूप से संगठित स्रोतों के माध्यम

क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता इसलिए व्यावसायिक बैंकों के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पहल की जा रही है निश्चित ही वह सराहनीय है लेकिन इतना अवश्य कह सकते हैं कि इन वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वह ग्रामीण क्षेत्र में आवास कर रहे व्यक्तियों को उनकी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति में और अधिक वृद्धि करें जिससे हम लोगों के जीवन स्तर में द्रुति गति से विकास हो सके। साख प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा बैंकों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट किये गये हैं जो निम्न हैं :—

1. व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से साख प्राप्त होने से कृषि क्षेत्र में पर्याप्त कृषि यन्त्रों का प्रयोग कर पाना सम्भव हो सका है जिससे कृषि क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है।
2. सिचाई के साधनों के लिए व्यावसायिक बैंकों से वित्त प्राप्त होने से सिचाई के साधनों में विकास हो सका है। जिससे कृषि क्षेत्र की एक मूल समस्या का कुछ मात्रा में निदान किया जा सका है जिससे उत्पादन स्तर में वृद्धि हो सकी है।
3. बैंकों द्वारा वित्त प्राप्त होने से ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जा सकी क्योंकि बैंकों के द्वारा दुधारू पशुओं को क्रय कराकर एक आर्थिक इकाई को जन्म दिया है।
4. व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण करने से हम लोगों की वित्तीय समस्या का कुछ हद तक निदान हो सका है क्योंकि इस कार्ड के माध्यम से हम लोगों को बिना किसी बड़ी समस्या के वित्त की उपलब्धता हो जाती है।
5. बैंकों से ऋण प्राप्त होने से निश्चित ही कारोबार में वृद्धि हो सकी है। आदि बिन्दुओं पर जहां एक ओर साख प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा बैंकिंग प्रणाली की सराहना की वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्तियों के द्वारा वित्त प्राप्त होने के सम्बन्ध में समस्यायें भी प्रकट की। जिसको निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है।

वित्त प्राप्त करने के सम्बन्ध में व्यक्त की गई समस्यायें : सर्वे के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ है कि जहां एक ओर बैंकिंग कार्यप्रणाली पर लोगों के द्वारा सन्तोष व्यक्त किया गया वहीं कुछ लोगों को पर्याप्त मात्रा में वित्त प्राप्त न हो पाने के सम्बन्ध में कुछ समस्यायें भी प्रकट की गई व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में बैंकों से आज भी वित्त प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिससे हम लोगों के सामने आज भी वित्तीय समस्या है जिससे हम लोग अपने लगे हुये क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे हैं इस सम्बन्ध में ज्यादातर लोगों का विचार इस ओर था कि हम लोगों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वह कृषि क्षेत्र में अपर्याप्त सिचाई के साधनों का विकास होना रहा है। यदि व्यावसायिक बैंकों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऋण प्रदान किया जाय तो

निश्चित ही हम लोग बैंकों के द्वारा प्राप्त वित्त से कृषि क्षेत्र में व्याप्त सिचाई की समस्या के निजात के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं जिससे कृषि क्षेत्र का विकास होगा और कृषि अर्थव्यवस्था एक आर्थिक इकाई के रूप में उभर कर आयेगा। जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना सम्भव है क्योंकि जब तक कृषि क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना केवल एक कल्पना है वहीं कुछ व्यक्तियों के द्वारा यह भी प्रकट किया गया क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की एक गम्भीर समस्या है यदि इन वित्तीय संस्थाओं के द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार अपनाने हेतु पर्याप्त मात्रा में वित्त प्रदान किया जाय तो निश्चित ही हम लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया हो सकते हैं जिससे हम लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा जबकि जनपद में कुछ व्यक्तियों के द्वारा अन्य समस्यायें भी प्रकट की गई :—

1. आवश्यक शर्तों को पूरा करने में कठिनाई।
2. अपर्याप्त वित्त ।
3. परिवर्तित ब्याज दर ।
4. किसान क्रेडिट कार्ड में दर्शाई गई रकम की मात्रा को बैंकों के द्वारा न दिया जाना।
5. पूंजीगत निवेश को बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋण की उपलब्धता न कराना।
6. सेवा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य बैंकों से ऋण प्राप्त करने पर सेवा क्षेत्र की बैंक द्वारा वित्त प्रदान कराने में असमर्थता जाहिर करना आदि बिन्दुओं पर विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा असन्तोष जाहिर किया गया।

4. औरैया जनपद : औरैया जनपद में 4 व्यावसायिक बैंकों की 28 शाखायें कार्यरत है। इन शाखाओं में से अध्ययन के लिए 8 शाखाओं का चयन किया गया और इन शाखाओं के द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र द्वारा जिन व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया गया उनका 25 प्रतिशत अध्ययन के लिए चयन किया गया इन चयनित व्यक्तियों की नामावली निश्चित बैंक शाखाओं से प्राप्त कर व्यक्तिगत रूप से प्रश्नावली के माध्यम से साख प्राप्त व्यक्तियों के विचार जाने गये। औरैया जनपद में वित्तीय वर्ष 2006—07 में अध्ययन के लिए चयनित 667 व्यक्तियों के द्वारा 30215 हजार रुपये के विभिन्न व्यावसायिक बैंक से वित्त प्राप्त किये गये। जो वित्त जिन व्यक्तियों को प्राप्त हुये हैं उसकी मात्रा व व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति तथा समय आदि को सारणी संख्या 123 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–123

औरैया जनपद में अध्ययन के लिए चयनित आर्थिक स्थिति के आधार पर साख प्राप्त लाभार्थियों का विवरण (वर्ष 2006–07) धनराशि हजार रुपये में

आर्थिक स्थिति	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	लाभार्थी संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का समयावधि के आधार पर वितरण					
			अल्पकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या	मध्यकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या	दीर्घकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. निम्न आय वर्ग	2950	180	1180	70	1320	102	450	08
2. मध्यम आय वर्ग	9921	348	2055	137	4200	168	3666	43
3. उच्च आय वर्ग	17344	139	4360	48	6375	75	6609	16
योग–	**30215**	**667**	**7595**	**255**	**11895**	**345**	**10725**	**67**

सारणी संख्या 123 से यह स्पष्ट है कि औरैया जनपद में अध्ययन के लिए चयनित बैकों द्वारा साख प्राप्त व्यक्तियों का 25 प्रतिशत अर्थात 667 व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष 2006–07 में 30215 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। इस वितरित ऋण में निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 180 व्यक्तियों को 2950 हजार रुपये के ऋण दिये गये, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 348 व्यक्तियों को 9921 हजार रुपये के ऋण दिये गये व उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत 139 व्यक्तियों को 17344 हजार रुपये के ऋण दिये गये। जनपद में यह वितरित ऋण विभिन्न समयावधियों को ध्यान में रखकर दिये गये। जिसके तहत 255 व्यक्तियों को 7595 हजार रुपये के अल्पकालीन समय के लिए ऋण दिये। अल्पकालीन समय में निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 70 व्यक्तियों को 1180 हजार रुपये के ऋण दिये गये, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 137 व्यक्तियों को 2055 हजार रुपये के ऋण दिये व उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत 48 व्यक्तियों को 4360 हजार रुपये के अल्पकालीन ऋण दिये गये। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में सबसे ज्यादा मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण दिये गये लेकिन ऋण की मात्रा उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के मध्य अधिक रही। जनपद में 345 व्यक्तियों को 11895 हजार रुपये के मध्यकालीन ऋण दिये गये मध्यकालीन ऋण के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग के 102 व्यक्तियों को 1320 हजार रुपये के ऋण दिये गये, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 168 व्यक्तियों को 4200 हजार रुपये के ऋण दिये गये व 75 उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को 6375 हजार रुपये के ऋण दिये गये। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में सबसे ज्यादा मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों व निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण दिये गये। लेकिन ऋण की मात्रा उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के मध्य अधिक रही। जनपद में 67 व्यक्तियों को

10725 हजार रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिये गये। दीर्घकाल समय के लिए वितरित इस ऋण में निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 8 व्यक्तियों को 450 हजार रुपये के, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 43 व्यक्तियों को 3666 हजार रुपये के व उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत 16 व्यक्तियों को 6609 हजार रुपये के दीर्घकाल समय के लिए ऋण दिये गये। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि दीर्घकाल समय के लिए सबसे ज्यादा मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण तो दिये गये किन्तु ऋण की मात्रा उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के मध्य अधिक रही।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि औरैया जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र में सबसे अधिक मध्यकालीन ऋण दिये गये। तत्पश्चात् अल्पकाल व मध्यकाल समय के लिए व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराये गये। जहां तक ऋण की मात्रा का प्रश्न है तो औसत रूप से ऋण की मात्रा दीर्घकाल समय के लिए सबसे अधिक दी गई जो कृषि क्षेत्र में बढ़ते निवेश का संकेत है।

औरैया जनपद में साख प्राप्त व्यक्तियों द्वारा धन का उपयोग : औरैया जनपद में जिन व्यक्तियों को विभिन्न व्यावसायिक बैंक शाखाओं से साख प्राप्त हुआ है उन व्यक्तियों से सम्पर्क करने पर यह ज्ञात हुआ है कि जो तीन प्रकार के आय वर्ग पर आधारित व्यक्ति थे उसमें से उच्च व मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त साख की अधिकाधिक मात्रा का सदुपयोग कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास किया गया, क्योंकि साख प्राप्त परिवारों से सम्पर्क किया गया उनके द्वारा यह ज्ञात कराया गया कि हम लोगों ने जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न बैंक शाखाओं में आवेदन किये हुये थे जो बैंकों ने आवेदन को स्वीकार करते हुये हम लोगों को वित्त प्रदान किये हैं उस वित्त को आवेदन में दर्शाये गये उद्देश्यों में ही सम्पूर्ण वित्त को व्यय किया है। जिससे हम लोगों के द्वारा जिस क्षेत्र के लिए ऋण प्राप्त किया गया है। उस क्षेत्र का विकास किया गया। जिससे हमारी आय में वृद्धि हुयी है। जिस कारण से हम लोग यह कह सकते हैं कि व्यावसायिक बैंकों के द्वारा जो वित्त प्रदान किया गया है उसका हम लोगों के दैनिक जीवन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है इस सन्दर्भ में हम लोग यह भी कह सकते हैं कि व्यावसायिक बैंके अपने उद्देश्य मे सफल साबित हुई हैं और बैंके आगे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहभागिता का निर्वाहन करती रहें। वहीं निम्न आय वर्ग के परिवारों का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि इस वर्ग के परिवारों की माली हालत बहुत अच्छी न होने के कारण एक तो इन लोगों को पर्याप्त मात्रा में अपेक्षाकृत वित्त ही प्राप्त नहीं हो सका और दूसरा जो प्राप्त भी हुआ वह अनुत्पादक कार्यों में ज्यादातर व्यक्तियों द्वारा लगाया गया जिससे औसत रूप में एक बात उभरकर आई है कि इस वर्ग

बैंकों से प्राप्त वित्त का बहुत अधिक लाभ नहीं उठाया जा सका जिससे इन लोगों की आर्थिक स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती।

उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यावसायिक बैंकों के वित्त का सबसे अधिक प्रभाव मध्यम आय वर्ग व उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के ऊपर पड़ा है। जबकि निम्न आय वर्ग के व्यक्ति बैंकों के वित्त से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो सके। यदि हम कृषि क्षेत्र में बैंकों के वित्त के प्रभाव को स्पष्ट करें तो कहा जा सकता है चूंकि कृषि क्षेत्र का एक बड़ा भाग मध्य आय वर्ग के मध्य पाया जाता है चूंकि मध्य आय वर्ग के ऊपर बैंकिंग वित्त का अनुकूल प्रभाव पड़ा है इसलिए कहा जा सकता है कि बैंकिंग वित्त से कृषि क्षेत्र पर अनुकूल ही प्रभाव पड़ा है अर्थात कह सकते हैं कि बैंकों के द्वारा लोगों को जो ऋण मुहैया कराये जा रहे हैं उससे कृषि क्षेत्र के विकास में सहायता प्राप्त हुयी है।

साख प्राप्त लाभार्थियों द्वारा बैंकिंग प्रणाली के सम्बन्ध में प्रकट किये गये विचार:

औरैया जनपद में जिन व्यक्तियों को विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से साख प्राप्त हुआ है उन व्यक्तियों के विचारों को सुना गया उनके द्वारा निम्न विचार प्रकट किये गये :–

1. व्यावसायिक बैंकों के द्वारा वित्त प्राप्त होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में वृद्धि हो सकी है।
2. व्यावसायिक बैंकों से वित्त प्राप्त होने से कृषि क्षेत्र में पर्याप्त सुधार हुये हैं।
3. किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों के द्वारा निर्गत करने से कृषकों की वित्तीय समस्या का निदान हो सका है।
4. बैंकों के द्वारा समय–समय पर स्वरोजगार के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक कर उन्हें ऋण प्रदान किया जाता है।
5. बैंकों के वित्त प्रदान करने से कृषि यन्त्रीकरण का विकास हुआ है जिसमें प्रमुख रूप से ट्रैक्टरों की मात्रा में वृद्धि हुई है जिससे कृषि क्षेत्र में अनेकों समस्याओं का समाधान हो सका है।

साख प्राप्त व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की गयी समस्यायें : औरैया जनपद में जिन व्यक्तियों को विभिन्न व्यावसायिक बैंक शाखाओं से साख प्राप्त हुआ है। उन्होंने उन बैंक शाखाओं के सन्दर्भ में कुछ समस्यायें भी प्रकट की जो निम्न हैं :–

1. पर्याप्त मात्रा में वित्त की उपलब्धता न कराना जिससे आवश्यक कार्यों की पूर्ति में वित्त का बाधक बनना।
2. किसान क्रेडिट कार्ड में स्पष्ट की गयी धनराशि की मात्रा उपलब्ध न कराना ।
3. कृषि यन्त्रीकरण के सम्बन्ध में जमीनी पात्रता की ऊँची शर्त होना जिससे इच्छुक एक बड़ा वर्ग कृषि यन्त्र क्रय करने से वंचित रह जाता है।
4. सिचाई की सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त वित्त की उपलब्धता न कराना।
5. ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में बारहशाला बनवाना जिसमें अनावश्यक रूप से धन का अपव्यय होना।
6. धन के उपयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार की विधिवत जानकारी न उपलब्ध कराना।
7. ब्याज की परिवर्तित दर ।
8. रोजगार के क्षेत्र में ठोस पहल न करना आदि बिन्दुओं पर साख प्राप्त व्यक्तियों द्वारा बैंकिंग कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में असन्तोष जाहिर किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि आज भी कृषि क्षेत्र में बैंकों के द्वारा पर्याप्त वित्त नहीं प्राप्त हो सका।

कानपुर नगर जनपद :

कानपुर नगर जनपद में 7 व्यावसायिक बैंकों की 34 शाखायें कार्यरत हैं इन कार्यरत शाखाओं में से अध्ययन के लिए 10 शाखाओं का चयन किया गया है जो जनपद के सभी 10 विकासखण्डों में ऋण की उपलब्धता प्रदान कर रही हैं। उनके द्वारा जिन व्यक्तियों को जनपद में वित्त प्रदान किया गया है उन व्यक्तियों में से 25 प्रतिशत व्यक्तियों का अध्ययन के लिये चयनित किया गया है। और इन चयनित व्यक्तियों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में दितरित ऋण तथा साख प्राप्त व्यक्तियों की संख्या को सारणी संख्या 124 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–124

कानपुर नगर जनपद में अध्ययन के लिए चयनित आर्थिक स्थिति के आधार पर साख प्राप्त लाभार्थियों का विवरण (वर्ष 2006–07) धनराशि हजार रुपये में

आर्थिक स्थिति	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	लाभार्थी संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का समयावधि के आधार पर वितरण					
			अल्पकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या	मध्यकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या	दीर्घकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. निम्न आय वर्ग	18450	369	7600	225	4525	115	6325	29
2. मध्यम आय वर्ग	81236	883	27390	498	15375	205	38471	180
3. उच्च आय वर्ग	91329	410	30510	426	19250	110	41569	74
योग–	**191015**	**1662**	**65500**	**949**	**39150**	**430**	**86365**	**283**

सारणी संख्या 124 से यह स्पष्ट है कि अध्ययन के लिए जिन 1662 व्यक्तियों का चयन किया गया है इनके द्वारा विभिन्न बैंक शाखओं से 191015 हजार रुपये के वित्त प्राप्त किये गये हैं। इनके द्वारा प्राप्त इस वित्त में निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 369 व्यक्तियों को 18450 हजार रुपये के ऋण दिये गये, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 883 व्यक्तियों को 81236 हजार रुपये के ऋण व उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत 410 व्यक्तियों को 91329 हजार रुपये के ऋण दिये गये। जनपद में इन व्यक्तियों को व्यावसायिक बैंकों के द्वारा 949 व्यक्तियों को 65500 हजार रुपये के ऋण अल्पकालीन समय के लिए दिये गये। अल्पकालीन समय के लिए जनपद में वितरित ऋण में निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 225 व्यक्तियों को 7600 हजार रुपये के ऋण, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 498 व्यक्तियों को 29390 हजार रुपये के ऋण व उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत 226 व्यक्तियों को 30510 हजार रुपये के अल्पकालीन ऋण दिये गये। जनपद में 430 व्यक्तियों को 39150 हजार रुपये के मध्यकालीन ऋण दिये गये। मध्यकालीन ऋण के अन्तर्गत 115 निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को 4525 हजार रुपये के ऋण, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 205 व्यक्तियों को 15375 हजार रुपये के व उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत 110 व्यक्तियों को 19250 हजार रुपये के मध्यकालीन ऋण दिये गये। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में सबसे अधिक मध्य आय वर्गीय व्यक्तियों को तत्पश्चात् निम्न व उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण का वितरण किया गया। जनपद में 283 व्यक्तियों को 86365 हजार रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिये गये। जनपद में निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 29 व्यक्तियों को 6325 हजार रुपये के, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 180 व्यक्तियों को 38471 हजार रुपये के व उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत 74 व्यक्तियों को 41569

हजार रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिये गये। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में सबसे ज्यादा मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों को तत्पश्चात् उच्च व निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण प्रदान किये गये। जहां तक ऋण की मात्रा का प्रश्न है तो सबसे अधिक उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को धनराशि प्रदान की गयी।

कानपुर नगर जनपद में साख प्राप्त व्यक्तियों द्वारा धन का उपयोग : कानपुर नगर जनपद में तीनों प्रकार की आर्थिक स्थिति में जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्तियों को बैंकों के द्वारा वित्त प्रदान किया गया है इन वित्त प्राप्त व्यक्तियों से प्रश्नावली को भरवाकर यह ज्ञात किया गया कि इन्होंने धन का किस प्रकार से उपयोग किया है तो पता चला कि जनपद में सबसे ज्यादा धन का उपयोग उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा दीर्घकालीन व मध्यकालीन समय के लिए प्राप्त किये गये धन का सबसे अधिक सदुपयोग हुआ है। क्योंकि इस समय के लिए सबसे ज्यादा ट्रैक्टर व सिचाई के साधन तथा इससे हटकर कृषि से सम्बन्धित अन्य बड़े कार्यों को पूरा करने के लिए बैंकों से वित्त प्राप्त किये गये थे जिसका इन लोगों ने इसी क्षेत्र में उपयोग कर कृषि क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन कर कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधार किये जिससे कृषि क्षेत्र में परिवर्तन की स्थिति देखने में आयी है। अर्थात् यह कहा जा सकता है कि इस वर्ग के व्यक्तियों द्वारा जो दीर्धकाल व मध्यकाल समय के लिए ऋण प्राप्त हुआ था उसका सदुपयोग कर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की है जबकि इसी वर्ग के द्वारा अल्पकाल समय में लिये गये ऋण का इतनी अधिक मात्रा में सदुपयोग नहीं हो सका है, जनपद में मध्यम आय वर्ग के परिवारों के द्वारा सबसे ज्यादा दीर्घकाल समय के लिए प्राप्त किये गये ऋण का सदुपयोग हुआ है, क्योंकि इस समय के लिए प्राप्त धन से सबसे ज्यादा ट्रैक्टर क्रय किये गये। जिससे कृषि क्षेत्र के विकास के साथ–साथ व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है क्योंकि ट्रैक्टर के द्वारा न सिर्फ कृषि क्षेत्र में आवश्यक तकनीकी यन्त्रों का प्रयोग ही सम्भव हुआ बल्कि इसके द्वारा दिन–प्रतिदिन की होने वाली आय से व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ हालांकि इस समय के लिए लिये गये ऋण में कुछ व्यक्ति ऐसे भी पाये गये हैं जिन्होंने ट्रैक्टर तो ले लिया लेकिन उस ट्रैक्टर के द्वारा कोई बहुत अधिक लाभ नहीं प्राप्त कर सके जिससे उनके सामने एक नई समस्या प्रकट हुई। जनपद में मध्यआय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा अल्पकाल व मध्यकाल समय में भी लिये गये ऋण का भी लगभग व्यक्तियों के द्वारा सदुपयोग ही किया गया है और जिन व्यक्तियों के द्वारा बैंकों से प्राप्त वित्त का सदुपयोग नहीं किया गया है उन व्यक्तियों से जब ऋण के सदुपयोग न करने के सम्बन्ध में पूछा गया तो ज्ञात हुआ कि हम लोगों का पैत्रिक ऋण ग्रस्तता के कारण हमारे द्वारा जो ऋण प्राप्त किया गया उस

ऋण का एक बड़ा भाग अनावश्यक खर्चों में व्यय कर दिया गया। जिससे कि हम लोगों के द्वारा प्राप्त वित्त से लाभ नहीं प्राप्त किया जा सका। वहीं जनपद में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा यह ज्ञात कराया गया कि इस वर्ग के द्वारा लगभग 55 से 65 प्रतिशत व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त साख का सही तरीके से उपयोग करना बताया गया है। जबकि शेष लगभग 40–45 प्रतिशत तक व्यक्तियों के द्वारा धन का उपयोग उद्देश्य के आधार पर न कर पाना स्पष्ट किया गया है। जिन व्यक्तियों के द्वारा धन के उद्देश्य के आधार पर धन का उपयोग न कर पाना रहा है उन व्यक्तियों के द्वारा धन का उद्देश्य के आधार पर उपयोग न कर पाने के सम्बन्ध में विभिन्न राय व्यक्त की गयी हैं जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा सगे सम्बन्धियों का कर्जदार होना, कुछ व्यक्तियों के द्वारा स्वास्थ्य समस्याओं से निजात पाने के लिए धन का दवाओं के रूप में प्रयोग करना व कुछ व्यक्तियो के द्वारा भवन निर्माण आदि में व्यय करना तथा कुछ व्यक्तियों के द्वारा पुत्र–पुत्रियो के शादी विवाह आदि में धन के व्यय हो जाने का स्पष्टीकरण किया गया है। जिसके कारण इन व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त साख से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। अतः कहा जा सकता है कि इन वर्ग के व्यक्तियों के ऊपर या इन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार नहीं हो सकां

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि व्यावसायिक बैंकों के वित्त का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। या यह कहा जा सकता है कि व्यवसायिक बैंकों के द्वारा वित्त प्राप्त होने से कृषि क्षेत्र को विकसित करने में सहायता प्राप्त हुयी है अर्थात कृषि क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक विकसित हुआ।

साख प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा प्रकट किये गये विचार : कानपुर नगर जनपद में जिन व्यक्तियों को व्यावसायिक बैंक शाखाओं से वित्त प्राप्त हुआ है उन व्यक्तियों ने बैंकों के सन्दर्भ में या वित्त के उपयोग के सन्दर्भ में निम्न विचार प्रकट किये :–

1. व्यावसायिक बैंकों के वित्त के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सहायता प्राप्त हुयी है।
2. बैंकों के द्वारा वित्त प्राप्त होने से कृषि क्षेत्र में कार्यशील पूंजी की उपलब्धता प्राप्त हो सकी है।
3. व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक का प्रयोग सम्भव हो सका है।
4. व्यावसायिक बैंकों के वित्त प्रदान करने से साहूकारों व महाजनों के शोषण से बचा जा सका है।
5. किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों के द्वारा निर्गत होने से आकस्मिक वित्त की आवश्यकता से निजात मिला है।

आदि बिन्दुओं पर साख प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा विचार प्रकट किये गये। इन साख प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों के विकास होने से ग्रामीण क्षेत्र की वित्तीय समस्याओं का एक सीमा तक निदान हो सका है। वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्तियों के द्वारा व्यावसायिक बैंकों से पर्याप्त मात्रा में आज भी ऋण उपलब्ध न हो पाना व व्यावसायिक बैंकों के द्वारा समय समय पर ब्याज दर में परिवर्तन किया जाना एक समस्या स्पष्ट की गई है।

कानपुर देहात जनपद : जनपद कानपुर देहात में 5 व्यावसायिक बैंकों की 29 शाखायें कार्यरत हैं जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक वित्तीय सहायतायें प्रदान की जा रही हैं। इसी की पुष्टि करने के लिए जनपद में कार्यरत इन सभी बैंकों की 30 प्रतिशत बैंक शाखाओं अर्थात् 9 बैंक शाखाओं जो जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में कार्यरत हैं इनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में जितने लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया है, इन साख प्राप्त लाभार्थियों में से 25 प्रतिशत लाभार्थियों का रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर चयन कर उनके द्वारा प्राप्त साख तथा साख के उपयोग व साख का उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव आदि को सारणी संख्या 125 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–125

कानपुर देहात जनपद में अध्ययन के लिए चयनित आर्थिक स्थिति के आधार पर साख प्राप्त लाभार्थियों का विवरण (वर्ष 2006–07) धनराशि हजार रुपये में

आर्थिक स्थिति	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	लाभार्थी संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का समयावधि के आधार पर वितरण					
			अल्पकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या	मध्यकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या	दीर्घकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. निम्न आय वर्ग	19500	300	5425	125	7647	143	6428	32
2. मध्यम आय वर्ग	57395	417	18900	210	18150	165	20345	42
3. उच्च आय वर्ग	33022	151	9900	60	7790	38	15332	53
योग–	**109917**	**868**	**34225**	**395**	**33587**	**346**	**42105**	**127**

सारणी संख्या 125 से यह स्पष्ट है कि जनपद कानपुर देहात में वित्तीय वर्ष 2006–07 में 9 व्यावसायिक बैंक शाखाओं द्वारा जनपद के लगभग सभी विकास खण्डों में अध्ययन के लिए चयनित किये गये 868 व्यक्तियों को व्यावसायिक बैंकों द्वारा 109917 हजार रुपये के ऋण

वितरित किये। इस वितरित ऋण में निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 300 व्यक्तियों को 19500 हजार रुपये के ऋण दिये गये, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 417 व्यक्तियों को 57395 हजार रुपये व उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत 151 व्यक्तियों को 33022 हजार रुपये के ऋण वितरित किये। जनपद में इस वितरित ऋण में से 395 व्यक्तियों को 34225 हजार रुपये के ऋण अल्पकालीन समय के लिए दिये गये। अल्पकाल समय के लिए वितरित इस ऋण में निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 125 व्यक्तियों को 5425 हजार रुपये, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 210 व्यक्तियों को 18900 हजार रुपये व उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत 60 व्यक्तियों को 9900 हजार रुपये के अल्पकालीन समय के लिए ऋण दिये गये। जनपद में 346 व्यक्तियों को 33587 हजार रुपये के मध्यकालीन ऋण दिये गये। जनपद में मध्यकालीन समय के लिए वितरित इस ऋण में निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 143 व्यक्तियों को 7647 हजार रुपये के, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 165 व्यक्तियों को 18150 हजार रुपये के व उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत 38 व्यक्तियों को 7790 हजार रुपये के मध्यकालीन समय के लिए ऋण दिये गये। जनपद में 127 व्यक्तियों को 42105 हजार रुपये के दीर्घकाल समय के लिए ऋण दिये गये। जनपद में दीर्घकाल समय के लिए वितरित इस ऋण में निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 32 व्यक्तियों को 6428 हजार रुपये, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 42 व्यक्तियों को 20345 हजार रुपये के व उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत 53 व्यक्तियों को 15332 हजार रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिये गये।

इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में सबसे अधिक व्यक्तियों को अल्पकाल समय के लिए ऋण दिये गये। तत्पश्चात् मध्यकाल व दीर्घकाल समय के लिए व्यक्तियों को ऋण दिये गये हैं, जबकि ऋण की मात्रा सबसे अधिक दीर्घकाल समय के लिए दी गई।

जनपद में वितरित ऋण का उपयोग : जनपद कानपुर देहात में अध्ययन में यह पाया गया कि जिन 868 व्यक्तियों का चयन कर अध्ययन किया गया उनके द्वारा विभिन्न समयों में प्राप्त धनराशि का विभिन्न आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा उपयोग का स्तर अलग–अलग रहा है, क्योंकि अध्ययन के अन्तर्गत यह पाया गया है कि जनपद में उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न बैंक शाखाओं से जो ऋण प्राप्त किया गया है उसका सर्वाधिक मात्रा में उपयोग हुआ है। इस प्रकार के वर्ग के व्यक्तियों से सम्पर्क कर यह ज्ञात हुआ है कि इस वर्ग के जितने भी व्यक्तियों ने किसी भी समय के लिए जिस किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त किया है उसी उद्देश्य में इन व्यक्तियों के द्वारा धन का उपयोग किया गया है जिससे उस क्षेत्र विशेष का विकास हुआ है।

क्षेत्र विशेष का विकास होने से व्यक्तियों की आय में वृद्धि हुई है जिससे यह कहा जा सकता है कि इनके जीवन पर व्यावसायिक बैंकों का अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

जनपद में मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न बैंक शाखाओं से जो ऋण प्राप्त किया है। इन व्यक्तियों से सम्पर्क कर यह पाया गया है कि इस वर्ग के अन्तर्गत उन व्यक्तियों के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त किया गया है जिन व्यक्तियों ने दीर्घकाल समय के लिए ऋण प्राप्त किये हैं, क्योंकि अध्ययन में यह पाया गया है कि दीर्घकाल समय के लिए जिन व्यक्तियों ने ऋण लिया है उन व्यक्तियों में लगभग 95 प्रतिशत व्यक्तियों ने जिस उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त किया है उसी उद्देश्य में ऋण को लगाया भी और उस विशेष उद्देश्य से अधिकाधिक मात्रा में आय अर्जित की। जबकि जनपद में मध्यकालीन समय के लिए विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न बैंक शाखाओं से जो साख प्राप्त किया गया है उसमें से लगभग 75–85 प्रतिशत व्यक्तियों के द्वारा धन का सदुपयोग किया गया है क्योंकि इन व्यक्तियों के द्वारा जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त किया गया है उसी उद्देश्य की पूर्ति में ऋण को लगाकर उस क्षेत्र विशेष का विकास किया जिससे उस क्षेत्र विशेष से अतिरिक्त आय प्राप्त की जिससे व्यक्तिगत आय में वृद्धि हुई। व्यक्तिगत आय में वृद्धि होने के कारण जीवन स्तर में सुधार हुआ। और जीवन स्तर में सुधार होने का मतलब है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदत्त वित्त का अनुकूल प्रभाव होना स्पष्ट होता है। जनपद में इसी आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा अल्पकाल समय के लिए जो ऋण प्राप्त किया गया है उसका लगभग 65 से 75 प्रतिशत तक ही सदुपयोग हो पाया है। शेष ऋण की मात्रा व शाख प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा धन का उपयोग नहीं किया जा सका। जिन व्यक्तियों के द्वारा धन का सदुपयोग नहीं किया गया है उन व्यक्तियों से धन के सदुपयोग न कर पाने के कारणों पर चर्चा की गई तो पता चला कि ये व्यक्ति ज्यादातर असंगठित संगठनों के ऋणी थे। जिस कारण इन व्यक्तियों ने जो व्यावसायिक बैंकों से ऋण की मात्रा प्राप्त की उसको असंगठित संगठनों के ऋण की अदायगी में ही अपने प्राप्त साख को व्यय कर दिया। जिससे इनके द्वारा धन का सदुपयोग नहीं हो पाया। जबकि अध्ययन के अन्तर्गत यह भी पाया गया है कि इस समय के लिए जिन व्यक्तियों ने ऋण प्राप्त किया है उसका एक बड़ा भाग पारिवारिक खर्चों व आकस्मिक स्थितियों से निपटने में भी धन का व्यय हो जाता है। जिससे आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं स्पष्ट होता।

निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा जनपद में विभिन्न बैंक शाखाओं से जो ऋण प्राप्त किया है। उसमें से जिन व्यक्तियों के द्वारा दीर्घकाल समय के लिए ऋण प्राप्त किया गया है

उसमें से लगभग 60 से 65 प्रतिशत व्यक्तियों के द्वारा धन का सदुपयोग करना स्पष्ट होता है, क्योंकि अध्ययन में यह पाया गया है कि इन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में पूर्व समय की तुलना में परिवर्तन स्पष्ट होता है जबकि इस समय के लिए शेष व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त साख का सदुपयोग न कर पाना इन व्यक्तियों की माली हालत ठीक न होना स्पष्ट होता है। इन व्यक्तियों की माली हालत ठीक न होने के कारण इन व्यक्तियों के द्वारा जो भी साख प्राप्त किया गया उसकी एक बड़ी मात्रा को अनुत्पादक कार्यों में व्यय करना पड़ा जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार नहीं हो सका। जनपद में इस वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा मध्यकाल समय के लिए प्राप्त किये गये साख का अपेक्षाकृत दीर्घकाल समय के लिए प्राप्त साख की तुलना में और कम मात्रा में उपयोग हो पाया है। इस समय के लिए प्राप्त साख का लगभग 50 प्रतिशत भाग ही सदुपयोग हो पाया है। शेष जिन व्यक्तियों के द्वारा धन का कोई बहुत उपयोग नहीं हो पाया है उन व्यक्तियों से जब धन का उपयोग न हो पाने के कारणों पर चर्चा की गई तो पता चला कि इन व्यक्तियों के द्वारा असंगठित स्रोतों से इतनी मात्रा में ऋण ले रखा था कि व्यावसायिक बैंकों से जो ऋण प्राप्त हुआ वह असंगठित स्रोतों की ब्याज अदायगी व मूलधन अदायगी के रूप में ही व्यय कर दिया गया। जिससे इस वर्ग के व्यक्तियों के सामने एक समस्या पुनः प्रकट हो गई कि ये व्यक्ति असंगठित स्रोतों के स्थान पर संगठित स्रोतों के कर्जदार हो गये। बावजूद इसके कि इनके द्वारा धन का उपयोग ही नहीं किया जा सका। जनपद में इस वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा अल्पकाल समय के लिए जो ऋण प्राप्त किया गया है उसके तो एक बहुत बड़े भाग का दुरुपयोग ही हुआ है। क्योंकि अल्पकाल समय के लिए जो ऋण बैंक शाखायें प्रदान करती हैं वह कृषि क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देती हैं लेकिन इस वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा कृषि क्षेत्र के दिन–प्रतिदिन की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति के लिए धन का उपयोग ही नहीं किया गया बजाय इसके इनके द्वारा खाद्यांश पदार्थ क्रय करने व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ असंगठित स्रोतों से लिये हुए कर्ज के भुगतान करने में ही लगभग राशि समाप्त हो गई जिससे व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋण का इस वर्ग के व्यक्तियों के ऊपर कोई अनुकूल असर नहीं हुआ।

इस प्रकार विवरण से स्पष्ट है कि व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त ऋण का सबसे ज्यादा उपयोग उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा किया गया। तत्पश्चात मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा जबकि निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के ऊपर बैंकिंग वित्त का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ सका। अतः यह कहा जा सकता है कि आज भी निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों की माली

हालत ठीक न होने के कारण बैंकों के द्वारा जो वित्त प्रदान किया जाता है उसके लाभ से ये व्यक्ति आज भी वंचित हैं।

साख प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा दिये गये सुझाव : कानपुर देहात जनपद में जिन 868 व्यक्तियों को विभिन्न बैंक शाखाओं से वित्त प्राप्त हुआ है इन व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके इनके विचार ज्ञात किये गये। इन व्यक्तियों का व्यावसायिक बैंकों के विकास व इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में वित्त प्रदान करने के सम्बन्ध में व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त होने वाले धन से इन व्यक्तियों के जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव व सुझाव को स्पष्ट किया गया जो निम्न हैं :-

1. व्यावसायिक बैंकों का ग्रामीण क्षेत्र में विकास होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय समस्याओं से एक सीमा तक निजात प्राप्त हो सका है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को असंगठित संगठनों के शोषण से बचाया जा सका है।
2. व्यावसायिक बैंकों के विकास होने से एक सीमा तक साहूकारों महाजनों पर अंकुश लगाया जा सका है क्योंकि आज इन व्यक्तियों के द्वारा सामान्य शर्तों पर ऋण प्राप्त हो रहा है।
3. बैंकों से साहूकारों की अपेक्षा ऋण लेने में कठिनाई अवश्य होती है परन्तु साहूकारों की अपेक्षा ब्याजदर कम होने के कारण आर्थिक स्थिति पर बहुत विपरीत असर नहीं पड़ता।
4. व्यावसायिक बैंकों से वित्त प्राप्त होने से कृषि क्षेत्र में निवेश का स्तर बढ़ा है जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि हुई है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि होने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।
5. किसानों को समय पर बैंकों से ऋण प्राप्त होने से कृषि क्षेत्र में आने वाली विभिन्न समस्याओं से निजात मिला है।

कानपुर देहात जनपद में साख प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा जहां एक ओर बैंकिंग प्रणालियों की भूर-भूर प्रशंशा की गई वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्तियों के द्वारा बैंकों की कार्यप्रणालियों से सम्बन्धित समस्यायें भी प्रकट की गई जो निम्न हैं :-

1. व्यावसायिक बैंकों से पर्याप्त मात्रा में ऋण प्राप्त न हो पाना जिससे कृषि क्षेत्र में आवश्यक पूंजी का निवेश नहीं हो पाता।
2. व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त होने में शर्तों व पात्रता में कठिनाई होना जिससे समय पर ऋण नहीं प्राप्त हो पाता।
3. व्यावसायिक बैंकों द्वारा सामान्य व निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध

कराने में आनाकानी करना। उससे किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता।

4. विभिन्न क्षेत्रों व विभिन्न समयों में ऋण की ब्याज दर में परिवर्तन होना।
5. बैंक शाखाओं में कुशल व प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी होना जिससे आये दिन बैंकिंग कार्यप्रणाली में कठिनाई होना।

कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त जनपदों का अलग–अलग अध्ययन करने के पश्चात यह आवश्यक हो जाता है कि कानपुर क्षेत्र में कार्यरत बैंक शाखाओं द्वारा प्रदत्त ऋण व लाभार्थियों की स्थिति पर विचार किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुये कानपुर क्षेत्र में कार्यरत 188 बैंकों में से अध्ययन के लिए चयनित 57 बैंक शाखाओं द्वारा साख प्राप्त लाभार्थियों में से 25 प्रतिशत लाभार्थियों की स्थितियों का विश्लेषण व उनके द्वारा प्राप्त साख की मात्रा व साख के उपयोग के सन्दर्भ में विचार प्रकट करने के लिए सारणी संख्या 126 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या–126

कानपुर क्षेत्र में अध्ययन के लिए चयनित आर्थिक स्थिति के आधार पर साख प्राप्त लाभार्थियों का विवरण (वर्ष 2006–07) धनराशि हजार रु0 में

आर्थिक स्थिति	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण	लाभार्थी संख्या	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का समयावधि के आधार पर वितरण					
			अल्पकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या	मध्यकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या	दीर्घकालीन ऋण	लाभार्थी संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. निम्न आय वर्ग	75745	2127	25543	978	28655	1015	21547	134
2. मध्यम आय वर्ग	473116	5047	148550	2598	137260	1780	187306	669
3. उच्च आय वर्ग	407693	1870	137090	945	91920	586	178683	339
योग–	**956564**	**9044**	**311183**	**4521**	**257835**	**3381**	**387536**	**1142**

सारणी संख्या 126 से यह स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में कार्यरत 57 बैंक शाखाओं से साख प्राप्त लाभार्थियों का 25 प्रतिशत अर्थात 9044 व्यक्तियों को 956554 हजार रुपये के ऋण प्राप्त हुये। इन साख प्राप्त व्यक्तियों में निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 2127 व्यक्तियों को 75745 हजार रुपये के, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 5047 व्यक्तियों को 473116 हजार रुपये के व उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत 1870 व्यक्तियों को 407693 हजार रुपये के ऋण वितरित किये गये। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि क्षेत्र में सबसे अधिक मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण वितरित किये गये किन्तु

ऋण की मात्रा उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को औसत रूप से ज्यादा प्रदान की गई। क्षेत्र में इस वितरित ऋण में से 4521 व्यक्तियों को 311183 हजार रुपये के अल्पकालीन समय के लिए ऋण दिये गये। अल्पकालीन समय के लिए क्षेत्र में वितरित इस ऋण में निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 978 व्यक्तियों को 25543 हजार रुपये के, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 2598 व्यक्तियों को 148550 हजार रुपये के व उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत 945 व्यक्तियों को 137090 हजार रुपये के अल्पकालीन ऋण दिये गये। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि अल्पकालीन समय के लिए कानपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण प्रदान किये गये तत्पश्चात निम्न व उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण दिये गये। कानपुर क्षेत्र में 3381 व्यक्तियों को 257835 हजार रुपये के मध्यकाल समय के लिए ऋण दिये गये। क्षेत्र में मध्यकाल समय के लिए वितरित इस ऋण में निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 1015 व्यक्तियों को 28655 हजार रूपये के, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 1780 व्यक्तियों को 137260 हजार रुपये के व उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत 586 व्यक्तियों को 91920 हजार रुपये के मध्यकालीन ऋण प्रदान किये गये। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में मध्यकालीन समय के लिए वितरित ऋण में सबसे अधिक मध्यवर्ग के व्यक्तियों को ऋण प्रदान किये गये। तत्पश्चात् निम्न व उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण दिये गये। कानपुर क्षेत्र में 1142 व्यक्तियों को 387536 हजार रुपये के दीर्घकाल समय के लिए ऋण वितरित किये गये। दीर्घकाल समय के लिए इस वितरित ऋण में निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 134 व्यक्तियों को 21547 हजार रुपये के, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 669 व्यक्तियों को 187306 हजार रुपये के व उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत 339 व्यक्तियों को 178683 हजार रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिये गये। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में दीर्धकाल समय में सबसे अधिक ऋण मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को तत्पश्चात् उच्च व निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण प्रदान किये गये।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कानपुर क्षेत्र में सबसे अधिक व्यक्तियों को अल्पकाल समय के लिए तत्पश्चात् मध्यकाल व दीर्घकाल समय के लिए ऋणों का वितरण किया गया। जहां तक ऋण की मात्रा का प्रश्न है सबसे अधिक दीर्घकाल समय के लिए ऋण की मात्रा प्रदान की गई तत्पश्चात् अल्पकाल व मध्यकाल समय के लिए ऋण वितरित किये गये।

कानपुर क्षेत्र में साख प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा वित्त का उपयोग : कानपुर क्षेत्र में 9044 व्यक्तियों द्वारा क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न बैंक शाखाओं से जो वित्त प्राप्त किया गया है उस

वित्त के उपयोग के सम्बन्ध में अध्ययन में यह पाया गया है कि जिन व्यक्तियो ने बैंकों से साख प्राप्त किया है उनमें से उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर 3 वर्ग रहे हैं और इन तीनों ही वर्गों के द्वारा धन के उपयोग में परिवर्तन रहा है। जैसा की अध्ययन में पाया गया है कि जिन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अर्थात् जिनकी वार्षिक आय 20,000 रुपये तक है उनके द्वारा बैंकों से प्राप्त वित्त का आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि जिन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति 21,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक वार्षिक आय के बीच है। उनके द्वारा बैंकों से वित्त प्राप्त करने के पश्चात् आर्थिक स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन हुआ है। जबकि जिनकी वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से ऊपर है उनके द्वारा विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त साख का सबसे अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ा है।

अध्ययन में यह भी पाया गया है कि निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के अन्तर्गत एक बड़ी मात्रा में आज भी विभिन्न सगे सम्बन्धी , साहूकार, महाजन व भूमि–धरों के ऋणी हैं जिनके कारण वह जो भी व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त करते हैं उस प्राप्त ऋण का एक बड़ा भाग इन व्यक्तियों से लिये गये ऋण की अदायगी में चला जाता है जिससे इस वर्ग के व्यक्तियों में बैंकों से ऋण लेने का विकास की दृष्टिकोण से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि ऋण लेकर यह किसी क्षेत्र में न लगाकर ऋण की अदायगी करने में ही खर्च कर देते हैं जिससे जिस क्षेत्र में धन लगाना चाहते हैं उस क्षेत्र में धन नहीं लगा पाने के कारण इनकी आय में वृद्धि नही हो पाती जिससे इनके जीवन पर व्यावसायिक बैंकों के वित्त का अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। जैसा कि अध्ययन में पाया गया है कि आज भी 25 से 35 प्रतिशत तक व्यक्तियों के द्वारा जो वित्त विभिन्न व्यावसायिक बैंक शाखाओं से साख प्राप्त किया गया है उस वित्त का इन व्यक्तियों के ऊपर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है केवल इतना अवश्य परिवर्तन हुआ है कि असंगठित स्रोतों के शोषण में कुछ अवश्य कमी आई है। इस वर्ग के व्यक्ति आज भी विकास रहित जीवन जी रहे हैं।

कानपुर क्षेत्र में मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों द्वारा बैंक शाखाओं से लिये गये ऋण के सम्बन्ध में अध्ययन में यह पाया गया है कि इस वर्ग के 70–85 प्रतिशत तक व्यक्तियों द्वारा धन का सदुपयोग किया गया है जिससे इन व्यक्तियों की आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन हुआ है। शेष जिन व्यक्तियों द्वारा धन का सदुपयोग नही किया गया है उनके विषय में अध्ययन में पाया गया है कि वे व्यक्ति या तो असंगठित संगठनों के चंगुल में आज भी फंसे हुये हैं या फिर उनकी माली हालात ठीक न होने के कारण उनके द्वारा प्राप्त वित्त का अनुत्पादक कार्यों में व्यय किया गया है।

जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सका है।

कानपुर क्षेत्र में उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न बैंक शाखाओं से जो वित्त प्रदान किया गया है उनके सम्बन्ध में अध्ययन में पाया गया है कि इन व्यक्तियों के द्वारा जिस भी समय के लिए ऋण प्राप्त किया गया है उसमें से लगभग धन का सदुपयोग ही किया गया है। क्योंकि अध्ययन में यह पाया गया है कि इन व्यक्तियों की आर्थिक स्थितियों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है जो इस बात का संकेत है कि उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों पर व्यावसायिक बैंकों के वित्त का सबसे ज्यादा अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

कानपुर क्षेत्र में उपरोक्त तीनों प्रकार के आय वर्ग के व्यक्तियों का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो गया है कि व्यावसायिक बैंकों के वित्त का सबसे अधिक प्रभाव उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों पर पड़ा है। इसके बाद मध्यम व निम्न आय वर्ग के व्यक्ति व्यावसायिक बैंकों के वित्त से प्रभावित हुये हैं। अर्थात् कहा जा सकता है कि व्यावसायिक बैंकों के वित्त का कृषि क्षेत्र में अनुकूल ही प्रभाव रहा है। या यह कह सकते हैं कि व्यावसायिक बैंकों के वित्त प्रदान करने से कृषि क्षेत्र में विकास किया जा सका है। हालांकि आज भी पर्याप्त मात्रा में कृषि क्षेत्र को पूंजीगत निवेश नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं जिससे कृषि क्षेत्र में तकनीकी उपकरणों का व सिचाई समस्याओं का आज भी अभाव है जैसा कि अध्ययन में पाया गया है।

साख प्राप्त व्यक्तियों के विचार : कानपुर क्षेत्र में साख प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा बैंकों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार प्रकट किये गये :–

1. व्यावसायिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में वित्त की अधिकाधिक मात्रा देने से कृषि निवेश में वृद्धि हुई है। कृषि निवेश में वृद्धि होने से कृषि के ढाँचे में परिवर्तन हो सका है। जिससे कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक का प्रयोग हो सका है।
2. व्यावसायिक बैंकों के वित्त प्रदान करने से साहूकारों, महाजनों, भू–स्वामियों, व्यापारियों व कमीशन एजेण्टों आदि के द्वारा किये जाने वाले शोषण में कमी आई है।
3. व्यावसायिक बैंकों के वित्त प्रदान करने के उपरान्त कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कृषि यन्त्रीकरण का प्रयोग सम्भव हो सका है।
4. किसानों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है।
5. वंशानुक्रम ऋण ग्रस्तता में कमी आई है। जिससे जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

6. कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक का प्रयोग होने से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है।
7. मण्डियों तक कृषि उपज को ले जाने में मदद् मिली है।
8. कुण्ठा व हीनता में कमी आई है, जिसके कारण कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।
9. कृषि भू–भाग को बढ़ाने में सहायता प्राप्त हुई है।
10. भमि परिक्षण होने से रासायनिक क्रियाओं का प्रयोग सम्भव हुआ है।
11. सिचाई साधनों का विकास हुआ है।
12. कृषि सहायक उद्योगों का विकास हुआ है।
13. कृषि क्षेत्र में कृषि श्रमिकों की संख्या में कमी आई है।
14. व्यापारिक फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
15. दुधारू पशुओं की मात्रा में वृद्धि हुई है, जबकि दूध न देने वाले पशुओं की संख्या में कमी आई है।
16. किसान क्रेडिट कार्ड को निर्गत करने से किसानों की दिन–प्रतिदिन की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हो सकी है। जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों का भी विकास हुआ है।
17. असंगठित संगठनों के शोषण में कमी आई है। क्योंकि इन संगठनों के माध्यम से आज पहले की तुलना में सरल शर्तों पर वित्त प्राप्त हो सका है।
18. कृषि क्षेत्र में नये–नये बीज व कृषि उपकरणों का प्रयोग सम्भव हुआ है जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। आदि विचारों को साख प्राप्त लाभार्थियों द्वारा व्यक्त किये गये।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यावसायिक बैंकों के विकास होने से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समस्याओं से एक सीमा तक निपटा जा सका है। जिससे असंगठित संगठनों के शोषण से किसानों को बचाया जा सका है। व्यापारिक बैंकों के वित्त प्रदान करने से कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्र का विकास हुआ है। जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकी है। जिसके कारण वंशानुक्रम ऋण ग्रस्तता में कमी आई है।

वित्त प्राप्त करने के सम्बन्ध में साख प्राप्त करने वाले लाभार्थियों द्वारा व्यक्त की गई समस्यायें : कानपुर क्षेत्र में विभिन्न बैंक शाखाओं से वित्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों द्वारा वित्त प्राप्त करने के सम्बन्ध में कुछ समस्यायें भी व्यक्त की गई हैं। साख प्राप्त लाभार्थियों का

कहना है कि :–

1. बैंक शाखाओं के द्वारा पर्याप्त मात्रा में वित्त प्राप्त नहीं हो सका है। जिससे आवश्यक पूंजी की कमी महसूस होती रहती है जिसके कारण कृषि क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में वित्त का प्रयोग सम्भव नहीं हो सका है।
2. व्यावसायिक बैंकों के द्वारा वित्त प्राप्त करने में अनावश्यक रूप से विभिन्न शर्तों को थोपा जाता है जिसके कारण समय पर धन प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सकता, जिससे ग्रामीण लोग मजबूर होकर असंगठित संगठनों से वित्त प्राप्त करते हैं।
3. पात्रता की शर्तें ऊँची होने के कारण इच्छुक व्यक्ति ऋण प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। जिसके कारण ये व्यक्ति चाह कर भी कृषि क्षेत्र में उत्पादन स्तर में सुधार नहीं कर पाते हैं।
4. व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड में दर्शाई गई रकम की मात्रा आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध नहीं कराई जाती।
5. व्यावसायिक बैंकों में प्रशिक्षित व कुशल कर्मचारियों की कमी होने के कारण समय पर किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हो पाती जिससे कृषक लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं।
6. ब्याज दर में प्रत्येक समय में परिवर्तन होने से आर्थिक हानि होती है।
7. ऋण अदायगी में किश्तों का समय से न दे पाने के कारण किसानों से अतिरिक्त ब्याज वसूला जाता है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति कुप्रभावित होती है।
8. व्यावसायिक बैंक कर्मचारियों के द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण किया जाता है।
9. सेवा क्षेत्र की बैंक शाखा के अतिरिक्त अन्य बैंक शाखा से ऋण प्राप्त कर लेने के पश्चात सेवा क्षेत्र की बैंक से ऋण प्राप्त कर पाना कठिन हो जाता है जिससे पर्याप्त मात्रा में वित्त प्राप्त नहीं हो पाता।
10. सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों की जानकारी बैंक कर्मचारियों के द्वारा किसानों को समय से नहीं दी जाती है और न ही किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि साख प्राप्त करने के उपरान्त साख को सुनियोजित तरीके से लगा कर उत्पादन स्तर में वृद्धि कर सकें और प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि कर सकें आदि बिन्दुओं पर साख प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा व्यावसायिक बैंकों की कार्यप्रणाली पर असन्तोष जाहिर किया गया है।

निष्कर्ष :

वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत पर प्राथमिक संमकों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक संमकों के अन्तर्गत आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से विभिन्न बैंक शाखओं में जाकर व विभिन्न साख प्राप्त लाभार्थियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके उनके द्वारा व्यक्त विचारों एवं उनके द्वारा प्राप्त की रकम को वर्तमान अध्याय में स्पष्ट किया गया है। वर्तमान अध्याय के अन्तर्गत कानपुर क्षेत्र में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों में से अध्ययन के लिए रैण्डम सैम्पलिंग के माध्यम से 30 प्रतिशत इकाइयों का चयन किया गया है। इन इकाइयों के द्वारा कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में जो ऋण वितरित किया गया है व जिन व्यक्तियों को साख प्राप्त हो सका है उन व्यक्तियों के विचार जानने के लिए साख प्राप्त लाभार्थियों का रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर 25 प्रतिशत व्यक्तियों को अध्ययन के लिए चयन किया गया है। अध्ययन के लिए चयन कर इन व्यक्तियों के द्वारा कानपुर क्षेत्र की विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में उनकी नामावली प्राप्त की गई है। जहां तक बैंकिंग इकाइयों व लाभार्थियों की संख्या के अध्ययन का प्रश्न है प्रत्येक प्रकार की बैंक जो कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में कार्य कर रही है जनपद स्तर पर विभिन्न व्यावसायिक बैंकों के नामों के आधार पर 30 प्रतिशत इकाइयों को अध्ययन के लिए चयन किया गया है। अध्ययन के लिए चयन में यह भी स्थिति उत्पन्न हुई है कि यदि किसी बैंक की कम शाखायें जनपद में कार्यरत हैं तो उसका चयन 30 प्रतिशत से अधिक भी हुआ है और संख्या कम होने पर चयन से वंचित भी हो गई हैं लेकिन अध्ययन के लिए चयन करते समय एक बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया है कि कानपुर क्षेत्र में विभिन्न जनपदों में विकासखण्ड स्तर पर कार्यरत किसी न किसी व्यावसायिक बैंक शाखा का अध्ययन के लिए अवश्य चयन किया गया है जिससे अध्ययन क्षेत्र का विस्ता हो सके और सही आंकड़े प्राप्त किये जा सकें। यही स्थिति लाभार्थियों के चयन के सम्बन्ध में लागू की गई है। इसमें भी कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में कार्यरत विकासखण्डों में पहुंचने की कोशिश की गई है।

कानपुर क्षेत्र में 188 व्यावसायिक बैंकों की शाखायें कार्यरत हैं जिसमें से अध्ययन के लिए 57 बैंकों शाखाओं का चयन किया गया है। इन सभी बैंक शाखाओं के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में कानपुर क्षेत्र के सभी जनपदों में 3716838 हजार रुपये के 36202 व्यक्तियों को वित्त प्रदान किये गये हैं। यह वित्त विभिन्न समयों के लिए दिये गये हैं। अल्पकाल समय के लिए क्षेत्र में वितरित ऋण का 32.3 प्रतिशत भाग, मध्यकाल समय के लिए क्षेत्र में वितरित

ऋण का 24.8 प्रतिशत भाग व दीर्घकाल समय के लिए क्षेत्र में वितरित ऋण का 42.9 प्रतिशत भाग ऋण प्रदान किया गया। इस प्रकार कानपुर क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का सबसे अधिक वित्त दीर्घकाल समय के लिए प्रदान किये गये। जिससे कृषि क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ाया जा सके। जिससे कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक का प्रयोग सम्भव हो सके जिससे कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कानपुर क्षेत्र में विभिन्न समयों के लिए जो ऋण वितरित किये गये हैं वह विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये दिये गये हैं। प्राथमिकता क्षेत्र में जो ऋण वितरित किये गये हैं उसमें से 75.2 प्रतिशत या 2795940 हजार रुपये के ऋण प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र में निवेश किये गये हैं। कृषि क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक बैंक शाखाओं द्वारा वितरित यह ऋण ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों को क्रय करने, सिचाई सुविधाओं का विकास करने, कोल्ड स्टोरेज खोलने, अनाज भण्डार गृह खोलने, दिन–प्रतिदिन की कृषि क्षेत्र में वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करने, भवन निर्माण, खेतों तक पहुंचने के लिए मोटर साइकिल आदि क्रय करने के लिए यह ऋण वितरित किये गये। कानपुर क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त लघु उद्योग के विकास करने के लिए कानपुर क्षेत्र में वितरित ऋण का 8 प्रतिशत या 297173 हजार रुपये के ऋण 1584 व्यक्तियों को दिये गये। लघु उद्योग क्षेत्र में ऋण प्रदान करने से निश्चित ही लघु उद्योग क्षेत्र का विकास हुआ है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में आवास करने वाले व्यक्तियों को एक ओर जहां रोजगार प्राप्त हुआ है वहीं दूसरी ओर लघु उद्योग उद्यमियों की आय में वृद्धि हो सकी है तथा अतिरेक उत्पादन हो सका है। कानपुर क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य प्राथमिकता क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 16.8 प्रतिशत या 624290 हजार रुपये 5369 व्यक्तियों को दिये गये। अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत सघन मिनी डेरी का विकास करने के लिए, पालतू पशुओं को क्रय करने के लिए, मतस्य पालन करने के लिए, कुक्कुट पालन करने के लिए, मधुमक्खी पालन करने के लिए एवं अन्य विभिन्न प्रकार के कृषि एवं उससे सम्बन्धित या ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा की गई जिससे कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों का विकास हो सके। जिससे कृषि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी ग्रामीण क्षेत्र में आवास करने वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो सके।

कानपुर क्षेत्र में इन विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए जो विभिन्न बैंक शाखाओं के द्वारा ऋण वितरित किये गये है। इनमें शाखा स्तर पर व जनपद स्तर पर ऋण वितरण में परिवर्तन की स्थिति रही है। प्रत्येक क्षेत्र में ऋण वितरण अलग–अलग स्तर पर हुआ है।

कानपुर क्षेत्र में इन 57 बैंक शाखाओं से जिन व्यक्तियों को साख प्राप्त हो सका है उनका जनपद स्तर पर अध्ययन के लिए 25 प्रतिशत व्यक्तियों का चयन किया गया है। जिसमें से फर्रूखाबाद जनपद के अन्तर्गत 1842 व्यक्तियों का अध्ययन के लिए चयन किया गया, कन्नौज जनपद के अन्तर्गत 964 व्यक्तियों का अध्ययन के लिए चयन किया गया, इटावा जनपद के अन्तर्गत 3041 व्यक्तियों का अध्ययन के लिए चयन किया गया, औरैया जनपद में 667 व्यक्तियों का अध्ययन के लिए चयन किया गया, कानपुर नगर जनपद के अन्तर्गत 1662 व्यक्तियों का अध्ययन के लिए चयन किया गया व कानपुर देहात जनपद में 868 व्यक्तियों का अध्ययन के लिए चयन किया गया। इस प्रकार कानपुर क्षेत्र में कुल 9044 व्यक्तियों का अध्ययन के लिए चयन किया गया है।

कानपुर क्षेत्र में अध्ययन के लिए चयनित इन व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बैंक शाखा जाकर उनकी नामावली प्राप्त की गई तथा प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्नावली के माध्यम से ऋण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त जानकारी में यह पाया गया कि कानपुर क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को किसी भी व्यावसायिक बैंक शाखा से ऋण प्राप्त हुआ है उनकी आर्थिक स्थिति भिन्न–भिन्न प्रकार की रही है अतः कानपुर क्षेत्र में साख प्राप्त व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को अध्ययन की दृष्टिकोण से 3 भागों में विभक्त किया गया है–

1. **निम्न आय वर्ग के व्यक्ति :** इस वर्ग के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को रखा गया है जिनकी चल अचल या किसी भी प्रकार के आय के स्रोतों से वार्षिक आय 20,000 रुपये तक है या जिनके पास भू–राजस्व लेखे में एक बीघे से पाँच बीघे तक सिंचित भूमि पाई जाती है। उन्हेंनिम्न आय वर्ग के अन्तर्गत रखा गया है या इन्हें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की श्रेणी में रखा जा सकता है।

2. **मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति :** मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को रखा गया है जिनकी वार्षिक आय चल–अचल किसी भी प्रकार की सम्पत्ति या स्रोतों से वार्षिक आय 21,000 हजार रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक है या जिनके पास भू–राजस्व लेखे के अनुसार 6 बीघे से लेकर 25 बीघे तक सिंचित भूमि पाई जाती है। इन्हें गरीबी रेखा से ऊपर और आयकर विभाग से विभिन्न करों से मुक्त रखा गया है। इस प्रकार के व्यक्तियों को इस श्रेणी में रखा गया है।

3. **उच्च आय वर्ग के व्यक्ति :** उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को रखा गया है जिनकी किसी भी प्रकार के स्रोतों से वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से अधिक है। या जिनके पास भू–राजस्व लेखे के अनुसार 25 बीघे से ऊपर सिंचित भूमि पाई जाती है। आयकर विभाग द्वारा जिनसे विभिन्न कर वसूल किये जाते हैं इन्हें उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत रखा गया है।

कानपुर क्षेत्र में इन तीनों ही प्रकार के आय वर्ग के व्यक्तियों को विभिन्न बैंक शाखाओं के द्वारा वित्त प्रदान किया गया है। जहां तक विभिन्न व्यक्तियों के मध्य ऋण के वितरण का प्रश्न है तो सबसे ज्यादा मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराये गये हैं। जबकि औसत रूप से ऋण की मात्रा सबसे ज्यादा उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को दी गई है। जबकि कानपुर क्षेत्र में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को कम ही ऋण उपलब्ध हो पाया है।

ऋण का उपयोग : कानपुर क्षेत्र में अध्ययन करने के पश्चात् यह स्पष्ट हुआ है कि इन तीनों ही प्रकार के आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा जो विभिन्न बैंक शाखाओं से ऋण प्राप्त किया गया है उसमें से उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा सबसे अधिक प्राप्त वित्त का सदुपयोग किया गया है क्योंकि उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के जीवन स्तर में द्रुत गति से विकास हुआ है। जबकि इसके बाद मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा भी ऋण का अपेक्षाकृत निम्न आय वर्ग की तुलना में अधिक सदुपयोग किया गया है। इस प्रकार के वर्ग के व्यक्तियों के ऊपर भी व्यावसायिक बैंकों के वित्त का अनुकूल प्रभाव पड़ा है। किन्तु निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा धन का अपेक्षाकृत कम ही उपयोग कर पाना अध्ययन में पाया गया है। इस वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा धन का उचित उपयोग न कर पाने के कारण व्यावसायिक बैंकों के वित्त का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है जैसा कि अध्ययन से स्पष्ट है।

कानपुर क्षेत्र में विभिन्न आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न बैंक शाखाओं से प्राप्त ऋण व उसके उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सका है कि व्यावसायिक बैंकों के विकास होने से ग्रामीण क्षेत्र में वित्त की उपलब्धता हो सकी है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विकास में जो वित्तीय बाधायें उत्पन्न होती थी उससे एक सीमा तक निपटा जा सका है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो रहा है। व्यावसायिक बैंकों के द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के पर्याप्त अवसर सुलभ हुये हैं। जैसा कि अध्ययन से स्पष्ट हो सका है। कृषि

क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों के वित्त प्रदान करने से असंगठित संगठनों से प्राप्त वित्त में कमी आई है जिससे किसानों को असंगठित संगठनों के शोषण से बचाया जा सका है क्योंकि जैसा कि अध्ययन में पाया गया है कि दिन–प्रतिदिन कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा प्रदान की जा रही वित्त की मात्रा में वृद्धि हो रही है। जो इस बात को स्पष्ट करती है कि जहां व्यावसायिक बैंकों के विकास न होने के पहले कृषि क्षेत्र में वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति असंगठित संगठनों के माध्यम से प्राप्त होती थी वहीं अब संस्थागत स्रोतों से प्राप्त हो रही है। जहां तक संस्थागत व गैर संस्थागत स्रोतों का प्रश्न है निश्चित ही गैर संस्थागत स्रोतों की अपेक्षा संस्थागत स्रोतों से साधारण जनहित की रक्षा की जा सकी है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से जो भी कार्य सम्पादित किये जाते हैं वह इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किये जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे लाभ प्राप्त हो सके। इसी का पर्याय व्यावसायिक बैंकें भी हैं। जहां तक गैर संस्थागत स्रोतों का प्रश्न है इन स्रोतों के माध्यम से जनहित की रक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि इन स्रोतों के द्वारा जो भी कार्य किये जाते हैं वह व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर ही किये जाते हैं और जहां पर व्यक्तिगत लाभ सर्वोपरि होता है वहां पर निश्चित ही साधारण जनहित की रक्षा नहीं की जा सकती और इसी का पर्याय गैर संस्थागत स्रोत भी रहे हैं जहां पर किसानों का अनुचित शोषण भी किया गया है जैसा कि पिछले अध्यायों में स्पष्ट किया जा चुका है।

कानपुर क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा वित्त प्रदान करने से अध्ययन के प्रारम्भ में स्पष्ट की गई परिकल्पना की व्यावसायिक बैंकों के वित्त प्रदान करने से कृषि साख का ढॉचा विस्तृत व मजबूत हो सका है। निश्चित ही इसकी पुष्टि हो जाती है। जैसा कि अध्ययन में पाया गया है।

कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों के वित्त प्रदान करने से गैर संस्थागत संगठनों के शोषण से किसानों को बचाया जा सका है। क्योंकि व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त वित्त की मात्रा में दिन–प्रतिदिन वृद्धि होने से इस परिकल्पना की भी पुष्टि हो जाती है कि व्यावसायिक बैंकों के वित्त प्रदान करने से असंगठित संगठनों के शोषण से किसानों को बचाया जा सका है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सका है।

तीसरी परिकल्पना की व्यावसायिक बैंकों के वित्त प्रदान करने से कृषि क्षेत्र में निवेश का स्तर बढ़ सका है इसकी भी पुष्टि हो जाती है क्योंकि आज कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक

बैंकों के द्वारा आवश्यकतानुसार वित्त प्राप्त हो सका है। जिससे कृषि क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन किया जा सका है जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन स्तर में वृद्धि हुयी है।

चौथी परिकल्पना की व्यावसायिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने से कृषि अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक इकाई के रूप में देखा जा सकता है इसकी भी कहीं हद तक पूर्ति ही हो जाती है। क्योंकि कृषि क्षेत्र में निवेश का स्तर बढ़ने से निश्चित ही उत्पादन स्तर में वृद्धि हुई है। और उत्पादन स्तर में वृद्धि होने से यह अवश्य कहा जा सकता है कि कृषि अर्थव्यवस्था में यदि और अधिक सुधार किये जायें तो निश्चित ही कृषि क्षेत्र भी आर्थिक इकाई हो सकता है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निश्चित ही व्यावसायिक बैंकों के विकास के साथ–साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास सम्भव हो सका है क्योंकि व्यावसायिक बैंकों के द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ध्यान में रखकर ऋण का वितरण किया जा रहा है। जिससे असहाय दुर्लभ व कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की वित्तीय समस्याओं का समाधान हुआ है। जिससे इनके जीवन स्तर में अपेक्षाकृत सुधार हो सका है।

जैसा कि अध्ययन में पाया गया है कि आज भी पर्याप्त मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे व्यक्तियों के सामने वित्त की समस्या है अतः वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त प्रदान किये जायें और यह वित्त सबसे ज्यादा मात्रा में दीर्घकालिक समय को ध्यान में रखकर दिये जायें जिससे कृषि क्षेत्र में निवेश का स्तर बढ़ा सके चूंकि कानपुर क्षेत्र की आधे से अधिक आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही है और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन आज भी कृषि क्षेत्र है। इसलिए जब तक कृषि क्षेत्र मे पर्याप्त मात्रा में निवेश नहीं होगा तब तक कृषि क्षेत्र का विकास नहीं होगा और जबतक कृषि क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना सम्भव नहीं है ऐसी स्थिति में भंयकर अपराध होते हैं। अतः किसी भी विषम स्थिति से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर वित्त की आवश्यकता है जैसा कि आज देखा जा रहा है कि भारतीय कृषि पूर्ण रूप से सिचाई के अभाव से तृस्त है। जैसा कि अध्ययन में पाया गया है कि कानपुर क्षेत्र में जितने भी भू–भाग पर खेती की जाती है उसका एक बड़ा भाग असिंचित क्षेत्र रहता है और इस असिंचित क्षेत्र में अतिरिक्त फसल का उत्पादन कर पाना सम्भव नहीं हो सकता।

यह असिंचित क्षेत्र पूर्णतया मानसून पर निर्भर है यदि समय पर मानसून आता है वर्षा होती है तो असिंचित क्षेत्र में बोवाई की जा सकती है जिससे फसले उत्पादित की जा सकती हैं। अन्यथा की स्थिति में सम्भव नहीं है और कृषि क्षेत्र का बड़ा भू–भाग परती के रूप में पड़ा रहता है। जैसा कि वर्तमान में कुछ वर्षों से मानसून में गिरावट आई है जिसके कारण वर्षा में कमी आयी है या वर्षा की असमानता की स्थिति हो गयी है। जिसके कारण सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है और इस सूखा जैसी स्थिति से निपटने के लिए निश्चित तौर पर व्यापक पैमाने पर वित्त की आवश्यकता है। जिसको वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाना सम्भव है अतः व्यावसायिक बैंकों को चाहिए कि वे पर्याप्त मात्रा में वित्त प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग प्रदान करे।



अध्याय - आठ

अध्याय - आठ

निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय – आठ : निष्कर्ष एवं सुझाव

वर्तमान शोध प्रबन्ध के निष्कर्ष के रूप में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि साख प्रणाली का अर्थ साख या ऋण की उस व्यवस्था से लगाया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए किसानों को ऋण प्राप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि अभी भी निजी क्षेत्र में है, फिर भी सरकार द्वारा समय–समय पर किसानों की आर्थिक सहायता के लिए प्रयत्न किये जाते रहे हैं पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले इस दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं किया जा सका था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा कृषि विकास के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में सरकार द्वारा कृषि विकास के लिए आवश्यक साख प्रदान करने के लिए विभिन्न स्रोतों की जानकारी के लिए राष्ट्र स्तर पर एक अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी की नियुक्ति की गयी कमेटी ने यह पाया कि कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने के कार्य गैर संस्थागत स्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार किसानों द्वारा लिए जाने वाले ऋणों का लगभग 93 प्रतिशत भाग अभी भी पेशेवर व कृषि महाजनों, सगे सम्बन्धियों, व्यापारी एवं कमीशन एजेन्टों, भू–स्वामियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त साख के संस्थागत स्रोतों से किसानों की ऋण आवश्यकता का मात्र 7 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। इसके अन्तर्गत सहकारी संगठन, सरकार एवं व्यापारिक बैंक है।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने कृषि साख प्रदान करने के लिए सहकारी संगठनों को सबसे उपयुक्त साधन माना था और कमेटी ने सहकारी संगठनों के विकास के सम्बन्ध में अपनी सिफारिश की थी। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी के सिफारिशों के पश्चात लगभग एक दशक तक विचारकों द्वारा कृषि क्षेत्र में साख या ऋण प्रदान करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये जाते रहे हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात विचारकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ ऐसा अनुभव किया जाने लगा कि तीव्र दर से कृषि विकास केवल सहकारी संगठनों के द्वारा प्रदत्त ऋणों के आधार पर नहीं किया जा सकता इसके लिए एक बड़ी मात्रा में ऋण या वित्तीय संसाधनों

की आवश्यकता है। जो केवल सहकारी संगठनों के माध्यम से प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है बल्कि इसके लिए बहुएजेन्सी दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है। इस विचार के परिणामसवरूप अन्य संस्थागत श्रोतों का विकास किया जाना आवश्यक समझा गया वर्ष 1967 में व्यापारिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण किया गया इसके पश्चात वर्ष 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तत्पश्चात वर्ष 1980 में 6 प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य इन बैंकों को कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना था।

वर्तमान में कृषि साख के संस्थागत श्रोतों के अन्तर्गत मुख्य रूप से सहकारी संगठन, व्यापारिक बैंक एवं सरकार यह कार्य सम्पादित कर रहे हैं। अपने सीमित साधनों और सीमित कार्य क्षेत्र के कारण सहकारी संगठनों को एक निश्चित सीमा तक सफलता प्राप्त हो सकी है। कृषि क्षेत्र में एक बड़ी मात्रा में आवश्यक वित्त प्रदान करने का कार्य मुख्य रूप से व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है।

अपने पर्याप्त संसाधनों और विस्तृत कार्य क्षेत्र होने के कारण कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। वर्तमान अध्ययन ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विकास के लिए प्राप्त होने वाले संस्थागत वित्त से सम्बन्धित है।

कृषि क्षेत्र में संस्थागत वित्त मुख्यतया दो श्रोतों से प्राप्त होता है–

1. सहकारी संगठन
2. व्यापारिक बैंक

उपरोक्त के संदर्भ में वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि विकास तथा इनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले वित्त से कृषि अर्थव्यवस्था किस सीमा तक प्रभावित हुई है, इसका मूल्यांकन करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र को चुना गया है। यह एक व्यष्टि प्रकार का अध्ययन है, जो प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित है। प्राथमिक समंक कानपुर क्षेत्र के उन बैंकों के कार्यालयों के अधिकारियों, लाभार्थियों, सम्बन्धित व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके ज्ञात किये जायेंगे। और द्वितीय समंक कानपुर क्षेत्र में

कार्यरत विभिन्न व्यापारिक बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट एवं उनके द्वारा प्रकाशित अन्य रिपोर्टों तथा प्रकाशनों एवं वैलेन्स सीटों से प्राप्त किये जायेगें।

वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाना है।

1. वाणिज्यिक बैंकों के वित्त प्रदान करने के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत वित्त का ढॉचा अधिक विस्तृत एवं मजबूत हो सका है।
2. वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से किसानों को पर्याप्त मात्रा में वित्त प्राप्त होने के परिणामस्वरूप कृषि के विकास में सहायता प्राप्त हुई है।
3. कृषि के लिए आवश्यक वित्त प्रदान करने के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक वित्त पोषण के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए उत्पादन के कार्य में आवश्यक गठनात्मक ढांचा का विकास एवं विस्तार हुआ है।
4. किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।
5. किसानों को महाजनो के आर्थिक शोषण से बचाया जा सकता है।

कृषि साख के संगठित स्रोतों के अन्तर्गत उन संगठनों या स्रोतों को रखा गया है। जिन संगठनों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र के लिए वित्त या ऋण निम्न संस्थागत या संगठनों के माध्यम से प्राप्त होता है।

1. व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. सहकारी बैंकिंग व्यवस्था या बैंक
4. सरकार द्वारा

इन संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 में कृषि क्षेत्र में संस्थागत वित्त का लगभग 24.5 प्रतिशत सहकारी बैंकों द्वारा, 9.4 प्रतिशत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा व 66.3 प्रतिशत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किया गया था। कृषि क्षेत्र में कृषि आवश्यकता का इन संस्थागत स्रोतों से कृषि क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करने के कार्य में निरन्तर वृद्धि हुयी है इनके

क्रियाकलापों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण केन्द्र एवं राज्य सरकार की कृषि नीति के अन्तर्गत कृषि विकास को प्राथमिकता प्रदान करना रहा है। कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक से अधिक वित्त प्रदान करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र का निर्धारण किया जाता रहा है। प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि, लघु उद्योग एवं समाज के कमजोर वर्ग को रखा गया है।

वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात इन बैंकों द्वारा अधिक से अधिक ऋण कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 1969 में इन बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋण का मात्र 3.6 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र को दिया गया था। राष्ट्रीयकरण के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का 15 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष वित्त या ऋण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसे वर्ष 1985 तक प्राप्त किया जाना था। इस लक्ष्य को बाद में बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया जिसे वर्ष 1987 तक प्राप्त करने का लक्ष्य था। वर्ष 1990 तक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अधिक से अधिक ऋण कृषि क्षेत्र को प्रदान किये गये थे। जो इन बैंकों में कृषकों के ऋण खातों की संख्या से स्पष्ट हैं। वर्ष 1969 में कृषि क्षेत्र के ऋण प्राप्तकर्ताओं के खातों की संख्या बैंकों के कुल खातों की संख्या में 8.1 प्रतिशत थी। जो वर्ष 1988 में बढ़कर 60.1 प्रतिशत हो गयी।

यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रदान किये गये वित्त/ऋणों की मात्रा में विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि वाणिज्यिक बैंकों के विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिये गये ऋणों में वृद्धि के साथ–साथ कृषि क्षेत्र के लिए दिये जाने वाले ऋणों में भी वृद्धि हुयी है।

इस बात का अनुमान बैंकों के कृषि क्षेत्र में लगे हुये ऋणों की रकम द्वारा लगाया जा सकता है। वर्ष 1969 में इन बैंकों का कुल 483.30 करोड़ रुपये का ऋण विभिन्न क्षेत्रों में लगा हुआ था। जो वर्ष 1988 में बढ़कर 28467.8 करोड़ रुपये हो गया। इस लगे हुये ऋण का लगभग 30 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र में लगा हुआ था।

राष्ट्रीकरण से पहले इन बैंकों द्वारा बड़े व मध्यम आकार के उद्योगों एवं थोक

व्यापार के लिए 78 प्रतिशत ऋण दिया गया पर राष्ट्रीयकरण के पश्चात वर्ष 1988 में इन क्षेत्रों को प्राप्त ऋण कम होकर 41 प्रतिशत हो गया इसके विपरीत प्राथमिकता क्षेत्र को प्राप्त होने वाले ऋण में निरन्तर वृद्धि हुयी है।

वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीकरण के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में वित्त प्रदान करने को प्राथमिकता प्रदान की गयी जिन्हें राष्ट्रीयकरण के पहले वित्त नहीं प्रदान किया जाता। इसके अन्तर्गत लघु ऋण प्राप्तकर्ताओं को वित्त प्रदान करने को प्राथमिकता प्रदान की गयी। इसके अन्तर्गत कृषि, लघु पैमाने के उद्योग, सड़क एवं जल परिवहन, फुटकर व्यापार और छोटे मोटे व्यवसायी वर्गों को ऋण प्रदान करने का कार्य किया गया। इन वर्गों को राष्ट्रीयकरण के पहले कोई महत्व नहीं प्रदान किया जाता था। वाणिज्यिक बैंकों के वित्त का बहुत छोटा भाग ही इन्हें प्राप्त हो पाता था।

परिणामस्वरूप वर्ष 1969 से 1988 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के लघु ऋण प्राप्तकर्ताओं के खातों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुयी है। इन ऋण प्राप्तकर्ताओं पर लगे हुये ऋण की मात्रा वर्ष 1969 में 441 करोड़ रुपये थी। जो वर्ष 1988 में बढ़कर 28468 करोड़ रुपये हो गयी थी।

वर्ष 1988 में कुल वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का 45.8 प्रतिशत ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया। राष्ट्रीयकरण के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समक्ष यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि इनके द्वारा दिये जाने वाले वित्त का 15 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को प्रदान किया जाये। इस लक्ष्य को वर्ष 1985 तक प्राप्त किया जाना था। बाद में इसको बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया। जिसे वर्ष 1989 तक प्राप्त किया जाना था। इस लक्ष्य के सन्दर्भ मे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपने कुल ऋण का 16.8 प्रतिशत ऋण वर्ष 1988 में दिया गया था।

नौंवी पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के समयावधि में कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्रों में 229000 करोड़ रुपये के ऋण दिये जाने के लक्ष्य का निर्धारण किया गया। जबकि

वास्तविक रूप में 233700 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये गये। इसी प्रकार दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) में कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्रों में सभी बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से 736570 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये गये। जो नौवीं पंचवर्षीय योजना काल की तुलना में तीन गुना अधिक रहा है। वर्ष 2004–05) कृषि क्षेत्र को 115.2 हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया जो लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक था। जबकि लक्ष्य 105 हजार करोड़ रुपये का निर्धारित किया गया था। वर्ष 2005–06 में पिछले वर्षों की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक ऋण कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्रों में वितरित किया गया।

व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक : व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक से अभिप्राय उन सभी बैंकिंग संस्थाओं से लगाया जाता है जो किसी अर्थव्यवस्था में रुपये के लेन देन या व्यवसाय का कार्य करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर वाणिज्यिक बैंकों का कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए उन सभी बैंकिंग संस्थाओं पर विचार किया गया है। जो कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए ऋण प्रदान करने का कार्य करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर सभी बैंकिंग संगठनों को व्यवसायिक बैंकों के अन्तर्गत रखा जाता है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत कुल 218 अनुसूचित (विदेशी बैंकों सहित) वाणिज्यिक बैंक हैं इनमें से 161 सार्वजनिक क्षेत्र के हैं जिनमें से 133 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर. आर. बी.) हैं, और ये सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि का 75.2 प्रतिशत एकत्र करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे ऋण प्राप्तकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए विशेष रूप से की गयी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा बाकी 28 बैंकों में 19 राष्ट्रीयकृत, एस.बी.आई. समूह के 8 व आई.बी.बी.आई. लिमिटेड हैं और ये सभी तरह का बैंकिंग व्यवसाय करते हैं।

कानपुर क्षेत्र : वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य 17 मण्डलों में विभक्त हैं। वर्तमान अध्ययन कानपुर क्षेत्र के सन्दर्भ में किया गया है। कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत 6 जनपद आते हैं। जो क्रमशः फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर व कानपुर देहात हैं। इन जनपदों में

दिया गया है। भूमि के विभिन्न उपयोगों में सबसे अधिक भूमि कृषि कार्य में लगी हुयी है अतः व्यवसायिक बैंकों का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव को इसके सन्दर्भ में व्यक्त किया जायेगा।

1. **अर्थव्यवस्था का प्रारूप** : कानपुर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्यता कृषि प्रधान है। अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता को भूमि के उपयोग तथा क्षेत्र में लगी अधिकांश जनसंख्या के आधार पर स्पष्ट किया गया है। कानपुर क्षेत्र का प्रतिवेदित क्षेत्रफल 1489694 हेक्टेयर में से 1006208 हेक्टेयर क्षेत्र पर कृषि की जाती है जो प्रतिवेदित क्षेत्र का 67.5 प्रतिशत है इसी प्रकार जनसंख्या के दृष्टिकोण से वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार क्षेत्र की जनसंख्या 11209520 रही है।

(क) भूमि का उपयोग : कानपुर क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल 14776 वर्ग किलोमीटर है जिसमें प्रतिवेदित क्षेत्र 1489694 हेक्टेयर है यह प्रतिवेदित क्षेत्र विभिन्न उपयोगों में लगा हुआ है। जो निम्न हैं। वनों के अन्तर्गत लगी भूमि 65810 हेक्टेयर या प्रतिवेदित क्षेत्र का 4.4 प्रतिशत, खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लगी भूमि 133610 हेक्टेयर या प्रतिवेदित क्षेत्र का 9.5 प्रतिशत, ऊसर व खेती के अयोग्य भूमि 81665 हेक्टेयर या 4.8 प्रतिशत, कृष्य बेकार भूमि 38302 हेक्टेयर या प्रतिवेदित क्षेत्र का 2.6 प्रतिशत , चरागाह तथा अन्य वृक्ष झाड़ियों की भूमि 27438 हेक्टेयर या प्रतिवेदित क्षेत्र का 1.8 प्रतिशत, वर्तमान परती एवं अन्य परती 152658 हेक्टेयर या प्रतिवेदित क्षेत्र का 10.2 प्रतिशत तथा शेष शुद्ध बोया गया क्षेत्र 994009 हेक्टेयर या कुल रिपोर्ट की गयी भूमि का 66.7 प्रतिशत है।

(ख) जनसंख्या : क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुयी है। जनगणना वर्ष 2001 के आधार पर क्षेत्र की 11209520 जनसंख्या में 1470990 जनसंख्या कृषि कार्यों में किसी न किसी रूप में लगी हुयी है। जो कुल जनसंख्या का 13.1 प्रतिशत है और कार्यशील जनसंख्या का 42.8 प्रतिशत है जो कृषि कार्य करती है।

2. **जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण** : जनसंख्या के आर्थिक वर्गीकरण से आशय जनसंख्या के उस वर्गीकरण से है जिसके अन्तर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगी हुयी

जनसंख्या को वर्गीकृत किया गया है। कानपुर क्षेत्र की जनसंख्या में आय अर्जित करने वालों की संख्या 3438357 या कुल जनसंख्या का 30.7 प्रतिशत है। और आश्रितों की संख्या 7771173 या कुल जनसंख्या का 69.3 प्रतिशत है।

इसी आय अर्जित करने वाली जनसंख्या का विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगा होना जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण कहलाता है। इस दृष्टिकोण से कानपुर क्षेत्र की जनसंख्या में 33.6 प्रतिशत कृषक, 9.2 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 3.4 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग में लगी जनसंख्या, 33.2 प्रतिशत अन्य कर्मकर व 20.6 प्रतिशत अन्य मुख्य कर्मकर हैं।

3. **कृषि अर्थव्यवस्था :** कानपुर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के समान कृषि प्रधान है। कृषि के अन्तर्गत कानपुर क्षेत्र में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है जिसके अन्तर्गत गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, लाही/सरसों, तिलशुद्ध, मूंगफली, अलसी, दालें, चना, गन्ना व आलू आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है जिसका उत्पादन स्तर लगा क्षेत्रफल व प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन आदि को अध्याय की सारणी संख्या 38 में दर्शाया गया है इन विभिन्न फसलों में सबसे बड़े क्षेत्र में गेहूं की फसल उत्पादित की जाती है तत्पश्चात अन्य फसलों का उत्पादन होता है।

4. **कृषि आगतों की उपलब्धि एवं उपयोग :** औद्योगिक उत्पादन की भांति कृषि उत्पादन में विभिन्न आगतों की आवश्यकता होती है सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में सुधार तथा विकास के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से किसानों को कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक आगतों की आपूर्ति की जाती है। जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके और कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। कृषि आगतों की सुविधाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाओं को स्पष्ट किया जा सकता है जैसे– रासायनिक उर्वरकों का वितरण, सिचाई सुविधाओं का विकास, ट्रैक्टर एवं कृषि यन्त्रीकरण तथा अन्य तमाम प्रकार के यन्त्र क्लीनिक आदि।

5. **कृषि साख के स्रोत :** कृषि साख के स्रोतों में उन स्रोतों को रखा जाता है जिनके

माध्यम से कृषि क्षेत्र के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण या आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। कृषि साख के स्रोत ग्रामीण साख के स्रोत का एक अंग है। ग्रामीण साख के स्रोतों के अन्तर्गत उन सभी स्रोतों को रखा गया है। जिनके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न आर्थिक क्रियाओं और कार्यक्रमों के लिए ऋण प्राप्त होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसके विकास के लिए वर्तमान में जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनमें प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम राशि जिसके अन्तर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कुछ वर्गों को ऋण प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाती है, इसके तहत कमजोर वर्गों को ऋण, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को ऋण, व विभेदी ब्याज दर योजना तथा स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना और कृषि के लिए ऋण इत्यादि कार्यक्रमों के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। कृषि क्षेत्र के लिए ऋण मुख्यतया दो स्रोतों से प्राप्त होता है।

1. कृषि साख के असंगठित स्रोत
2. कृषि साख के संगठित स्रोत

कृषि साख के असंगठित स्रोतों के अन्तर्गत उन व्यक्तियों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को रखा गया है जिनके द्वारा किसानों को ऋण प्राप्त होता है तथा संगठित स्रोतों के अन्तर्गत उन स्रोतों को रखा गया है जिनके माध्यम से किसानों को ऋण सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा प्राप्त होता है। ये संस्थायें मुख्यरूप से तीन प्रकार की हैं।

1. सहकारी साख संस्थायें
2.. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. वाणिज्यिक बैंक

वर्तमान अध्ययन का क्षेत्र वाणिज्यिक बैंकों के वित्त तक सीमित है इसलिए इस अध्ययन के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राप्त ऋण के विभिन्न अंगों व स्वरूपों पर भी विचार किया जायेगा।

भारतीय प्रबन्धन के अधीन पहला सीमित दायित्व वाला बैंक अवध कामर्शियल बैंक था जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। इसके बाद सन् 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई।

बैंकिंग कम्पनी अधिनियम फरवरी 1949 में पारित हुआ जिसे संशोधन के बाद बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के रूप में जाना गया। इस अधिनियम के जरिए बैंकिंग व्यवस्था पर नियमन का कानूनी अधिकार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को मिल गया।

देश के सबसे बड़े बैंक इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1955 में किया गया और इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक आफ इण्डिया कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 1959 में इसके 7 सहयोगी बैंकों का गठन किया गया। आर्थिक विकास में बैंकिंग व्यवस्था का योगदान सुनिश्चित करने के लिए 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश जारी किया गया। जिसके माध्यम से 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया गया और 15 अप्रैल 1990 को 6 अन्य प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

वर्तमान में बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत 218 अनुसूचित (विदेशी बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंक) है। इनमें से 161 सार्वजनिक क्षेत्र के हैं जिसमें 133 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और ये सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि का 75.2 प्रतिशत एकत्र करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे ऋण लेने वालों को और ऋण मुहैया कराने के लिए विशेष रूप से की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा बाकी 28 बैंकों में 19 राष्ट्रीयकृत हैं, 8 एस.बी.आई समूह के व 1 आई.डी.बी.आई. शामिल हैं। और ये सभी तरह का बैंकिंग व्यवसाय करते हैं।

कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में प्रायः लगभग सभी प्रकार के व्यावसायिक बैंक कार्यरत हैं जिनमें से कृषि क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करने का कार्य इन बैंकों की 188 शाखाओं द्वारा किया जा रहा है। सभी इकाइयों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना सीमित साधनों और समय मे सम्भव न होने के कारण इन बैंकों ी शाखाओं का चुनाव रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर किया गया है।

वर्तमान अध्ययन में 30 प्रतिशत इकाइयों का रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर चयन किया जायेगा।

वर्तमान अध्ययन में व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 2001 से 2007 तक वितरित ऋण में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में कानपुर क्षेत्र में इन बैंकों द्वारा 972.16

करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया था। जो वर्ष 2007 में बढ़कर 2264.39 करोड़ रुपये हो गया।

ऋण वितरण के अतिरिक्त इन बैंकों द्वारा ग्रामीण जनता की बचत भी स्वीकार की जाती हैं। इनके द्वारा स्वीकार की गई बचत में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में इन बैंकों में जनता की बचत की धनराशि 3019.51 करोड़ रुपये थी जो वर्ष 2007 में बढ़कर 5099.63 करोड़ रुपये हो गई।

इस समयावधि के बीच इन बैंकों में जमा धनराशि को सारणी संख्या 57 में स्पष्ट किया गया है। और इस सम्बन्ध में विभिन्न जनपदों की स्थिति को सारणी संख्या 51 से 56 तक स्पष्ट किया गया है।

यदि इन बैंकों के ऋण जमा अनुपात पर विचार किया जाय तो ऋण की तुलना में जमा का अनुपात वृद्धिमान रहा है। वर्ष 2001 में इसका ऋण जमा अनुपात 1 : 3.10 रहा है। जो वर्ष 2007 में कम होकर 1 : 2.25 हो गया है।

कानपुर क्षेत्र की स्थिति पर विचार किया जाय तो बैंकों के ऋण जमा अनुपात में निरन्तर कमी हुई है जिसे सारणी संख्या 62 से स्पष्ट किया गया है।

कानपुर क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण जमा अनुपात में दशक 2001 से 2007 के बीच निरन्तर कमी हुई है। वर्ष 2001 में 1 : 3.10 था। जो वर्ष 2007 में कम होकर 1 : 2.25 हो गया है। जो इस बात को स्पष्ट करता है कि इन बैंकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक ऋण दिया गया है। जो ऋण जमा अनुपात के बढ़ते हुये क्रम से स्पष्ट है।

इन बैंकों द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिकाधिक मात्रा में ऋण दिया जा रहा है। जिन उद्देश्यों के लिए इनकी स्थापना की गई थी। भले ही विभिन्न जनपदों की स्थिति अलग–अलग रही है परन्तु कानपुर क्षेत्र के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से यह कहा जा सकता है कि इन बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ऋण वितरण अधिकाधिक मात्रा में किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में वित्त प्रदान करने के संस्थागत ढॉचे का निर्माण करने में ये बैंकें सहायक हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में साख में उपयुक्त संस्थाओं के विकास न होने के कारण अधिकांश ग्रामीण साख असंगठित स्रोतों से प्राप्त होती थी। जो अब संगठित स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होने लगी है। वर्ष 1951–52 में

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने यह पाया था कि कुल ग्रामीण साख का 92.7 प्रतिशत भाग असंगठित स्रोतों से प्राप्त होता है जिनसे सम्बन्धित भू–स्वामी, कृषि महाजन, पेशेवर महाजन, व्यापारी एवं कमीशन एजेण्ट एवं अन्य व्यक्ति थे जो ग्रामीण साख उपलब्ध कराते थे वहीं संगठित स्रोतों से ग्रामीण साख से प्राप्त होने वाला हिस्सा 7.3 प्रतिशत था। जिसमें सरकार, सहकारी समितियां , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व व्यापारिक बैंक शामिल थे। वर्तमान में अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण की रिपोर्ट के लगभग 5 दशकों के पश्चात इस स्थिति में परिवर्तन हुआ है। क्योंकि उस समय (1951–52) ग्रामीण साख में व्यावसायिक बैंक का हिस्सा मात्र 0.9 प्रतिशत था जिसमें अब निश्चित रूप से वृद्धि हुई है।

अतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण साख की संरचना को संस्थागत बनाने में व्यावसायिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें अध्ययन के प्रारम्भ में स्पष्ट की गई परिकल्पना की इन बैंकों द्वारा ग्रामीण साख के संस्थागत स्वरूप को विकसित करने में सहायता प्राप्त हुई है। यह सिद्ध हो जाती है।

कृषि साख से अभिप्राय उस साख या वित्त से है जिसके माध्यम से कृषि उत्पादन एवं कृषि से सम्बन्धित अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में साख की आवश्यकता विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने की होती है। जिसमें कृषि एवं तत्सम्बन्धी क्रियाकलाप, लघु उद्योग एवं व्यापार व अन्य कृषि कार्य आदि इन सभी प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तीन प्रकार के समयों के आधार पर व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋणों का वितरण किया जाता है।

कानपुर क्षेत्र में कार्यरत व्यावसायिक बैंक व उनकी शाखाओं द्वारा राष्ट्रीयकरण के पश्चात से आज तक बैंकों के क्रियाकलापों में बहुत बड़ा अन्तर देखने को मिलता है। जहां राष्ट्रीयकरण के समय व उसके कुछ दशकों के पश्चात से आज व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। वहीं इन शाखाओं द्वारा अपने वितरित ऋण में निरन्तर वृद्धि हो रही है। और इनमें से भी जो ऋण का वितरण हो रहा है वह प्राथमिकता क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया जा रहा है क्योंकि विगत कुछ वर्षों में कानपुर क्षेत्र में कार्यरत बैंकों की शाखाओं द्वारा वितरित ऋण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कुल ऋण में से प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में दिन–प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। जहां तक कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न प्रशासनिक जनपदों के सन्दर्भ में विचार करें तो यह कहा जा सकता है कि विभिन्न जनपदों में से लगभग

जनपदों में वर्ष 2001–02 की तुलना में शाखा विस्तार भी हुआ है और कुल वितरित ऋण में भी वृद्धि हुई है। तथा वितरित ऋण में से प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण में भी वृद्धि हुई है इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि व्यावसायिक बैंकों को कृषि क्षेत्र में पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में कहीं हद तक सफलता प्राप्त हुई है। जो इस बात का संकेत है कि व्यावसायिक बैंकों का जो वर्ष 1967 में सामाजिक नियन्त्रण किया गया और उसके बाद इस बात को लेकर व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कि कृषि क्षेत्रों में जो सहकारी संगठन कृषि के तकनीकी विकास हेतु पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने में असफल रही हैं उसको व्यावसायिक बैंकों द्वारा सफल बनाया जा सकता है, के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीयकरण हुआ था। अतः यह कहा जा सकता है कि विभिन्न जनपदों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में व्यावसायिक बैंकें सफल सिद्ध हो रही हैं। इस प्रकार अध्ययन के प्रारम्भ में स्पष्ट की गई प्रथम परिकल्पना की वाणिज्यिक बैंकों के वित्त प्रदान करने के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ढांचा अधिक विस्तृत व मजबूत हो सका है इसकी पुष्टि हो जाती है।

दूसरी परिकल्पना कि वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से किसानों को पर्याप्त मात्रा में वित्त प्रदान होने के परिणामस्वरूप कृषि के विकास में सहायता प्राप्त हुई है। इसकी भी पुष्टि हो जाती है क्योंकि अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि कानपुर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर परिवर्तन व सुधार देखने में आया है जिसके पीछे व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण का योगदान प्रमुख रहा है क्योंकि अन्य वित्तीय संसाधन वित्त की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने में असफल या असमर्थ सिद्ध हुये हैं इसलिए व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण से कृषि क्षेत्र में विकास सम्भव हुआ है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण से कृषि क्षेत्र में व्यापक रूप से सुधार व विकास देखने को मिल रहा है।

व्यावसायिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में विभिन्न समयावधियों को ध्यान में रखकर ऋण दिये जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में दिन प्रतिदिन के उत्पादन की आवश्यकताओं के लिए अल्पकालीन ऋण दिये जाते हैं। जिनकी अवधि 9 महीने से 15 महीनों तक की होती है। व्यावसायिक बैंकों द्वारा 3270353 हजार रुपये के ऋण कृषि उत्पादन की अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिये गये, मध्यकालीन ऋण की आवश्यकता पूंजी निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत होती है इसके अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण का समय 15 महीने से लेकर 5 वर्ष

तक का होता है। इस समयावधि के लिए कानपुर क्षेत्र में 3083638 हजार रुपये के ऋण दिये गये। कृषि उत्पादन में पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। क्योंकि कृषि उत्पादन के लिए पूंजीगत संसाधन एकत्र करने के लिए एक बड़ी मात्रा में पूंजी के निवेश की आवश्यकता होती है जो व्यावसायिक बैंकों द्वारा ही सम्भव होता है। इन बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋण में से 466010 हजार रुपये के ऋण इस समय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दिये गये।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा इन तीनों प्रकार के ऋणों में मुख्यतया अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण दिये जा रहे हैं। जिसमें कानपुर क्षेत्र में सबसे अधिक दीर्घकालीन ऋण दिये जा रहे हैं। इसके पश्चात् अल्पकाल व मध्यकाल का नम्बर आता है। इन बैंकों द्वारा दिये जाने वाले दीर्घकालीन ऋण को अधिकाधिक मात्रा में प्रोत्सहित किया जाना चाहिए क्योंकि दीर्घकालीन ऋणों से किसान अपने उत्पादन कार्य के लिए आवश्यक पूंजी का प्रबन्ध करने के लिए समर्थ होगा। अतः कृषि को आर्थिक इकाई बनाने के लिए अर्थशास्त्रियों को दो दृष्टिकोण से विचार करना होगा।

प्रथम भूमि सुधार–जिसके लिए हमारे देश की सरकारें प्रयत्नशील हैं पर अर्थशास्त्रियों को यह देखना होगा कि भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है या नहीं। दूसरी ओर किसानों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का प्रबन्ध जिससे किसान अपनी उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ऐसा माना जाता है कि वित्त के संस्थागत स्रोतों के माध्यम से उसे उपयुक्त मात्रा में उचित शर्तों पर ऋण प्राप्त हो सकेगा। जिसके लिए व्यावसायिक बैंक कार्यरत हैं।

वर्तमान अध्ययन में प्राथमिक संमकों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक संमकों के अन्तर्गत आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से विभिन्न बैंक शाखओं में जाकर व विभिन्न साख प्राप्त लाभार्थियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके उनके द्वारा व्यक्त विचारों एवं उनके द्वारा प्राप्त की रकम को वर्तमान अध्याय में स्पष्ट किया गया है। वर्तमान अध्याय के अन्तर्गत कानपुर क्षेत्र में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों में से अध्ययन के लिए रैण्डम सैम्पलिंग के माध्यम से 30 प्रतिशत इकाइयों का चयन किया गया है। इन इकाइयों के द्वारा कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों

में वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में जो ऋण वितरित किया गया है व जिन व्यक्तियों को साख प्राप्त हो सका है उन व्यक्तियों के विचार जानने के लिए साख प्राप्त लाभार्थियों का रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर 25 प्रतिशत व्यक्तियों को अध्ययन के लिए चयन किया गया है। अध्ययन के लिए चयन कर इन व्यक्तियों के द्वारा कानपुर क्षेत्र की विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में उनकी नामावली प्राप्त की गई है। जहां तक बैंकिंग इकाइयों व लाभार्थियों की संख्या के अध्ययन का प्रश्न है प्रत्येक प्रकार की बैंक जो कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में कार्य कर रही है जनपद स्तर पर विभिन्न व्यावसायिक बैंकों के नामों के आधार पर 30 प्रतिशत इकाइयों को अध्ययन के लिए चयन किया गया है। अध्ययन के लिए चयन में यह भी स्थिति उत्पन्न हुई है कि यदि किसी बैंक की कम शाखायें जनपद में कार्यरत हैं तो उसका चयन 30 प्रतिशत से अधिक भी हुआ है और संख्या कम होने पर चयन से वंचित भी हो गई हैं लेकिन अध्ययन के लिए चयन करते समय एक बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया है कि कानपुर क्षेत्र में विभिन्न जनपदों में विकासखण्ड स्तर पर कार्यरत किसी न किसी व्यावसायिक बैंक शाखा का अध्ययन के लिए अवश्य चयन किया गया है जिससे अध्ययन क्षेत्र का विस्तार हो सके और सही आंकड़े प्राप्त किये जा सकें। यही स्थिति लाभार्थियों के चयन के सम्बन्ध में लागू की गई है। इसमें भी कानपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में कार्यरत विकासखण्डों में पहुंचने की कोशिश की गई है।

कानपुर क्षेत्र में 188 व्यावसायिक बैंकों की शाखायें कार्यरत हैं जिसमें से अध्ययन के लिए 57 बैंकों शाखाओं का चयन किया गया है। इन सभी बैंक शाखाओं के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता क्षेत्र में कानपुर क्षेत्र के सभी जनपदों में 3716838 हजार रुपये के 36202 व्यक्तियों को वित्त प्रदान किये गये हैं। यह वित्त विभिन्न समयों के लिए दिये गये हैं। अल्पकाल समय के लिए क्षेत्र में वितरित ऋण का 32.3 प्रतिशत भाग, मध्यकाल समय के लिए क्षेत्र में वितरित ऋण का 24.8 प्रतिशत भाग व दीर्घकाल समय के लिए क्षेत्र में वितरित ऋण का 42.9 प्रतिशत भाग ऋण प्रदान किया गया। इस प्रकार कानपुर क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का सबसे अधिक वित्त दीर्घकाल समय के लिए प्रदान किये गये। जिससे कृषि क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ाया जा सके। जिससे कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक का प्रयोग सम्भव हो सके जिससे कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कानपुर क्षेत्र में विभिन्न समयों के लिए जो ऋण वितरित किये गये हैं वह विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये दिये गये हैं। प्राथमिकता क्षेत्र में जो ऋण वितरित किये गये हैं उसमें से 75.2 प्रतिशत या 2795940 हजार रुपये के ऋण प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र में निवेश किये गये हैं। कृषि क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक बैंक शाखाओं द्वारा वितरित यह ऋण ट्रैक्टर एवं कृषि

उपकरणों को क्रय करने, सिचाई सुविधाओं का विकास करने, कोल्ड स्टोरेज खोलने, अनाज भण्डार गृह खोलने, दिन–प्रतिदिन की कृषि क्षेत्र में वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करने, भवन निर्माण, खेतों तक पहुंचने के लिए मोटर साइकिल आदि क्रय करने के लिए यह ऋण वितरित किये गये। कानपुर क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त लघु उद्योग के विकास करने के लिए कानपुर क्षेत्र में वितरित ऋण का 8 प्रतिशत या 297173 हजार रुपये के ऋण 1584 व्यक्तियों को दिये गये। लघु उद्योग क्षेत्र में ऋण प्रदान करने से निश्चित ही लघु उद्योग क्षेत्र का विकास हुआ है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में आवास करने वाले व्यक्तियों को एक ओर जहां रोजगार प्राप्त हुआ है वहीं दूसरी ओर लघु उद्योग उद्यमियों की आय में वृद्धि हो सकी है तथा अतिरेक उत्पादन हो सका है। कानपुर क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य प्राथमिकता क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण का 16.8 प्रतिशत या 624290 हजार रुपये 5369 व्यक्तियों को दिये गये। अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत सघन मिनी डेरी का विकास करने के लिए, पालतू पशुओं को क्रय करने के लिए, मतस्य पालन करने के लिए, कुक्कुट पालन करने के लिए, मधुमक्खी पालन करने के लिए एवं अन्य विभिन्न प्रकार के कृषि एवं उससे सम्बन्धित या ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा की गई जिससे कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों का विकास हो सके। जिससे कृषि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी ग्रामीण क्षेत्र में आवास करने वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो सके।

कानपुर क्षेत्र में इन विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए जो विभिन्न बैंक शाखाओं के द्वारा ऋण वितरित किये गये है। इनमें शाखा स्तर पर व जनपद स्तर पर ऋण वितरण में परिवर्तन की स्थिति रही है। प्रत्येक क्षेत्र में ऋण वितरण अलग–अलग स्तर पर हुआ है।

कानपुर क्षेत्र में इन 57 बैंक शाखाओं से जिन व्यक्तियों को साख प्राप्त हो सका है उनका जनपद स्तर पर अध्ययन के लिए 25 प्रतिशत व्यक्तियों का चयन किया गया है। जिसमें से फर्रूखाबाद जनपद के अन्तर्गत 1842 व्यक्तियों का अध्ययन के लिए चयन किया गया, कन्नौज जनपद के अन्तर्गत 964 व्यक्तियों का अध्ययन के लिए चयन किया गया, इटावा जनपद के अन्तर्गत 3041 व्यक्तियों का अध्ययन के लिए चयन किया गया, औरैया जनपद में 667 व्यक्तियों का अध्ययन के लिए चयन किया गया, कानपुर नगर जनपद के अन्तर्गत 1662 व्यक्तियों का अध्ययन के लिए चयन किया गया व कानपुर देहात जनपद में 868 व्यक्तियों का अध्ययन के लिए

चयन किया गया। इस प्रकार कानपुर क्षेत्र में कुल 9044 व्यक्तियों का अध्ययन के लिए चयन किया गया है।

कानपुर क्षेत्र में अध्ययन के लिए चयनित इन व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बैंक शाखा जाकर उनकी नामावली प्राप्त की गई तथा प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्नावली के माध्यम से ऋण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त जानकारी में यह पाया गया कि कानपुर क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को किसी भी व्यावसायिक बैंक शाखा से ऋण प्राप्त हुआ है उनकी आर्थिक स्थिति भिन्न–भिन्न प्रकार की रही है अतः कानपुर क्षेत्र में साख प्राप्त व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को अध्ययन की दृष्टिकोण से 3 भागों में विभक्त किया गया है–

1. **निम्न आय वर्ग के व्यक्ति :** इस वर्ग के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को रखा गया है जिनकी चल अचल या किसी भी प्रकार के आय के स्रोतों से वार्षिक आय 20,000 रुपये तक है या जिनके पास भू–राजस्व लेखे में एक बीघे से पाँच बीघे तक सिंचित भूमि पाई जाती है। उन्हें निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत रखा गया है या इन्हें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की श्रेणी में रखा जा सकता है।

2. **मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति :** मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को रखा गया है जिनकी वार्षिक आय चल–अचल किसी भी प्रकार की सम्पत्ति या स्रोतों से वार्षिक आय 21,000 हजार रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक है या जिनके पास भू–राजस्व लेखे के अनुसार 6 बीघे से लेकर 25 बीघे तक सिंचित भूमि पाई जाती है। इन्हें गरीबी रेखा से ऊपर और आयकर विभाग से विभिन्न करों से मुक्त रखा गया है। इस प्रकार के व्यक्तियों को इस श्रेणी में रखा गया है।

3. **उच्च आय वर्ग के व्यक्ति :** उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को रखा गया है जिनकी किसी भी प्रकार के स्रोतों से वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से अधिक है। या जिनके पास भू–राजस्व लेखे के अनुसार 25 बीघे से ऊपर सिंचित भूमि पाई जाती है। आयकर विभाग द्वारा जिनसे विभिन्न कर वसूल किये जाते हैं इन्हें उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत रखा गया है।

कानपुर क्षेत्र में इन तीनों ही प्रकार के आय वर्ग के व्यक्तियों को विभिन्न बैंक

शाखाओं के द्वारा वित्त प्रदान किया गया है। जहां तक विभिन्न व्यक्तियों के मध्य ऋण के वितरण का प्रश्न है तो सबसे ज्यादा मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराये गये हैं। जबकि औसत रूप से ऋण की मात्रा सबसे ज्यादा उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को दी गई है। जबकि कानपुर क्षेत्र में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को कम ही ऋण उपलब्ध हो पाया है।

धन का उपयोग : कानपुर क्षेत्र में अध्ययन करने के पश्चात् यह स्पष्ट हुआ है कि इन तीनों ही प्रकार के आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा जो विभिन्न बैंक शाखाओं से ऋण प्राप्त किया गया है उसमें से उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा सबसे अधिक प्राप्त वित्त का सदुपयोग किया गया है क्योंकि उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के जीवन स्तर में द्रुत गति से विकास हुआ है। जबकि इसके बाद मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा भी ऋण का अपेक्षाकृत निम्न आय वर्ग की तुलना में अधिक सदुपयोग किया गया है। इस प्रकार के वर्ग के व्यक्तियों के ऊपर भी व्यावसायिक बैंकों के वित्त का अनुकूल प्रभाव पड़ा है। किन्तु निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा धन का अपेक्षाकृत कम ही उपयोग कर पाना अध्ययन में पाया गया है। इस वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा धन का उचित उपयोग न कर पाने के कारण व्यावसायिक बैंकों के वित्त का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है जैसा कि अध्ययन से स्पष्ट है।

कानपुर क्षेत्र में विभिन्न आय वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न बैंक शाखाओं से प्राप्त ऋण व उसके उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सका है कि व्यावसायिक बैंकों के विकास होने से ग्रामीण क्षेत्र में वित्त की उपलब्धता हो सकी है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विकास में जो वित्तीय बाधायें उत्पन्न होती थी उससे एक सीमा तक निपटा जा सका है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो रहा है। व्यावसायिक बैंकों के द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के पर्याप्त अवसर सुलभ हुये हैं। जैसा कि अध्ययन से स्पष्ट हो सका है। कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों के वित्त प्रदान करने से असंगठित संगठनों से प्राप्त वित्त में कमी आई है जिससे किसानों को असंगठित संगठनों के शोषण से बचाया जा सका है क्योंकि जैसा कि अध्ययन में पाया गया है कि दिन–प्रतिदिन कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा प्रदान की जा रही वित्त की मात्रा में वृद्धि हो रही है। जो इस बात को स्पष्ट करती है कि जहां व्यावसायिक बैंकों के विकास न होने के पहले कृषि क्षेत्र में वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति असंगठित संगठनों के माध्यम से प्राप्त होती थी वहीं अब संस्थागत स्रोतों से प्राप्त हो रही है। जहां तक संस्थागत व गैर संस्थागत स्रोतों का प्रश्न है निश्चित ही गैर संस्थागत स्रोतों की अपेक्षा संस्थागत स्रोतों से साधारण जनहित

की रक्षा की जा सकी है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से जो भी कार्य सम्पादित किये जाते हैं वह इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किये जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे लाभ प्राप्त हो सके। इसी का पर्याय व्यावसायिक बैंकें भी हैं। जहां तक गैर संस्थागत स्रोतों का प्रश्न है इन स्रोतों के माध्यम से जनहित की रक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि इन स्रोतों के द्वारा जो भी कार्य किये जाते हैं वह व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर ही किये जाते हैं और जहां पर व्यक्तिगत लाभ सर्वोपरि होता है वहां पर निश्चित ही साधारण जनहित की रक्षा नहीं की जा सकती और इसी का पर्याय गैर संस्थागत स्रोत भी रहे हैं जहां पर किसानों का अनुचित शोषण भी किया गया है जैसा कि पिछले अध्यायों में स्पष्ट किया जा चुका है।

कानपुर क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा वित्त प्रदान करने से अध्ययन के प्रारम्भ में स्पष्ट की गई परिकल्पना की व्यावसायिक बैंकों के वित्त प्रदान करने से कृषि साख का ढॉचा विस्तृत व मजबूत हो सका है। निश्चित ही इसकी पुष्टि हो जाती है। जैसा कि अध्ययन में पाया गया है।

कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों के वित्त प्रदान करने से गैर संस्थागत संगठनों के शोषण से किसानों को बचाया जा सका है। क्योंकि व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त वित्त की मात्रा में दिन–प्रतिदिन वृद्धि होने से इस परिकल्पना की भी पुष्टि हो जाती है कि व्यावसायिक बैंकों के वित्त प्रदान करने से असंगठित संगठनों के शोषण से किसानों को बचाया जा सका है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सका है।

तीसरी परिकल्पना की व्यावसायिक बैंकों के वित्त प्रदान करने से कृषि क्षेत्र में निवेश का स्तर बढ़ सका है इसकी भी पुष्टि हो जाती है क्योंकि आज कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा आवश्यकतानुसार वित्त प्राप्त हो सका है। जिससे कृषि क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन किया जा सका है जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन स्तर में वृद्धि हुयी है।

चौथी परिकल्पना की व्यावसायिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने से कृषि अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक इकाई के रूप में देखा जा सकता है इसकी भी कहीं हद तक पूर्ति ही हो जाती है। क्योंकि कृषि क्षेत्र में निवेश का स्तर बढ़ने से निश्चित ही उत्पादन स्तर में वृद्धि हुई है। और उत्पादन स्तर में वृद्धि होने से यह अवश्य कहा जा सकता है कि कृषि

अर्थव्यवस्था में यदि और अधिक सुधार किये जायें तो निश्चित ही कृषि क्षेत्र को भी एक आर्थिक इकाई बनाया जा सकता है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निश्चित ही व्यावसायिक बैंकों के विकास के साथ–साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास सम्भव हो सका है क्योंकि व्यावसायिक बैंकों के द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ध्यान में रखकर ऋण का वितरण किया जा रहा है। जिससे असहाय दुर्लभ व कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की वित्तीय समस्याओं का समाधान हुआ है। जिससे इनके जीवन स्तर में अपेक्षाकृत सुधार हो सका है।

जैसा कि अध्ययन में पाया गया है कि आज भी पर्याप्त मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे व्यक्तियों के सामने वित्त की समस्या है अतः वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त प्रदान किये जायें और यह वित्त सबसे ज्यादा मात्रा में दीर्घकालिक समय को ध्यान में रखकर दिये जायें जिससे कृषि क्षेत्र में निवेश का स्तर बढाया जा सके, चूंकि कानपुर क्षेत्र की आधे से अधिक आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्र मे निवास कर रही है और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को जीविकोपार्जन का मुख्य साधन आज भी कृषि क्षेत्र है। इसलिए जबतक कृषि क्षेत्र मे पर्याप्त मात्रा में निवेश नहीं होगा तब तक कृषि क्षेत्र का विकास नहीं होगा और जबतक कृषि क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना सम्भव नहीं है ऐसी स्थिति में भंयकर अपराध होते हैं। अतः किसी भी विषम स्थिति से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर वित्त की आवश्यकता है जैसा कि आज देखा जा रहा है कि भारतीय कृषि पूर्ण रूप से सिचाई के अभाव से तृस्त है। जैसा कि अध्ययन में पाया गया है कि कानपुर क्षेत्र में जितने भी भू–भाग पर खेती की जाती है उसका एक बड़ा भाग असिंचित क्षेत्र रहता है और इस असिंचित क्षेत्र में अतिरिक्त फसल का उत्पादन कर पाना सम्भव नहीं हो सकता। यह असिंचित क्षेत्र पूर्णतया मानसून पर निर्भर है यदि समय पर मानसून आता है वर्षा होती है तो असिंचित क्षेत्र में बोवाई की जा सकती है जिससे फसले उत्पादित की जा सकती हैं। अन्यथा की स्थिति में सम्भव नहीं है और कृषि क्षेत्र का बड़ा भू–भाग परती के रूप में पड़ा रहता है। जैसा कि वर्तमान में कुछ वर्षो से मानसून में गिरावट आई है जिसके कारण वर्षा में कमी आयी है या वर्षा की असमानता की स्थिति हो गयी है। जिसके कारण सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है और इस सूखा जैसी स्थिति से निपटने के लिए निश्चित तौर पर व्यापक पैमाने पर वित्त की आवश्यकता है। जिसको वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाना सम्भव है अतः

चाहिए कि वे पर्याप्त मात्रा में वित्त प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग प्रदान करे।

देश में आर्थिक आयोजन के प्रारम्भ में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने कृषि विकास का सारा दायित्व सहकारी साख संगठन पर डाला था और देश के विचारक भी यह समझते थे कि सहकारी बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से कृषि विकास हो सकेगा। और ग्राम स्वराज्य की स्थापना हो सकेगी। इसलिए कमेटी ने यह स्पष्ट किया था कि अगर देश में सहकारिता असफल होती है तो भारत का भविष्य अंधकारमय होगा। कमेटी की सिफारिशों के 10 वर्षों के पश्चात् श्री बैकुण्ठ लाल मेहता कमेटी ने यह पाया था कि सहकारी बैंकिंग व्यवस्था अभी भी कमजोर बनी हुयी है। उनका संगठन सक्षम इकाइयों के आधार पर किया जाना चाहिए। यद्यपि सहकारी बैंकिंग व्यवस्था का योगदान जो मात्र 1.2 प्रतिशत सन् 1951–52 में था वह बढ़कर लगभग 12 प्रतिशत हो गया है। पर सहकारी बैंकिंग व्यवस्था से कृषि के लिए आवश्यक पूंजी नहीं प्राप्त हो सकी थी। इस दिशा में विकास उस समय प्रारम्भ हुआ जब विचारकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और ग्रामीण ऋण व्यवस्था में बहु एजेन्सी दृष्टिकोण अपनाया गया। इस दिशा में व्यावसायिक बैंक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

बहुएजेन्सी दृष्टिकोण अपनाये जाने के पश्चात् किसी विशेष संगठन को एक सक्षम इकाई बनाने का प्रश्न हल हो चुका है। वर्तमान में कृषकों की आर्थिक स्थिति या देश की निर्धनता समाप्त करने के लिए कृषि को सक्षम इकाई बनाने का प्रश्न सामने आ गया है। और कृषि को सक्षम इकाई बनाने के लिए तकनीक में परिवर्तन की आवश्यकता है। उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन दीर्घकालीन होता है पर दीर्घकालीन परिवर्तन के माध्यम से जनसाधारण की आर्थिक समस्याओं को हल नही किया जा सकता।

यद्यपि यह कहा जाता है कि जैसे–जैसे किसी देश का आर्थिक विकास होता जाता है उस देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व कम होता जाता है फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक बड़ा व्यवसाय है। और अधिकांश जनसंख्या उससे अपनी आजीविका अर्जित करती है। कृषि उत्पादन श्रम प्रधान उत्पादन तकनीकी पर निर्भर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या में तीव्रदर से वृद्धि होने के कारण कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और प्रछन्न बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है। प्रछन्न बेरोजगारी की स्थिति रैडनर

नर्क्स (Ragner Nurks) के अनुसार एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अन्तर्गत श्रम की सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है या ऋणात्मक होती है। इस स्थिति के अन्तर्गत भारतीय कृषि में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हुये हैं जिसे उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन करके ही हटाया जा सकता है। उत्पादन की वैकल्पिक तकनीक पूंजी प्रधान उत्पादन तकनीक है जिसके लिए अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी की प्राप्ति या निर्माण बचत के स्तर पर निर्भर है। पर बचत का स्तर देश में निम्न होने के कारण यह सम्भव नहीं है ऐसी स्थिति में एक ओर कृषि क्षेत्र में पूंजी की प्राप्ति के लिए इन बैंकों के माध्यम से ऋण की प्राप्ति कराई जा सकती है। जिससे किसानों को शोषण से बचाया जा सके क्योंकि बैंक संगठनात्मक साख के स्रोत हैं दूसरी ओर लोगों के बचत स्तर को बढ़ाने के लिए उन बैंकों द्वारा दिये गये ऋण के प्रयोग पर कड़ी निगाह रखनी होगी। जिससे इनका सदुपयोग हो सके। जिससे जनसाधारण का बचत स्तर बढ़ सके और कृषि क्षेत्र में पूंजी की प्राप्ति हो सके जिसके माध्यम से कृषि को एक सक्षम इकाई बनाया जा सके।



परिशिष्ट : 1

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Attar Chand : Economics Planning and Development Vol. I
2. Angrish, A.C. : Regional Economics Planning in India
3. Adiseshiah : Forty Years of Economics Development.
4. Agrawal B.P. : "Commercial Banking in India after Nationalisation" Classical Publishing Company, New Delhi, 1982.
5. Anand S.C. : Handbook on Regional Rural Banks.
6. Basu S.K : Commercial Banks and Agriculture Credit- A Study in Regional Disparity in India.
7. Bhopal Singh : Co-operative Credit and Regional Development- A study of Pauri Garhwal- Negi.
8. B.B. Battacharya : India's Economics Crisis, Debt. Burden and Stablisation.
9. Bedi, H.L. : Practical Banking Advances.
10. Chaubey B.N. : "Principles and Practices of co-operative Banking in India." Asia Publishing House, 1968

11. Conant Charles A : "A History of Modern Banks of issue"

12. Chanana Charanjeet : Agriculture Finance in India- Role of Commercial Banks

13. Chaudhery D.N. : Bank Finance Practical Aspects.

14. Chaudhery D.N., Agrawal, H.N : Modern Banking in India

15. Chauhan Dilip J. : Rule of Commercial Banks in Agricultural Deveopment.

16. Chaudhary, T.P.S and Sharma J.N. : Crop Loan System- A study in Andhrpradesh

17. Dendkar, V.N. : Dicussion Reorganisation of Rural credit in India.

18. Dahya I.N. : Dynamics of Economics Life in Rural India.

19. Dermine, J. : European Banking in the 190s

20. DR. Hukka, V.N : H.R.D. in Banking Sector.

21. Desai, S.S.M. : Rural Banking in India

22. Desai, R.G. : Short term Finance for Agriculture Development- A study of Small Farmers Service Societies of Balia District in Karnataka.(Ph.D. Thesis)

23. Desai, V.K. : "Rural Economics "

24. Elias, A.H. : "Operational Problems of Rural Banking"

25. Eastern Book Co. : Regional Rural Banks Act 1976

26. Ghosh, D.N. : Banking Policy in India.

27. Gupta, K. : Credit Planning and Management

28. Garhwal, S. : Commercial Banking and Economic Development

29. Ghosh, M.N. : Economic Development and Change

30. G.K. Chadha : Policy Perspectives in Indian Economic Development.

31. Ganguly, A.K. : Rural Banking.

32. Gaikwad, V.K and Parma D.S. : Serving small Farmers Centre for Management of Agriculture.

33. Horne, H. Oliver : "A History of Savings Banks" Oxford University Press, London, 1947.

34. Jatara. : Lead Bank Scheme.

35. Jain, A.K. : Nationalized Banks and Rural Credit.

36. Jacob, J. : Nationalized Banks and Agricultural Finance with Special Reference to M.P. (Ph.D. Thesis)

37. Joshi, N.C. : Indian Banking

38. Jain, L.C. : "Indiginous Banking in India" Macilan, Landon, 1929

39. John, H. Wood : Commercial Bank Loan and investment Behariour

40. Kalyankar, S.P. : Crop Loan overdues of Co-operative.

41. Khoury : Recent Development in International Banking of Finance.

42. Kripashankar : "Economics Development of Uttar Pradesh" Arthik Anusandhan Kendra Allahabad, 1970.

43. Krishnaswamy, O.R. : "Fundamentals of Co-operation"

44. Lal Chhote : Finance of Agriculture in Eastern U.P.

45. Lal Wani, S.J. : Charging Profile of Indian Banking.

46. Mathur B.S. : "Co-operative in India" Sahitya Bhavan, Agra.

47. Malya Paramjeet & Rao, V.C. : Agricultural Finance by Commercial Banks.

48. Menon, C.R.B. : A Rural Credit Scheme for India.

49. Mohsin, M. : Financing Planing and Control.

50. Mesh Ram, P.J. : Institutional Credit in India.

51. Mishra, R.P., Sundaram K.V. : Multi-level, Planing and Integrated rural Development

52. Mathur, O.P. : Public Sector Bank in India's economy.

53. Naidu, V.T. : Farm Credit and Co-operatives in India

54. Naidu, L.K. : Financing Weaker Sections by Commercial Banks, Bank Finance for rural Development

55. Nigam, B.M.L. : "Banking Law and Practice" Vani Educational Books Ghaziabad, 1985.

56. Nigam, B.M.L. : Banking and Economic Growth

57. Nabard : "Development Through Credit" 1982.

58.Pundir, J.K. : Banking Bureaucracy and Social Network.

59. Plumpre, A.F.W. : Central Banking in the British Division.

60. Pandey, L.K. : Development of Banking in Inida Since 1949-1968.

61. Pandey, R.K. : Institutional Credit of Agriculture in India.

62. Panan, Dikar, S.C. : Banking in India.

63. P.V. Rajeev : Economic Development of Asian Countries

64. Rao. B. Ramchandra : Current Trends in Indian Banking

65. Rao, M.K. : Management of Central Co-operating Banks.

66. Reddy, A.G.N : Rural Dynamics Development.

67. Rangrajan, C. : Innovations in Banking The Indian Experience

68. Sharma, J.K. : Bank Credit and Economics Development in India.

69. Syed Mohammad ismail : Critical Analysis of Capitalism, Socialism and Islamic Economics.

70. Sexena, H.K. : Credit Finance for Integrated Rural Development Program in Balia District of East U.P.

71. Satya Sundaram : Financing of I.R.D.P.

72. Sarda, D.P. : Hand Book in Working Capital Finance

73. Subramanyam : Modern Banking Moetary Policy and Finance.

74. Sriniwas, M. : Organisation and Management of Co-operative Bank.

75. Singh, Hira. : Rule of Agricultural Credit in Economic Development of India Agriculture (Ph.D. Thesis)

76. Singh, Ajeet : Rural Development and Banking in India.

77. Subramaya, S. : Trends and Progress of Banking in India.

78. Singh, M.P. : Economics of Government Expenditure Growth.

79. Sarkar, K.C. : Cooperative movement in united Provinces.

80. Savage, D.T. : Money and Banking.

81. Singh, J.P. : Supply of Demand for Agricultural Credit.

82. Thingalaya, N.K.	:	On Bankers and Economics.
83. Trescott, P.B.	:	Money Banking and Economic Welfare
84. Thomos, Rollin, G.	:	Our Modern Banking and Monetry System.
85. U.N.A.P.D.I.	:	Local Lavel planing and Rural Development.
86. Verma, R.R.	:	Rural Development and Anti-Poverty Program Vol. 2
87. Vishwanathan, B.S.	:	The Rule of Development Banks in Indian Agriculture.
88. Vyas, M.R.	:	Evaluation and Management of RRBs.
89. Wihtool, R	:	The Asian Development Bank in Rural Development.
90. W.N. Vyas, S.N. Samadani	:	Crossing the Poverty line
91. White, Horace	:	Money and Banking
92. Yadav, S.S.	:	Rural Development and Poverty.

परिशिष्ट : 2

पत्र-पत्रिकायें

1. आर्थिक चेतना
2. इकोनामिक पोलिटिकल
3. कामर्स
4. खादी ग्राम उद्योग
5. योजना
6. सम्पदा
7. बिजनेस स्टैण्डर्ड
8. सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश शासन राज्य योजना आयोग, लखनऊ
9. सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश शासन राज्य योजना आयोग, लखनऊ
10. सांख्यिकीय पत्रिका उत्तर प्रदेश शासन राज्य योजना आयोग, लखनऊ
11. दैनिक जागरण – कानपुर संस्करण
12. हिन्दुस्तान – कानपुर संस्करण
13. राष्ट्रीय सहारा – कानपुर संस्करण
14. वार्षिक ऋण योजना
15. Reserve Bank Of India Bulletin
16. Banking Statics
17. Annual Report On Trends And Progress of Banking In India
18. Economic Times
19. Times of India
20. Monthly Commentary on Indian Economics
21. The Indian Economic and Social History Review
22. Quarterly Economic Report

परिशिष्ट : 3

प्रश्नावली

1. नाम .... पता ....

....

....

विकासखण्ड का नाम ....

जनपद का नाम ....

2. बैंक का नाम जहाँ से ऋण प्राप्त हुआ है ....

(A) आपकी हैसियत क्या है कृषक/भूमिहीन कृषक यदि कृषक तो आपके पास कितनी भूमि कृषि के लिए है ....

(B) क्या इस भूमि से आपके परिवार का भरण–पोषण हो जाता है ....

3. ऋण की रकम ....

4. यह ऋण कितने समय के लिए प्राप्त किया गया ....

5. ऋण प्राप्त करने का उद्देश्य क्या था ....

6. क्या आपने ऋण का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त किया था उसमें किया है/नहीं ....

7 क्या आपको ऋण की रकम वापस करने में कठिनाई हो रही है/नही यदि है तो क्यों ....

8. क्या यह ऋण आपको अल्पकालीन या एक वर्ष के समय के लिए प्राप्त हुआ था ? है/नहीं, यदि है तो यह किस उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया..............

....

9. क्या इस ऋण से आपकी आय में वृद्धि हुई है– है/नहीं, यदि नहीं तो क्यों.......

....

10. क्या आपको मध्यमकालीन ऋण प्राप्त हुआ है– है/नहीं, यदि है तो ऋण की रकम...

ऋण का उद्देश्य ....

ऋण की अदायगी का समय ....

क्या आपने ऋण की अदायगी समय से की है– हाँ/नहीं, नहीं तो क्यों ....

....

11. क्या आपके द्वारा लिये गये ऋण से आपकी आय में वृद्धि हुई है ....

यदि नहीं तो क्यों ....

12. क्या आपने बैंक से दीर्घकालीन समय के लिए ऋण प्राप्त किया है– है/नहीं ...

..............................यदि है तो ऋण की अदायगी का समय ....

.ऋण का उद्देश्य ....

ऋण की रकम ....

13. आपने बैंक से जितना ऋण लिया है उससे आपके परिवार की आय में वृद्धि हुई या नहीं, यदि नहीं तो क्यों ....

14. आपको बैंक से ऋण प्राप्त करने में किन–किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ....

....

15. आपने बैंक से ऋण लेने के लिए जिस दिन प्रार्थना पत्र दिया था उसके कितने दिनों बाद ऋण प्राप्त हो सका ....

16. बैंक से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में बैंक की कार्यप्रणाली के विषय में अपने विचार दीजिए। ....

....

बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अपने सुझाव दीजिए। ....

....

....

....

....